रिकॉर्ड ऊंचाई पर रक्षा निर्यात

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, पिछले वित्त वर्ष में देश का रक्षा निर्यात बढ़कर 38,424 करोड़ रुपये हो गया, जो न केवल एक नया कीर्तिमान है, बल्कि यह पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 62.66 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि भी दर्शाता है. रक्षा निर्यात का यह रिकॉर्ड रक्षा क्षेत्र में देश की बढ़ती ताकत, आत्मनिर्भरता और वैश्विक स्तर पर बढ़ते प्रभाव का संकेत है. यह इसका भी ठोस प्रमाण है कि दुनिया भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं और उन्नत मैन्युफैक्चरिंग पर अब तेजी से भरोसा कर रही है. रक्षा मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के नजरिये और सरकार द्वारा लागू किये गये नीतिगत सुधारों की वजह से ही यह सब कुछ संभव हो पाया है. ईज ऑफ डुइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए रक्षा खरीद विभाग ने निर्यात प्रक्रिया को तो आसान बनाया ही है, एक नये ऑनलाइन पोर्टल के साथ एसओपी भी लागू की गयी है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मुताबिक, इस उपलब्धि में सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्र की अहम भूमिका रही. इस दौरान सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान 54.84 फीसदी रहा, तो निजी कंपनियों ने 45.16 प्रतिशत का योगदान दिया. ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारत का रक्षा क्षेत्र अब एक मजबूत, सहयोगी और आत्मनिर्भर व्यवस्था के रूप में विकसित हो रहा है. विशेषज्ञों के अनुसार, भारत के रक्षा उत्पादों की बढ़ती गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धी कीमतें और तकनीकी क्षमता ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग बढ़ायी है तथा आने वाले वर्षों में रक्षा निर्यात को और बढ़ाने के लिए सरकार नयी रणनीतियों और साझेदारियों पर भी काम कर रही है. रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले पांच साल में देश का रक्षा निर्यात करीब तीन गुना बढ़ गया है. आज भारत दुनिया के 80 से ज्यादा देशों को रक्षा उपकरण और सिस्टम निर्यात कर रहा है. रक्षा मंत्रालय ने पिछले वित्त वर्ष में एक और उपलब्धि हासिल की है. मंत्रालय ने अपने पूंजीगत बजट का पूरा इस्तेमाल कर लिया है. लगातार दूसरे साल रक्षा मंत्रालय ने अपने पूरे पूंजीगत बजट का इस्तेमाल किया है. इस तरह का प्रभावी खर्च न केवल सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण को गति देगा, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास को भी मजबूत करेगा. इसके अलावा, इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा, क्योंकि पूंजीगत खर्च का प्रभाव कई क्षेत्रों में दिखाई देता है, जिससे निवेश बढ़ता है और रोजगार के नये अवसर पैदा होते हैं.

पिछले वित्त वर्ष में देश का रक्षा निर्यात बढ़कर 38,424 करोड़ रुपये हो गया, जो उससे पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 62.66 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि है. यह उपलब्धि रक्षा क्षेत्र में देश की बढ़ती ताकत, आत्मनिर्भरता और वैश्विक स्तर पर बढ़ते प्रभाव का संकेत है.

अस्थिर विश्व को राह दिखा सकता है भारत

जी एन बाजपेयी
सेबी और एलआइसी के पूर्व चेयरमैन

प्रवीण तिवारी
पूर्व उप महाप्रबंधक और लेखा परीक्षक
editor@thebillionpress.org

आज विश्व में वर्चस्व की दौड़ चल रही है, जिसने भू-राजनीतिक शांति को पीछे छोड़ दिया है. बढ़ती प्रतिस्पर्धा, बहुपक्षीय मानदंडों का क्षरण और नियम आधारित व्यवस्था का पतन वैश्विक अनिश्चितता को जन्म दे रहा है, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के अब तक के लाभ खतरे में पड़ सकते हैं. हाल की प्रभुत्ववादी गतिविधियां उस स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती हैं, जो आर्थिक विकास की नींव है.

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद के लगभग 75 वर्षों की व्यापक वैश्विक शांति एक विकसित होती नियम आधारित व्यवस्था और मुक्त बाजार सिद्धांतों पर आधारित नवशास्त्रीय आर्थिक ढांचे से चिह्नित रही. मांग और आपूर्ति के परस्पर प्रभाव तथा संसाधनों के कुशल आवंटन ने इस व्यवस्था को मजबूती दी. इसके तहत जो द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था उभरी, उसमें संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन जैसे वैश्विक संस्थानों ने, कुछ बड़े और ताकतवर देशों के प्रभाव में होने के बावजूद, विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक और गैर-व्यापारिक विवादों को सुलझाने में बड़ी भूमिका निभायी.

वॉशिंगटन कंसेंसस और अर्थशास्त्री डेविड रिकार्डो के तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत से प्रभावित आर्थिक व्यवस्था ने पूंजी और वस्तुओं के मुक्त प्रवाह को बढ़ावा दिया. वॉशिंगटन कंसेंसस ये दस आर्थिक सिद्धांत और बाजार केंद्रित सुधार हैं, जिन्हें विकासशील देशों में व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाये रखने के लिए लागू किया गया. इनके जरिये उदारीकरण, निजीकरण और विनियंत्रण को बढ़ावा दिया गया. इनके जरिये दुनियाभर में पूंजी और वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही शुरू हुई. इसका परिणाम अर्थशास्त्रियों द्वारा वर्णित 'महान संतुलन काल' के रूप में सामने आया, जो 1980 के दशक के मध्य से 2007 तक चला. इस दौरान महंगाई कम रही, आर्थिक वृद्धि स्थिर रही और आर्थिक अस्थिरता में भी कमी आयी. अधिकांश देशों ने न केवल प्रगति की, बल्कि लाखों लोग गरीबी से बाहर भी आये. इस वैश्विक उदार आर्थिक व्यवस्था ने चीन जैसी नयी आर्थिक महाशक्तियों को उभरने का अवसर दिया. सोवियत संघ के विघटन के बाद एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हुआ, जिसने एकतरफा नीतियों और वैश्विक संस्थानों की उपेक्षा को जन्म दिया. वैश्विक स्तर पर आय में वृद्धि के साथ-साथ अलबत्ता देशों के भीतर और देशों के बीच आर्थिक असमानता भी बढ़ी. इसने कई स्थानों पर दक्षिणपंथी राजनीति और आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया. साथ ही, एक नयी बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का हिस्सा बनने की महत्वाकांक्षा भी बढ़ी. आज विश्व में वर्चस्व की दौड़ चल रही है, जिसने भू-राजनीतिक शांति को पीछे छोड़ दिया है. बढ़ती प्रतिस्पर्धा, बहुपक्षीय मानदंडों का क्षरण और नियम आधारित व्यवस्था का पतन वैश्विक अनिश्चितता को जन्म दे रहा है, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के अब तक के लाभ खतरे में पड़ सकते हैं. हाल की प्रभुत्ववादी गतिविधियां उस स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती हैं, जो आर्थिक विकास की नींव है. सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक अनिश्चितताएं कम करने तथा अशांत विश्व से मानवता को बचाने के लिए एक स्थिरकारी शक्ति की जरूरत है. मध्यम शक्ति वाले देशों के पास अंतरराष्ट्रीय संबंधों में संतुलन स्थापित करने का सुनहरा अवसर है, जो सहयोग, बहुपक्षवाद और नियम आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देकर अनिश्चितता को कम कर सकते हैं. भारत इस दिशा में लोकतांत्रिक 'मध्यम शक्तियों' के एक गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए सक्षम है.

भारत की कई विशेषताएं हैं. एक तो यह कि भारत विश्व का सबसे बड़ा जीवंत लोकतंत्र और एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति है. दूसरी, भारत ने हमेशा संप्रभुता के सम्मान, आक्रामकता से परहेज और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया है. हाल की कुछ घटनाओं के बावजूद भारत ने कूटनीतिक संतुलन और व्यावहारिकता बनाये रखी है. कई अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों ने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने में भारत की भूमिका का समर्थन किया है. तीसरी, भारत की विश्वसनीयता मजबूत संस्थागत आधार पर टिकी है-जैसे कि एक बहुलतावादी राजनीतिक प्रणाली, जो शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन को सुनिश्चित करती है, एक संविधान जो कानून के शासन को बनाये रखता है, और प्रभावी प्रशासन. चौथी, दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और हिंद-प्रशांत के संगम पर स्थित भारत की भौगोलिक स्थिति उसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है. तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और तकनीकी क्षमताओं के साथ भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं, डिजिटल शासन और विकास सहयोग को प्रभावित करने की क्षमता रखता है. मध्यम शक्ति का नेतृत्व सहयोग, सह-अस्तित्व और पारस्परिक सम्मान पर आधारित होना चाहिए, न कि प्रभुत्व, दबाव और क्रूर आत्मस्वार्थ पर, जैसा कि हाल की घटनाओं में देखा गया. भारत ने ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ कई द्विपक्षीय व्यापार समझौते किये हैं, जो सहयोग, समझदारी और आपसी सम्मान के सिद्धांतों पर आधारित हैं. ये देश और संगठन बहुपक्षवाद और अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान के पक्षधर हैं. एक महत्वपूर्ण मध्यम शक्ति के रूप में भारत विकसित और विकासशील देशों तथा वैश्विक उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु बन सकता है. नया गठबंधन संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे बहुपक्षीय संस्थानों को सुदृढ़ और अधिक न्यायसंगत बनाने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार भारत की कूटनीतिक प्राथमिकता होनी चाहिए. साथ ही, भारत को जी-20, ब्रिक्स और क्वाड जैसे मंचों में अपनी भागीदारी बढ़ानी चाहिए. वर्तमान वैश्विक उथल-पुथल ने कई देशों को नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की जरूरत पर जोर देने के लिए प्रेरित किया है. भारत को ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, जापान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और यूरोपीय संघ जैसे देशों के साथ जलवायु परिवर्तन, समुद्री सुरक्षा, साइबर शासन और आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर सहयोग करना चाहिए, दुनिया जहां भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देखती है, वहीं भारत को अंतरिक्ष, रक्षा, विमानन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर और कुशल मानव संसाधन जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनकर वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए. भारत को आर्थिक कूटनीति और विविधता, लोकतांत्रिक मजबूती तथा सभ्यतागत विरासत जैसी सांस्कृतिक शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए. हालांकि, मध्यम शक्तियों के नेतृत्व में कई चुनौतियां भी हैं, जैसे ढांचागत सुविधाओं की कमी, आर्थिक असमानता और प्रशासनिक जटिलताएं, इस संदर्भ में खासकर महाशक्तियों के साथ संतुलित संबंध बनाये रखना और संघर्ष की स्थितियों में विवेकपूर्ण कूटनीति अपनाना आवश्यक होगा. विखंडन, संकट और संघर्ष से भरा मौजूदा वैश्विक परिदृश्य भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है. भारत को अपनी क्षमताओं का उपयोग कर एक स्थिर, समावेशी और नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभानी चाहिए.

(ये लेखकद्वय के निजी विचार हैं)

सही कदम है आइडीबीआइ के विनिवेश को रोकना

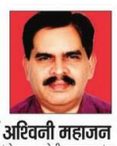

डॉ अश्विनी महाजन
राष्ट्रीय सह-संयोजक, स्वदेशी जागरण मंच
ashwanimahajan@rediffmail.com

पिछले कुछ वर्षों से सरकार, आइडीबीआइ बैंक के रणनीतिक विनिवेश की दिशा में कदम बढ़ा रही थी. पर हाल की रिपोर्टों के अनुसार, सरकार ने अब इस बैंक का विनिवेश रोक दिया है. आइडीबीआइ बैंक, जो कुछ वर्ष पहले एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था, अब घाटे से उबर चुका है और एक मुनाफा कमाने वाली संस्था बन गया है. इसलिए इस बैंक को निजी हाथों में सौंपने से रोका जाना एक सही नीति है.

वर्ष 1991 में नयी आर्थिक नीति की शुरुआत के बाद से, जिसमें तीन मुख्य आयाम शामिल थे- उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण- बैंकों के निजीकरण का मुद्दा हमेशा ही एक विवादास्पद विषय रहा है. सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश दो तरीकों से होता है- रणनीतिक बिक्री से और बाजार आधारित शेयर बिक्री से. रणनीतिक बिक्री में अक्सर मूल्यांकन से जुड़ी समस्याएं, बोली लगाने वालों की सीमित संख्या और पारदर्शिता की कमी के आरोप सामने आते हैं. इसके विपरीत, शेयर बाजार के जरिये किया जाने वाला विनिवेश अधिक पारदर्शी होता है, इसमें अधिक लोगों की भागीदारी होती है और इससे शेयरों का सही मूल्य तय हो पाता है.

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निजी संस्थाओं को बेचने का कोई इतिहास नहीं रहा है. फिर भी, अलग-अलग बैंकों के विलय के जरिये बैंकों की कुल संख्या में निश्चित रूप से कमी आयी है. जहां कुछ समय पहले तक सार्वजनिक क्षेत्र के 27 बैंक थे, वहीं अब उनकी संख्या घटकर मात्र 12 रह गयी है. इसके अतिरिक्त, एक और बैंक है, जिसका नाम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (आइडीबीआइ) है, जिसमें केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम की शेयरहोल्डिंग मिलाकर सरकार का कुल नियंत्रण लगभग 95 प्रतिशत हो जाता है. विशेष रूप से आइडीबीआइ बैंक के मामले में, पिछले कुछ वर्षों से सरकार रणनीतिक विनिवेश की दिशा में कदम बढ़ा रही थी, और इस संबंध में पहले प्रस्ताव आमंत्रित किये गये थे. हाल की रिपोर्टों के अनुसार, सरकार ने अब इस बैंक के रणनीतिक विनिवेश को रोक दिया है. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण को लेकर महत्वपूर्ण तर्क दिये जाते रहे हैं. पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के आलोचकों के, खासकर आइडीबीआइ के मामले में, अपने मजबूत तर्क हैं. आइडीबीआइ बैंक, जो कुछ वर्ष पहले एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था, अब घाटे से उबर चुका है और एक मुनाफा कमाने वाली संस्था बन गया है. हालांकि, इसके निजीकरण के समर्थकों का पहला तर्क यह है कि आइडीबीआइ के निजीकरण से बाजार अनुशासन को बढ़ावा मिलेगा और पूंजी का कुशल आवंटन होगा. दूसरा, यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को नौकरशाही की देरी और राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करेगा. इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी. तीसरा, निजीकरण से परिसंपत्ति की गुणवत्ता और एनपीए के प्रबंधन में सुधार हो सकता है. चौथा, निजीकरण बैंकिंग सेवाओं में नवाचार, ग्राहक केंद्रित उत्पादों और डिजिटल बदलाव के जरिये प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ा सकता है. पांचवां, निजीकरण प्रबंधन बोर्ड की अधिक मजबूत जवाबदेही, पारदर्शिता और बेहतर अनुपालन मानकों के जरिये कॉरपोरेट प्रशासन में सुधार कर सकता है. छठा, भारत सरकार ने आइडीबीआइ बैंक को चालू रखने के लिए उसमें बार-बार पूंजी डाली है. निजीकरण करदाताओं के पैसे पर बार-बार होने वाले पूंजीकरण को कम करने में मदद कर सकता है.

भारत और दुनियाभर में निजी क्षेत्र के बैंकों के दिवालिया होने का एक इतिहास रहा है. लेकिन, ऐसा एक भी मामला नहीं है जहां कोई सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक दिवालिया हुआ हो और जमाकर्ताओं का पैसा डूब गया हो. दूसरी बात, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर लोगों का भरोसा आम जनता को अपनी बचत इन बैंकों में जमा करने के लिए प्रोत्साहित करता है. जब 1969 में पहली बार 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 1980 में छह और बैंकों का, तो सरकार का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास को बढ़ावा देना था. यह देखते हुए कि कृषि, छोटे पैमाने के उद्योग, शिक्षा, निर्यात को बढ़ावा देना आदि प्राथमिक महत्व के क्षेत्र हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के जरिये इन 'प्राथमिक क्षेत्रों' के लिए ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी. आरबीआइ के तमाम नियमों, उप नियमों और निर्देशों के बावजूद, निजी क्षेत्र के बैंक उस तरह से वित्तीय समावेशन का काम नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर रहे हैं.

नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 'जीरो बैलेंस' वाले जन धन खाते खोले गये, जिससे वित्तीय समावेशन सुनिश्चित हुआ. अब तक ऐसे 51 करोड़ जन धन खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से केवल 1.4 करोड़ खाते ही निजी बैंकों ने खोले हैं. यह तथ्य वित्तीय समावेशन में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका के बारे में बहुत कुछ कहता है. दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत छह करोड़ महिलाओं को दिये जाने वाले 90 प्रतिशत आजीविका ऋण सार्वजनिक क्षेत्र के और उनके द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ही उपलब्ध कराये जा रहे हैं. इसी तरह, रेहड़ी-पटरी वालों को ऋण देने का काम भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा ही किया जाता है. ऐसी स्थिति में निजी क्षेत्र के बैंकों का मुनाफा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से अधिक होता है. इसलिए यह कहना कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण कर हम बैंकों के लाभ बढ़ा सकते हैं, तो यह काम वित्तीय समावेशन की लागत पर होगा. इसलिए आइडीबीआइ बैंक का रणनीतिक विनिवेश, उसे निजी हाथों में सौंपने से रोका जाना एक सही नीति है. **(ये लेखक के निजी विचार हैं.)**

देश दुनिया

एकपक्षीय नहीं थीं बीते वर्ष सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर हुई कार्रवाई

बीते वर्ष सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर कार्रवाई के कारण देश में विद्रोह भड़क उठा, जिसने अंततः सरकार गिरा दी. हालांकि, वह विद्रोह राजनीतिक गतिरोध, व्यापक भ्रष्टाचार और आर्थिक विकास तथा रोजगार के अवसरों की कमी से उपजा था, पर जिस महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया, वह है नेपाल जैसे समाज में बड़ी तकनीकी कंपनियों और सोशल मीडिया की भूमिका. सितंबर, 2025 में इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर सरकार की कार्रवाई एकपक्षीय नहीं थी. यह एक संप्रभु देश और उन बड़ी तकनीकी कंपनियों के बीच के संघर्ष की अभिव्यक्ति थी, जिन्होंने वैश्विक दक्षिण के कई देशों से कहीं अधिक धन, शक्ति और प्रभाव अर्जित किया है. मेटा, गूगल, एक्स और टिकटॉक जैसी कंपनियां ऐसे मूल्यों, लक्ष्यों और रणनीतियों के साथ काम करती हैं, जो शायद ही कभी किसी देश के मूल्यों, लक्ष्यों और रणनीतियों के अनुरूप होती हैं. फिर भी, ओली सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय के विरुद्ध भड़के विद्रोह के पीछे दो प्रमुख कारक नजर आते हैं. पहला, सरकार ने उपरोक्त कंपनियों पर सामूहिक प्रतिबंध लगा दिया, जिससे देश के लगभग सभी सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप बंद हो गये. नेपाल की बड़ी जनसंख्या विदेशों में रहती है और अपने परिवार से संवाद के लिए इन एप पर निर्भर है. दूसरा, यह प्रतिबंध तब लगाया गया, जब भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के खिलाफ देश में डिजिटल अभियान चल रहा था. हालांकि, इन घटनाक्रमों के बीच, सोशल मीडिया की भूमिका से जुड़े मूल मुद्दे नेपाली सरकार और जनता की दृष्टि से ओझल हो गये. क्या और किस हद तक उपरोक्त प्लेटफॉर्म बीत वर्ष की हिंसा के लिए जिम्मेदार थे, हिंसा बढ़ाने में उनके एल्गोरिदम की क्या भूमिका थी और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या सुरक्षा उपाय होने चाहिए? इन प्रश्नों की गहन जांच बड़ी तकनीकी कंपनियों को अधिक जवाबदेह बनाने में निर्णायक साबित हो सकती है.

-महेश कुशवाहा

बोधि वृक्ष

आंतरिक दृष्टि

आप अपने मन के सहारे परम पुरुष या परम ब्रह्म तक सीधे नहीं पहुंच सकते. मन की अपनी सीमाएं हैं- वह बार-बार प्रयास करके लौट आता है, क्योंकि उसे जिस सत्य की तलाश है, वह कल्पना और सामान्य ज्ञान की पकड़ से परे है. ब्रह्म को न तो मन से जाना जा सकता है, न ही वाणी से व्यक्त किया जा सकता है. जब साधक ब्रह्मानंद की अवस्था में स्थापित होता है, तब मन, बुद्धि और शब्द सब विलीन हो जाते हैं, क्योंकि वहां केवल एक ही सत्ता रहती है : परम आनंद. इस अवस्था तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को अपनी चेतना को जाग्रत और प्रफुल्लित करना होता है. जब वह उस सर्वोच्च सत्ता के निकट पहुंचता है, तब मन का अस्तित्व क्षीण हो जाता है और मन के छह शत्रु- काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या- भी स्वतः समाप्त हो जाते हैं. यही वह क्षण है जब साधक भय से पूर्णतः मुक्त हो जाता है और एक गहन शांति का अनुभव करता है. सर्वोच्च चेतना अदृश्य प्रतीत होती है, क्योंकि उसे हमारी सामान्य इंद्रियां नहीं देख सकतीं. यह कोई बाहरी दृष्टि का विषय नहीं है, आंतरिक अनुभव का क्षेत्र है. ब्रह्म को पाने के लिए साधना, उपासना और गहरे आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होती है. बाहरी दृष्टि हमें केवल रूप व भेद दिखाती है, जबकि आंतरिक दृष्टि एकत्व का अनुभव कराती है. जिसे हम बाहरी रूप से एक सामान्य मनुष्य, पशु या निर्जीव वस्तु मानते हैं, वही आंतरिक दृष्टि से एक चेतन सत्ता के रूप में प्रकट होती है. आध्यात्मिक साधना का मूल उद्देश्य भी यही है- अनेक में एक को देखना. इस अद्वैत दृष्टि को पाने के लिए आत्मनिरीक्षण ही एकमात्र मार्ग है. जब परम सत्ता हर वस्तु में अंतर्निहित है. उसे जानने के लिए व्यक्ति को अपने अस्तित्व के सबसे सूक्ष्म और गहरे स्तर तक पहुंचना पड़ता है. वह हमारे अंतरतम में, हमारी मूल चेतना में निवास करती है- वही हमारे 'मैं' के भाव का आधार है. इसलिए उसे 'गुहाहित' कहा गया है, अर्थात जो हृदय की गुफा में स्थित है. जब साधक अपने विचारों को सूक्ष्म बनाते हुए अंतर्ज्ञान के स्तर तक पहुंचता है, तब उसके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं.

-श्री श्री आनंदमूर्ति

कुछ अलग

युद्ध के माहौल में भरवां बैंगन

राकेश सोहम्
लेखक
sohamsahitya@gmail.com

युद्ध जारी है. छुट्टी का दिन युद्ध की विभीषिका से तबाह हो रहा है. जनकलाल टीवी के सामने डटे हुए हैं. एंकर असल युद्ध से ज्यादा बमबारी कर रहे हैं. मिसाइलें दाग रहे हैं. हवाओं में बारूद की गंध फैला रहे हैं. ईंधन में होने वाली बमबारी की धमक उनके घर में महसूस हो रही है. इसी बीच श्रीमती जनकलाल ने रसोई से फायरिंग शुरू कर दी, "अजी सुनते हो! कब तक टीवी के सामने जमे रहोगे? पूरा दिन हो गया है. अरे चिंटू के पापा! यह युद्ध है, क्रिकेट का एकदिवसीय मैच नहीं है, जो सुबह शुरू हुआ और शाम को समाप्त हो जायेगा." जनकलाल सतर्क हो गये. हालांकि वह टीवी के सामने से हिल नहीं पा रहे थे. जैसे उन्हें डर था कि वे हटेंगे और कोई भटकी हुई मिसाइल उनके घर पर आ गिरेगी!

युद्ध की विभीषिका में फंसे जनकलाल को निकालने के लिए श्रीमती जनकलाल को युद्ध के मैदान में कूदना पड़ा. उन्होंने पारंपरिक योद्धा की भांति एक हाथ में थाली और दूसरे में बड़ा-सा चाकू थाम रखा था. जनकलाल उन्हें

देखकर घबरा गये. पीठ दिखाकर भागना मुनासिब नहीं था. सो आंखें मलते हुए आत्मसमर्पण की मुद्रा में आ गये. उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर श्रीमती जी ने एक हाथ में थाली और दूसरे में चाकू क्यों थामे रखी है. जनकलाल कुछ समझ पाते, इससे पहले ही श्रीमती जनकलाल उनके हाथों में थाली थमाते हुए ट्रंप जैसी हो गयीं. जैसे कह रही हों, मेरा नब्बे प्रतिशत काम निपट गया है. युद्ध जल्द ही समाप्त होगा. लेकिन जनकलाल तैयार न हुए. ईंधन हो गये. बोले, "टीवी चालू रहेगा. तुम काम बताओ बस." श्रीमती जनकलाल बोलीं, "मैं आज भरवां बैंगन बना रही हूं. थाली में बैंगन और प्याज हैं. बराबर से काट देना. और हां ध्यान रखना, चाकू तेज है. दो देशों की लड़ाई में बेकसूर जनता की तरह घायल न हो जाना." रसोई की ओर कूच करते हुए श्रीमती जनकलाल सच बयान कर गयीं. युद्ध का दर्द जनता को ही भुगतना पड़ता है. युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भी महंगाई की मार लंबे समय तक झेलनी पड़ती है.

उधर टीवी एंकर की बमबारी जारी थी. जनकलाल चाकू लेकर सब्जियों पर टूट पड़े. तभी एंकर ने कोई काल्पनिक मिसाइल दागते हुए बुर्ज खलीफा को खतरे में डाल दिया. जनकलाल रसोई की ओर दौड़े और थाली को पटककर वापस बैठक की ओर दौड़ गये. तभी श्रीमती जनकलाल के चीखने की आवाज आयी, गो कि कोई मिसाइल आ गिरी हो, "हे भगवान! यह क्या किया? बैंगन को प्याज की तरह बारीक-बारीक कतर दिया है और प्याज को भरवां बैंगन की तरह." जनकलाल के घर पर भीषण युद्ध के बादल मंडरा रहे थे.

आपके पत्र

महिला आरक्षण से आयेगा बदलाव

राजनीति में महिला आरक्षण महत्वपूर्ण कदम है. महिलाओं को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए ऐसा करना उचित होगा. इतिहास में रजिया सुल्तान, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, मोहसिन किदवई और मीरा कुमार जैसी महिलाओं ने साहसिक और प्रभावशाली कार्य किये. इनका योगदान साबित करता है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी देश को नया आयाम दे सकती है. महिला नेतृत्व से निर्णयों में विविधता आती है और सामाजिक न्याय व विकास को भी मजबूती मिलती है. इससे लोकतंत्र और भी मजबूत होगा.

एसएम अक्बर आलम, गया

फुटबॉल स्टेडियम की हालत दयनीय

रामनगर नगर परिषद वार्ड सात में स्थित अर्जुन विक्रम शाह फुटबॉल स्टेडियम काफी समय से उपेक्षित है. स्टेडियम की चहारदीवारी और मेट गेट अधूरा है, जिससे असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है. पुलिस इसको लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है. स्टेडियम ट्रस्ट के अधीन होने के बावजूद यहां कोई विकास नहीं हुआ. जीर्णोद्धार के संबंध में डीएम और नगर परिषद कार्यपालक अधिकारी से कई बार अनुरोध किया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.

लव राज, पश्चिम चंपारण

बच्चों को भी प्रतिदिन 1-3 घंटे सक्रिय रहना चाहिए. आउटडोर खेल, योग, वॉक या डांस बच्चों को फिट रखते हैं. लंबे समय तक बैठने से बचने के लिए हर 20 मिनट में ब्रेक लेना जरूरी है.

बच्चों में मोटापा सतर्कता से बचाव संभव

आज के दौर में बच्चों में मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है. हालांकि, चाइल्डहुड ओबेसिटी से बचाव संभव है.

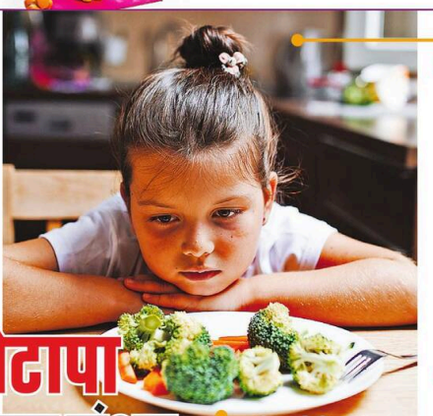

संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और अनुशासित दिनचर्या अपनाकर बच्चों को स्वस्थ और फिट रखा जा सकता है. कुछ छोटी-छोटी सावधानियां, भविष्य की बड़ी बीमारियों से बचा सकती हैं.

डॉ पंकज गर्ग
नियोनेटोलॉजिस्ट
नयी दिल्ली

ऑनलाइन पढ़ाई, बढ़ता स्क्रीन टाइम, कम शारीरिक गतिविधि और जंक फूड की आदतों ने इस जेनरेशन के लिए चाइल्डहुड ओबेसिटी के खतरे को और बढ़ा दिया है. विशेषज्ञ मानते हैं कि समय रहते कदम न उठाये गये, तो यह एक बड़ी महामारी का रूप ले सकती है. भारत में लगभग एक करोड़ 88 लाख से ज्यादा बच्चे मोटापे से प्रभावित हैं. डबल्यूएचओ के अनुसार, हर पांच में से एक बच्चा ओवरवेट या मोटापे का शिकार है. शहरी क्षेत्रों में 20 से 30 प्रतिशत बच्चे इस समस्या से जूझ रहे हैं. खास बात यह है कि 60-70 प्रतिशत बच्चे बड़े होकर भी मोटे बने रहते हैं.

मोटापा क्यों है खतरनाक

मोटापा सिर्फ वजन बढ़ना नहीं, बल्कि एक मेटाबॉलिक समस्या है. इससे कम उम्र में ही बीपी, डायबिटीज, थायरॉयड व हृदय रोग हो सकते हैं. इससे बच्चे मानसिक रूप से भी प्रभावित होते हैं. मोटापे को लेकर मजाक पर उनमें आत्मविश्वास की कमी, एंग्जायटी व डिप्रेशन बढ़ सकता है.

बच्चों में कैसे पहचानें मोटापा

बच्चों का वजन ग्रोथ चार्ट और बीएमआइ इंडेक्स से आंका जाता है. सामान्यतौर पर 23 तक बीएमआइ सामान्य, 23-27 ओवरवेट और 27 से अधिक मोटापा माना जाता है. बच्चे के कमर की साइज अपनी हाइट से आधे से कम होना चाहिए. अगर ज्यादा हो, तो मोटापे का रिस्क रहता है.

मोटापे के रिस्क फैक्टर की करें रोकथाम

करीब 90 प्रतिशत मामलों में गलत जीवनशैली जिम्मेदार होती है, जैसे खराब खान-पान और कम एक्टिविटी. वहीं 10 प्रतिशत मामलों में जेनेटिक या हार्मोनल कारण होते हैं. यदि परिवार में मोटापा या डायबिटीज है, तो बच्चों में जोखिम बढ़ जाता है. यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया के वैज्ञानिकों द्वारा किये गये एक अध्ययन के अनुसार, एफटीओ जीन बच्चों के खान-पान को काफी प्रभावित करता है. इस कारण से बच्चे अधिक कैलोरी ग्रहण करने लगते हैं, जो भविष्य में ओबेसिटी की संभावना बढ़ा देती है.

गर्भावस्था से ही पड़ता है असर

मोटापे की नींव गर्भावस्था से ही पड़ सकती है. मां का असंतुलित आहार या स्वास्थ्य समस्याएं बच्चे को प्रभावित करती हैं. इस दौरान संतुलित आहार व जांच जरूरी है.

शुरुआती खान-पान का महत्व

छह माह तक ब्रेस्ट फीड और छह महीने के बाद बच्चों को घर का बना पूरक आहार देना चाहिए. बाजार के फार्मूला फूड और मीठे उत्पादों में शुगर ज्यादा होती है, जो नुकसानदायक है. एक साल से छोटे बच्चों को नमक और चीनी देने से बचें.

जबरदस्ती खिलाना गलत

कई माता-पिता बच्चों को जरूरत से ज्यादा खिलाते हैं. गोल-मटोल बच्चे को हेल्दी मानना गलत है. बच्चे को उसकी भूख के अनुसार ही खाना देना चाहिए. जबरदस्ती खिलाने से मोटापा बढ़ सकता है.

परिवार की आदतों का असर

बच्चे वही सीखते हैं, जो घर में देखते हैं. यदि माता-पिता जंक फूड खाते हैं, तो बच्चे भी वही अपनाते हैं, इसलिए घर में हेल्दी खाने की आदत डालना जरूरी है. दिन में तीन मुख्य भोजन और दो हेल्दी स्नैक्स दें. ताजे फल, सब्जियां, दाल, दूध, अंडा जैसे पौष्टिक आहार शामिल करें. रिफाइंड मैदा, ज्यादा चीनी और पैक्ड फूड से दूरी रखें. नट्स और बीज जैसे हेल्दी फैट को प्राथमिकता दें.

मील टाइम बने फैमिली टाइम

परिवार के साथ बैठकर खाने से अच्छी आदतें विकसित होती हैं. इससे इमोशनल इटिंग कम होती है और बच्चे संतुलित भोजन करते हैं. खाने के समय मोबाइल और टीवी से दूरी रखें. क्योंकि, मोबाइल देखते हुए बच्चे ज्यादा खा लेते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता.

दिनचर्या और नींद का महत्व

देर रात तक जागने से खाने की गलत आदतें बढ़ती हैं. बच्चों को समय पर सोने और सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए. इसके साथ स्क्रीन टाइम पर भी नियंत्रण जरूरी है. दो साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. बड़े बच्चों के लिए भी स्क्रीन टाइम सीमित रखें.

बातचीत : रजनी अरोड़ा

हेल्दी टिप्स

दूषित पानी बच्चों की सेहत के लिए खतरनाक

पानी का हमारे स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है. अगर पानी दूषित होता है, तो यह स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है. ज्यादातर पेट से संबंधित बीमारियां दूषित पानी पीने की वजह से होती हैं.

हेपेटाइटिस : हेपेटाइटिस बीमारी भी दूषित पानी से ज्यादा फैलता है. इसके 5 वायरस हैं, जिन्हें ए, बी, सी, डी और इ नाम से जाना जाता है. इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक बी होता है.

बचाव के उपाय : सबसे जरूरी है कि बच्चे को हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाएं. साथ ही बच्चे को अच्छी तरह फिल्टर किया हुआ पानी ही पिलाएं. इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियों को सेवन कराएं.

मलेरिया : मलेरिया बुखार परजीवी मच्छर से फैलता है. ये मच्छर गंदे पानी में ही पैदा होते हैं. इस बीमारी से बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं. गर्भवती महिलाओं के लिए तो मलेरिया घातक बीमारी है.

बचाव के उपाय : मलेरिया के अधिकतर लक्षण फ्लू, डेंगू और चिकनगुनिया जैसे ही होते हैं. अगर बच्चे को तेज बुखार व ठंड लगे तो डॉक्टर को दिखाएं. बच्चे को आराम कराएं व खाने में तरल आहार दें.

हैजा : हैजा भी गंदे पानी से होने वाली एक बीमारी है. यह रोग विबियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया से फैलता है. दूषित पानी के अलावा यह गंदे खाने, दूध व कटे हुए फल से भी फैलता है.

बचाव के उपाय : शरीर में पानी के स्तर को बनाये रखने के लिए बच्चे को नारियल पानी पिलाएं. तरल पदार्थों का सेवन अधिक कराएं. पानी को पीने से पहले उसे उबाल लें. पानी का साफ होना बहुत जरूरी है.

टाइफाइड : पानी से जुड़ी बीमारियों में टाइफाइड भी शामिल है. यह साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से फैलता है. कटे हुए फल-सब्जियां व दूषित पानी पीने से यह बीमारी होती है.

बचाव के उपाय : अगर बच्चे में टाइफाइड के लक्षण जैसे- बुखार व हाथ-पैर में दर्द दिखें, तो उबला हुआ पानी ही पिलाएं. बच्चे को लहसुन की कलियां कूटकर गर्म पानी के साथ देना लाभकारी हो सकता है.

इंटेंशनल रिप्लांटेशन से बच सकते हैं दांत

केस स्टडी

एक 15 वर्षीय लड़की दाहिने हिस्से के दांत में दर्द की शिकायत लेकर आयी. दर्द पिछले 15 दिनों से हो रहा था. जांच में पता चला कि एक महीने पहले उसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट (आरसीटी) हुआ था, जो फेल हो गया था. एक्स-रे से पता चला कि दांत की जड़ में एक टूटा हुआ डिवाइस फंसा हुआ था और जड़ों के पास इन्फेक्शन था. मरीज सर्जरी से बचना चाहती थी, इसलिए इंटेंशनल रिप्लांटेशन का निर्णय लिया. सबसे पहले दांत को बहुत सावधानी से निकाला गया, ताकि दांत की जड़ों व कॉर्टिकल प्लेट्स को कोई नुकसान न पहुंचे. दांत को पूरी प्रक्रिया के दौरान उसके ऊपरी हिस्से यानी क्राउन से ही पकड़ा गया. इसके बाद जड़ों की सफाई की गयी व फंसा हुआ टुकड़ा निकाला गया. इसके बाद जड़ के अंतिम सिरे को काटकर 'बायोडेंटीन' से सील कर दिया गया. अंत में, दांत को वापस उसकी जगह पर लगा दिया गया और फाइबर स्प्लिंट की मदद से उसे सुरक्षित कर दिया गया. उपचार के 12 महीने बाद जब दोबारा जांच की गयी, तो दांत पूरी तरह से ठीक हो चुका था, संक्रमण खत्म हो गया था और कोई दर्द नहीं था.

अक्सर दांतों में किसी प्रकार का गंभीर संक्रमण होने पर रूट कैनाल ट्रीटमेंट का सहारा लिया जाता है, लेकिन कई बार यह प्रक्रिया फेल हो जाती है. ऐसे मामलों में यदि सामान्य इलाज काम नहीं आता व सर्जरी भी संभव नहीं होती, तब 'इंटेंशनल रिप्लांटेशन' यानी दांत को निकालकर दोबारा लगाने की प्रक्रिया बेहतर साबित हो सकती है.

डॉ नवीन मिश्रा
हेड ऑफ कंजरवेटिव डेंटिस्ट्री
आइजीआइएमएस, पटना

क्या है इंटेंशनल रिप्लांटेशन

इंटेंशनल रिप्लांटेशन दांतों के संक्रमण के उपचार की एक किफायती प्रक्रिया है, जिसमें उपचार के लिए एक दांत को निकाला जाता है और फिर से मसूड़े में लगा दिया जाता है. पहले इसे सबसे खराब स्थिति वाले दांतों को बचाने के लिए अंतिम उपाय माना जाता था, लेकिन लगातार बेहतर हो रही तकनीक के कारण इसे अब बेहतर उपचार विकल्प के रूप में देखा जाता है. यह मसूड़े की सर्जरी की तुलना में बेहतर होता है और इसमें जटिलता भी बहुत हद तक कम होती है.

बातचीत : अजय कुमार

बरतनी पड़ती है सावधानी

इस पूरी प्रक्रिया की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि दांत कितनी देर तक मुंह से बाहर रहता है. पेरियोडोंटल लिगामेंट (दांत के जड़ में मौजूद) कोशिकाओं को जीवित रखने के लिए इस समय को कम-से-कम रखा जाना चाहिए. यदि दांत 15 मिनट से अधिक समय तक बाहर रहता है, तो दांत की जड़ के गलने का खतरा बढ़ जाता है, जिसका परिणाम नकारात्मक हो सकता है.

किन स्थितियों में उपयुक्त नहीं

हर मामले में इंटेंशनल रिप्लांटेशन नहीं किया जा सकता. टूटे हुए दांतों, गंभीर पेरिओडोंटल बीमारी (मसूड़ों की बीमारी) वाले दांतों आदि के लिए यह प्रक्रिया उपयुक्त नहीं है.

सिटी की खबरें

सिटी बाइट्स

वर्ल्ड हेल्थ डे पर रेड क्रॉस सोसाइटी का रक्तदान शिविर

पटना. विश्व स्वास्थ्य दिवस पर मंगलवार को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बिहार राज्य शाखा में स्वास्थ्य के लिए एक साथ : विज्ञान के साथ खड़े हो थीम पर विशेष कार्यशाला हुई. रेड क्रॉस सभागार में हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता सोसाइटी के चेयरमैन डॉ विनय बहादुर सिन्हा ने की. मौके पर लगे रक्तदान शिविर में 60 युवाओं और वॉलिंटियर्स ने रक्तदान किया. डॉ विनय बहादुर सिन्हा ने कहा कि रेड क्रॉस पॉली क्लिनिक में टीबी के मरीजों के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं, प्रधानमंत्री के आह्वान पर टीबी को पूरी तरह खत्म करने का प्रयास हो रहा है. कहा कि विज्ञान और आधुनिक रिसर्च के माध्यम से ही लाइफ टाइम बढ़ाया जा सकता है. सदस्य अजीत कुमार सिंह ने कहा कि आज सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय कारणों से मानव ही नहीं, बल्कि पूरा जीव-जंतु जगत प्रभावित हो रहा है. मौके पर कोषाध्यक्ष दिनेश कुमार जायसवाल डॉ इन्दू भूषण प्रसाद के अलावे महासचिव मो. सलाहुद्दीन खां, डॉ धनंजय कुमार, डॉ दीपक शरण, डॉ इकबाल अहमद सहित रेड क्रॉस के कई पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे.

अक्षय तृतीया : रूप अलंकार ज्वेलर्स दे रहा ऑफर

पटना. पटना के प्रतिष्ठित ज्वेलरी ब्रांड रूप अलंकार ज्वेलर्स ने अक्षय तृतीया पर ग्राहकों के लिए खास ऑफर की घोषणा की है. पिछले 38 वर्षों से भरोसे का नाम रहे इस प्रतिष्ठान के बोरिंग रोड और खाजपुरा स्थित शोरूम में यह ऑफर उपलब्ध है. निदेशक मनीष कुमार के अनुसार, सोने के आभूषणों की मेकिंग चार्ज पर 7.5 प्रतिशत तक और डायमंड ज्वेलरी पर फ्लैट 20 प्रतिशत की छूट दी जा रही है. अक्षय तृतीया और लग्न के सीजन को देखते हुए शोरूम सभी दिन खुले रहेंगे, जिससे ग्राहकों को खरीदारी में सुविधा मिले. ग्राहक अग्रिम बुकिंग भी करा सकते हैं. रूप अलंकार ज्वेलर्स अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता, हॉलमार्क आभूषण और आकर्षक डिजाइनों के लिए जाना जाता है. शादी-विवाह और त्योहारों के लिए यहां विशेष कलेक्शन उपलब्ध हैं, जिससे ग्राहकों को बेहतर विकल्प मिल सकें.

डाक विभाग में तकनीकी पदों पर होगी प्रतिनियुक्ति

पटना. डाक विभाग ने डाक प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र में सहायक प्रबंधक (लेवल-7) एवं तकनीकी पर्यवेक्षक (लेवल-6) के पदों पर प्रतिनियुक्ति को लेकर योग्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है. चयन के बाद इनकी तैनाती मैसूर, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, पटना, कोच्चि और विशाखापत्तनम में हो सकती है. आवेदन चार अप्रैल से शुरू होकर 23 मई शाम पांच बजे तक ऑनलाइन मोड में होगा. आवेदन के बाद अभ्यर्थी आवेदन पत्र की प्रति निकालकर हस्ताक्षरित कर संबंधित संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी को जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा. साथ ही सभी प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां अपलोड करना अनिवार्य है.

एससी-एसटी अत्याचार निवारण एक्ट में तीन माह में 288 पीड़ितों को ₹209.78 लाख दिया गया मुआवजा

- एसडीओ व एसडीपीओ को मामले की जानकारी होने पर घटनास्थल पर जाकर सहायता करने का निर्देश

संवाददाता,पटना

बैठक करते जिलाधिकारी, साथ में अन्य अधिकारी

डीएम डॉ त्यागराजन एसएम ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत जिला सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक की. उन्होंने कहा कि अत्याचार का संपूर्ण निवारण व पीड़ितों को त्वरित गति से न्याय दिलायी जा रही है. जिला प्रशासन की ओर से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रति अत्याचार के विरूद्ध शून्य सहिष्णुता के सिद्धांत का अनुसरण किया जा रहा है. अधिनियम अंतर्गत सभी दर्ज मामलों में प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति, मुआवजा, पेंशन, यात्रा भत्ता आदि का भुगतान किया जा रहा है. क्षेत्रों में कैंप लगाकर ऐसे परिवारों को विभिन्न प्रकार की योजनाओं से लाभांवित किया जाता है. डीएम ने कहा कि जनवरी से अभी तक तीन माह में 197 कांडों के 288 पीड़ितों के बीच कुल 209.78 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया है.

पिछले साल 1062 पीड़ितों के मुआवजा भुगतान के लिए स्वीकृति प्रदान करते हुए कुल 752.92 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया था. डीएम ने एसडीओ व एसडीपीओ को तुरंत घटना स्थल पर जाकर पीड़ितों से संपर्क स्थापित कर नियमानुसार सहायता करने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया. बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी संजीव कुमार रत्न ने जानकारी दी कि वर्तमान में कुल 137 पेंशनरों का नियमित तौर पर पेंशन भुगतान किया जा रहा है. उन्होंने भौतिक व वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत किया. पटना जिले में नौकरी के लिए योग्य 12 आश्रितों को समूह """घ""" में सरकारी नौकरी प्रदान की गई है. बैठक में बाढ़ के विधायक सियाराम सिंह के अलावा अन्य विधायकों के प्रतिनिधि,एसएसपी कार्तिकेय केशर्मा, डीडीसी श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर,पद्म श्री सुधा वर्गीस सहित अन्य अधिकारी व गैर सरकारी सदस्य उपस्थित थे.

डीएम ने सभी एसडीओ को अपने-अपने क्षेत्र में शिविर लगा कर योजनाओं का लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया. नए राशन कार्ड, मुख्यमंत्री कबीर अंत्येष्टि योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना सहित सभी लोक-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों को मिले. सिविल सर्जन को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में दिव्यांगजन (यूडीआइडी) कार्ड निर्गत करने के लिए कैंप लगाने को कहा. डीएम ने कहा कि ऐसे मामलों में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की सूचना डायल 112 एवं जिला नियंत्रण कक्ष (0612-2219810/2219234) को दी जा सकती है.

रॉयल एनफील्ड की नयी मोटरसाइकिल हंटर 350 लांच

संवाददाता, पटना

भारत में मिड-सेगमेंट मोटरसाइकिल सेगमेंट को और मजबूत करते हुए रॉयल एनफील्ड ने अपनी नयी 2026 हंटर 350 को कंपनी के अधिकारी के देख रेख में लांच कर दिया है. यह बाइक खासतौर पर युवाओं और परफॉरमेंस पसंद करने वाले राइडर्स को ध्यान मे रखकर तैयार की गयी है. ये बातें लांचिंग के दौरान बलप्रदा मोटर्स के निदेशक प्रतीक कुमार ने कहीं. कहा कि कंपनी ने नये मॉडल में कई अपडेट्स और फीचर्स जोड़े हैं, जिससे यह पहले से अधिक पावरफुल और आकर्षक बन गयी है. कार्यक्रम में कंपनी के अधिकारी आरबीएम रोशन मैथ्यू,एसएम मिहिर खतुआ आदि मौजूद थे.

ब्रेस्ट कैंसर से बचाव व इलाज पर डॉक्टरों ने किया मंथन

कॉन्फ्रेंस में ब्रेस्ट कैंसर के इलाज और बचाव पर चर्चा करते चिकित्सक.

संवाददाता, पटना

एसोसिएशन ऑफ ब्रेस्ट सर्जन्स ऑफ इंडिया (एबीएसआइ) और सवेरा कैंसर हॉस्पिटल की ओर से आयोजित दो दिवसीय एबीएसआइ स्किलकॉन-2026 कॉन्फ्रेंस में ब्रेस्ट कैंसर से इलाज और बचाव पर चर्चा की गई. इनमें देश-विदेश से आये डॉक्टरों ने आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों और स्तन संरक्षण के महत्व को नई दिशा दी. कार्यक्रम में इंग्लैंड से पटना आए भारतीय मूल के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ ऋषिकेश परमेश्वर ने इंग्लैंड की तरह भारत में भी स्तन संरक्षण पर विशेष जोर देने की बात कही. उन्होंने ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी को भविष्य की तकनीक को बताया. इस दौरान सवेरा कैंसर हॉस्पिटल में आयोजित इस कार्यशाला के पहले दिन लाइव ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी का आयोजन हुआ, जिसमें देश-विदेश के विशेषज्ञ सर्जनों ने भाग लिया. इस कार्यक्रम का आयोजन अध्यक्ष एवं वरिष्ठ कैंसर सर्जन डॉ वीपी. सिंह की देखरेख में हुआ. इसमें डॉ वीवी सिंह ने कहा कि कैंसर तेजी से बढ़ती गंभीर बीमारी है, जिसे समय रहते पहचान और उपचार के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है. वहीं आयोजन सचिव डॉ आकाश कुमार सिंह ने बताया कि इस प्रकार की कार्यशालाएं चिकित्सकों के कौशल को निखारने और बेहतर उपचार सुनिश्चित करने में सहायक होती हैं.

हरिद्वार में ग्राहक पंचायत की राष्ट्रीय बैठक संपन्न

पटना. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं राष्ट्रीय साधारण सभा तीन से पांच अप्रैल तक शांतिकुंज में हुई. इसमें देश के 36 प्रांतों से 276 प्रमुख कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर संगठन को मजबूत बनाने पर मंथन किया. उद्घाटन सत्र में गायत्री परिवार के प्रमुख व्यवस्थापक योगेंद्र गिरी ने कहा कि ग्राहक पंचायत आर्थिक क्षेत्र में जागरूकता का कार्य कर रही है. उन्होंने सेवा भाव से किए जा रहे कार्यों की सराहना की. बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय व्यवस्था प्रमुख मंगेश भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण भाई शाह, संगठन मंत्री दिनकर सबनीस, उपाध्यक्ष अशोक पांडेय और सचिव जयंत भाई कथिरिया ने भी अपने विचार रखे. बिहार से अजय यादव और शिव शंकर कुशवाहा ने प्रतिनिधित्व किया. सभा में बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर कानून, सस्ती व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था तथा ऊर्जा संकट में सरकार के साथ सहयोग करने का प्रस्ताव पारित हुआ.

खगौल ग्रिड से दीघा ग्रिड को मिलेगा बिजली का नया स्रोत

- 50 मीटर ऊंचे मोनोपोल पर से खींची जा रही 132 केवी लाइन

संवाददाता, पटना

खगौल ग्रिड से दीघा ग्रिड को एक नया स्रोत मिलेगा. इसके लिए 50 मीटर ऊंचे मोनोपोल (ट्रांसमिशन टावर) पर 132 केवी लाइन खींची जा रही है. शहर में उपलब्ध कम जगह में भी यह लग सके, इसलिए छह से 12 मीटर तक के चौड़े बेस की जगह कम चौड़े गोलाकार बेस वाले मोनो पोल का इस्तेमाल किया जा रहा है. यह लगभग तीन मीटर व्यास का है. 17 किमी के इस फीडर में 51 मोनोपोल का इस्तेमाल किया गया है . इनके बीच की दूरी 150 मीटर है. डेढ़ साल से चल रहे काम को इस माह पूरा होने की संभावना है. इस नये ट्रांसमिशन फीडर की क्षमता 300 मेगावाट होगी. इतने अधिक विद्युत लोड और शहरी क्षेत्र की घनी आबादी को देखते हुए ही इसे 50 मीटर ऊंचे मोनोपोल पर ले जाया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह के दुर्घटना की आशंका न रहे.

300 मेगावाट की क्षमता होने के कारण यह न केवल दीघा ग्रिड को बिजली की आपूर्ति करेगा, बल्कि दीघा ग्रिड से किसी अन्य ग्रिड को भी बिजली देने में सक्षम होगा. आमतौर पर एक ग्रिड को 150 मेगावाट क्षमता के ही सोर्स फीडर की जरूरत पड़ती है. दीघा ग्रिड को बिजली आपूर्ति करने वाला यह दूसरा स्रोत होगा, क्योंकि उसे दीघा न्यू ग्रिड से पहले से ही बिजली की आपूर्ति की जा रही है. यह विद्युत आपूर्ति मोनोपोल की बजाय अंडरग्राउंड केबल के माध्यम से की जा रही है. एक नया स्रोत मिल जाने से पहले से आपूर्ति कर रहे फीडर में किसी तरह की बाधा आने पर भी दीघा ग्रिड की बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होगी और उससे जुड़े लीड्स एशियन और आसपास के अन्य पीएसएस की बिजली आपूर्ति जारी रखी जा सकेगी. साथ ही, बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में भी सुधार होगा और क्षेत्र की लगभग तीन लाख आबादी को बेहतर वोल्टेज वाली क्वालिटी बिजली दी जा सकेगी.

पूर्णिया में मातृ-शिशु मृत्यु दर कम करने में जुटी स्वास्थ्य टीम

पटना. बिहार सरकार और यूनिसेफ ने संयुक्त रूप से मंगलवार को पूर्णिया के एक होटल में कार्यशाला की. इसमें उच्च जोखिम गर्भावस्था की पहचान, ट्रैकिंग, प्रबंधन और संस्थागत प्रसव पर चर्चा हुई. पूर्णिया के डीएम अंशुल कुमार ने कहा कि मातृ और शिशु स्वास्थ्य जिले के विकास का सबसे महत्वपूर्ण पैमाना है. फील्ड स्तर पर कोई भी मामला ट्रैकिंग से छूटना नहीं चाहिए और डाटा एंट्री में किसी भी प्रकार का विलंब न हो. हर उच्च जोखिम मामले का अनिवार्य रूप से अस्पताल में ही प्रसव कराने का निर्देश दिया. बताया कि पूर्णिया ने उच्च जोखिम गर्भावस्था की पहचान और उसके सफल प्रबंधन में पूरे बिहार में प्रथम स्थान हासिल किया है. प्रखंड स्तर पर बायसी, अमौर और रूपौली ने सर्वाधिक सक्रियता दिखायी है. कार्यशाला में यूनिसेफ के स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ सिद्धार्थ शंकर रेड्डी, सीएस डॉ पीके कनौजिया, जिला कार्यक्रम प्रबंधक सौरेंद्र दास, संजय कुमार दिनकर और आलोक कुमार आदि थे.

अमर उजाला

प्रवाह

7 साल बेमिसाल

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक

स्थापना : 18 अप्रैल 1948 • आगरा

नई दिल्ली ■ बुधवार, 8 अप्रैल 2026

वोट डालना इकलौता ऐसा अवसर है, जहां गरीब आदमी अमीर के बराबर होता है। -एफ बी मेयर

करीब आधी सदी बाद चंद्रमा की कक्षा में मनुष्य की उपस्थिति दर्ज करने वाला आर्टेमिस-2 अभियान सिर्फ चंद्रमा तक पहुंचने की कहानी नहीं है, बल्कि मानवता की उस अटूट जिज्ञासा का भी प्रतीक है, जो हमें नई सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित करती है।

चांद के पार

मानव सभ्यता के इतिहास में एक बार फिर चंद्रमा की कक्षा में मनुष्य की उपस्थित दर्ज हो गई है और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का आर्टेमिस-2 मिशन इस दिशा में निर्णायक साबित हुआ है। मिशन का मूल उद्देश्य चार अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की कक्षा तक ले जाकर सुरक्षित पृथ्वी तक वापस लाना है। अपोलो अभियान के बाद यह पहला ऐसा प्रयास है, जिसमें मनुष्य चंद्रमा के इतने करीब पहुंचा है। हालांकि, इस मिशन में चंद्रमा पर उतरने की कोई योजना नहीं है, लेकिन यह भविष्य के आर्टेमिस-3 मिशन के लिए मार्ग जरूर प्रशस्त करेगा। आर्टेमिस-2 मिशन इस मायने में भी ऐतिहासिक है कि इसने पिछले 50 वर्षों में पृथ्वी से मनुष्य द्वारा तय की कई सबसे लंबी दूरी का नया रिकॉर्ड बनाया है। चार अंतरिक्ष यात्रियों के साथ ओरियन अंतरिक्ष यान चंद्रमा के सूदूर हिस्से के पास से गुजरते हुए पृथ्वी से करीब दो लाख 52 हजार 752 मील की दूरी तक पहुंचा, जिससे 1970 में अपोलो-13 अभियान में बना दो लाख 48 हजार 655 मील का रिकॉर्ड टूट गया है। जाहिर है कि आर्टेमिस-2 महज एक उड़ान नहीं, बल्कि 'अज्ञात' अंतरिक्ष में 'ज्ञात' की सीमा को कुछ और बढ़ाने का मानवीय प्रयास है। हालांकि, इस अभियान में कोई भारतीय अंतरिक्ष यात्री शामिल नहीं था, लेकिन आर्टेमिस-2 की कामयाबी इसरो के रोडमैप को ताकत ही देगी। अभियान से प्राप्त होने वाला उच्च स्तरीय तकनीकी डाटा इसरो के गगनयान मिशन जैसे महत्वपूर्ण मिशनों के लिए निस्संदेह उपयोगी साबित होगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में राष्ट्रों के बीच सहयोग को प्रगाढ़ बनाने के लिए 2020 में संपन्न आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर कर 2023 में भारत भी इसका सदस्य बन चुका है। गौरतलब है कि यह समझौता बाह्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में अन्वेषण और उपयोग को बेहतर बनाने के लिए सिद्धांतों, दिशानिर्देशों और सर्वोत्तम प्रथाओं का एक व्यावहारिक समूह है। जाहिर है, आर्टेमिस-2 अभियान में भारत महज पर्यवेक्षक नहीं, बल्कि एक हितधारक की भूमिका में भी है। आगामी आर्टेमिस मिशनों के तहत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने की नासा की योजना है। ऐसे में, चंद्रयान-3 का चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने का अनुभव इसरो को निस्संदेह ऐसे अभियानों के लिए एक प्रमुख भागीदार के रूप में स्थापित करेगा। लगभग आधी सदी बाद मनुष्य को चंद्रमा तक ले जाने वाला नासा का यह अभियान अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में एक नई इबारत लिख सकता है, जो सिर्फ चंद्रमा तक पहुंचने की कहानी नही हैं, बल्कि मानवता की उस अटूट जिज्ञासा का भी प्रतीक है, जो हमें नई सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित करती है।

सत्ता ही नहीं, साख की भी लड़ाई

कल केरल, असम और पुडुचेरी में होने वाले चुनाव राजनीतिक दलों की तुलना में उनसे जुड़े बड़े नामों के लिए 'अग्नि परीक्षा' साबित हो सकते हैं। केरल में पिनाराई विजयन, असम में हिमंत बिस्वा सरमा और पुडुचेरी में एन रंगास्वामी की साख का सवाल तो है ही, चुनावी नतीजों के राजनीतिक निहितार्थ भी गहरे होंगे।

केरल में 81 वर्षीय पिनाराई विजयन अगर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रचते हैं, तो वह देश में मार्क्सवादी पार्टी की एकमात्र सरकार को बचा सकेंगे। हालांकि, उनके नेतृत्व में, सत्ताधारी वामपंथी दल पिछले साल के स्थानीय निकाय चुनावों में फीके प्रदर्शन के बाद अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए संघर्ष ही कर रहा है। केरल को कम्युनिस्टों का आखिरी गढ़ माना जाता है, क्योंकि 2018 में त्रिपुरा में सत्ता गंवाने और 2011 में अपने पुराने गढ़ पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से हाशिये पर चले जाने (एक भी विधायक न होने) के बाद यही एकमात्र राज्य बचा है। दूसरी ओर, कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है, जबकि भाजपा भी राज्य में तीसरी ताकत के रूप में खुद को स्थापित करने की कोशिश में है।

विजयन की मुश्किलों के तार खुद उनकी पार्टी सीपीआई (एम) के भीतर ही देखे जा सकते हैं। कई मार्क्सवादी दिग्गज उनके काम करने के तरीके से नाखुश हैं और उन पर वामपंथ के 'मूल सिद्धांतों' को कमजोर करने व पिछले दस वर्षों में व्यापार और व्यवसायों के प्रति अधिक मित्रवत होने का आरोप लगाते हैं। उन पर 'सॉफ्ट हिंदुत्व' की ओर झुकाव का आरोप भी लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का उनकी सरकार द्वारा समर्थन किए जाने से वामपंथी दल को हिंदू मतदाताओं का नुकसान उठाना पड़ा है, जो राज्य की आबादी का लगभग 54.73 प्रतिशत हैं। अब, अपने पहले के रुख में बदलाव के चलते विजयन हिंदू समर्थक समूहों की बहुत अधिक आलोचना नहीं कर रहे हैं।

शेखर अय्यर
वरिष्ठ पत्रकार

विजयन अपने चुनावी अभियान में साफ तौर पर 'विकास' (विकासनम) को ही सबसे बड़ा मुद्दा बता रहे हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि उनके नेतृत्व में केरल ने कई कठिन दौरों का मजबूती से सामना किया है-चाहे वह 2018 की विनाशकारी बाढ़ हो या कोविड महामारी का दौर। साथ ही, उन्होंने पूरे राज्य में बड़ा आर्थिक बदलाव लाया है और कई कल्याणकारी योजनाओं के जरिये गरीब तबके का भी ख्याल रखा है। वहीं, कांग्रेस ईसाइयों के बीच अपने मजबूत आधार पर दांव लगा रही है, जिनकी आबादी में हिस्सेदारी 18.38 प्रतिशत है। साथ ही, राहुल गांधी के जोरदार चुनावी प्रचार के चलते कांग्रेस को उम्मीद है कि मुस्लिम मतदाता, जो करीब 26.56 प्रतिशत हैं, इस बार वामपंथियों से दूरी बनाकर यूडीएफ के साथ आएंगे, क्योंकि यूडीएफ में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) एक अहम साझीदार है। दूसरी ओर, भाजपा के लिए सबसे अनुकूल स्थिति यह होगी कि राज्य के हिंदू मतदाता एकजुट होकर उसके पक्ष में वोट करें। अगर ऐसा होता है, तो भाजपा इतनी सीटें हासिल कर सकती है कि वह सत्ताधारी एलडीएफ और पिनाराई विजयन के सामने मजबूती से उभर सके। हालांकि, इसकी संभावना कम ही है, फिर भी, बीजेपी केरल में ईसाई समुदाय के साथ सक्रिय रूप से नेटवर्क बना रही है। उसने बीडीजेएस, ट्वेंटी-20 पार्टी, केरल कांग्रेस (डेमोक्रेटिक), केरल कामराज कांग्रेस और लोक जनशक्ति पार्टी जैसी कई छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन पक्का कर लिया है।

असम में, हिमंत बिस्वा सरमा को पूरा भरोसा है कि वह बीजेपी को लगातार तीसरी बार सत्ता में लाएंगे और खुद दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कांग्रेस के संगठनात्मक आधार को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। कांग्रेस का संगठन राहुल गांधी की उस पसंद के कारण लड़खड़ा गया है, जिसमें उन्होंने एकमात्र गौरव गोगोई को ही असम में पार्टी की किस्मत का फैसला करने वाला बना दिया था। असम में अवैध प्रवासन ने वहां की मूल गैर-मुस्लिम आबादी के मन में गहरी चिंताएं पैदा कर दी हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर, हिमंत ने जमीनी स्तर पर कई मोर्चों पर विकास करके अपना काम बखूबी निभाया है। इनमें कमजोर वर्गों, खासकर महिलाओं को नकद आर्थिक सहायता देना भी शामिल है। कांग्रेस पिछले एक दशक से विपक्ष में है, जबकि बीजेपी लगातार दो बार सत्ता का सुख भोग चुकी है। चुनावी चर्चा एक बार फिर जनसांख्यिकीय बदलाव और अवैध घुसपैठिये जैसे वैचारिक मुद्दों पर केंद्रित हो गई है और कांग्रेस असम के बहुसंख्यक लोगों की चिंताओं को समझने में नाकाम रही है। 2021 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 93 सीटों पर चुनाव लड़कर 60 सीटों पर जीत हासिल की थी और सरकार बनाई थी। यही नहीं, 2014 के बाद से भाजपा ने असम में कोई भी बड़ा चुनाव नहीं हारा है। ऐसे में, मौजूदा माहौल को देखते हुए पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की मजबूत दावेदार नजर आ रही है। खास बात यह है कि कांग्रेस नेता गौरव गोगोई के पिता तरुण गोगोई वही नेता थे, जिन्होंने कभी राज्य में कांग्रेस को दोबारा मजबूती से खड़ा किया था। 2001 से 2016 तक मुख्यमंत्री रहते हुए वह असम के इतिहास में सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहने वाले नेता बने। उनके ही एक करीबी हिमंत अब बीजेपी का चेहरा हैं और उन्होंने गौरव के लिए चुनौती को इतना मुश्किल बना दिया है कि गौरव असम के बहुसंख्यक लोगों को अपने पक्ष में करने में नाकाम रहे हैं।

केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में सारा दारोमदार 75 साल के नटेसन कृष्णसामी गौंडर रंगास्वामी पर है, जिन्हें आम तौर पर 'एनआर' के नाम से जाना जाता है। वह मई 2021 से मुख्यमंत्री के पद पर हैं। इससे पहले वे 2001 से 2008 तक और 2011 से 2016 तक भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। रंगास्वामी अपनी खुद की पार्टी, 'ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस' (एआईएनआरसी) के संस्थापक अध्यक्ष हैं। इस पार्टी का गठन 2011 में कांग्रेस से अलग होने के बाद किया गया था। वह 'नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस' (एनडीए) का नेतृत्व कर चुके हैं, जिसमें बीजेपी एक अहम सदस्य है। उनके विरोधी कांग्रेस (उनकी पुरानी पार्टी) और द्रमुक ने मिलकर चुनाव के लिए एक गठबंधन बनाया था। लेकिन, विपक्ष के इस गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, इस बात पर दोनों पार्टियों के बीच की आपसी खींचतान की वजह से यह गठबंधन अब टूटा हुआ-सा नजर आ रहा है। नौ अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए राहुल गांधी और द्रमुक प्रमुख एमके स्टालिन ने अलग-अलग प्रचार किया।

इस केंद्रशासित प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वी नारायणसामी, जिन्हें उनकी अपनी ही पार्टी ने किनारे कर दिया है, ने कहा है कि कांग्रेस में उनके अपने ही साथियों ने केंद्रीय एजेंसियों के दबाव में आकर इस्तीफा दे दिया और भाजपा में शामिल हो गए। बीजेपी के साथ रिश्तों में तनाव होने के बावजूद, रंगास्वामी मतदाताओं के साथ अपने सीधे जुड़ाव की वजह से इस मुकाबले में बढ़त बनाए हुए हैं।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

एपीजे अब्दुल कलाम

हर इन्सान अपनी प्रतिभा को अलग-अलग रूपों में प्रदर्शित करता है। ठीक वैसे ही, जैसे कुछ बीज सीधे पेड़ बन जाते हैं और कई नष्ट हो जाते हैं। पर वे भी व्यर्थ नहीं जाते, बल्कि खाद बनकर अगली पीढ़ी की जड़ों को मजबूत करते हैं।

निरंतरता ही विकास का आधार है

अक्सर हम अपनी वर्तमान समस्याओं और सीमित संसाधनों को ही अपनी अंतिम नियति मान लेते हैं, ठीक उसी 'ईगो' नामक शिशु की तरह, जो गर्भ के अंधेरे को ही पूरी दुनिया समझ बैठा था। गर्भ में पल रहे दो शिशुओं 'ईगो' और 'स्पिरिट' की कहानी मैंने इंटरनेट पर पढ़ी थी। स्पिरिट, ईगो से कहता है, 'मुझे पता है कि तुम्हें यह स्वीकार करना कठिन लगेगा, पर मेरा विश्वास है कि जन्म के बाद भी जीवन है।' ईगो उत्तर देता है, 'मूर्ख मत बनो। अपने चारों ओर देखो। यही सब कुछ है। तुम हमेशा इस वास्तविकता से परे क्यों सोचते रहते हो?' स्पिरिट कहता है, 'ईगो, मेरा मानना है कि एक 'मां' भी होती है।' इस पर ईगो हंसता है और कहता है कि क्या तुमने कभी मां को देखा है, तुम्हें पता भी है कि मां क्या होती है? तुम यह क्यों नहीं मान लेते कि यही सब कुछ है। यही वास्तविकता है।

स्पिरिट कहता है, 'ईगो, हम जो दबाव और अंधेरा लगातार महसूस करते हैं, जो हलचल हमें असहज कर देती है, यह एहसास कि हम जैसे-जैसे बढ़ रहे हैं, हमें संकुचित किया जा रहा है, क्या यह संकेत नहीं है कि हम एक नए जीवन की ओर बढ़ रहे हैं, जहां हम प्रकाश देखेंगे?' तब ईगो स्पिरिट से पूछता है कि तुमने कभी प्रकाश को देखा है भला? तुम्हें कैसे पता कि वह क्या होता है? इसलिए, यह दबाव और अंधकार ही जीवन है। थक हारकर स्पिरिट आखिरी बार कहता है, 'ईगो, मुझे विश्वास है कि इस कष्टों के बाद हम न केवल प्रकाश देखेंगे, बल्कि मां से मिलने का आनंद भी अनुभव करेंगे।'

मैं अपने देश के लोगों से यह कहना चाहता हूं कि हमें अपनी वर्तमान परिस्थितियों से कभी भी संतुष्ट होकर नहीं बैठना चाहिए। भारत की स्वतंत्रता के बाद के दशकों में हमें जो कुछ भी मिला, वह हमारी प्रगति का केवल एक छोटा-सा हिस्सा है। एक छात्र ने मुझे पत्र लिखा-एक बरगद के पेड़ की पूरी शक्ति उसके बीजों में ही होती है। हर इन्सान लगभग एकसमान होता है, लेकिन अपनी प्रतिभाओं को अलग-अलग रूपों में प्रदर्शित करता है। ठीक उसी तरह, जैसे कुछ बीज सीधे पेड़ बन जाते हैं और कई बीज नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो बीज मिट्टी में मिलते हैं, वे भी व्यर्थ नहीं जाते; वे खाद बनकर अगली पीढ़ी की जड़ों को मजबूती प्रदान करते हैं। दरअसल, यह निरंतरता ही विकास का आधार है। उस छात्र ने मुझसे यह भी पूछा कि मैंने कैसे सुनिश्चित किया कि मेरे साथ काम करने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की क्षमताएं व्यर्थ न जाएं या उनका विकास समय से पहले रुक न जाए? मैंने उसे उत्तर भी दिया और बताया कि मैंने वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों के साथ एकजुट टीम के रूप में काम किया है, ताकि कम समय में लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। हमने कठिन समय में एक-दूसरे का हाथ थामा और असफलताओं से मिले सबक को अपनी अगली जीत की सीढ़ी बनाया।

-इग्नाइटेड माइंड्स के अनूदित अंश

असफलताओं से सीखें

सूत्र

हमें सीमित सोच के अंधकार में बंधकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि विश्वास, साहस और दूरदृष्टि के साथ एक उज्ज्वल भविष्य की कल्पना करनी चाहिए; जैसे बीज में विशाल वृक्ष बनने की शक्ति होती है, वैसे ही हर व्यक्ति में अपार क्षमता छिपी होती है, जिसे सही मार्गदर्शन, परिश्रम और टीम की शक्ति से विकसित किया जा सकता है।

दूसरा पहलू

शरीर के किसी हिस्से में होने वाली असामान्य सूजन या गांठ को ट्यूमर कहते हैं, वहीं कैंसर कोशिकाओं में होने वाला जेनेटिक बदलाव है।

हर गांठ का मतलब कैंसर नहीं होता

ट्यूमर और कैंसर, ये दोनों शब्द अक्सर एक-दूसरे के लिए इस्तेमाल कर दिए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता और हर कैंसर गांठ की शक्ल में नहीं दिखता? आम लोगों के साथ-साथ कई बार स्वास्थ्य क्षेत्र के पेशेवर भी इन्हें लेकर भ्रम में पड़ जाते हैं। इसलिए यह समझना बेहद जरूरी है कि ट्यूमर व कैंसर में असल अंतर क्या है और सही शब्दों का इस्तेमाल क्यों मायने रखता है।

सारा सैसन

जरूरी नहीं कि हर ट्यूमर घातक हो, पर कैंसर की कोशिकाएं आसपास के ऊतकों पर हमला करती हैं और शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल सकती हैं।

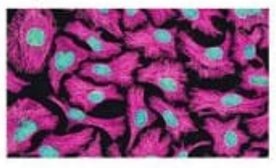

ट्यूमर या कैंसर की सही पहचान के लिए अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन या एमआरआई जैसी जांचें की जाती हैं। ऊतक का सैंपल लेकर माइक्रोस्कोप से जांच की जाती है, जिससे यह तय होता है कि ट्यूमर घातक है या नहीं।

दरअसल, ट्यूमर का मतलब है शरीर के किसी हिस्से में होने वाली असामान्य सूजन या गांठ। यह शरीर के किसी भी हिस्से-जैसे फैट, मांसपेशियों, हड्डियों, नसों या ग्रंथियों-में बन सकता है। लेकिन हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता। ट्यूमर दो तरह के होते हैं-सौम्य (यानी कैंसर-रहित) और घातक (यानी कैंसर संबंधी)। कई सौम्य ट्यूमर बिल्कुल हानिरहित होते हैं, जैसे लिपोमा (त्वचा के नीचे फैट का जमाव) या हेमेंजियोमा (रक्त वाहिकाओं का बढ़ना)। हालांकि, कुछ सौम्य ट्यूमर अपनी जगह की वजह से परेशानी खड़ी कर सकते हैं, जैसे गर्भाशय के फाइब्रॉइड या पिट्यूटरी एडेनोमा, जो हार्मोन असंतुलन पैदा कर सकते हैं। ऐसे मामलों में भले ये कैंसर न हों, लेकिन इलाज या सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। दूसरी तरफ, कैंसर एक ऐसी स्थिति है, जिसमें शरीर की कोशिकाएं जेनेटिक बदलाव (म्यूटेशन) के कारण अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती हैं और शरीर के प्राकृतिक नियंत्रण तंत्र से बाहर हो जाती हैं। कैंसर की सबसे बड़ी पहचान यह है कि इसकी कोशिकाएं आसपास के ऊतकों पर हमला करती हैं और शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल सकती हैं। यही इसे खतरनाक बनाते हैं। कई कैंसर ठोस गांठ (ट्यूमर) बनाते हैं, जैसे स्तन या फेफड़े का कैंसर, लेकिन कुछ, जैसे ल्यूकेमिया, बिना गांठ बनाए भी विकसित होते हैं। ट्यूमर या कैंसर की सही पहचान के लिए अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन या एमआरआई जैसी जांचें की जाती हैं, और जरूरत पड़ने पर ऊतक का सैंपल लेकर माइक्रोस्कोप से जांच की जाती है, जिससे यह तय होता है कि ट्यूमर घातक है या नहीं। कुछ मामलों में सर्जरी करके ट्यूमर निकाला जाता है। लेकिन कैंसर का इलाज आमतौर पर सर्जरी के साथ रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी जैसे तरीकों के संयोजन से किया जाता है।

सबसे अहम बात यह है कि इनके सही शब्दों का इस्तेमाल बेहद जरूरी है। 'कैंसर' शब्द के साथ डर जुड़ा होता है, लेकिन आज कई तरह के कैंसर का इलाज संभव है और मरीज पूरी तरह ठीक भी हो सकते हैं। स्पष्ट और सही संवाद ही बेहतर इलाज की पहली सीढ़ी है। संक्षेप में कहें, तो ठोस कैंसर को ट्यूमर कहा जा सकता है, लेकिन सभी ट्यूमर घातक नहीं होते। यही अंतर समझना और समझाना, दोनों ही जरूरी हैं।

- द कन्वर्सेशन

आंकड़े

इलेक्ट्रिक वाहन

पेट्रोल-डीजल से चलने वाली गाड़ियों के मुकाबले अब इलेक्ट्रिक वाहन ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं।

नॉर्वे	97
नेपाल	73
नीदरलैंड	56
चीन	53
स्विट्जरलैंड	33

आंकड़े इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने वाले देशों के, प्रतिशत में। | स्रोत : अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी व एम्बर

गरुड़ की मातृभक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अमरता का वरदान और अपना वाहन बनने का आशीर्वाद दिया।

मातृभक्ति और आशीर्वाद

पौराणिक कथाओं के अनुसार, ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थीं, जिनमें विनता और कद्रू भी थीं। दोनों बहनें थीं, पर आपस में ईर्ष्या करती थीं। ऋषि कश्यप ने उन्हें वरदान मांगने को कहा, तो विनता ने दो शक्तिशाली पुत्र मांगे और कद्रू ने हजार सर्प पुत्र। दोनों के पुत्र अंडों से उत्पन्न होने वाले थे। समय आने पर कद्रू के पुत्र जन्म ले चुके थे, पर विनता के नहीं।

अधीर होकर विनता ने एक अंडा समय से पहले फोड़ दिया, जिससे अरुण का जन्म हुआ। अधूरे शरीर के कारण अरुण ने विनता को शाप दिया कि वह दासी बनेगी, और मुक्ति तभी मिलेगी, जब दूसरा पुत्र उसे मुक्त कराएगा। लंबे समय बाद दूसरा अंडा फूटा, तो विनता के पुत्र के रूप में गरुड़ ने जन्म लिया। जब गरुड़ को अपनी माता की दासता का कारण पता चला, तो उन्होंने सर्पों से शाप से मुक्ति का उपाय पूछा। सर्पों ने उनसे अमृत लाने की शर्त रखी। गरुड़ स्वर्ग पहुंचे, सुरक्षा को पार किया और अमृत कलश ले आए। मार्ग में भगवान विष्णु प्रकट हुए और उनकी निःस्वार्थ भावना तथा मातृभक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अमरता का वरदान दिया और अपना वाहन बनने का आशीर्वाद दिया। गरुड़ अमृत लेकर सर्पों के पास पहुंचे, और विनता शाप से मुक्त हो गईं।

अंतर्यात्रा

संकलित

इसके बाद गरुड़ ने चालाकी से सर्पों को स्नान के लिए भेजा। उसी समय देवराज इंद्र अमृत वापस ले गए। सर्पों ने उस कुशा घास को चाटना आरंभ किया, जिस पर अमृत कलश रखा था जिससे उनकी जीभ दो भागों में बंट गई।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 8 अप्रैल, 1951

विश्वयुद्ध किसी भी क्षण छिड़ने की आशंका

विश्व युद्ध किसी भी क्षण छिड़ जाने की आशंका

आम चुनावों में प्रचार की छूट होगी

बीबीसी **(लंदन रेडियो) का कहना है कि इस समय वाशिंगटन में अफवाह फैली है कि कोरिया का युद्ध ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि किसी भी वक्त महायुद्ध का डंका बज सकता है। व्हाइट हाउस में गहमागहमी वाले माहौल के बीच लगातार बैठकें हो रही हैं।**

जंग, जलजला और जलवायु

पश्चिम एशिया के युद्ध और बढ़ते उत्सर्जन के बीच भारत ने जलवायु प्रतिबद्धता व विकास की संतुलित रणनीति अपनाकर मिसाल पेश की है।

डॉ. सीमा जावेद

मुद्दा

एक तरफ, दुनिया तेल और गैस की आपूर्ति शृंखलाओं के टूटने, बढ़ती कीमतों और गहरी अनिश्चितता से जूझ रही है, वहीं दूसरी ओर, भारत ने जलवायु परिवर्तन के प्रति एक साहसिक व सुनियोजित प्रतिबद्धता दिखा कर दुनिया को हैरान कर दिया है। भारत एक ऐसा देश है, जहां अगले दशक में बिजली की मांग लगभग दोगुनी होने वाली है, जहां इलेक्ट्रिक वाहन, डाटा सेंटर और आर्थिक विकास ऊर्जा के नियमों को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं। उसने ऊर्जा असुरक्षा और कल की जलवायु महत्वाकांक्षा के बीच, विकास और जिम्मेदारी, आकांक्षा और संयम के बीच एक संतुलन की कहानी लिख कर दुनिया के सामने एक बार फिर एक मिसाल पेश की है। ऐसे में, असली सवाल यह नहीं है कि भारत विकास करेगा या नहीं। सवाल यह है कि वह उस विकास को गति देने के लिए कौन सा तरीका चुनेगा?

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध से न केवल ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है, बल्कि पर्यावरण पर भी इसका प्रभाव सामने आने लगा है। युद्ध की शुरुआत से अब तक 50 लाख टन ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन हो चुका है, जो 84 देशों के कुल उत्सर्जन से भी अधिक है। देश और दुनिया जलवायु और ऊर्जा से जुड़ी दोहरी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे माहौल में, भारत ने 2031 से 2035 तक की अवधि के लिए अपने राष्ट्रीय स्तर पर उत्सर्जन में कटौती के निर्धारित योगदान (एनडीसी) को मंजूरी देकर नए जलवायु लक्ष्य तय किए हैं। ये लक्ष्य स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बढ़े अहम कदम माने जा रहे हैं। इसके तहत उत्सर्जन तीव्रता में 47 फीसदी की कमी और बिजली क्षमता का 60 प्रतिशत गैर-जीवाश्म स्रोतों से हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है।

गौरतलब है कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने हाल ही में 2026 से 2036 तक के लिए एक नया नेशनल जनरेशन एडिक्वेसी प्लान जारी किया है। इसके अनुसार, भारत में बिजली की मांग आने वाले 10 वर्षों में लगभग दोगुनी हो सकती है। इस बढ़ती मांग के पीछे कई कारण हैं-जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों का तेजी से बढ़ना, डाटा सेंटरों की संख्या में इजाफा, और देश की अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास करना। इन सभी कारणों से बिजली की खपत लगातार बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में, जब देश को इतनी ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी, तब भी भारत ने 2035 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए जो लक्ष्य तय किए हैं, वे सच में चौंकाने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि भारत एक साथ विकास भी करना चाहता है और पर्यावरण की जिम्मेदारी भी निभाना चाहता है।

अब सोलर बिजली की धड़कन बनेगा और 2035 की बिजली ज्यादातर 'ग्रीन' होगी। 2035-36 तक भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता 1,121 गीगावाट तक पहुंच सकती है। इसमें से करीब 70 प्रतिशत, यानी 786 गीगावाट, गैर-जीवाश्म स्रोतों से आएगा। 2035 तक सोलर अकेले 45 प्रतिशत स्थापित क्षमता का हिस्सा बन सकता है। कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भारत दुनिया में चौथे पायदान पर है। भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 220 गीगावाट से अधिक हो गई है। बहुत कम देश इतने बड़े पैमाने और इतनी तेजी से नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ पाए हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश भी बन गया है। ऐसे में, 2035 तक 60 फीसदी गैर-जीवाश्म ईंधन से उत्पादित ऊर्जा का लक्ष्य यह दिखाता है कि भारत अपनी घरेलू वास्तविकताओं को भी समझ रहा है।

मेरकॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2035-36 तक 900 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता को ग्रिड से जोड़ना प्रस्तावित है। इसके लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। करीब 1,37,500 सर्किट किलोमीटर नई लाइनें बिछाई जाएंगी। साथ ही, सबस्टेशन क्षमता भी बढ़ाई जाएगी।

पीएम-कुसुम योजना, पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना, और हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस जैसी पहलें पहले से ही यह दिखा रही हैं कि भारत गैर-जीवाश्म ईंधन (जैसे सौर और पवन ऊर्जा) से बनने वाली बिजली की हिस्सेदारी बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस के तहत, बड़े उपभोक्ता, जिनकी बिजली खपत एक किलोवाट से ज्यादा है, अब सीधे बिजली उत्पादकों से साफ और हरित ऊर्जा खरीद सकते हैं। यह भारत की जलवायु से जुड़ी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है।

सिर्फ इतना ही नहीं, भारतीय रेलवे, जिसमें हर दिन करीब 2.6 करोड़ लोग यात्रा करते हैं, अब 100 प्रतिशत विद्युतीकरण के करीब है। उसके पास 898 मेगावाट सौर ऊर्जा है ओर लगभग 70 प्रतिशत बिजली सीधे ट्रेनों को चलाने में मदद करती है।

आईटी शेयरों में तेजी से सेंसेक्स 509.73 अंक चढ़ा, निफ्टी 23,000 के पार

48,820 करोड़ रुपये बढ़ी बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों की पूंजी

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजारों में लगातार चौथे कारोबारी सत्र में तेजी जारी रही। शुरुआती गिरावट से उबरने के बाद बीएसई सेंसेक्स करीब 510 अंक चढ़ गया, जबकि निफ्टी 23,000 के पार पहुंच गया। कच्चे तेल में नरमी की उम्मीद और दुनिया के अन्य बाजारों में तेजी से निवेशकों की धारणा मजबूत हुई। इसके अलावा आईटी शेयरों में खरीदारी से बाजार में सुधार हुआ।

उतार-चढ़ाव भरे सत्र में बीएसई सेंसेक्स 509.73 अंक यानी 0.69 प्रतिशत बढ़कर 74,616.58 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इसमें 1,403.91 अंकों का उतार-चढ़ाव आया। सेंसेक्स 74,686.32 के ऊपरी स्तर तक गया, जबकि इसका न्यूनतम स्तर 73,282.41 रहा। उधर, 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 155.40 अंक यानी 0.68 प्रतिशत चढ़कर 23,123.65 अंक पर बंद हुआ। मंगलवार की तेजी के साथ बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों की कुल बाजार पूंजी करीब 48,820 करोड़ बढ़कर 429 लाख करोड़ रूपये हो गई।

74,616.58 पर बंद हुआ बीएसई सेंसेक्स 509.73 अंक या 0.69% बढ़कर

शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने मंगलवार को 8,692.11 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। हालांकि, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 7,979.50 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

इन शेयरों में दिखी सबसे अधिक तेजी

सेंसेक्स की कंपनियों में से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, सन फार्मा और हिंदुस्तान यूनिलीवर प्रमुख रूप से लाभ में रहीं। दूसरी तरफ, नुकसान में रहने वाले शेयरों में इंटरग्लोब एविएशन, अदाणी पोर्ट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाइटन शामिल हैं।

- विशेषज्ञों के मुताबिक, बाजार में सुधार मुख्य रूप से नए सौदे को पूरा करने के लिए की गई खरीद और चुनिंदा क्षेत्रों की मजबूती के कारण हुआ।
- जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के विनोद नायर ने कहा, युद्ध की आशंकाओं के कारण बाजार की बढ़त सीमित रही। आईटी और धातु शेयरों में निवेशकों की रुचि देखी गई।

रुपये में 16 पैसे की गिरावट

निवेशकों की सतर्कता के बीच मंगलवार को भारतीय रुपया कमजोर होकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 16 पैसे गिरकर 93.06 पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपये की शुरुआत 93.05 के स्तर पर हुई। यह 92.86 के उच्च स्तर तक भी पहुंचा। सोमवार को रुपया 28 पैसे मजबूत होकर 92.90 पर बंद हुआ था।

चांदी 2,000 रुपये सस्ती, सोना भी गिरा

मंगलवार को सराफा बाजार में सोना और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। 99.9 फीसदी शुद्धता वाला सोना 600 रुपये सस्ता होकर 1,53,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। सोमवार को सोना 1,53,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत 2,000 रुपये गिरकर 2.40 लाख प्रति किलोग्राम रह गई। पिछले सत्र में यह 2.42 लाख रुपये प्रति किलोग्राम थी।

भारत बना निवेश का पसंदीदा ठिकाना, एशिया-प्रशांत में शीर्ष स्थान

मजबूत आर्थिक वृद्धि के बूते भारत वैश्विक निवेश केंद्र बनने की ओर अग्रसर: मैकिन्से

नई दिल्ली। वैश्विक निवेशकों की नजर में भारत सबसे आकर्षक बाजार के रूप में उभर रहा है। मैकिन्से के एक सर्वे के मुताबिक, एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सीमित साझेदारों (लिमिटेड पार्टनर्स) ने भारत को निवेश के लिए शीर्ष स्थान दिया है। 50 से अधिक संस्थाओं पर किए गए सर्वे में 31 फीसदी निवेशकों ने भारत को पहला स्थान दिया, जबकि 76 फीसदी ने इसे अपने शीर्ष तीन निवेश विकल्पों में शामिल किया। एशिया-प्रशांत के कुल निवेश में भारत की हिस्सेदारी भी 12 फीसदी से बढ़कर करीब 21 फीसदी हो गई है। यह रुझान ऐसे समय में दिखा, जब भू-राजनीतिक और आर्थिक दबावों के कारण एशिया-प्रशांत क्षेत्र के अन्य बाजारों में निवेश गतिविधियां धीमी पड़ी हैं। भारत ने इस सुस्ती के बीच बेहतर प्रदर्शन किया है। देश में निजी इक्विटी व उद्यम पूंजी निवेश 2016-20 से 2021-25 के बीच 1.6 गुना बढ़कर 207 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। एजेंसी

इन क्षेत्रों में सर्वाधिक निवेश

2021-25 के दौरान तीन-चौथाई निवेश प्रमुख सेक्टरों में हुआ।

टेक्नोलॉजी	29 फीसदी
वित्तीय सेवाएं	15 फीसदी
आईटी सेवाएं	13 फीसदी

भारत पर बढ़ता भरोसा

सर्वे के अनुसार, भारत अब एशिया-प्रशांत में कुल निवेश का एक-तिहाई से अधिक हिस्सा आकर्षित कर रहा है। यूरोपीय निवेशकों की हिस्सेदारी 60 फीसदी तक पहुंच गई है। भारत में होने वाले कुल निवेश का करीब 64 फीसदी निजी बाजारों में लगाया जा रहा है। 50 फीसदी से अधिक निवेशक भारत में निवेश बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, सिर्फ 5 फीसदी ही निवेश घटाने के पक्ष में हैं।

चुनौतियां भी कम नहीं

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां भी मौजूद हैं, जैसे-मुद्रा जोखिम, जटिल कर प्रणाली, व्यापार करने में कठिनाइयां, अनुबंध लागू करने की समस्या और सीमित क्षेत्रों में निवेश का अधिक केंद्रित होना। विशेषज्ञों का मानना है कि पूंजी बाजार में सुधार और नियामकीय बाधाओं में कमी लाने के बाद निवेश और बढ़ सकता है।

जीडीपी : राज्यों व जिलों के लिए मसौदा दिशा-निर्देश जारी

राज्यों के जीएसडीपी आधार वर्ष में होगा संशोधन, अनुमानों के संकलन के लिए समान मानक

नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्तर पर जीडीपी की तरह अब राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के आधार वर्ष को भी संशोधित किया जाएगा। इससे राज्यों के आर्थिक प्रदर्शन का अधिक सटीक और तुलनात्मक अनुमान लगाया जा सकेगा।

अनुमानों के संकलन के लिए एक समान मसौदा दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं। इससे जिलों और राज्यों में एकरूपता, विश्वसनीयता और तुलनीयता सुनिश्चित होगी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के मुताबिक, अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना को अधिक सटीक रूप से प्रतिबिंबित करने व अद्यतन डाटा स्रोतों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय लेखा के आधार वर्ष को 2022-23 में संशोधित किया गया है। इसके अतिरिक्त, जिला घरेलू उत्पाद (डीडीपी) संकलन हेतु व्यापक मसौदा दिशा-निर्देश भी तैयार किए गए हैं। ये दिशा-निर्देश राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को मानकीकृत अवधारणाओं, परिभाषाओं, डेटा स्रोतों और अनुमान प्रक्रियाओं के उपयोग द्वारा जिला-स्तरीय अनुमान संकलित करने के लिए संरचित रूपरेखा प्रदान करते हैं। ब्यूरो

जिला घरेलू उत्पाद के आकलन के लिए नए दिशा-निर्देश

किसी जिले के भीतर एक निश्चित अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के आधार पर जिला घरेलू उत्पाद की गणना की जाती है। ये आंकड़े जिलों के बीच आर्थिक प्रदर्शन की तुलना करने, पिछड़े क्षेत्रों की पहचान करने और स्थानीय विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने में सहायक होते हैं। आधार वर्ष 2022-23 के साथ नई शृंखला के तहत जिला घरेलू उत्पाद के आकलन के लिए नए दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

न्यूज डायरी

मॉर्गन स्टेनली ने भारत का जीडीपी अनुमान घटाया

नई दिल्ली। मॉर्गन स्टेनली ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के वास्तविक जीडीपी अनुमान को 30 आधार अंक घटाकर 6.5 फीसदी से 6.2 फीसदी कर दिया है। मॉर्गन स्टेनली ने कहा कि औद्योगिक लागत बढ़ने से उत्पादन में कटौती हो रही है, साथ ही रुपये की कमजोरी से आयातित वस्तुओं पर महंगाई भी बढ़ रही है। एजेंसी

इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 24.6 फीसदी बढ़ी

नई दिल्ली। इलेक्ट्रिक वाहनों की खुदरा बिक्री वर्ष 2025-26 के दौरान 24.6 फीसदी बढ़कर 24.52 लाख इकाई हो गई। फाडा के अनुसार, दोपहिया वाहनों की बिक्री 14 लाख इकाइयों को पार कर गई, जबकि इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों की बिक्री लगभग दो लाख इकाइयों के करीब पहुंच गई। एजेंसी

आईडीबीआई बैंक विनिवेश के लिए नया प्रस्ताव

नई दिल्ली। आईडीबीआई बैंक के विनिवेश को आगे बढ़ाने के लिए सरकार संभावित खरीदारों से संशोधित वित्तीय बोलियां मांग सकती है। बैंक के अधिग्रहण के लिए फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स और एमिरेट्स एनबीडी प्रमुख बोलीदाताओं के रूप में सामने आए हैं। एजेंसी

एअर इंडिया के सीईओ विल्सन का इस्तीफा, उत्तराधिकारी की तलाश तेज

मुंबई। एअर इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एवं प्रबंध निदेशक कैंपबेल विल्सन ने इस्तीफा दे दिया है। एयरलाइन ने उनके उत्तराधिकारी की तलाश के लिए एक समिति का गठन किया है।

न्यूजीलैंड मूल के विल्सन पिछले चार वर्ष से टाटा समूह के स्वामित्व वाली एअर इंडिया के सीईओ एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। नए उत्तराधिकारी की घोषणा होने तक वह पद पर बने रहेंगे। इस साल भारतीय विमानन क्षेत्र में यह दूसरा बड़ा नेतृत्व परिवर्तन है। हाल ही में इंडिगो ने विली वॉल्श को नया सीईओ नियुक्त किया था। अपने इस्तीफे में विल्सन ने कहा कि एअर इंडिया के विकास के अगले चरण के लिए बागडोर सौंपने का यह सही समय है। टाटा ग्रुप के 2022 में एअर इंडिया के अधिग्रहण के बाद विल्सन को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उनका इस्तीफा ऐसे समय हुआ है जब कंपनी घाटे, परिचालन चुनौतियों और बढ़ती नियामकीय सख्ती से जूझ रही है। एजेंसी

एजीआर बकाया मामले में वोडाफोन आइडिया को राहत

नई दिल्ली। दूरसंचार विभाग ने वोडाफोन-आइडिया के समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) से जुड़े बकाये के पुनर्मूल्यांकन की समय-सीमा जून तक बढ़ा दी है। पहले इस प्रक्रिया को 31 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया था। स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क की समीक्षा के चलते समय-सीमा बढ़ाई गई है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वोडाफोन-आइडिया को राहत देते हुए वित्त वर्ष 2006-07 से 2018-19 तक के एजीआर बकाये को 87,695 करोड़ रुपये पर स्थिर कर दिया है। एजेंसी

दूरदराज क्षेत्रों में खुलेंगे बैंकिंग आउटलेट व टच पॉइंट, ग्राहकों को मिलेंगी बेहतर सेवाएं

नई दिल्ली। बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच आसान बनाने के लिए रिजर्व बैंक मौजूदा नियमों में बड़ा बदलाव कर रहा है। इसके लिए नया मसौदा तैयार कर लिया गया है। गांव-कस्बों में बैंकिंग सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बैंकिंग आउटलेट व टच पॉइंट खुलेंगे। इन आउटलेट के जरिये खाता खोलने, पैसा निकालने, जमा करने, ट्रांसफर करने, चेक, पासबुक व एटीएम कार्ड समेत तमाम सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

नए नियमों के साथ इस व्यवस्था को जुलाई से लागू करने की तैयारी है। बिजनेस बैंकिंग आउटलेट व बैंकिंग टच पॉइंट के लिए अलग अलग व्यापार प्रतिनिधि (बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट) रखे जाएंगे। ये बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट अपनी सहायता के लिए उप-एजेंट भी रख सकेंगे। इनके कार्यों के लिए संबंधित बैंक पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा। बैंकिंग आउटलेट सप्ताह में 5 दिन और रोजाना कम से कम चार घंटे काम करेंगे। छोटे लेनदेन वाले बैंकिंग टच प्वाइंट के लिए कोई समय तय नहीं होगा। दोनों श्रेणियों में परिश्रामिक भी दिया जाएगा। ब्यूरो

मिलेंगी ये सुविधाएं

- बैलेंस जांच, मिनी स्टेटमेंट, डेबिट कार्ड जारी व ब्लॉक
- चेक सेवाएं, आधार/मोबाइल लिंकिंग, पासबुक अपडेट, बिल भुगतान
- शिकायत दर्ज, ऋण/बीमा/पेंशन, केवाईसी अपडेट, नोट व सिक्के

व्यापार प्रतिनिधि बनने के मानक

बैंक अपनी नीति के आधार पर किसी व्यक्ति या संस्था को प्रतिनिधि बना सकते हैं। एक संस्था कई बैंकों के साथ भी समझौता कर सकती है। नियुक्ति से पहले वित्तीय मजबूती, प्रबंधन, नकदी संभालने की क्षमता आदि की जांच जाएगी।

जमा वृद्धि के मामले में बेहतर रहा निजी बैंकों का प्रदर्शन

नई दिल्ली। वित्त वर्ष 25-26 की चौथी तिमाही के दौरान निजी क्षेत्र के बैंकों ने सरकारी बैंकों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। निजी बैंकों की जमा वृद्धि 12 से 17 फीसदी के बीच रही, जबकि सरकारी बैंकों में यह 2 से 14 फीसदी तक सीमित रही। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 2.43 लाख करोड़ रुपये के साथ शीर्ष पर रहा। सरकारी बैंकों में बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे अधिक 14.33 फीसदी की बढ़त दर्ज की। कर्ज के मोर्चे पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सबसे अधिक 2.92 लाख करोड़ रुपये का कर्ज बांटा। एजेंसी

एजुकेशन & कॅरिअर

समय और शिक्षा का सही उपयोग ही असली सफलता है।

इतनी भी मुश्किल नहीं स्टार्टअप की राह

अगर आप स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हैं, तो चुनौतियों को बाधा के रूप में नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तौर पर लें

दीना डेनहम स्मिथ
हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू

- *आत्म-संदेह कोई नया कार्य शुरू करने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है।*
- *इसे कमजोरी मानकर छिपाने के बजाय एक संकेत के रूप में देखें।*
- *ध्यान दें कि यह किन परिस्थितियों में बढ़ता है- जैसे बड़े निर्णय, फंडिंग की कमी या धीमी प्रगति।*
- *खासकर बड़े फैसलों या चुनौतियों के समय इसे पहचानें।*
- *इसके पीछे के कारणों और पैटर्न को जानें।*
- *पैटर्न समझने पर आत्म-संदेह डर नहीं, बल्कि जागरूकता में बदल जाता है।*

आज के समय में हर दूसरे व्यक्ति का सपना होता है कि वह एक सफल उद्यमी बने और अपने सपनों को पूरा करे। इसके लिए लोग कड़ी मेहनत भी करते हैं, लेकिन सच यह है कि उद्यमिता की राह आसान नहीं होती। इस रास्ते में कई तरह की चुनौतियां आती हैं, जिनसे निपटना हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसे में खुद को लगातार प्रेरित और लक्ष्य के प्रति समर्पित बनाए रखना काफी मुश्किल हो जाता है। यदि आप आत्मविश्वास से भरे हैं और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं, तो आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं।

■ आत्म-संदेह को समझें

आत्म-संदेह कुछ नया करने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है। इसे कमजोरी मानकर छिपाने के बजाय एक संकेत की तरह देखें। ध्यान दें कि यह कब बढ़ता है- बड़े निर्णयों के समय, फंडिंग की कमी में या धीमी प्रगति के दौरान। जब आप इसके पैटर्न को पहचान लेते हैं, तो यह डर नहीं, बल्कि जागरूकता में बदल जाता है।

■ तथ्यों पर दें ध्यान

जब भी संदेह पैदा हो, अपने विचारों को तथ्यों से अलग करें। खुद से पूछें कि इस डर के पक्ष व विपक्ष में क्या प्रमाण हैं? जब आप अपने विचार लिखेंगे, तो इससे आपको स्पष्टता मिलेगी और आप तार्किक निर्णय ले पाएंगे।

Harvard Business Review

■ सही लोगों से जुड़ें

उद्यमिता का सफर अक्सर अकेलापन लेकर आता है, जो आत्म-संदेह को बढ़ाता है। इसलिए भरोसेमंद लोगों, मेंटर्स या दोस्तों के साथ नियमित बातचीत करें। उनसे पूछें कि आप क्या नजरअंदाज कर रहे हैं या कहां जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। यह संवाद आपकी सोच को संतुलित करेगा।

■ उद्देश्य को केंद्र में रखें

आप हर सफलता और असफलता को अपनी व्यक्तिगत क्षमता से जोड़ने के बजाय, अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित करें। आप यह सोचें कि क्या और किस लिए कर रहे हैं। ऐसे में नेतृत्व व्यक्तिगत परीक्षा नहीं, बल्कि एक साझा उद्देश्य बन जाता है और मानसिक दबाव कम होने लगता है।

■ प्रगति को पहचानें

अपनी पहचान को केवल परिणामों से न जोड़ें। जीवन के अन्य पहलुओं जैसे, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास को भी महत्व दें। साथ ही, छोटी-छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाएं। यह न केवल प्रेरणा देता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

8 अप्रैल, 1950 आज का दिन

भारत-पाकिस्तान के बीच दिल्ली समझौता हुआ था। इसका उद्देश्य विभाजन के बाद दोनों देशों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और युद्ध की संभावना को टालना था।

- 1894 : भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी का निधन हुआ था।
- 1979 : अमेरिकी टेलीविजन शो 'ऑल इन द फैमिली' का अंतिम एपिसोड प्रसारित हुआ।
- 1982 : तेलुगु फिल्म अभिनेता अल्लु अर्जुन का जन्म हुआ।
- 2024 : मेक्सिको, अमेरिका और कनाडा के कुछ हिस्सों में पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा गया था।

व्रत त्योहार

आज : वैशाख कृष्ण पक्ष षष्ठी।
कल : गुरु अर्जुनदेव जयंती, वसंत ऋतु, सूर्य उत्तरायणे, उत्तर गोले।
राहुकाल : दिन में 13.30 से 15.00 तक

कल का पंचांग

सूर्योदय : 06.06
सूर्यास्त : 18.38
(भारतीय मानक समयानुसार)

विक्रमी संवत 2083, 19 चैत्र मास शक 1948, चैत्र मास 27 प्रविष्टे, 20 सव्वाल हिजरी 1447, वैशाख कृष्ण पक्ष सप्तमी 21.19 तक उपरांत अष्टमी, मूल नक्षत्र 08.47 तक उपरांत पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, परिध योग 17.57 तक उपरांत शिव योग, विष्टि (भद्रा) करण 08.10 तक उपरांत बव करण, चंद्रमा धनु राशि में दिन-रात।

amarujala.com/astrology

राशिफल

■ पं. विनोद त्यागी

मेष : अटके कार्य में सफलता मिलेगी। कानूनी मामले में सावधानी बरतें। व्यवसाय में धन लाभ होगा।

वृष : स्वजनों से मनमुटाव हो सकता है। आर्थिक क्षेत्र में सावधानी बरतें। नौकरी में मन नहीं लगेगा।

मिथुन : नई योजना सफल होगी। नौकरी में उन्नति हो सकती है। आय का नया साधन बन सकता है।

कर्क : स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। शासन-सत्ता का सहयोग मिलेगा। व्यवसाय में उत्तम लाभ होगा।

सिंह : नौकरी में अधिकारी अनुकूल रहेंगे। पुत्र से मतभेद संभव है। संहत नरम रहेगी।

कन्या : दिनमान सामान्य रहेगा। कार्यक्षेत्र में व्यस्त रहेंगे। नौकरी में नई परेशानी आ सकती है।

तुला : नौकरी में प्रभाव बढ़ सकता है। व्यवसाय में उत्तम लाभ होगा। परिवार में आनंद रहेगा।

वृश्चिक : मानसिक उत्तेजना से बचें। योजना में सफलता संदिग्ध रहेगी। आर्थिक स्थिति यथावत बनी रहेगी।

धनु : आत्मबल बना रहेगा। पूर्वनियोजित कार्य सफल होगा। नौकरी में पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है।

मकर : मानसिक तनाव बना रहेगा। नौकरी में स्थिति अनुकूल रहेगी। अचानक व्यय हो सकता है।

कुंभ : सामाजिक कार्यों में रुचि रहेगी। धन संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। मनोइच्छा की पूर्ति संभव है।

मीन : नौकरी में मान-सम्मान बढ़ेगा। सरकारी क्षेत्र से अर्थ प्राप्ति संभव है। व्यवसाय में लाभ होगा।

सुडोकू

		6	9					
		8		6	3	1		
1			7				9	
2		3					5	9
6	1					3		2
	7				4			1
		5	2	1		8		
					6	2		

5	2	6	9	4	1	7	3	8
7	9	8	5	6	3	1	2	4
1	3	4	7	2	8	5	9	6
2	4	3	1	8	7	6	5	9
8	5	9	6	3	2	4	1	7
6	1	7	4	9	5	3	8	2
3	7	2	8	5	4	9	6	1
4	6	5	2	1	9	8	7	3
9	8	1	3	7	6	2	4	5

सुडोकू 81 वर्गों का ग्रिड है, जो 9 वर्गों के ब्लॉक में बंटा हुआ होता है। कुछ वर्गों के अंक लिखे हैं और खाली वर्गों में 1 से लेकर 9 तक के अंक लिखने होते हैं। कोई नंबर 1 पंक्ति, कॉलम या 9 वर्ग वाले छोटे ब्लॉक में दोबारा नहीं आ सकता है।

उत्तर

Job Alert अमर उजाला
Real-time job alerts
amarujala.com/jobs

यूपीएसएसएससी में संभावनाएं
आबकारी सिपाही के पदों पर रिक्तियां

722 पद
आवेदन की अंतिम तिथि : 24 जून, 2026
आयु-सीमा : न्यूनतम 18 वर्ष व अधिकतम 40 वर्ष
यहां आवेदन करें : upsssc.gov.in

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ■ 577 पद
ट्रेनी के पदों पर रिक्तियां
आवेदन की अंतिम तिथि : 01 मई, 2026
आयु-सीमा : न्यूनतम 18 वर्ष व अधिकतम 30 वर्ष निर्धारित
यहां आवेदन करें : nclcil.in

भारत संचार निगम लिमिटेड ■ 120 पद
वरिष्ठ कार्यकारी प्रशिक्षु के पदों पर मौके
आवेदन की अंतिम तिथि : 15 अप्रैल, 2026
वेतनमान : रुपये 24,900 से लेकर रुपये 50,500 तक
यहां आवेदन करें : bsnl.co.in

आईआरसीटीसी साउथ जोन ■ 84 पद
हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर के पदों पर आवेदन आमंत्रित
वॉक-इन-इंटरव्यू की तिथि : 25, 27 व 28 अप्रैल, 2026
योग्यताएं : बीएससी, बीबीए व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें : irctc.com

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ■ 59 पद
मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर आवेदन आमंत्रित
आवेदन की अंतिम तिथि : 13 अप्रैल, 2026
योग्यताएं : संबंधित विषय में इंजीनियरिंग व अन्य पात्रताएं
यहां आवेदन करें : engineersindia.com

एनएचआईडीसीएल में मौके ■ 37 पद
यंग प्रोफेशनल के पदों पर निकली भर्ती
आवेदन की अंतिम तिथि : 14 अप्रैल, 2026
पात्रताएं : मास्टर डिग्री, बीई, बीटेक व अन्य निर्धारित योग्यताएं
यहां आवेदन करें : nhidcl.com

विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन जारी...
नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा : उपायुक्त (वित्त) का पद रिक्त।
■ आवेदन की अंतिम तिथि : 06 जून, 2026
■ navodaya.gov.in
सीएसआईआर-खनिज एवं पदार्थ प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर : मल्टी-टास्किंग स्टाफ के पद खाली।
■ आवेदन की अंतिम तिथि : 21 अप्रैल, 2026
■ immt.res.in

अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए हमें udaan@amarujala.com पर ई-मेल करें।

इंटर्नशिप प्रोग्राम

यूआईडीएआई इंटर्नशिप प्रोग्राम

- संस्थान : भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई)
- अवधि : न्यूनतम छह माह
- सीट : 28
- पात्रताएं : बीटेक, बीई, एमटेक, ग्रेजुएशन, पोस्ट-ग्रेजुएशन व अन्य निर्धारित योग्यताएं
- अंतिम तिथि : 15 अप्रैल, 2026
- आधिकारिक लिंक : tinyurl.com/5yhdy5fr

फेलोशिप अलर्ट

एनजीओ फेलोशिप प्रोग्राम

- संस्थान : ताइवान अंतरराष्ट्रीय विकास गठबंधन
- पात्रताएं : सामुदायिक विकास, पर्यावरण, शिक्षा, महिला अधिकार, नागरिक सहभागिता, मानवाधिकार, आपदा राहत, दिव्यांग समावेशन, बाल व परिवार कल्याण तथा सामाजिक नवाचार-उद्यमिता क्षेत्रों में कार्यरत एनजीओ पेशेवर।
- आयु-सीमा : आयु 25 से 40 वर्ष के बीच।
- आवेदन लिंक : TAIWANAID.ORG/EN/NEWS/50124
- अंतिम तिथि : 01 जून, 2026

एग्जाम अलर्ट

एम्स नर्सिंग ऑफिसर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट

- परीक्षा की तिथि : 11 अप्रैल, 2026
- इस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य ज्ञान/योग्यता तथा नर्सिंग से कुल 100 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-तिहाई नकारात्मक अंकन का प्रावधान है।
- यहां से प्रवेश-पत्र डाउनलोड करें

aiimsexams.ac.in

बीपीएससी एईडीओ परीक्षा-2026

- परीक्षा की तिथि : 14 से 21 अप्रैल, 2026
- इस परीक्षा में प्रश्न पत्र-एक में सामान्य भाषा, प्रश्न पत्र-दो में सामान्य अध्ययन तथा प्रश्न पत्र-तीन में सामान्य योग्यता से कुल 300 अंकों के 300 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे।
- यहां से प्रवेश-पत्र डाउनलोड करें

bpsc.bihar.gov.in

सामान्य ज्ञान

साधना सप्ताह पहल

- क्या है : साधना सप्ताह, मिशन कर्मयोगी का एक हिस्सा है। इसका क्रियान्वयन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के कौशल, दृष्टिकोण और ज्ञान का विकास करना है।
- चर्चा में क्यों : साधना सप्ताह पहल भारत में सिविल सेवाओं को आधुनिक और बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम बनकर उभरी है।

टार बॉल्स

- क्या है : टार बॉल्स कच्चे तेल के छोटे, गहरे रंग के, चिपचिपे या सख्त पिंड होते हैं, जो समुद्र में तैरते हैं या तटों पर आ जाते हैं। ये पर्यावरणीय प्रभावों से परिवर्तित तेल के अवशेष होते हैं।
- चर्चा में क्यों : पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत के तटीय क्षेत्रों को तेल रिसाव से बचाने के उद्देश्य से 'टार बॉल्स प्रबंधन नियम, 2026' का मसौदा जारी किया है।

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

बंगाल की मतदाता सूची

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब जब बमुश्किल एक पखवाड़ा रह गया है, तब चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) का जिलेवार ब्योरा जारी कर पारदर्शिता बरतने की कोशिश की है। निस्संदेह, इस कार्य के लिए उसकी सराहना की जाती, अगर उसने शुरू से स्वतः ही यह प्रक्रिया अपनाई होती और सुप्रीम कोर्ट को बार-बार एसआईआर से जुड़े मामलों की सुनवाई न करनी पड़ती। बिहार और बंगाल की प्रक्रिया में तो शीर्ष अदालत को हस्तक्षेप तक करना पड़ा। बहरहाल, एसआईआर के बाद पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से अब तक 90 लाख से अधिक नाम हटाए गए हैं, जो वहां की पिछली मतदाता संख्या का लगभग 12 प्रतिशत है। इतनी बड़ी संख्या में हुई सफाई का चुनावी नतीजों पर क्या असर पड़ेगा, इसका विश्लेषण तो खैर परिणाम आने के बाद होगा, अलबत्ता अभी यह संतोष जताया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर न्यायिक अधिकारियों की गहन निगरानी में यह प्रक्रिया पूरी हुई है और जिन 60 लाख नामों को संदिग्ध सूची में डाला गया था, उनमें से 32.68 लाख नाम पुनः शामिल कर लिए गए हैं।

जिन लोगों के नाम न्यायिक अधिकारियों की जांच के बाद भी मतदाता सूची से हटाए गए हैं, शीर्ष अदालत ने उनके लिए हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक ट्रिब्यूनल गठित करने का आदेश पहले ही पारित कर रखा है। जाहिर है, उनके पास अभी एक और मौका है। जिन जिलों से सर्वाधिक नाम हटाए गए हैं, उनमें मुर्शिदाबाद से करीब 4.5 लाख, नॉर्थ 24 परगना से 3.2 लाख और मालदा से 2.3 लाख नाम शामिल हैं, यानी इन तीन जिलों में ही लगभग 10 लाख नाम सही नहीं पाए गए। बताने की जरूरत नहीं कि विधानसभा चुनावों में कुछ सौ और हजार मतों से नतीजे इधर या उधर होते हैं। ऐसे में, इन तीन जिलों की 65 सीटों पर राजनीतिक विश्लेषकों की पैनी नजर रहेगी। पूर्व के नतीजों से इनका समाजशास्त्रीय तुलनात्मक अध्ययन भी रोचक होगा। पश्चिम बंगाल के साथ-साथ 12 अन्य राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों में भी एसआईआर की प्रक्रिया हुई, पर जितना विवाद बंगाल में खड़ा हुआ, उतना अन्य जगहों पर नहीं हुआ।

एसआईआर के बाद पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से 90 लाख से अधिक नाम हटाए गए हैं, जो वहां की पिछली मतदाता संख्या का करीब 12 प्रतिशत है।

हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र की जीवंतता निर्विवाद निर्वाचन प्रक्रिया पर निर्भर करती है और इस प्रक्रिया की शुरुआत साफ-सुथरी मतदाता सूची से होती है। यह पहली बार है, जब मतदाता सूची को लेकर इस कदर हंगामा हुआ और मुकदमेबाजी हुई है। देश के राजनीतिक दलों की सराहना की जाएगी कि उन्होंने चुनाव प्रक्रिया को कामयाब बनाने में अब तक अपने अच्छे आचरण का प्रदर्शन किया है। चुनावों में धांधली व प्रशासनिक पक्षपात के आरोपों-प्रत्यारोपों के बावजूद उन्होंने जनादेश का हमेशा सम्मान किया और सुचारू रूप से सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। देश के तमाम राजनीतिक दलों को यह याद रखना चाहिए कि चुनाव आयोग एक सांविधानिक संस्था है और उसकी गरिमा को अक्षुण्ण रखने की नैतिक जिम्मेदारी सभी की है। एकाधिक आयुक्तों के बड़बोलेपन को सांविधानिक संस्था का क्षरण मानकर उस पर हमले करना, राष्ट्रीय हितों पर कुठाराघात होगा। संविधान निर्माताओं ने हर स्वायत्त संस्था की निगरानी और संतुलन की व्यवस्था कर रखी है, इसलिए एसआईआर को देशहित में जरूरी कवायद के रूप में देखने की जरूरत है। निर्वाचन आयुक्तों को भी गरिमा के अनुकूल आचरण करना चाहिए, ताकि इतिहास में उनके नाम को किसी शर्मनाक संदर्भ में न याद किया जाए।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 08 अप्रैल, 1951

युद्ध विस्तार की चर्चा

आखिर संयुक्त राष्ट्रीय सेनाएं भारी संख्या में 38वें अक्षांश को पार कर ही गयीं। इससे एक बार फिर स्पष्ट हो गया है कि अमरीका और उसके साथी कोरिया में युद्ध बन्द करना नहीं चाहते। यही नहीं, अब चीन की भूमि पर भी युद्ध विस्तार करने की गर्म चर्चा होने लगी हैं। बताया जाता है कि जनरल मेकार्थर को यह अनुमति मिल गयी है कि यदि साम्यवादी चीन अपने विमानों को भारी संख्या में युद्ध में झोंके, तो वे मंचूरिया-स्थित चीनी अड्डों पर बम वर्षा कर दें।

इसका क्या परिणाम होगा, यह सरलता से समझा जा सकता है। स्वतंत्रता और सुरक्षा के नाम पर एशिया तृतीय विश्व-युद्ध का समर-स्थल बने बिना नहीं रह सकेगा। अमरीका की ओर से लगातार इस बात का प्रचार किया जा रहा है कि साम्यवादी मंचूरिया की सीमा पर भारी सेना एकत्र रहे हैं, जिसमें सभी चीनी ही नहीं हैं। अन्य कौन-कौन से राष्ट्रों के सैनिक उसमें भाग ले रहे हैं, यह नहीं बताया गया, किन्तु संकेत निश्चित रूप से रूस की ओर है। 'न्यूयार्क टाइम्स' के मास्को स्थित संवाददाता ने जो समाचार दिया है, उससे पता चलता है कि रूस में इस समय युद्ध की तैयारियों का कोई चिह्न नजर नहीं आ रहा है और सब स्त्री-पुरुष इस समय वसन्त कालीन बुवाई में लगे हुए हैं।

यहां यह उल्लेख कर देना भी मनोरंजक होगा कि ताइपेह के राष्ट्रवादी सूत्रों के अनुसार साम्यवादियों ने अपनी एक अंतर्राष्ट्रीय वायु सेना बनायी है। उसका प्रधान कार्यालय मकदन में बताया जाता है और अन्य श्वेत, रूसी, भारतीय, बर्मी, फिलिस्तीनी तथा उत्तरी कोरियाई कर्मचारी भी सम्मिलित हैं।

हाल में संयुक्त राष्ट्र संघ के महामंत्री श्री त्रिग्वेली ने भी लेकसक्सेस में पत्रकारों के सामने एक वक्तव्य देते हुए कहा है कि कोरिया में लड़ाई जारी रखने के सिवा कोई चारा नहीं है। इसका कारण उन्होंने यह बताया है कि साम्यवादियों की ओर से शांति-स्थापना के प्रयत्न का कोई उत्तर नहीं मिल रहा। यदि वह अपना दिल टटोलें, तो स्वयं को भी इसी बात का दोषी पायेंगे। रणभूमि में साम्यवादियों का प्रतिरोध बढ़ गया और सबसे ताजे समाचारों के अनुसार उन्होंने 38वें अक्षांश के उत्तर में संयुक्त राष्ट्रीय सेनाओं की प्रगति रोक दी है। फलस्तीन में अशांति : इजराइल-जार्डन सीमा पर एक छुटपुट घटना हो गयी, जिसके परिणामस्वरूप एक इजराइली पुलिस मैन को प्राणों से हाथ धोने पड़े।

तलाक अब छिपाने की बात नहीं

यहां स्कैन करें

क्षमा शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार

आज तलाक के 58 प्रतिशत मामलों में पहल लड़कियां कर रही हैं। एक तरफ यह चौंकाने वाला तथ्य है, तो वहीं यह एहसास कराने वाला भी कि वे अब सशक्त हो रही हैं।

हाल ही में उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में एक अनोखी घटना देखने को मिली। यहां के रिटायर्ड जज ज्ञानेंद्र शर्मा की बेटी का विवाह साल 2018 में हुआ था। खबर के मुताबिक, विवाह के बाद से ही बेटी प्रणिता को परेशान किया जाने लगा था। अंततः उसने तलाक के लिए आवेदन किया। इसी 3 अप्रैल को तलाक मंजूर हुआ, तो प्रणिता को फूल-मालाएं पहनाई गईं। अदालत से अपने घर तक का रास्ता उसने ढोल बजाते, खुशी मनाते तय किया। बकौल प्रणिता- 'परिवार से पूरा समर्थन मिला, जिससे लड़ने की ताकत मिली। तमाम लड़कियों से कहूंगी कि कोई परेशान करे, तो चुप न रहें।' प्रणिता के पिता ने कहा कि मेरी बेटी शादी से दुखी थी, तो उसे खुशियां देना मेरा दायित्व था। वह ढोल-नगाड़ों के बीच विदा हुई थी। आज उसे उसी सम्मान के साथ वापस लेकर आया हूं। कोई मुआवजा भी नहीं लिया।'

कुछ साल पहले मध्य प्रदेश में भी एक पिता बेटी के ससुराल बैंड-बाजा लेकर गए। उन्होंने भी यही कहा था कि जिस तरह से बेटी को घर से विदा किया, उसी तरह से वापस ले जा रहा हूं। यह समाज को संदेश है कि यदि शादी न चले, तो यह शर्म की बात नहीं है, न ही किसी से छिपाने की, बल्कि सभी को सूचना देने की है कि हमारी लड़की का एक खराब रिश्ता खत्म हो चुका है।

हमारे समाज की यह समस्या है कि कोई शादी अगर न चले, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी लड़की पर डाल दी जाती है। अक्सर सुनने को मिलता है कि जरूर लड़की ने ही कुछ ऐसा किया होगा, जिससे रिश्ता नहीं चला। यही कारण है कि बहुत सी स्त्रियां, हजार मुश्किलें और अपमान झेलते हुए, कभी बच्चों के नाम पर, तो कभी समाज में उपहास के डर से अपने रिश्ते को बचाए रखना चाहती हैं। इसके लिए वे तमाम तरह के दुर्व्यवहार, हिंसा और लांछन को झेलती हैं। इनमें दहेज की मांग को पूरा न होने के कारण होने वाली हिंसा भी शामिल है। दूसरों को छोड़िए, अधिकांश मामलों में लड़की के परिवार वाले ही उसे यह सलाह देते हैं कि जैसे भी हो, निभा लो। यह सच है कि लड़कियां बदल गई हैं। वे पढ़-लिख गई हैं। बहुत सी बेटियां आत्मनिर्भर भी हैं, लेकिन तब भी वे बहुत सी कठिनाइयों को झेलने के लिए अभिशप्त हैं।

ऐसे में, मेरठ या मध्य प्रदेश की घटनाएं, माता-पिता की सोच में क्रांतिकारी बदलाव को दिखा रही हैं। माता-पिता अब नहीं चाहते कि किसी रिश्ते को चलाने और निभाने के नाम पर बेटी पूरी जिंदगी नरक भोगे। अनेक अध्ययन और रिपोर्टें बता रही हैं कि समाज में तलाक बढ़ रहे हैं। हालांकि, अब भी ये पश्चिमी देशों के मुकाबले बहुत कम हैं। ये एक से 1.1 प्रतिशत हैं। इतनी कम संख्या होने के बावजूद पिछले दो दशकों में तलाक की घटनाएं 50 फीसदी बढ़ गई हैं। गौर कीजिए, यही वे दो दशक हैं, जिनमें भारत ने मध्यवर्ग के तेज उभार और उसकी सोच को बदलते हुए देखा है।

अपने देश में कम तलाक होने का बड़ा कारण समाज का वह दबाव भी है, जो इसे ठीक नहीं मानता। यदि लोगों की बातचीत पर गौर करें, तो हर जगह यह सुनाई पड़ जाएगा कि 'अमुक को उसके पति ने छोड़ दिया।' जैसे कि पति को ही केवल यह अधिकार है कि वह पत्नी को छोड़ दे। 'जरूर लड़की में ही कमी रही होगी।' लड़कियों के तलाक न लेने का एक बड़ा कारण उनका आर्थिक रूप से सक्षम न होना, अपने परिवार का साथ न मिलना और लंबी कानूनी प्रकिया भी है।

अब स्थिति बदल रही है। बड़ी संख्या में लोग बिना तलाक लिए भी अलग-अलग रह रहे हैं। अलग रहने वालों की संख्या, छोटे शहरों और गांवों में अधिक है। जगह-जगह परिवार अदालतों की शुरुआत इस ओर संकेत कर रही है कि लड़कियां बदल रही हैं। आज 58 प्रतिशत लड़कियां तलाक की पहल कर रही हैं। एक तरफ यह चौंकाने वाला तथ्य है, तो दूसरी ओर यह एहसास कराने वाला भी कि लड़कियां जुल्म सहने से इनकार करने लगी हैं।

साल 2011 की जनगणना के अनुसार, दक्षिण भारत में उत्तर भारत के मुकाबले अधिक तलाक होते हैं। उत्तर के मुकाबले वहां स्त्रियां अधिक स्वायत्त और कामकाजी हैं। उत्तर भारत में यह सामाजिक शर्म अधिक है। यह भी एक तथ्य है कि अधिकांश मामलों में जब तक स्त्रियां सहती रहती हैं, विवाह चलता रहता है। तलाक के कारणों में घरेलू हिंसा, पत्नी का अधिक पैसे कमाना, पत्नी से अधिक से अधिक की मांग या पति का नपुंसक होना या विवाहेतर संबंध भी हैं। भारत में महाराष्ट्र में सबसे अधिक 18.7 प्रतिशत, कर्नाटक में 11.7 फीसदी, उत्तर प्रदेश में 8.8 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 8.2 फीसदी, दिल्ली में 7.7 प्रतिशत, तमिलनाडु में 7.1 प्रतिशत, तेलंगाना में 6.7 फीसदी और केरल में 6.3 प्रतिशत तलाक के मामले दर्ज किए गए हैं। कामकाजी जोड़ों में अधिक तलाक का होना भी स्त्री सशक्तीकरण को दर्शाता है।

पिछले दिनों अदालतों के एकाधिक ऐसे फैसले आए हैं, जिनमें कहा गया कि शादीशुदा स्त्री या पुरुष का बिना तलाक लिए लिव-इन में रहना अपराध नहीं है। एक जमाने में 'एडल्टरी' को अपराध माना जाता था, लेकिन अब वह अपराध नहीं है ! हां, ऐसा रिश्ता तलाक का आधार बन सकता है। सबसे गौर करने लायक बात यह है कि अब छोटे शहरों और गांवों में भी तलाक की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं, जहां वृद्धावस्था में लोग अलग हो रहे हैं। अब तो कई स्त्रियां तलाक के बाद 'ब्रेकअप पार्टी' भी देती हैं। सूचना-क्रांति ने लड़कियों के लिए दुनिया के दरवाजे खोल दिए हैं। टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया, अखबारों तक उनकी पहुंच है। उनमें बराबरी की भावना और जागरूकता बढ़ी है। अपनी खुशी और मानसिक स्वास्थ्य, किसी भी रिश्ते से बड़ा है, यह भावना भी उनमें नजर आती है। अब तो बाकायदा दूसरी शादी के लिए वैवाहिक विज्ञापन भी आने लगे हैं।

इसका एक पहलू यह भी है कि कई बार बहुत मामूली कारणों से तलाक के लिए मुकदमे किए जा रहे हैं। हनीमून से लौटकर या विवाह के एक सप्ताह बाद ही तलाक के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। जन्मदिन की मुबारकबाद क्यों नहीं दी या घुमाने नहीं ले गए अथवा पति दांत साफ नहीं करता, नहाता नहीं है, पत्नी के मुकाबले अपने परिवार को अधिक प्राथमिकता देता है, ऐसी शिकायतें भी तलाक के आवेदनों का आधार बन रही हैं। निस्संदेह, ये शिकायतें हास्यास्पद लगती हैं, लेकिन कुल मिलाकर इनसे यह तो परिलक्षित होता ही है कि समाज बदल रहा है।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

बाहरी कंपनियों पर निर्भर रहने से नुकसान होगा

यहां स्कैन करें

नितिन पई | निदेशक, तक्षशिला संस्थान

बीती 31 मार्च को ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) ने धमकी दी कि वह ईरान पर अमेरिकी-इजरायली हमलों के जवाब में 18 प्रौद्योगिकी कंपनियों को निशाना बनाएगा। इनमें से ज्यादातर अमेरिकी कंपनियां हैं। बाद में, उसने बहरीन स्थित अमेजन के डाटा सेंटर पर हमला किया भी।

यह एहसास ही बेहद चौंकाता है कि नागरिक-सैन्य जुड़ाव, नेटवर्क-केंद्रित युद्ध और एआई आधारित घातक हथियारों की वजह से प्रौद्योगिकी कंपनियां युद्ध में निशाना बन सकती हैं। हालांकि, असैन्य ढांचों पर हमला करने (जो युद्ध अपराध हो सकता है) और सैन्य अभियानों का हिस्सा बनने वाली निजी कंपनियों को निशाना बनाने (जो युद्ध अपराध नहीं है) के बीच एक बड़ा नैतिक और कानूनी अंतर है। अमेरिकी व इजरायली फौज ने बेशक ईरान के विश्वविद्यालयों और इस्पात संयंत्रों पर हमले किए, लेकिन उनके बारे में उन्होंने दावा किया कि वे ईरान की सैन्य क्षमता में योगदान दे रहे थे।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपनी सरकारों के हाथों की कठपुतली बनना चाहिए या नहीं, यह फैसला उनके शेयरधारकों को लेना है, पर ईरान की धमकी और कार्रवाई से यही आभास होता है कि वे इस तरह के फैसलों की जद में आने से नहीं बच सकतीं। यहां भारत के लिए भी चुनौती कम नहीं है। नई दिल्ली को अपने रक्षा, सुरक्षा और आर्थिक ही नहीं, ऊर्जा से जुड़े ढांचों को भी विदेशी कंपनियों पर निर्भरता से मुक्त करने के लिए व्यवस्थित रूप से कदम बढ़ाना चाहिए। बेशक, यह आसान काम नहीं है, पर ऐसा करना निहायत जरूरी है। भारत के लिए अपने रक्षा खर्च को दोगुना करने की एक बड़ी वजह यह भी होनी चाहिए।

भारत को रक्षा, सुरक्षा और आर्थिक ही नहीं, ऊर्जा से जुड़े ढांचे को भी विदेशी कंपनियों पर निर्भरता से मुक्त करने का प्रयास करना होगा।

साल 2024 में, अमेरिका की सॉफ्टवेयर कंपनी 'पलान्टिर' के सीईओ एलेक्स कार्प ने अपनी किताब में कहा था कि 'प्रौद्योगिकी क्षेत्र का यह दायित्व है कि वह उस राष्ट्र का समर्थन करे, जिसने उसके उदय को संभव बनाया'। उनके विचार में सिलिकॉन वैली का अस्तित्व और सफलता अमेरिकी सरकार की देन है, इसलिए उसे वाशिंगटन के भू-राजनीतिक एजेंडे का समर्थन करके इस ऐतिहासिक कर्ज को चुकाना चाहिए। चीन के साथ भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धा को देखते हुए, प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए अमेरिकी सरकार के साथ सहयोग करना जरूरी है, खास तौर से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में अपनी अजेय पकड़ को मजबूत बनाने के लिए। कार्प इसके लिए प्रौद्योगिकी क्षेत्र की बौद्धिक संस्कृति की आलोचना करते हैं कि वह राष्ट्र व उसके उद्देश्य की अनदेखी करती है। वह सिलिकॉन वैली की आधुनिक पीढ़ी के नए अभिजात वर्ग के ध्वजवाहक है, जिसने स्थानीय राजनीतिक विकल्पों के अनुसार सफलतापूर्वक अपने व्यावसायिक हितों को ढाला है और वाशिंगटन की विदेश नीति के साथ तालमेल बनाया है। उनका कहना यह नहीं है कि प्रौद्योगिकी कंपनियों को अमेरिकी सेना का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वैश्विक उदारवादी व्यवस्था को बढ़ावा मिलता है, बल्कि इसलिए कि अमेरिका असल में चीन, रूस, ईरान जैसे प्रतिद्वंद्वियों का सामना कर रहा है और पश्चिमी टेक कंपनियों का अपने देश के प्रति दायित्व है।

हालांकि, ऐसा सोचने वाले वह अकेले नहीं हैं। तकनीकी क्षेत्र के कई अन्य दिग्गजों ने भी अमेरिकी हितों के समर्थन में बयान जारी किए हैं। कुछ तो अमेरिकी सेना में शामिल भी हो गए हैं। यहां तक कि एंथ्रोपिक कंपनी ने भी यह एलान किया है कि वह सैन्य उपयोग से सहमत है और अमेरिका की रक्षा करने में विश्वास करती है। गौरतलब है कि यह वही कंपनी है, जिसका पेंटागन के साथ बड़ा विवाद हुआ था, जब उसने अपनी तकनीक का इस्तेमाल अमेरिकी नागरिकों की निगरानी करने और स्वचालित हथियारों को पावर देने के कामों में करने से मना कर दिया था।

इसका अर्थ यह है कि अमेरिकी टेक कंपनियों को वाशिंगटन की विदेश नीति का एक औजार मानना गलत नहीं होगा। ऐसा हमने तब भी देखा था, जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला बोला, तब माइक्रोसॉफ्ट ने अपने रूसी उपभोक्ताओं के लिए अपनी सेवाएं बंद कर दीं। इस लिहाज से भी देखें, तो बहुराष्ट्रीय या बाहरी कंपनियों पर निर्भरता खत्म करने को लेकर हमें अब संजीदगी दिखानी चाहिए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

मन को कैसे समझें

मन के रूप को समझने के लिए अन्वेषण का पथ क्या है? शरीर में जो 'मैं' के रूप में उदित होता है, वह मन है। जब कोई खोज करता है कि सर्वप्रथम मैं का विचार शरीर में कहां से उदित होता है, तो उसे पता चलता है कि यह हृदय से उदित होता है। वह मन के उदित होने का स्रोत है। मन में उदित होने वाले समस्त विचारों में मैं का विचार प्रथम है।

मन स्थिर (प्रशांत) कैसे होगा? 'मैं कौन हूं' के अन्वेषण द्वारा ही मन शांत होगा। मैं कौन हूं का विचार अन्य सभी विचारों को नष्ट कर देगा तथा जिस प्रकार शव जलाने वाला लुआठा भी अंत में स्वयं जल जाता है, उसी प्रकार यह भी स्वयं नष्ट हो जाएगा। तब वहां स्वरूप-दर्शन होगा।

जब व्यक्ति खोज करे कि मैं कौन हूं, तो मन अपने स्रोत में वापस चला जाता है और उदित विचार शांत हो जाता है। इसके बारंबार अभ्यास से मन अपने स्रोत में रहने की दक्षता विकसित कर लेता है। मन जो सूक्ष्म है, जब बुद्धि व ज्ञानेंद्रियों द्वारा बाहर जाता है, तो स्थूल नाम, रूप प्रकट होते हैं और जब यह हृदय में निवास करता है, तब नाम, रूप विलुप्त हो जाते हैं। मन को बाहर जाने से रोककर, उसे हृदय में स्थिर करने को अहंमुख या अंतर्मुखी होना कहते हैं। मन को हृदय से बाहर जाने देने को बहिर्मुखी होना कहते हैं।

इस प्रकार, जब मन हृदय में निवास करता है, तो मैं जो सभी विचारों का मूल है, लुप्त हो जाता है और सदैव अस्तित्वमान स्वरूप प्रकाशित होता है। व्यक्ति चाहे जो भी करे, उसे बिना 'मैं' के, अहंकार के कर्म करना चाहिए। जब कोई इस प्रकार से कर्म करता है, तो उसके समक्ष सब कुछ 'शिव स्वरूप' में प्रकट होगा।

आत्म-विचार के अतिरिक्त, कोई अन्य उपाय उपयुक्त नहीं है। यदि दूसरे उपायों से मन-नियंत्रण का प्रयास किया जाए, तो लगता है कि मन नियंत्रित है, किंतु वह पुनः प्रकट हो जाता है। प्राणायाम द्वारा भी मन स्थिर हो जाएगा, पर वह तभी तक नियंत्रित रहेगा, जब तक प्राण नियंत्रित है और जब श्वसन आरंभ होगा, तो मन पुनः गतिशील हो जाएगा और संचित वासनाओं के अनुरूप भटकेगा।

व्यक्ति चाहे जो भी करे, उसे बिना 'मैं' के अहंकार के कर्म करना चाहिए। जब कोई इस प्रकार से कर्म करता है, तब उसके समक्ष सब कुछ 'शिव स्वरूप' में प्रकट होता है।

मन और प्राण, दोनों का स्रोत एक ही है। निश्चित ही विचार मन का रूप है। मैं का विचार, मन का प्रथम विचार है और यही अहंकार है। जहां से अहंकार उत्पन्न होता है, वहीं से श्वसन भी आरंभी होता है। इसलिए जब मन स्थिर होता है, तो श्वास नियंत्रित हो जाता है और जब श्वास नियंत्रित होता है, तो मन स्थिर हो जाता है। सुषुप्ति में यद्यपि मन स्थिर रहता है, किंतु श्वास नहीं रुकता है। यह ईश्वरीय इच्छा के कारण है, ताकि शरीर सुरक्षित रहे और लोग यह नहीं समझें कि यह मर गया है।

रमण महर्षि

ओम बिरला | लोकसभाध्यक्ष

हमारी सभ्यता के उद्भव से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक की यात्रा ऋषि-मुनियों और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान से समृद्ध रही है। यह सशक्त विरासत हमें प्रेरणा देती है कि हम चुनौतियों के बीच भी आगे बढ़ते हुए नए भारत के निर्माण की दिशा में अग्रसर रहें।

प्रतियोगी छात्रों की परीक्षा लेता गैस संकट

पटना के मुसल्लहपुर हाट की तंग गलियों से लेकर प्रयागराज के कटरा और दिल्ली के वजीराबाद तक, एक समानांतर दुनिया बसती है, जहां हर सुबह भविष्य की इबारत लिखी जाती है। यह दुनिया उन हजारों मेधावी छात्रों की है, जो ग्रामीण अंचलों से आंखों में ऊंचे पदों का सपना लिए इन शहरों के छोटे-छोटे कमरों में डेरा डालते हैं। इन नौजवानों के लिए सफलता का रास्ता केवल किताबों से होकर नहीं गुजरता, बल्कि रसोई के उस छोटे से चूल्हे से भी होकर जाता है, जिस पर उनकी दिनचर्या टिकी होती है। आज जब इन छात्र-बहुल इलाकों में रसोई गैस की किल्लत और कालाबाजारी चरम पर है, तो इसका सबसे करारा प्रहार उन्हीं सपनों पर हुआ है, जो पहले से ही महंगाई की मार से पस्त थे।

इन इलाकों में 5 किलो वाला 'छोटू सिलेंडर' छात्रों का सबसे विश्वसनीय साथी माना जाता है। इसे एक से दूसरे कमरे में ले जाना आसान होता है और यह बजट के अनुकूल भी होता है। किंतु मौजूदा संकट ने इस सुविधा को एक बड़ी मुसीबत में बदल दिया है। गैस की आपूर्ति बाधित होते ही अवैध रिफिलिंग केंद्रों पर लूट मच गई है। जो गैस कभी सीमित बजट में मिल जाती थी, उसे अब 400 से 500 रुपये प्रति किलो तक की दर से भरवाने की नौबत आ गई है। 5,000 रुपये के कुल मासिक बजट में रहने वाले छात्रों के लिए यह अतिरिक्त खर्च किसी आर्थिक सुनामी से कम नहीं है, जो उनकी पूरी जमा-पूंजी को चंद दिनों में निगल जाता है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिनके पास गैस खत्म हो गई है, उनके लिए अब किताबों से ज्यादा चिंता रात के भोजन के इंतजाम की है। ग्रामीण इलाकों से आने वाले इन छात्रों के माता-पिता अक्सर किसान या दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जो खुद आधा पेट खाकर अपने बच्चों को शहर भेजते हैं। घर से आने वाले पैसे का एक-एक रुपया उम्मीदों के भारी बोझ से लदा होता है, इसलिए ये छात्र अपनी बुनियादी जरूरतों और सेहत से समझौता कर लेते हैं, पर अपनी मुश्किलों का जिक्र माता-पिता से नहीं करते।

इस संकट का सबसे कड़वा पहलू सिस्टम की बेरुखी है। इन युवाओं के पास कोई स्थायी आवासीय पता न होने के कारण वे सरकारी योजनाओं या सब्सिडी से वंचित हैं। नतीजतन, बिचौलिए उनकी विवशता का फायदा उठाते हैं। समय की मांग है कि सरकार और प्रशासन इन छात्रों के लिए 'विशेष ईंधन राहत योजना' तैयार करे। यदि इन छोटे कमरों में जलने वाले चूल्हे शांत हो गए, तो उन उम्मीदों की आंच भी मद्धम पड़ जाएगी, जो देश का भविष्य गढ़ने के लिए शहरों तक आई हैं।

हरिओम हंसराज, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

सिलेंडर का संकट

छोटा सिलेंडर अब आसानी से मिल रहा

पश्चिम एशिया के तनाव और आपूर्ति श्रृंखला में आई मुश्किलों के बाद देश में गैस संकट बढ़ने की बात कही जा रही है। हालांकि, जो व्यवस्था अब तक दिखी है, उसमें लगता यही है कि संकट उतना बड़ा नहीं है, जितनी उसकी अफवाह। जमाखोरों ने ऐसा माहौल बना दिया है, मानो रसोई गैस मिलना मुश्किल हो गया है, जबकि असलियत में ऐसा नहीं है। अगर ऑनलाइन बुकिंग की जाती है, तो एक-दो दिन में गैस की आपूर्ति कर दी जाती है। हां, उन लोगों को जरूर दिक्कत हो रही थी, जो कालाबाजारियों के भरोसे थे। मजदूरों और छात्रों की परेशानी की वजह यही थी।

किंतु सरकार ने समय रहते तत्परता दिखाई और अब कोई भी व्यक्ति बिना किसी एड्रेस प्रूफ के छोटा सिलेंडर खरीद सकता है। यह कदम निश्चय ही प्रवासी मजदूरों, छात्रों और उन लोगों के लिए मददगार साबित होगा, जिनके पास शहर में कोई स्थायी पता नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक, अब ग्राहकों को अधिकृत एजेंसी के पास जाना होगा और अपनी एक फोटो आईडी दिखानी होगी, जिसके बाद उनको तुरंत सिलेंडर मिल जाएगा। यह सही है कि पहले पांच किलो वाले गैस सिलेंडर के लिए भी कई सारे दस्तावेजों की जरूरत होती थी, जिस कारण प्रवासियों को दिक्कतों को सामना करना पड़ता था और वे मजबूरन खुले बाजार से छोटा सिलेंडर खरीदते थे। हालांकि, इससे उन्हें कोई खास परेशानी नहीं हो रही थी, उनकी मुश्किलें तो तब बढ़ीं, जब खुले बाजार में गैस के दाम बेहिसाब बढ़ने लगे। नतीजतन, किलो की दर से सिलेंडर भरवाने वाले इन लोगों को कालाबाजारी करने वाले लूटने लगे। इसीलिए, कई लोगों ने वापस गांव लौटने का फैसला किया। मगर सरकार इन सबसे वाकिफ थी। पहले तो उसने यह भरोसा दिया कि गैस की कोई किल्लत नहीं है और उलटी-सीधी दरों पर जो लोग खुले में गैस बेच रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद उसने छोटे सिलेंडर की खरीद-प्रक्रिया को भी काफी आसान बना दिया। इस कारण, उन लोगों की मुश्किलें दूर होती दिख रही हैं, जिनके घर का चूल्हा छोटे सिलेंडर से जला करता था।

देखा जाए, तो इस पूरे घटनाक्रम में कुछ दोष इन प्रवासियों का भी है। यह सही है कि उनके पास स्थायी पता नहीं होता, लेकिन किराये के मकान में भी अधिकृत एजेंसी से गैस सिलेंडर लिए जा सकते हैं। इसके बाद उनको छोटे सिलेंडर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अलबत्ता, बड़ा सिलेंडर उनके लिए कहीं अधिक सस्ता सौदा साबित होगा। इसलिए, हमेशा अधिकृत एजेंसी से ही गैस लेने का प्रयास करना चाहिए।

दीपक, टिप्पणीकार

जंग के समय हम कैसे जिएं

आनंद बख्शी के लिखे एक प्रसिद्ध फिल्मी गीत की पंक्ति है– जिंदगी हर कदम एक नई जंग है...। दुनिया के आम लोगों पर शायद यह गीत अक्षरश: लागू होता है। एक के बाद एक वैश्विक आपदाओं का सिलसिला टूट नहीं रहा है। ताजा आपदा ईरान युद्ध से पैदा हुई है। ऐसे में, क्या करना चाहिए? कैसी बड़ी सावधानियां बरतनी चाहिए? ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश में पेश है अटल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जेएनयू के प्रोफेसर ब्रजेश कुमार तिवारी का आलेख...

आज भारत का आम आदमी किसी युद्धभूमि में नहीं खड़ा, फिर भी वह युद्धों की मार झेल रहा है। वह दफ्तर जा रहा है, बच्चों की फीस भर रहा है, ईएमआई चुका रहा है, माता-पिता की दवाइयां खरीद रहा है, लेकिन उसकी जेब, नौकरी, बचत और मानसिक शांति पर दूर कहीं चल रही गोलाबारी का असर पड़ रहा है। आज की स्थिति में दुनिया सिर्फ रूस-यूक्रेन या अमेरिका-इजरायल व पश्चिम एशिया की खबरों से नहीं, बल्कि फैलती हुई असुरक्षा से घिरी हुई है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सिपरी) ने 2024 को बिगड़ती वैश्विक सुरक्षा का साल बताया था और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के अनुसार, अप्रैल 2025 के अंत तक जबरन विस्थापित लोगों की संख्या 13 करोड़ तक पहुंच गई थी। रूस-यूक्रेन के बाद अब ईरान और अमेरिका के बीच खुला सैन्य टकराव तथा होर्मुज संकट ने यह साफ कर दिया है कि आम आदमी यह कहकर खुद को दिलासा नहीं दे सकता कि युद्ध हमारे देश में नहीं है।

सिलेंडर का इंतजार : भारत में एक बड़ी आबादी रसोई गैस की किल्लत झेल रही है। अनेक जगहों पर सिलेंडर के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है। कीमतों में कुछ इजाफा हुआ है और आगे के लिए आशंका बनी हुई है।

तबाही का मंजर : ईरान, लेबनान सहित पश्चिम एशिया के कम से कम छह देशों में बम वर्षा हो रही है। लोग मारे जा रहे हैं और युद्ध का जल्दी कोई अंत नहीं दिख रहा है।

युद्ध का असर खर्च-बजट पर

युद्ध का असर सिर्फ बम से नहीं, बिल से दिखता है। किसी भी बड़े टकराव की सबसे तेज लहर- तेल, गैस, समुद्री ढुलाई, बीमा, उर्वरक और खाद्य कीमतों के रास्ते घरों तक पहुंचती है। सैन्य तनाव ने शिपिंग प्रवाह को गंभीर रूप से बाधित किया है। वर्ल्ड बैंक के ताजा कमोडिटी अपडेट ने मार्च 2026 में ऊर्जा मूल्य सूचकांक में 41.6 प्रतिशत, कच्चे तेल में 40.5 प्रतिशत और उर्वरक कीमतों में 26.2 प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज की है। भारत के लिए यह जोखिम और बड़ा है, क्योंकि यह आयात पर निर्भर है। इसलिए पश्चिम एशिया की आग देश के कोने-कोने के पेट्रोल पंप, ट्रक भाड़े, हवाई किराये और सब्जी मंडी तक पहुंच रही है।

जब तीसरे विश्व युद्ध की आशंका सता रही है, तब दूसरे विश्व युद्ध की याद स्वाभाविक है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने सिर्फ मलबा नहीं, पुनर्निर्माण भी देखा था। अर्थव्यवस्थाएं फिर खड़ी हुईं, उपनिवेशवाद पीछे हटने लगा और विकास को वैश्विक राजनीतिक लक्ष्य की तरह देखा जाने लगा। विश्व बैंक के ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि 1960 का दशक तेज आर्थिक वृद्धि, विश्व व्यापार के विस्तार और अपेक्षाकृत कम महंगाई का दशक था। इसी दौर में यह भरोसा भी बना कि संयुक्त राष्ट्र युद्ध रोकने, देशों को बातचीत की मेज पर लाने और नए स्वतंत्र देशों को वैधता देने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। हालांकि, आज तस्वीर बदलती दिखती है, जहां संयुक्त राष्ट्र बेअसर दिख रहा है। जब अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं कमजोर दिखती हैं, तब बाजार अस्थिर होते हैं, तेल महंगा होता है, आपूर्ति श्रृंखलाएं टूटती हैं और दूर हो रहे युद्ध की आंच पास के तमाम घरों तक कमोबेश पहुंचती है।

उदारीकण का खुशनुमा दौर

फिर एक दौर आया, भारत में कंप्यूटर का प्रसार और आर्थिक उदारीकरण लगभग एक साथ घटित हुआ। 1991 के बाद भारत ने लाइसेंस-परमिट राज से धीरे-धीरे बाहर निकलना शुरू किया और इसी समय सूचना-प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, सॉफ्टवेयर सेवाओं और बाद में डिजिटल भुगतान की दुनिया खुली। इसका सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि आम आदमी के लिए अवसरों का दायरा बहुत बढ़ा। 1991 के बाद सेवा क्षेत्र ने नई छलांग लगाई। ई-कॉमर्स ने रोजगार-उद्यमिता की नई संभावनाएं पैदा कीं। कंप्यूटर व मोबाइल ने आम आदमी को बाजार से सीधे जोड़ा है। आर्थिक सर्वे 2025-26 के अनुसार, भारत की प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय 1990-91 में मौजूदा कीमतों पर 6,126 रुपये थी, जो 2025-26 में 2,19,575 रुपये तक पहुंच गई।

महामारी ने दिया झटका

बढ़ रहे भारत को वैश्विक महामारी कोविड ने तगड़ा झटका दिया था, यह केवल एक स्वास्थ्य संकट नहीं था। आम भारतीय के जीवन पर बहुस्तरीय हमला था। भारत में इसका आर्थिक असर अत्यंत गहरा था। करोड़ों परिवारों की आय टूटी, लाखों छोटी दुकानें और काम-धंधे चरमरा गए, मध्य वर्ग को पहली बार समझ आया कि स्थिर नौकरी भी अस्थिर हो सकती है। कोविड का सबसे क्रूर असर असंगठित व निम्न-मध्य आय वर्ग पर पड़ा। इलाज, दवाओं, ऑक्सीजन, यात्रा, देखभाल और काम के नुकसान का संयुक्त असर केवल गरीब पर नहीं, मध्य वर्ग पर भी भारी पड़ा। महामारी चली गई, पर उसके घाव भारतीय समाज की नसों में मौजूद हैं।

कोविड के बाद जब विकसित भारत का सपना सड़कों, डिजिटल भुगतान, विनिर्माण, स्टार्टअप, बुनियादी ढांचे और बढ़ती अर्थव्यवस्था के सहारे जमीन पर बुना जाने लगा था, तभी दुनिया ने फिर करवट बदली। पहले रूस-यूक्रेन युद्ध ने ऊर्जा, खाद्यान्न और उर्वरक के वैश्विक बाजारों को झकझोर दिया और अब पश्चिम एशिया के संघर्ष, विशेषकर इजरायल-ईरान तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य पर बने संकट ने आम आदमी को फिर से यह याद दिला दिया है कि आज की दुनिया में दूर का युद्ध भी घर की रसोई तक पहुंचता है।

कुछ संभली थी जिंदगी

भारत ने महामारी और लॉकडाउन के बाद मजबूत आर्थिक रिकवरी दिखाई और इसकी आर्थिक वृद्धि तेज हुई। बीच में टैरिफ का भी तनाव हमने देखा, लेकिन आम आदमी की जिंदगी सिर्फ ग्रोथ रेट से नहीं चलती; वह पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, स्कूल फीस, अस्पताल, किराया और रोजमर्रा की ढुलाई के बिल से चलती है। आज आम आदमी यह महसूस कर रहा है कि वह मेहनत करके आगे बढ़ता है, और दुनिया की राजनीति उसे पीछे खींच लेती है। आम आदमी को सबसे बड़ा नुकसान महंगाई नाम के चुपचाप बढ़ने वाले कर से होता है। युद्ध आम आदमी को एक साथ दो तरफ से काटता है, आय अनिश्चित होती है और अनिवार्य खर्च चढ़ते चले जाते हैं। बड़ा आघात नौकरी पर भी पड़ता है।

युद्ध से भारत में हर फैक्टरी बंद नहीं होती, लेकिन अनिश्चितता बढ़ते ही कंपनियां भर्ती टालती हैं, निर्यात ऑर्डर सावधानी से लेती हैं, वेतन वृद्धि सीमित करती हैं और अस्थायी कर्मचारियों पर दबाव बढ़ाती हैं। यही वह बिंदु है, जहां मध्य वर्ग सबसे असुरक्षित हो जाता है, उसकी जीवन शैली स्थिर आय पर टिकी होती है।

आम आदमी करे उपाय

फिलहाल, सबसे जरूरी सवाल यह है कि अगर युद्ध और वैश्विक अस्थिरता ऐसे ही अंतरालों पर आते रहेंगे, तो भारत का आम आदमी कैसे जिएगा? अब बात सिर्फ कमाई की नहीं, हमें सहन-क्षमता की योजना बनानी पड़ेगी। जो मध्य वर्ग कल तक वेतन वृद्धि, बड़ी कार, विदेश यात्रा और बड़े ईएमआई के बारे में सोच रहा था, उसे अब लचीलेपन (रेजिलेन्स) की भाषा सीखनी पड़ेगी। अब नौकरी की दुनिया में एक स्किल और एक नियोक्ता पर टिके रहना जोखिम भरा है। घरेलू मांग वाले क्षेत्रों, सार्वजनिक सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त, डिजिटल अनुपालन, डेटा, लॉजिस्टिक्स, स्थानीय विनिर्माण और ऐसी भूमिकाओं की तरफ झुकाव बढ़ाना होगा, जिनकी उपयोगिता वैश्विक झटकों में भी बनी रहे। आम आदमी को अतिरिक्त आय के लिए भी समय के साथ तैयार होना होगा, जिससे मुख्य आय रुकने पर पूरा घर न डगमगाए।

बचत, बीमा, नकदी की ताकत

महामारी ने भारतीय परिवारों को यह सिखाया कि बचत, बीमा और तरल नकदी कोई वित्तीय आदत नहीं, बल्कि जीवन रक्षा का साधन है। बचत को विविध उपकरण (डाइवर्सिफाइड इंस्ट्रूमेंट्स) में लगाना होगा, कुछ हिस्सा तरल संपत्ति में होना चाहिए। आज के दौर में एक सामान्य नागरिक के लिए बचत खाता, ऋण तक पहुंच, जीवन व सामान्य बीमा, पेंशन और उपयुक्त निवेश, यह बुनियादी वित्तीय टोकरी है, विलासिता नहीं। 9 से 12 महीनों के अनिवार्य खर्च जितना इमरजेंसी कार्पस फण्ड बनाएं, वहीं बड़ी ईएमआई वाली लाइफ स्टाइल से बचना होगा।

संभलकर करें कोई खर्च

साथ ही, परिवारों को खर्च का नैतिक पुनर्गठन करना होगा। आज का विवेक यह नहीं कि किसने बड़ा फोन खरीदा; आज का विवेक यह है कि कौन परिवार अस्पताल, बेरोजगारी, स्कूल-शिफ्ट, किराये के संकट, बुजुर्ग देखभाल या अचानक रिलोकेशन का खर्च बिना टूटे वहन कर सकता है। बच्चों की शिक्षा में स्किल और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ज्यादा ध्यान देना होगा। सरकारों को समझना होगा कि 21वीं सदी का सामाजिक कल्याण सिर्फ राशन या नकद अंतरण नहीं है। सस्ती और भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवा, शहरी सार्वजनिक परिवहन, कौशल उन्नयन, डिजिटल सुरक्षा, ऊर्जा विविधीकरण, रणनीतिक भंडारण और सामाजिक सुरक्षा का महत्व बढ़ गया है। झटकों से जूझने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि सिर्फ भावनात्मक राष्ट्रवाद से आम आदमी की रसोई नहीं चलती है।

मिलकर खोजना होगा समाधान

आखिरकार, ऐसी दुनिया में आदमी कैसे जिए? इस प्रश्न का जवाब हम सबको मिलकर ढूढ़ना होगा। अब हमें यह मानकर चलना होगा कि दुनिया लंबे समय तक स्थिर रहने वाली नहीं है। इसलिए जीवन की योजना भी किसी स्थायी शांति, निश्चित आय या बिना बाधा वाले भविष्य की कल्पना पर नहीं, बल्कि अनिश्चितताओं के बीच टिके रहने की समझ पर आधारित होनी चाहिए। सच यह है कि विकसित भारत की असली परीक्षा शांति के समय नहीं, संकट के समय होगी। यदि भारत को आगे बढ़ना है, तो उसे केवल विकास नहीं, झटकों को सहने की क्षमता भी बढ़ानी पड़ेगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

41.6
प्रतिशत वृद्धि हुई है ऊर्जा मूल्य सूचकांक में, मार्च के महीने में, वर्ल्ड बैंक के ताजा कमोडिटी अपडेट के अनुसार।

ऊर्जा : बचत जरूरी

ऊर्जा की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। भारत में भी कुछ किल्लत देखी जा रही है। हालांकि, अन्य देशों की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में दिख रही है, लेकिन अप्रैल के आखिर तक अगर स्थितियों में सुधार न हुआ, तो भारत में ऊर्जा की लागत-कीमत बढ़ना तय है। विशेषज्ञ यह मान रहे हैं कि सरकार और आम लोगों के लिए ऊर्जा बचत की योजना बनाकर चलना बेहतर है।

26.2
प्रतिशत वृद्धि हुई है उर्वरक मूल्य सूचकांक में, मार्च के महीने में, वर्ल्ड बैंक के ताजा कमोडिटी अपडेट के अनुसार।

कृषि : सचेत रहें किसान

युद्ध अगर जल्दी समाप्त नहीं हुआ। होर्मुज अगर जल्दी नहीं खुला, तो भारत में उर्वरक संबंधी संकट गहराएगा। किसानों के लिए समस्या पैदा होगी। कृषि लागत में इजाफा होगा, जिससे कृषि पदार्थों की कीमत बढ़ेगी। आम तौर पर सेवा क्षेत्र और निर्माण या विनिर्माण में जब कमी आती है, तो कृषि क्षेत्र ही सहारा बनता है। अत: किसानों को सचेत रहते हुए अपनी आपाद योजना तैयार रखनी पड़ेगी, ताकि कम से कम घाटा उठाना पड़े।

ईरान युद्ध से पहले और अब भारत में महंगाई

महीना	महंगाई दर
जनवरी-26	3.3
फरवरी-26	3.7
मार्च-26	4.1
अप्रैल-26	4.7

कोरोना से पहले और अब दूध की कीमत
(सामान्य दूध की कीमत प्रति लीटर)

वर्ष	कीमत
2019	40
2022	50
2024	58
2026	60

कोरोना से पहले और अब चावल की कीमत
(सामान्य चावल की कीमत प्रति किलोग्राम)

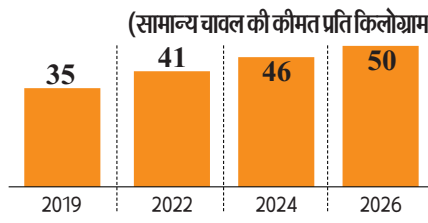

स्वर्ण की कीमत (साल 2008 की आर्थिक मंदी से आज तक, कीमत प्रति दस ग्राम)

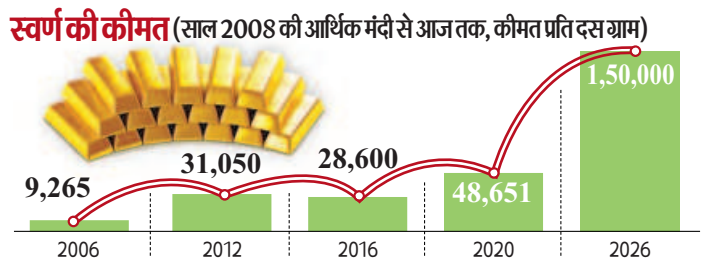

पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर)

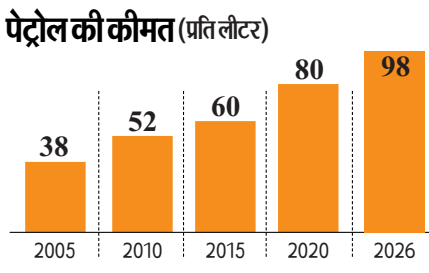

आज का विवेक यह नहीं कि किसने बड़ा फोन खरीदा; आज का विवेक यह है कि कौन परिवार अस्पताल, बेरोजगारी, स्कूल-शिफ्ट, किराये के संकट, बुजुर्ग देखभाल या अचानक कहीं जाने का खर्च बिना टूटे वहन कर सकता है। सरकारों को समझना होगा कि सस्ती और भरोसेमंद स्वास्थ्य-व्यवस्था, शहरी सार्वजनिक परिवहन, कौशल उन्नयन, डिजिटल सुरक्षा, ऊर्जा विविधीकरण, रणनीतिक भंडारण और सामाजिक सुरक्षा का महत्व बढ़ गया है। झटकों से जूझने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि सिर्फ भावनात्मक राष्ट्रवाद से आम आदमी की रसोई नहीं चलती है।

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

मेष : मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। माता की सेहत में सुधार होगा। धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में लाभ के अवसर मिल सकेंगे।

वृष : आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन परेशान हो सकता है। सेहत के प्रति सचेत रहें। परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। माता-पिता से धन की प्राप्ति हो सकती है।

मिथुन : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। कारोबार में वृद्धि होगी। किसी मित्र का सहयोग भी मिल सकता है। लाभ के अवसर मिलेंगे।

कर्क : आत्मविश्वास में कमी रहेगी। सेहत का ध्यान रखें। नौकरी में अफसरों का सहयोग भी मिलेगा। परंतु कार्यक्षेत्र में वृद्धि भी हो सकती है। आय भी बढ़ेगी।

सिंह : मन प्रसन्न रहेगा। परंतु आत्मविश्वास में कमी रहेगी। शैक्षिक कार्यों में सफल रहेंगे। मान-सम्मान में वृद्धि होगी। धार्मिक संगीत में रुचि बढ़ सकती है।

कन्या : मन परेशान हो सकता है। आत्मविश्वास में कमी भी रहेगी। धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। किसी पुराने मित्र से लंबे समय के बाद भेंट हो सकती है।

तुला : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। परंतु परेशान भी हो सकते हैं। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। पिता का साथ मिलेगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

वृश्चिक : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। वाणी में सौम्यता रहेगी। फिर भी धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें।

धनु : मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास भी भरपूर रहेगा। पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी। लेखनादि बौद्धिक कार्यों में मान-सम्मान की प्राप्ति हो सकती है।

मकर : मन परेशान रहेगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। धार्मिक कार्यों पर खर्च बढ़ सकता है। शैक्षिक कार्यों पर ध्यान दें।

कुंभ : मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। आत्मसंयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखें। बातचीत में भी संतुलन बनाए रखें। बौद्धिक कार्यों में भी मान-सम्मान की प्राप्ति होगी।

मीन : मन परेशान हो सकता है। धैर्यशीलता बनाए रखने के प्रयास करें। परिवार की जिम्मेदारी बढ़ सकती है। पिता का साथ मिलेगा। खर्चों में वृद्धि हो सकती है।

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋषिकांत गोस्वामी

08 अप्रैल, बुधवार, **शक संवत्** : 18 चैत्र (सौर) 1948, **पंजाब पंचांग** : 26 चैत्र मास प्रविष्टे 2083, **इस्लाम** : 19 शव्वाल, 1447, **विक्रमी संवत्** : वैशाख कृष्ण षष्ठी तिथि सायं 07.02 मिनट तक। मूल नक्षत्र (दिन रात), वरीयान योग सायं 05.11 मिनट तक पश्चात परिघ योग, वणिज करण, चंद्रमा धनु राशि में (दिन-रात)।
सूर्य उत्तरायण। सूर्य उत्तर गोल। बसंत ऋतु। दोपहर 12 बजे से दोपहर 01 बजकर 30 मिनट तक राहुकालम्। भद्रा सायं 07 बजकर 02 मिनट से। गण्डमूल विचार।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

कृपया ये बताएं कि दोष या संकेतों के आधार पर मुख्य द्वार की दिशा पता चलती है क्या?
तरुण कुमार, पटना

■ यदि घर में महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है, तो आपका मुख्य द्वार अग्नि कोण का हो सकता है। यदि संबंध अपने संबंधियों, मित्रों या अन्य लोगों से खराब हो रहे हों, तो आपका मुख्य द्वार उत्तर पश्चिम दिशा का हो सकता है। यदि खर्च अधिक हो रहे हों, तो मुख्य द्वार दक्षिण दक्षिण पश्चिम दिशा का हो सकता है। यदि घर में उदासी या नीरसता हो, तो मुख्य द्वार पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा का हो सकता है। यदि घर के लोगों को चिंता करने की बहुत आदत हो, तो यह पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा का हो सकता है।

वर्ग पहेली : 8292

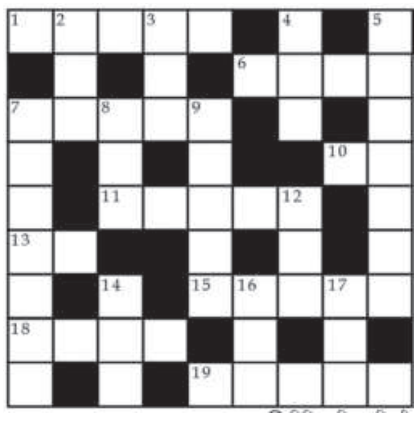

बाएं से दाएं
1. बहरा होने की स्थिति; सुनाई न देने का रोग (5)
6. एक मत; सहमत होने का भाव (4)
7. आशा के अनुकूल; आशा उत्पन्न करने वाला; प्रत्याशित (5)
10. जो समीप न हो; अंतर पर; अनासन्न; पार; फासले पर; हटकर (2)
11. नशीले पदार्थ का सेवन करना; मादक पदार्थ का उपयोग करना (2,3)
13. आकाश; आसमान; गगन (2)
15. अपमान करना; प्रतिष्ठा नष्ट करना; इज्जत मिट्टी में मिलाना (2,3)
18. झुकना; ढलकना; पिचकना; बचना; भय, संकोच या लज्जा के कारण छिपना; डांटना (4)
19. बसना; मकान तैयार करना; स्थायी तौर पर रहना; समृद्ध होना (2,3)

ऊपर से नीचे
2. आशाहीनता; निराशा (3)
3. अवनति; गिरावट; तबाही (3)
4. अथाह; गंभीर; गाढ़ा (3)
5. प्रतिकर्म करना; प्रतिशोध लेना; बदला चुकाना (4,3)
7. जिसने आयु भर के लिए एक बार चंदा जमा करवाया हो; जीवन पर्यंत सदस्य (4,3)
8. जलने की पीड़ा; दाह; ईर्ष्या (3)
9. कसर छोड़ना; त्रुटि होना (2,3)
12. प्रधान महिला पात्र; श्रेष्ठ नारी (3)
14. तैयार होना; परिपक्व होना; रंधना (3)
16. छोटा दुधारा हथियार (3)
17. एड़ी की बाहर निकली हड्डी; पैर का गट्टा (3)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8291

सुडोकू : 8274

* मध्यम

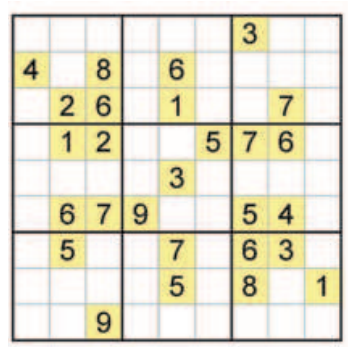

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8273

8	5	7	6	9	4	3	1	2
9	4	3	1	5	2	8	6	7
1	6	2	7	3	8	9	4	5
5	3	9	4	6	1	2	7	8
2	8	6	9	7	3	1	5	4
4	7	1	2	8	5	6	3	9
6	9	5	3	2	7	4	8	1
3	1	8	5	4	9	7	2	6
7	2	4	8	1	6	5	9	3

संपादकीय जागरण

बुधवार, 8 अप्रैल, 2026 : वैशाख कृष्ण - 6 वि. 2083

हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं

हठ छोड़ें अमेरिका-ईरान

ईरान पर होर्मुज समुद्री मार्ग खोलने के लिए दबाव बढ़ाने के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उसे दी गई अपनी नई धमकी में जिस तरह यह कहा कि रात भर में पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, जिसे फिर कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा, वह आज के युग की भाषा नहीं है। यह बर्बर कबीलाई युग की भाषा है, जब युद्ध के कोई नियम नहीं होते थे और हमलावर बर्बरता की पराकाष्ठा दिखाने में संकोच नहीं करते थे। 21वीं सदी में आदिम युग वाली भाषा सभ्य समाज के लिए चिंता का विषय है। क्या यह विचित्र नहीं कि ट्रंप एक ओर यह कह रहे हैं कि अमेरिका के हमलों में ईरान रात भर में मटियामेट हो सकता है और दूसरी ओर वे यह भी चाह रहे हैं कि ईरान के महान लोगों पर ईश्वर की कृपा हो? समझना कठिन है कि उनका इरादा क्या है? यदि वे समझौते की राह खोज रहे हैं तो उन्हें उसी हिसाब से सलीके से अपनी बात रखनी चाहिए। बीते कुछ दिनों से वे जैसी भाषा बोल रहे हैं, उससे तो बात बनने की बजाय बिगड़ती ही दिख रही है। इसमें संदेह नहीं कि अमेरिका ने इजरायल के साथ ईरान पर हमला बोलकर पश्चिम एशिया में एक गंभीर संकट खड़ा कर दिया, लेकिन इस संकट ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है तो ईरान के कारण भी।

ईरान ने समुद्री मार्ग होर्मुज को बाधित कर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। वह इस समुद्री मार्ग को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। यह वह जल मार्ग है, जिससे ऊर्जा के पांचवें हिस्से का नौवहन होता है। इस मार्ग के बाधित होने से पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट लगातार गहरा रहा है और इसके चलते तमाम देशों की सरकारों के साथ-साथ आम लोगों के समक्ष परेशानी खड़ी हो गई है। कहीं-कहीं तो उद्योग-धंधे बंद होने की नौबत आ गई है। गहराते ऊर्जा संकट के चलते महंगाई भी बढ़ रही है। एक तरह से ईरान ने होर्मुज पर कब्जा कर दुनिया को बंधक बनाने का काम किया है। उसकी लड़ाई तो अमेरिका और इजरायल से है। आखिर वह बाकी दुनिया को क्यों तंग कर रहा है? स्पष्ट है कि जहां अमेरिका को अपना रवैया बदलने की जरूरत है, वहीं ईरान को भी। ईरान का यह रवैया ठीक नहीं कि उसे अपनी बर्बादी की कोई परवाह नहीं। यदि वह युद्ध थामने के लिए लचीलेपन का परिचय देने के स्थान पर हठ दिखाता रहेगा तो फिर अपनी तबाही को ही निमंत्रण देगा। उसके जो समर्थक उसे अपने रवैये पर अड़े रहने के लिए उकसा रहे हैं, वे केवल अमेरिका और इजरायल को ही पस्त-परेशान होते हुए नहीं देखना चाहते। वे ईरान के भी शुभचिंतक नहीं कहे जा सकते, क्योंकि यह युद्ध जितना लंबा खिंचेगा, उसकी बदहाली उतनी ही बढ़ेगी। अच्छा होगा कि मानवता के लिए संकट बनते जा रहे इस युद्ध में बीच-बचाव करने के लिए भारत अपनी सक्रियता बढ़ाए।

नियोजित विकास की आस

दिल्ली की 1731 अनधिकृत कालोनियों में से 1511 को 'जैसा है, जहां है' के आधार पर नियमित करने का केंद्र सरकार के निर्णय को इन कालोनियों में रह रहे लोगों के लिए एक बड़ी राहत अवश्य है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि इस तरह से अवैध कालोनियों का नियमितीकरण दिल्ली के नियोजित विकास की परिकल्पना के विपरीत है। ऐसा नहीं है कि यह निर्णय पहली बार हुआ है, इससे पूर्व संप्रग सरकार के समय में भी 1900 से अधिक अनधिकृत कालोनियों का नियमितीकरण किया गया था, लेकिन नई अवैध कालोनियों को बसने से रोका नहीं गया।

अनियोजित कालोनियों के नियमन के साथ ही केंद्र सरकार ने दिल्ली में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) नीति को आगे बढ़ाने का भी निर्णय लिया है, जो सर्वथा उचित है। इसके तहत मेट्रो और आरआरटीएस कारिडोर के 500 मीटर के दायरे में नियोजित मिश्रित प्रयोग वाले विकास पर काम किया जाएगा। इससे दिल्ली के करीब 207 वर्ग किमी क्षेत्र में नियोजित विकास हो सकेगा। अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने से अवैध रूप से कालोनियां बसाने वालों के हौसले बढ़ते हैं, जो कतई नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह अवश्य कहा है कि अब नई अनधिकृत कालोनियां विकसित नहीं होने दी जाएंगी, इसे लेकर सख्ती बरती जाएगी। यह कदम भी अच्छा है।

अनधिकृत कालोनियों के नियमित होने से यहां के लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन यह नियोजित विकास की परिकल्पना के विपरीत है

कह के रहेंगे — माधव जोशी

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या बांग्लादेश की नई सरकार भारत के साथ संबंध सुधारने के प्रति गंभीर दिख रही है?

आज का सवाल

क्या सबरीमाला मामले में केंद्र का यह कहना सही है कि यह मुद्दा न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर का है?

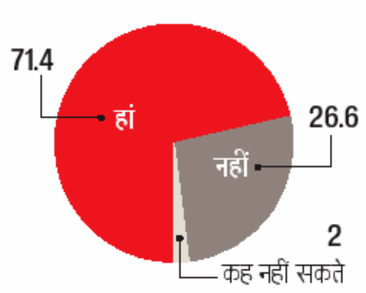

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

सत्ता की हैटट्रिक या विपक्ष की वापसी

राज कुमार सिंह

असम और केरलम में हार-जीत सिर्फ भावी सत्ता का ही फैसला नहीं, बल्कि दलों की दशा-दिशा को भी प्रभावित करेगी

इस समय तमाम निगाहें पश्चिम बंगाल चुनाव पर टिकी हैं, जहां 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा, लेकिन उससे पहले नौ अप्रैल को होने वाले असम और केरल के चुनाव में भी राजनीतिक दलों का बहुत कुछ दांव पर है। इन राज्यों में हार-जीत सिर्फ भावी सत्ता का ही फैसला नहीं करेगी, राजनीतिक दलों की दशा-दिशा को भी प्रभावित करेगी। दशकों तक कांग्रेस के दबदबे वाले असम के रास्ते ही भाजपा पूर्वोत्तर राज्यों की सत्ता पर काबिज हो पाई। जनसांख्यिकीय परिवर्तन से मूल पहचान के संकट को लेकर असें तक छात्र आंदोलन और हिंसा का शिकार रहे असम में 2016 में सरकार बनना भाजपा के लिए सुखद आश्चर्य ही था। वह आरएसएस और भाजपा की दशकों की मेहनत का भी प्रतिफल था, लेकिन कुछ श्रेय कांग्रेस की आत्मघाती राजनीति को भी दिया जाना चाहिए।

असम के बड़े कांग्रेस नेता रहे हिमंत बिस्वा सरमा के 2015 में भाजपा में शामिल होने के बाद ही पूर्वोत्तर राज्यों में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदले। बेशक असम का मुख्यमंत्री बनने के लिए हिमंत को पूर्वोत्तर में भाजपा के विस्तार की कठिन कसौटियों पर खरा उतरते हुए पांच साल इंतजार करना पड़ा, लेकिन आज वह उस क्षेत्र में पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। वे जिस तरह हिंदुत्व की आक्रामक राजनीति करते हैं, वह भाजपा को रास आ रही है। कांग्रेस में उनकी सेंधमारी जारी है और लगभग दो दर्जन पूर्व कांग्रेसियों को इस विधानसभा चुनाव में भाजपा से टिकट दिलवाने में भी वे सफल रहे हैं। हिमंत शैली की राजनीति असम समेत पूरे पूर्वोत्तर में ही भाजपा के लिए अभी तक फायदेमंद रही है। 126 सदस्यीय असम विधानसभा के चुनाव में हिंदू मतों का ध्रुवीकरण भाजपा की जीत का आजमाया हुआ नुस्खा है, जबकि कांग्रेस की आस अल्पसंख्यक मतों की गोलबंदी पर टिकी है, लेकिन वहां मूल और बाहरी का जटिल समीकरण भी है।

2016 के चुनाव में 64 प्रतिशत असमी हिंदुओं ने जहां राजग के पक्ष में मतदान किया, वहीं 24 प्रतिशत ने कांग्रेसनीत महाजोत को चुना। बंगाली हिंदुओं में 63 प्रतिशत ने राजग और 31 प्रतिशत ने महाजोत को वोट दिया। असमी मुसलमानों में 78 प्रतिशत ने महाजोत के पक्ष में मतदान किया, जबकि राजग को उनके सात प्रतिशत वोट ही मिले। बंगाली मुस्लिमों में से 76 प्रतिशत ने महाजोत को वोट दिया, जबकि राजग को मात्र छह प्रतिशत ने। 2021 के विधानसभा चुनाव में मतदान का रुझान बदला। राजग 67 प्रतिशत असमी हिंदुओं की पसंद बना, जबकि महाजोत को उनके 17 प्रतिशत वोट

अवधेश राजपूत

ही मिले। बंगाली हिंदुओं में भी राजग का मत प्रतिशत बढ़ कर 74 हो गया, जबकि महाजोत 23 प्रतिशत पर अटक गया, पर इसके बावजूद राजग 11 सीटें कम जीत पाया। महाजोत को 10 सीटों का फायदा हुआ। असम का सत्ता संग्राम इस बार भी इन दोनों गठबंधनों के बीच माना जा रहा है, लेकिन इस बार मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआइयूडीएफ महाजोत का हिस्सा नहीं है। पिछली बार महाजोत में 20 सीटों पर लड़कर 16 सीटें जीतने वाली एआइयूडीएफ इस बार अकेले लड़ रही है और उसे असदुद्दीन ओवैसी की एआइएमआइएम का समर्थन हासिल है। अजमल और ओवैसी की जुगलबंदी कांग्रेस के अल्पसंख्यक जनाधार में सेंध लगा सकती है। सीट बंटवारे पर कांग्रेस से तकरार के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा भी असम में पहली बार 16 सीटों पर किस्मत आजमा रहा है। उसकी उम्मीदें ऊपरी असम में केंद्रित चाय बागान कर्मियों के समुदाय पर टिकी हैं, जिन्हें आदिवासी माना जाता है। अन्य राज्यों से आकर बसे इन आदिवासियों की जनसंख्या, 2011 की जनगणना के मुताबिक 17 प्रतिशत के आसपास है। कई सीटों पर असर डाल सकने वाले ये आदिवासी मूलतः कांग्रेस समर्थक रहे हैं, लेकिन भाजपा भी इनमें सेंध लगाती रही है। एआइयूडीएफ और झामुमो की चुनाव मैदान में मौजूदगी कांग्रेस गठबंधन की मुश्किलें बढ़ाएगी, लेकिन विपक्षी मतों में इस बिखराव के बावजूद असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट सरीखे सहयोगियों के साथ मिल कर चुनाव जिताऊ बिसात बिछाने से भाजपा चूक गई तो पंथनिरपेक्षता के नाम पर वे अंततः कांग्रेस से ही हाथ मिलाएंगे। इसलिए इस सवाल का जवाब आसान नहीं कि राजग सत्ता की हैटट्रिक लगाएगा या विपक्ष वापसी करेगा?

केरलम की राजनीति वाम मोर्चा एलडीएफ और कांग्रेसनीत यूडीएफ के बीच बंटी रही है। केरलम ने हर चुनाव में सरकार बदल देने की अपनी परंपरा पिछली बार तोड़ दी। बंगाल और त्रिपुरा की सत्ता से बेदखल हो चुके वाम दलों के लिए 2021 का केरलम चुनाव परिणाम किसी संजीवनी से कम नहीं था। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में पासा पलट गया। 20 लोकसभा सीटों में से 18 यूडीएफ जीत गया। एलडीएफ के हिस्से एक ही सीट आई। भाजपा भी एक सीट जीतने में सफल रही। भाजपा तिरुअनंतपुरम में अपना मेयर बनाने में भी सफल रही, जहां से शशि थरूर सांसद हैं।

केरलम में राजग सत्ता का दावेदार भले ही न हो, पर अब वह राज्य की चुनावी राजनीति का तीसरा खिलाड़ी बन चुका है। उत्तरी केरलम क्षेत्र में यूडीएफ की बढ़त रहती है, पर सत्ता का फैसला आम तौर पर मध्य और दक्षिण क्षेत्र करते हैं। 26 प्रतिशत मुस्लिम और 18 प्रतिशत ईसाई मतदाताओं के मुकाबले केरलम में हिंदू वोटरों का प्रतिशत 56 है, पर भाजपा यहां उनकी पहली पसंद अभी तक नहीं बन पाई है। राजग को मिलने वाला मत प्रतिशत एलडीएफ और यूडीएफ के बीच सत्ता की जंग में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। एलडीएफ जीते या यूडीएफ, राष्ट्रीय राजनीति के नजरिये से सत्ता विपक्षी गठबंधन के ही पास रहेगी, लेकिन दलगत राजनीति की दृष्टि से यह चुनाव वामपंथ और कांग्रेस, दोनों के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। विजयन जनादेश पाने में सफल रहे तो एलडीएफ की सत्ता में हैटट्रिक होगी, वरना सत्ता राजनीति के मानचित्र से वामपंथ गायब हो जाएगा। अंतर्कलह से ग्रस्त कांग्रेस भी लगातार तीसरी चुनावी हार के बाद केरलम में भाजपा के विस्तार को शायद ही रोक पाए।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)
response@jagran.com

पश्चिम एशिया संकट : फंस गए रे ट्रंप

राजीव सचान

पश्चिम एशिया संकट का समाधान चाहे जब और जैसे हो, फिलहाल ट्रंप निरुपाय और कुंठित दिख रहे हैं

व्हाइट हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन में ट्रंप ● रेट्र

वर्ष 2010 की चर्चित फिल्म 'फंस गए रे ओबामा' एक कामेडी फिल्म थी। यह एक त्रासदी से उपजी थी। इसकी कहानी राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में अमेरिका में उभरे आर्थिक संकट से ग्रस्त भारत आए एक एनआरआइ से संबंधित थी। जैसे अमेरिका में आई मंदी ने उस वक्त सारे विश्व को परेशान किया, वैसे ही अमेरिका की ओर से इजरायल के साथ मिलकर ईरान पर किए गए हमले से आज सारा विश्व त्रस्त है। इस युद्ध को जारी हुए एक महीने से अधिक का समय बीत गया है और कहना कठिन है कि यह कब समाप्त होगा? यदि अमेरिका इजरायल का साथ नहीं देता तो इस युद्ध की नौबत ही नहीं आती, लेकिन ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने अहंकार के चलते ईरान को वेनेजुएला समझ लिया और बिना यह विचारे उस पर चढ़ाई कर दी कि उसने कितनी एवं कैसी सैन्य क्षमता हासिल कर ली है? वे इसे भी भांप नहीं सके कि ईरान पड़ोसी देशों में हमले करके और होर्मुज समुद्री मार्ग अवरुद्ध कर उनके पसीने छुड़ा देगा। वह फिलहाल सचमुच ऐसा करने में समर्थ है और ट्रंप को सूझ नहीं रहा है कि वे इस युद्ध से कैसे निकलें? एक ओर वे सबसे शक्तिशाली शासक और विश्व के नीति-नियंता होने के गुमान में हैं और दूसरी ओर ईरान को होर्मुज खोलने के लिए मोहलत पर मोहलत देकर अपनी कमजोरी भी जाहिर कर चुके। यदि उनकी सेना इतनी ही शक्तिशाली है तो ईरान की मारक क्षमता कम होने का नाम क्यों नहीं ले रही है? वह ऐसी-ऐसी मिसाइलें दागने में लगा हुआ है, जिससे अमेरिका भी दंग है और इजरायल भी। ट्रंप कभी ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने की धमकी देते हैं और कभी उससे शांति वार्ता की पहल करते हैं।

ट्रंप ने ईरान के समक्ष शांति वार्ता का जो प्रस्ताव रखा, उसने उसे खारिज ही नहीं किया, बल्कि उनका उपहास भी उड़ाया। वह उन्हें जवाबी धमकी भी दे रहा है। ट्रंप ने ईरान पर हमला करते समय कहा था कि वे वहां सत्ता परिवर्तन के साथ परमाणु हथियारों के निर्माण की उसकी क्षमता खत्म करना चाहते हैं। ईरान में सत्ता परिवर्तन के कोई आसार नहीं, जबकि उसके सुप्रीम नेता खामेनेई समेत कई बड़े सैन्य अफसर मारे जा चुके हैं। यह कहना भी कठिन है कि अमेरिका और इजरायल के हमलों में उसके परमाणु संयंत्र इतने बुरी तरह तबाह हो गए हैं कि वह फिर कभी परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल नहीं कर सकेगा।

अपनी टैरिफ नीति की लाठी से दुनिया को हांकने वाले ट्रंप न तो खाड़ी देशों को ईरान के हमलों से बचा पा रहे हैं और न ही अपने मित्र देशों और यहां तक कि नाटो देशों को इस युद्ध में सहयोग देने के लिए राजी कर पा रहे हैं। उनके मित्र देश उनका सहयोग करने के लिए इसलिए भी आगे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बहुत समय नहीं हुआ, जब उन्होंने ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी देकर उन्हें तंग किया था। ईरान ने इस माहौल की हवा निकाल दी है कि दुनिया में वही होगा, जैसा ट्रंप चाहेंगे और उनकी जिद के सामने अन्य देशों को झुकना ही होगा। ट्रंप यह कहते रहे हैं कि वे शांति के राष्ट्रपति हैं और सात-आठ युद्ध रोके हैं, लेकिन उनके पास इसका कोई जवाब नहीं कि वे रूस-यूक्रेन युद्ध क्यों नहीं रोक सके, जिस पर उन्होंने सबसे ज्यादा रियाज किया। शांति का स्वयंभू मसीहा होने के नाते वे खुद को नोबेल पुरस्कार का अधिकारी बताते रहे हैं और उसके न मिलने पर विलाप भी करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुल मिलाकर दुनिया को अस्थिर और अशांत ही किया है। वे अपने विरोधी देशों के साथ मित्र देशों से भी बुरा बर्ताव करने के आदी हैं। ट्रंप यह चाहते हैं कि सारी दुनिया उन्हें सलाम करे, लेकिन वे इसके लिए धौंस-धमकी का सहारा लेते हैं। इसी कारण वे आदर और सम्मान के पात्र नहीं और न हो सकते हैं। ट्रंप एक अविश्वसनीय और अराजक शासक हैं, क्योंकि वे अपने कहे से मुकरने, मनमानी करने और झूठ बोलने में माहिर हैं। वे ऐसा दिखाते हैं कि उनके पास दुनिया की हर समस्या का समाधान है, पर पश्चिम एशिया संकट उनके गले की हड्डी बन गया है। इससे वे कितने कुंठित हैं, इसका पता गत दिनों की उनकी गाली-गलौज वाली पोस्ट से मिला। उनकी भाषा का स्तर कुछ-कुछ हिंदी फिल्मों के इस डायलाग जैसा था-कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगा।

पश्चिम एशिया संकट में बुरी तरह फंस गए ट्रंप सहानुभूति के पात्र नहीं, क्योंकि उन्होंने मनमानी ही की। चूंकि ईरान अमेरिका और इजरायली हमलों से जूझ रहा है, इसलिए वह दुनिया के एक बड़े हिस्से में हमदर्दी हासिल कर रहा है, लेकिन यदि अमेरिका और इजरायल ने मनमानी की तो ईरान भी दूध का धुला नहीं। वहां की सत्ता एक निरंकुश और अपने ही लोगों के प्रति निर्मम बर्ताव करने वाली सत्ता है। उसने अपने ही हजारों लोगों को मारा है। वह इजरायल को दुनिया के नक्शे से मिटाने की सनक से बुरी तरह ग्रस्त है। यदि ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो इजरायल के अस्तित्व के लिए तो गंभीर खतरा बनेगा ही, पश्चिम एशिया में दादागीरी कर सबको तंग करेगा और हमास, हिजबुल्ला जैसे आतंकी संगठनों की और खुलकर मदद करेगा। पश्चिम एशिया संकट का समाधान चाहे जब और जैसे हो, फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति वहां बुरी तरह घिर गए हैं और उन पर 'फंस गए रे ट्रंप' जैसी फिल्म बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे खुद चलती-फिरती कामेडी बन गए हैं।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

गलती और सुधार

मनुष्य का जीवन पूर्णता की यात्रा नहीं, बल्कि निरंतर सीखने की अनवरत प्रक्रिया है। इस यात्रा में गलतियां हमारे पथ के पत्थर नहीं, बल्कि मार्गदर्शक रूपी दीपक हैं। गलती वह आईना है, जिसमें हम अपनी अपूर्णता, अपनी सीमाओं और अपने अहंकार को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी भूलों को स्वीकार कर, उनसे सीखकर सुधार का साहस करता है, वही आत्मविकास की दिशा में अग्रसर होता है। हम अनजाने में अनेक त्रुटियां करते हैं। कभी शब्दों में कठोरता आ जाती है, कभी निर्णयों में शीघ्रता, तो कभी संबंधों में उपेक्षा। यदि हम इन भूलों को अनदेखा कर आगे बढ़ जाते हैं, तो यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपने घर का दरवाजा खुला छोड़कर निश्चिंत होकर सो जाए। तब बाहरी खतरे धीरे-धीरे भीतर प्रवेश कर जाते हैं और हमें आभास भी नहीं होता कि हमारी सुरक्षा कितनी कमजोर हो चुकी है। इस क्रम में गलतियां हमारे व्यक्तित्व में धीरे-धीरे स्थायी दोष बन जाती हैं।

गलती को अपना गुरु बनाना केवल उसे स्वीकार करना नहीं, बल्कि उसके कारणों की तह तक जाना है। यह आत्ममंथन की वह प्रक्रिया है, जिसमें हम अपने भीतर झांकते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि हमसे कहां भूल हुई। यह प्रक्रिया कभी-कभी कष्टदायक होती है, क्योंकि यह हमारे अहंकार को चुनौती देती है। हालांकि यही पीड़ा हमारे विकास का आधार भी बनती है। जैसे कच्चा सोना अग्नि में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही मनुष्य अपनी भूलों की तपिश में निखरता है। यदि हम अपने व्यवहार की गलतियों को पहचान कर सुधार लें तो रिश्तों में आई दरारें भी भरी जा सकती हैं। जीवन हमें बार-बार यह सिखाता है कि पूर्णता कोई स्थायी अवस्था नहीं, बल्कि निरंतर सुधार की प्रक्रिया है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से डरता नहीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन का शिक्षक बना लेता है, वही सच्चे अर्थों में प्रगति करता है।

ममता कुशवाहा

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

अराजकता से त्रस्त बंगाल

'बेतुकी बयानबाजी' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में बंगाल की मुख्यमंत्री एवं टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की पहलगाम आतंकी हमले को लेकर की गई बेतुकी टिप्पणी पर जो तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है, वह उपयुक्त ही है। पाकिस्तान के रक्षामंत्री की अनर्गल बयानबाजी को आधार बनाते हुए पहलगाम हमले के लिए भाजपा पर तोहमत मढ़ना, दुश्मन देश की झूठी बात को शह देने जैसा है। बंगाल में प्रमुख विपक्षी दल भाजपा और सत्ता संभाल रही टीएमसी के बीच प्रायः तीखी बयानबाजी होती रहती है, लेकिन इसकी भी एक सीमा-रेखा होनी चाहिए। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर बंगाल की सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाए रखने वाली टीएमसी किसी भी हद तक जाने को तैयार बैठी है। विधानसभा चुनावों को निष्पक्ष रूप से करवाने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग को इस राज्य में सबसे अधिक कवायद करनी पड़ रही है। इसका प्रमुख कारण राज्य की प्रशासनिक मशीनरी का राजनीतिकरण होना माना जा रहा है। मालदा की अराजक घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट को भी राज्य के प्रशासन पर भरोसा नहीं रहा। ऐसे में बौखलाईं टीएमसी प्रमुख एवं राज्य की मुख्यमंत्री अपने वोटबैंक को मजबूत करने के लिए हर हथकंडा अपना रही हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अनर्गल बयानबाजी से प्रोत्साहित होकर ही कुछ अराजक तत्व राज्य में एसआइआर ड्यूटी पर तैनात न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने का दुस्साहस कर बैठे। इस खौफनाक अराजक घटना का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल की ध्वस्त होती कानून-व्यवस्था पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी कि 'भरोसा गंवा चुके हैं बंगाल के अधिकारी' राज्य सरकार को शर्मसार करने के साथ टीएमसी प्रमुख एवं राज्य की मुख्यमंत्री के गैरजिम्मेदाराना रवैये को रेखांकित करने वाली ही है।

डा. वीपी पाण्डेय, अलीगढ़

कभी दोस्त थे ईरान और इजरायल

इजरायल और ईरान के संबंध जानने के लिए ट्रिटा पारसी की पुस्तक 'ट्रेचरस अलायंस' पढ़नी चाहिए। इसमें ट्रिटा बताते हैं कि कभी ये देश परदे के पीछे मित्र हुआ करते थे। सुन्नी बहुल क्षेत्रों में जिस प्रकार इजरायल इकलौता यहूदी समुदाय का देश है। उसी प्रकार ईरान इकलौता पारसी एवं शिया समुदाय का देश है। इसलिए दोनों देश एक-दूसरे के प्रति समर्पित थे। वहां से किस तरह से दोनों देशों के बीच मतभेद पैदा हुए, यहां तक कि दोनों के बीच युद्ध भी हुए। अभी भी उक तरफ अमेरिका के साथ मिलकर इजरायल और दूसरी तरफ ईरान युद्ध लड़ रहे हैं। पुस्तक में बताया गया है कि जब ईरान में शाह मुहम्मद रेजा पहलवी की सत्ता थी, तब इजरायल और ईरान बहुत करीब थे। इजरायल ने तब के ईरान में अनेक तकनीकी संयंत्र स्थापित करने में सहयोग किया था। उस समय दोनों ने इराक और मिस्र जैसे देशों के विरुद्ध हाथ मिलाया था लेकिन यह मित्रता ईरान में सन 1979 में इस्लामी क्रांति आने के बाद टूट गई। खुमैनी ने इजरायल को दुश्मन घोषित कर दिया तभी से यह शत्रुता अभी तक चली आ रही है।

सुधीर गोयल, पिलखुवा हापुड़

एनसीईआरटी की पुस्तकों से राहत

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के सभी स्कूलों में कक्षा नौ से 12 तक केवल एनसीईआरटी की पुस्तकों को ही लागू किया जाएगा। यह कदम न केवल शिक्षा व्यवस्था में एकरूपता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि अभिभावकों के लिए भी बड़ी राहत लेकर आया है। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि कई निजी स्कूल प्राइवेट प्रकाशकों की महंगी किताबें अनिवार्य कर देते थे। इन पुस्तकों की कीमत अधिक होने के साथ-साथ हर साल उनमें मामूली बदलाव कर दिए जाते थे, जिससे अभिभावकों को हर वर्ष नई किताबें खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता था। ऐसे में एनसीईआरटी की पुस्तकों को अनिवार्य करना एक सराहनीय पहल है। ये किताबें न केवल किफायती होती हैं, बल्कि देशभर में एक समान पाठ्यक्रम को भी बढ़ावा देती हैं। इससे छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी मदद मिलती है, क्योंकि अधिकांश परीक्षाओं का आधार यही पाठ्यक्रम होता है। हालांकि इस निर्णय को प्रभावी ढंग से लागू करना भी उतना ही जरूरी है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी स्कूल इस नियम का पालन करें और अभिभावकों पर किसी प्रकार का अतिरिक्त आर्थिक दबाव न डाला जाए। कुल मिलाकर, यह फैसला शिक्षा को सरल, सुलभ और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, जिससे छात्रों और अभिभावकों दोनों को लाभ मिलेगा।

तरुण शर्मा, नंगली वाजिदपुर, नोएडा

पोस्ट

डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह ईरान की पूरी सभ्यता को नष्ट करने की बात कर रहे हैं, उसमें आधुनिक इतिहास के सबसे जघन्य युद्ध अपराध की गूंज सुनाई पड़ती है।

मिन्हाज मर्चेंट@MinhazMerchant

कनाडा के अधिकांश लोग अब अमेरिका से ज्यादा चीन को अधिक भरोसेमंद मानने लगे हैं। इससे ज्यादा कहने को और क्या ही बचता है। शोन रेन@shaunrein

पाकिस्तान के एक सीनेटर संयुक्त अरब अमीरात को बेचारा, असहाय और जरूरतमंद बताकर उस पर कटाक्ष कर रहे हैं। इससे पाकिस्तान की वही कुख्यात छवि पुख्ता होती है कि वह ऐसा सांप है जो दूध पिलाने वालों को भी डसने से बाज नहीं आता। जहक तनवीर@ZahackTanvir

जहां भारत भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को राजकीय सम्मान के साथ वायु सेना के विमानों से दुनिया भर में ले जा रहा है, पीएम बुद्ध का संदेश सब जगह ले जा रहे हैं और बुद्ध सर्किट बनाकर दुनिया के बौद्धों को आकर्षित कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान में मजहब में अंधे हो गए लोग आज भी बुद्ध की मूर्तियां तोड़ रहे हैं। जाहिल कहीं के।

दिलीप मंडल@Profdilipmandal

जनपथ

पवन 'ब'खेड़ा ने जड़ा ऐसा इक आरोप,
आया उस आरोप पर सरमा जी को कोप।
सरमा जी को कोप पुलिस ने मारा छापा,
अब पूरी कांग्रेस कर रही देखो स्यापा!
जहां नहीं आसान जीतकर खाना पेड़ा,
वहां बोल सच-झूठ करेंगे पवन बखेड़ा!!

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित
संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : **0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90** समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 36 अंक 263

खार्ग द्वीप पर 90 से ज्यादा हमले

10 रेलवे और हाइवे पुल, एक पेट्रोकेमिकल प्लांट और हवाई अड्डे पर ताबड़तोड़ हमले, 21 लोग मारे गए

- इजरायली हमले में तेहरान में यहूदी प्रार्थनास्थल सिनेगाग की इमारत ढही ,सऊदी अरब के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल संयंत्र पर ईरानी हमले में लगी आग
- इजरायल में ईरान, हिजबुल्ला और हाउती के मिसाइल और ड्रोन हमले, अमेरिका की धमकी के बाद ईरान में ऊर्जा ढांचों को बचाने सड़कों पर उतरे लोग

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: ईरान को आगे के हमलों की भयावहता से परिचित कराने के लिए मंगलवार को उसके महत्वपूर्ण ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की गई। **वाल स्ट्रीट जर्नल** ने मेहर न्यूज एजेंसी के हवाले से बताया कि ईरान के महत्वपूर्ण खार्ग द्वीप पर स्थित सैन्य ठिकानों पर 90 से ज्यादा हमले हुए। इसके अलावा 10 रेलवे और हाइवे पुल, एक पेट्रोकेमिकल प्लांट और हवाई अड्डे पर हमले हुए। काशान में रेलवे पुल पर हमले में तीन लोग मारे गए। ईरान ने भी जवाब में इजरायल के साथ-साथ सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और कुवैत पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए।

रायटर के अनुसार, अमेरिकी-इजरायली हमले में तेहरान के पश्चिमी शहर कराज में एक बिजली सबस्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन को नुकसान पहुंचा और बिजली व्यवस्था ठप हो गई। अलबोर्ज प्रांत में हवाई हमले में 18 लोग मारे गए। राजधानी तेहरान में एक के बाद एक कई धमाके हुए, जिसमें संभवतः पहाड़ों में बनाए गए हथियार भंडारों के साथ-साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। एक यहूदी प्रार्थनास्थल 'सिनेगाग' की इमारत ध्वस्त हो गई। इजरायल ने इस घटना के लिए दुख व्यक्त किया है। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने ईरान के 10 रेलवे और हाइवे पुलों को उड़ा दिया है। इजरायल ने ईरान के संयुक्त सैन्य कमान के वरिष्ठ कमांडर को निशाना बनाने का दावा किया है।

तेहरान में यहूदी प्रार्थना स्थल पर हमला। ईरानी समाचार एजेंसी ने इसकी वजह अमेरिकी या इजरायली हमले को बताया है● रायटर

ईरान का हमलाः एएनआइ के अनुसार, ईरान ने सऊदी अरब के जुबैल पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला किया और कहा कि ये हमला उसके साउथ पार्स गैस फील्ड से जुड़े असालुयेह पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हुए हमलों के जवाब में किया गया है। हमले के बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात की और हमले की कड़ी निंदा की। **एपी के अनुसार,** इजरायल में भी मिसाइल और ड्रोन से हमले हुए। ईरान के साथ-साथ हिजबुल्ला और हाउती ने भी उत्तरी और दक्षिणी इजरायल पर हमले किए। कतर ने चेतावनी दी है कि पश्चिम एशिया का सैन्य संघर्ष ऐसे स्तर पर पहुंचने जा रहा है, जहां से इसे नियंत्रित कर पाना असंभव होगा।

ईरान में ऊर्जा ढांचों को बचाने सड़कों पर उतरे लोग : एएनआइ ने तसनीम न्यूज एजेंसी के हवाले से बताया कि ईरान में लोगों ने देश के अलग-अलग इलाकों में स्थित ऊर्जा ढांचों के बाहर मानव शृंखला बनाकर एकजुटता का संदेश दिया। इसमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे भी शामिल हुए।

भारत ने ईरान में अपने नागरिकों को किया आगाह

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: युद्ध के बीच ईरान की स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। ट्रंप के बेहद आपत्तिजनक व आक्रामक बयानों के बाद भारतीय दूतावास ने ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और अगले 48 घंटे तक पूरी तरह घर के अंदर रहने की सलाह दी है।

तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने मंगलवार को जारी सलाह में कहा है कि तेजी से बदल रहे हालात को देखते हुए ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों को जहां हैं वहीं रहने, घर के अंदर शरण लेने की सलाह दी जाती है। आपातकालीन संपर्क नंबर भी दिए गए हैं जो निम्नवत हैं।

+98 9128109115,
+98 9128109109,
+98 9932179359

संयुक्त राष्ट्र में होर्मुज पर बहरीन के प्रस्ताव पर रूस और चीन का वीटो

संयुक्त राष्ट्र, रायटर: होर्मुज जलमार्ग की सुरक्षा और जहाजों की आवाजाही को लेकर मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में बहरीन द्वारा लाया गया प्रस्ताव रूस और चीन के वीटो के कारण पारित नहीं हो सका। 15 सदस्यीय परिषद में प्रस्ताव के पक्ष में 11 देशों ने मतदान किया, जबकि दो देशों, रूस और चीन, ने विरोध किया और दो सदस्य अनुपस्थित या तटस्थ रहे। रूस और चीन के नकारात्मक मत के कारण प्रस्ताव निरस्त हो गया।

बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल्लतीफ बिन राशिद अल जियानी ने मतदान के बाद कहा कि यह प्रस्ताव खाड़ी क्षेत्र में तेजी से बिगड़ती परिस्थितियों और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ रहे खतरे के मद्देनजर लाया गया था। उन्होंने कहा कि खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के देश विश्व ऊर्जा आपूर्ति के प्रमुख स्रोत हैं, इसलिए होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी है।

अल जियानी ने स्पष्ट कहा कि ईरान को अंतरराष्ट्रीय नौवहन के लिए इस मार्ग को बंद करने का कोई अधिकार नहीं है और वह दुनिया को जीवनोपयोगी ऊर्जा संसाधनों से वंचित नहीं कर सकता। होर्मुज जलडमरूमध्य से सामान्य परिस्थितियों में दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत तेल और गैस की आपूर्ति गुजरती है।

पश्चिम एशिया की स्थिति पर यूएनएससी में बैठक में मतदान करते सदस्य● एएफपी

गहराया संकट, ईरान की चेतावनी से ऊर्जा बाजार में बढ़ी बेचैनी

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध अब वैश्विक ऊर्जा संकट का रूप लेने लगा है। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने मंगलवार को चेतावनी दी कि यदि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों पर हमले की धमकी को अमल में बदला, तो अमेरिका और उसके सहयोगियों को क्षेत्र के तेल और गैस से वर्षों तक वंचित कर दिया जाएगा। ईरानी मीडिया में जारी बयान में यह भी कहा गया कि जवाबी कार्रवाई के लक्ष्यों के चयन में अब तक बरता गया संयम समाप्त कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन ने समीक्षा में कहा है कि इस बाधा से वैश्विक व्यापार, मुद्रास्फीति और ऊर्जा आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ रहा है। **एपी के अनुसार,** यूरोप में इसके प्रभाव साफ दिखने लगे हैं। फ्रांस में लगभग 18% पेट्रोल पंपों पर कम से कम एक प्रकार का ईंधन समाप्त हो गया, जिसके बाद सरकार ने करीब 900 अतिरिक्त टैंकर ट्रक आपूर्ति के लिए भेजे। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आइईए) ने चेताया है कि मार्च से अब तक 1.2 करोड़ बैरल से अधिक तेल आपूर्ति प्रभावित हो चुकी है और अप्रैल में संकट और गहरा सकता है।

राजनयिक सूत्रों के अनुसार चीन ने मतदान से पहले कहा कि मौजूदा मसौदा तनाव कम करने के बजाय सैन्य टकराव बढ़ा सकता है और इसमें सभी पक्षों की सुरक्षा चिंताओं का संतुलित उल्लेख नहीं है। इस बीच अमेरिका और उसके सहयोगी पहले ही इस मार्ग की निगरानी बढ़ा चुके हैं, जबकि बीमा प्रीमियम और समुद्री मालभाड़ा लगातार बढ़ रहा है।

पश्चिम एशिया युद्ध के बीच भारत-अमेरिका में तीन दिवसीय संवाद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: विदेश सचिव विक्रम मिसरी आठ से दस अप्रैल, 2026 तक तीन दिवसीय अमेरिका यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा भारत-अमेरिका के पूर्ण द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा और प्रमुख क्षेत्रों में चल रहे सहयोग को आगे बढ़ाने का मौका देगी। मिसरी अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से व्यापार, रक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा आपसी हित के क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इस यात्रा में खासतौर पर पश्चिम एशिया के मौजूदा युद्ध से दूर रहते हुए दोनों पक्ष रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी पर फोकस करेंगे।

ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई 'बेहोश', कोम में चल रहा इलाज : रिपोर्ट

- ब्रिटिश अखबार द टाइम्स ने अमेरिकी-इजरायली खुफिया आकलन के हवाले से किया दावा
- रिपोर्ट के अनुसार, शासन संबंधी किसी निर्णय प्रक्रिया में शामिल नहीं हो रहे मोजतबा

लंदन, एएनआइ: ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई को लेकर **ब्रिटिश अखबार द टाइम्स** ने दावा किया है कि अमेरिकी-इजरायली हमलों में घायल होने के बाद वह गंभीर हालत में बेहोश हैं और ईरान के पवित्र शहर कोम में उनका इलाज चल रहा है। अखबार ने मंगलवार को एक डिप्लोमैटिक मेमो के आधार पर यह रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें कहा गया है कि अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियों ने यह आकलन अपने खाड़ी सहयोगियों के साथ साझा किया है। मेमो के अनुसार मोजतबा खामेनेई फिलहाल शासन संबंधी किसी निर्णय प्रक्रिया में शामिल नहीं हैं और उनकी हालत अत्यंत गंभीर बनी हुई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि द टाइम्स ने वह मेमो देखा है, जिसमें पहली बार सुप्रीम लीडर की लोकेशन कोम बताई गई है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी से भी इस मेमो पर प्रतिक्रिया मांगी गई है, जबकि वाशिंगटन में पाकिस्तान दूतावास के भीतर कार्यरत ईरानी प्रतिनिधित्व से भी संपर्क किया गया है। अब तक तेहरान की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

युद्ध शुरू होने के बाद से मोजतबा खामेनेई सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं और उनके संदेश केवल सरकारी मीडिया के जरिए प्रसारित किए जाते रहे हैं। इसी बीच, द टाइम्स ने यह भी कहा है कि दिवंगत अयातुल्ला अली खामेनेई के पार्थिव शरीर को कोम में दफनाने की तैयारियां चल रही हैं, हालांकि अंतिम संस्कार की आधिकारिक तिथि घोषित नहीं की गई है। यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब ट्रंप द्वारा ईरान को समझौते के लिए दी गई मंगलवार रात आठ बजे (ईस्टर्न टाइम) की समयसीमा समाप्ति के करीब पहुंच गई।

'बिजली संयंत्रों को उड़ाने की धमकी युद्ध अपराध है'

वाशिंगटन, एपी: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के सभी पुलों और बिजली संयंत्रों को नष्ट करने की धमकी पर अंतरराष्ट्रीय कानून विशेषज्ञों ने गंभीर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यदि नागरिक बुनियादी ढांचे को व्यापक रूप से निशाना बनाया गया और उससे आम नागरिकों की जान पर असर पड़ा, तो इसे युद्ध अपराध माना जा सकता है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने ट्रंप द्वारा ईरान को दी गई चेतावनी पर गहरी चिंता व्यक्त की है। गुटेरेस ने दोहराया कि संघर्ष तब समाप्त होते हैं जब नेता विनाश के बजाय संवाद का विकल्प चुनते हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए राजनयिक प्रयासों को तेज करने का आह्वान किया। उनके निजी दूत जीन अर्नोल्ट इन प्रयासों में सहयोग देने के लिए क्षेत्र की यात्रा पर हैं। एंटोनियो गुटेरस के प्रवक्ता स्तेफान दुजारिक ने स्पष्ट कहा कि नागरिक ढांचे पर हमला अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत प्रतिबंधित है। कहा कि यदि किसी नागरिक ढांचे का सैन्य उपयोग भी हो रहा हो, तब भी हमला तभी वैध माना जाएगा जब उससे होने वाली नागरिक क्षति अनुपातहीन न हो।

ईरान के अहवाज में पुल पर ईरान के झंडे के साथ मानव शृंखला बनाए लोग● वीडियोग्रैब

साउथवेस्टर्न ला स्कूल की सैन्य कानून विशेषज्ञ रेचल वैनलैंडिंघम ने कहा कि बिजली संयंत्र नष्ट होने से अस्पताल, जल शोधन केंद्र व आवश्यक सेवाएं ठप पड़ सकती हैं। यूनिवर्सिटी आफ रीडिंग के अंतरराष्ट्रीय कानून विशेषज्ञ माइकल श्मिट ने कहा कि सैन्य लक्ष्य पर हमला तभी वैध है जब कम से कम नागरिक नुकसान सुनिश्चित किया जाए। ट्रंप ने कहा कि उन्हें युद्ध अपराध के आरोपों की चिंता नहीं है। ईरान के खिलाफ अमेरिकी दबाव के बीच कांग्रेस में भी मतभेद उभर आए हैं। रिपब्लिकन सीनेटर जोनी अर्न्स्ट ने ट्रंप के बयान को रणनीतिक दबाव बताया, जबकि डेमोक्रेटिक सीनेटर क्रिस वैन होलन ने इसे स्पष्ट युद्ध अपराध करार दिया।

पोप लियो ने कहा कि ईरान की आबादी के खिलाफ धमकियां अस्वीकार्य हैं। लियो ने दुनिया भर के नागरिकों से राजनीतिक प्रतिनिधियों से संपर्क करने और उनसे बढ़ते क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने का आग्रह करने का आह्वान किया है।

क्लासीफाइड
1800 203 8030

आवश्यकता

आवश्यकता है पहाडगंज स्थित गेस्ट हाउस में 1 हाउस कीपिंग मेटेनेंस प्रबंधक की जो साफ सफाई और उपकरणों की मेटेनेंस करा सके। बॉयोडेटा वाट्सएप-8447242560

RC Power Project Limited Hiring Tendering Specialist (Civil) with Experience in NHAI/CPWD/NHIDCL/Railway's Civil Tenders. Location Jaipur/ Delhi/ Agartala. Apply: hr@rcpplimited.com 8306001251, 9462163124.

बड़े आवासीय प्राजेक्ट के लिए यूपीवीसी खिड़कियों और दरवाजो के लगाने हेतु, ठेकेदार की आवश्यकता है। # 9711146800, 8448940985, Office Noida, Project-Gurugram.

सूचना

My clients Sh. Tej Singh S/O Late Ram Babu R/O U-105 Mangolpuri Delhi 110083 and his wife Smt Sudha have severed their relations completely with their son Rakesh and his wife Priyanka and their two minor children and have ousted them from their home for last several years and they are living separately and my clients are not responsible for their any act or conduct, whatsoever M. Husain Advocate

नाम परिवर्तन

I, Gurdial Singh Saini S/o Pritam Singh Saini, R/o H.No- A-52, Jain Colony Part-3, Matiala, Uttam Nagar, West Delhi, Delhi-110059, have Changed my name from Gurdial Singh Saini S/o Pritam Singh Saini to Gurdayal Singh S/o Preetam Singh for all future purposes.

I, Sanjeev kumar sharma S/o Late Phool Singh Sharma R/o I/849, Khera G.T.Road, Shahdara Delhi 110095 have Changed my name from Sanjeev Kumar to Sanjeev kumar sharma for all future purposes

इस्तांबुल में इजरायली वाणिज्य दूतावास के बाहर गोलीबारी

इजरायली दूतावास के बाहर हमलावरों के विरुद्ध मोर्चा संभालते पुलिसकर्मी● रायटर

इस्तांबुल, एपी: ईरान युद्ध के बीच तुर्किये के इस्तांबुल शहर में मंगलवार को उस इमारत को निशाना बनाकर हमला किया गया, जिसमें इजरायली वाणिज्य दूतावास स्थित है। हमलावरों ने इमारत के बाहर तैनात पुलिस पर गोलीबारी की। तुर्किये के अधिकारियों ने बताया कि एक हमलावर को ढेर कर दिया गया और दो घायल हो गए, जिन्हें पकड़ लिया गया।

इस्तांबुल के गवर्नर दावुत गुल ने पत्रकारों को बताया कि हमले के दौरान दो पुलिस अधिकारी भी घायल हुए। हमलावरों के पास लंबी बैरल वाले हथियार थे। दो हमलावर भाई थे, जबकि एक का ड्रग्स तस्करी से जुड़ा आपराधिक रिकार्ड था। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट तुर्किये में कई घातक हमले कर चुका है।

सभ्यता के अंत की कल्पना करने वाली कोई भाषा या कार्रवाई अस्वीकार्य : राहुल

नई दिल्ली, प्रेट्र : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक पूरी सभ्यता के नष्ट होने की धमकी के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि आधुनिक दुनिया में सभ्यता के अंत की कल्पना करने वाली कोई भी भाषा या कार्रवाई अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता।

एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कहा कि युद्ध दुखद हैं, फिर भी वे एक वास्तविकता बने हुए हैं। आधुनिक दुनिया में सभ्यता के अंत की कल्पना करने वाली कोई भी भाषा या कार्रवाई अस्वीकार्य है। उनकी यह टिप्पणी ट्रंप की उस धमकी के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने सहित समझौते पर पहुंचने की उनकी नवीनतम समय सीमा को पूरा करने में विफल रहता है तो मंगलवार रात को एक पूरी सभ्यता नष्ट हो जाएगी।

खाड़ी देशों की उड़ानें घट कर हुई एक चौथाई ,10 हजार से अधिक उड़ानें रद

- पश्चिम एशिया को रोजाना भारत से 300-350 उड़ानें थी, अब 80 से 90
- एअर इंडिया ने अकेले पिछले तीन हफ्तों में करीब 2500 उड़ानें रद की हैं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : भारत का एविएशन सेक्टर इन दिनों कई मोर्चों पर जूझ रहा है। पश्चिम एशिया में 28 फरवरी को शुरू हुए युद्ध के बाद इस क्षेत्र में भारतीय एयरलाइंस की रोजाना 300-350 उड़ानें घटकर मात्र 80-90 रह गई हैं। इसके चलते 28 फरवरी से अब तक भारतीय कैरियर्स द्वारा 10 हजार से अधिक उड़ानें रद हो चुकी हैं। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी असंगबा चुबा आओ ने मीडिया ब्रीफिंग में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत की कुल अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का 15 प्रतिशत पश्चिमी एशियाई देशों को होता था जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह बाजार उड्डयन कंपनियों के लिए कितना जरूरी रहा है। यह पूरी तरह से अस्थिर व अनिश्चित है। पूरे सेक्टर पर संचालन लागत बढ़ने का बहुत ही ज्यादा दबाव है।

युद्ध के बाद इस क्षेत्र का पूरा एयरस्पेस बंद हो गया है। इसके कारण एअर इंडिया ने पिछले तीन हफ्तों में करीब 2500 उड़ानें रद की हैं। पश्चिम एशिया संकट के अलावा एविएशन सेक्टर कई और गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है, इसमें सबसे अहम है ईंधन की आसमान छूती कीमतें और भारतीय रुपये की कमजोरी। अप्रैल 2026 से दिल्ली में एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमत 2,07,341 रुपये प्रति किलोलीटर तक पहुंच गई है।

उड़ान लैंडिंग और पार्किंग शुल्क में 25% की कटौती : मुंबई, प्रेट्र : एयरपोर्ट इकोनमिक रेगुलेटरी अथारिटी (एईआरए) ने एयरलाइन कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए प्रमुख हवाईअड्डों पर लैंडिंग और पार्किंग शुल्क में 25% की कमी की मंगलवार को घोषणा की। एईआरए ने आदेश में कहा कि यह कटौती तत्काल प्रभाव से लागू होगी और तीन महीने के लिए सभी घरेलू उड़ानों पर लागू होगी। सरकार द्वारा अथारिटी को दिए गए निर्देश के बाद यह शुल्क लागू किया गया है।

सरकार ने पांच किलो के एलपीजी सिलिंडर का कोटा दोगुना किया

नई दिल्ली, प्रेट्र : होर्मुज स्ट्रेट में भू-राजनीतिक तनाव के कारण एलपीजी आपूर्ति में बाधाओं को दूर करने के लिए केंद्र ने पांच किलोग्राम वाले एलपीजी सिलिंडर का राज्यों का दैनिक कोटा दोगुना कर दिया है। इससे प्रवासी श्रमिकों, छात्रों और दिहाड़ीदारों को राहत मिलेगी और यह सिलिंडर उन्हें सुगमता से उपलब्ध हो जाएगा। इस पांच किलो के इस एफटीएल सिलिंडर को लेने के लिए किसी पते की आवश्यकता नहीं होती और जरूरतमंद सिर्फ अपना पहचानपत्र दिखाकर इसे एलपीजी वितरण केंद्रों से आसानी से ले सकते हैं। दिल्ली में पांच किलो के इस सिलिंडर की कीमत 549 रुपये है। उधर 14.2 किलो के घरेलू एलपीजी सिलिंडर की कीमत 913 रुपये है। प्रवासी श्रमिकों के पास नियमित खाना पकाने के गैस कनेक्शन नहीं होते हैं। युद्ध के कारण ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान के चलते सरकार ने गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता दी है।

'इस्लामिक नाटो' का सपना टूटा, अलग-थलग पड़े मुनीर

नई दिल्ली, आइएएनएस : पाकिस्तान की वैश्विक राजनीति में अग्रणी बनने की हसरत अब एक रणनीतिक दुःस्वप्न में बदल चुकी है। कभी 'इस्लामिक नाटो' का नेतृत्व करने और पश्चिम एशिया में सुरक्षा प्रदाता बनने का ख्वाब देखने वाला इस्लामाबाद आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीयता के संकट से जूझ रहा है। 'फील्ड मार्शल' जनरल आसिम मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता कर तुर्किये, मिस्र और सोमालिया को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की थी, लेकिन मौजूदा वैश्विक संघर्षों ने पाकिस्तान की रणनीतिक खोखलेपन को उजागर कर दिया है।

जनरल मुनीर● इंटरनेट मीडिया

पाकिस्तान ने सऊदी अरब से रक्षा समझौता कर तुर्किये, मिस्र और सोमालिया को साथ लाने की कोशिश की थी

अवसरवाद और आंतरिक दबाव ने बिगाड़ा खेलः जब अमेरिका-इजरायल-ईरान संघर्ष गहराया, तो सऊदी अरब को उम्मीद थी कि पाकिस्तान अपने रक्षा समझौते का सम्मान करेगा। लेकिन पाकिस्तान की 'अवसरवादी' नीति आड़े आ गई। पाकिस्तान के सामने दोहरी चुनौती है-वह अपने देश की 15 प्रतिशत शिया आबादी को नाराज नहीं कर सकता, जो सेना के हर स्तर पर मौजूद हैं। दूसरी ओर, वह अमेरिका या इजरायल का साथ देकर सुन्नी बहुसंख्यक आबादी के गुस्से का जोखिम नहीं उठा सकता, जो इस युद्ध को धार्मिक चश्मे से देख रहे हैं। इस दोराहे पर खड़े पाकिस्तान की चुप्पी ने उसे खाड़ी देशों की नजरों में एक अविश्वसनीय साझेदार बना दिया है।

विफलता का आलम यह है कि मुनीर ने जब अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की, तो तेहरान ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। जनवरी 2025 में बलूचिस्तान में जैश-अल-अदल पर ईरानी हमलों ने दोनों देशों के बीच अविश्वास की खाई को और चौड़ा कर दिया है। घर में और बाहर गिरती साख को बचाने के लिए अब मुनीर अफगानिस्तान और बलूचिस्तान में आक्रामकता दिखा रहे हैं। काबुल में स्कूल पर बमबारी जैसी अमानवीय घटनाओं और 'आपरेशन सिंदूर' में मिली हार के बाद, मुनीर अपनी छवि बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।

सऊदी अरब पर ईरानी हमले क्षेत्रीय शांति के लिए खतरनाक : पाकिस्तान

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान के नागरिक और सैन्य नेतृत्व ने सऊदी अरब के पूर्वी क्षेत्र में स्थित ऊर्जा केंद्रों पर ईरान द्वारा किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की है। इस्लामाबाद ने इसे एक "खतरनाक वृद्धि" करार दिया है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम कराने के अंतिम प्रयासों में जुटा था। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा, 'पाकिस्तान सरकार सऊदी अरब के ऊर्जा केंद्रों पर ईरान द्वारा किए गए हमलों की स्पष्ट रूप से निंदा करती है और इस पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करती है।'

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, पी-2, सैक्टर - ओमेगा-1, ग्रेटर नौएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर-201308 (उ0प्र0)
दूरभाष नं0 0120-2395152/57/58 टोल फ्री नंबर : 18001808296, वेबसाइट : www.yamunaexpresswayauthority.com

पत्रांक : वाई.ई.ए./भूलेख/217/2026 दिनांक : 07.04.2026

सार्वजनिक सूचना

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा सैक्टर-08डी के अन्तर्गत 130 मीटर चौड़ी सड़क (जेवर-खुर्जा रोड से सैक्टर 08डी तक) आने वाले ग्रामों कमशः ग्राम थोरा व ग्राम बंकापुर की भूमि का सुनियोजित विकास हेतु सम्बन्धित कृषकों से आपसी सहमति के आधार पर प्राधिकरण द्वारा शासनादेश संख्या-314/77-3-16-163एम, दिनांक 23.02.2016 में तय प्रक्रियानुसार क्रय किया जाना प्रस्तावित है। क्रय की जाने वाली भूमि की दर हेतु विकल्प निम्नवत् हैं :-

(अ) रू0 3808/- प्रति वर्गमीटर (एक्सप्रेसिया सहित) एवं 07 प्रतिशत आबादी भूखण्ड।

अथवा

(ब) रू0 4300.00/- प्रति वर्गमीटर (एक्सग्रेसिया आदि सम्मिलित करते हुए)।

सैक्टर-08डी के अन्तर्गत 130 मीटर चौड़ी सड़क (जेवर-खुर्जा रोड से सैक्टर 08डी तक) आने वाले ग्रामों क्रमशः ग्राम थोरा व ग्राम बंकापुर के निम्न खसरा नम्बरान की भूमि को आपसी सहमति से क्रय किया जाना है जिसका विवरण निम्नलिखित तालिका में अंकित है :-

सैक्टर-08डी के अन्तर्गत 130 मीटर चौड़ी सड़क (जेवर-खुर्जा रोड से सैक्टर 08डी तक) के अन्तर्गत क्रय किये जाने वाले ग्रामवार खसरा नम्बरान का विवरण

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	130 मीटर रोड के अंतर्गत आ रहे ग्रामवार खसरा संख्या का विवरण, जिनका प्राधिकरण के पक्ष में क्रय किया जाना है	
		पूर्व क्रय हेतु प्रस्तावित खसरा नम्बरान	एयरपोर्ट में अर्जित अंश को छोड़कर क्रय हेतु प्रस्तावित खसरा नम्बरान
1.	थोरा	836, 897, 1165	826, 829, 835, 1142, 1272, 1271, 1268
2.	बंकापुर	248	238, 239

उपरोक्त भूमि क्रय किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह लिखित रूप में 15 दिन के अन्दर विशेष कार्याधिकारी/डिप्टी कलेक्टर, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

डिप्टी कलेक्टर

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मास्टर प्लान के अतिरिक्त प्लॉटिंग/हाउसिंग/कॉलोनी या किसी भी प्रकार का अन्य निर्माण पूरी तरह से अवैध है। सामान्यजन इस प्रकार की खरीद - फरोख्त से पूर्णतः सचेत रहें तथा कॉलोनाइजर के भ्रामक विज्ञापनों से बचें। अधिक जानकारी के लिए प्राधिकरण की वेबसाइट www.yamunaexpresswayauthority.com देखें।

युद्ध की आग

ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद शुरू हुए युद्ध को अब एक महीना से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अब भी तनाव और टकराव की आक्रामकता में कोई कमी नहीं देखी जा रही है। बीच-बीच में युद्ध विराम की बात उठती है और अगले ही दिन पहले से ज्यादा तीव्रता वाले हमलों के बीच गुम होकर रह जाती है। खबरों के मुताबिक, अमेरिका ने ईरान के खर्ग द्वीप पर फिर हमला किया। इसके अलावा, ईरान के अल्बोर्ज प्रांत में हुए ताजा हवाई हमले में कम से कम अठारह लोगों की मौत हो गई। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी ने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है कि अगर ईरान मंगलवार रात आठ बजे तक होर्मुज जलमार्ग से जहाजों की आवाजाही पूरी तरह बहाल नहीं करता है, तो उसके सभी बिजली संयंत्रों और पुलों पर बमबारी की जाएगी। सवाल है कि क्या अमेरिका को इस बात की फिक्र है कि नागरिक ढांचों पर होने वाले हमलों को युद्ध अपराधों के दायरे में देखा जा सकता है। ईरान में हमले की वजह से एक स्कूल की कई बच्चियों की मौत को लेकर पहले ही अमेरिका-इजराइल के रवैये पर तीखे सवाल उठ चुके हैं।

ऐसा लगता है कि इस युद्ध में हमले के ठिकाने चुनने के मसले पर मानवीयता के प्रश्न पीछे छूट गए हैं। जहां इजराइल और अमेरिका की ओर से ईरान पर मिसाइल की मार करने से लेकर बमबारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है, तो वहीं ईरान ने भी इजराइल सहित मध्य-पूर्व के देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला करने में कोई कमी नहीं की है। इससे इतर युद्ध की वजह से मध्य-पूर्व के समूचे प्रभावित इलाके में जिस पैमाने पर कच्चे तेल का उत्पादन और उसका कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है, उसका असर समूची दुनिया पर किसी न किसी रूप में पड़ रहा है। बहुत सारे देशों में तेल, गैस और खाद की आपूर्ति बाधित हुई है। विडंबना यह है कि यह सब देखने-समझने के बावजूद युद्ध को खत्म करने या कम से कम कुछ दिनों के विराम की बात भी ठोस तरीके से सिरा नहीं पकड़ रही है। एक ओर अमेरिका के राष्ट्रपति आए दिन ईरान में सब कुछ नष्ट कर देने की धमकी देते हैं, तो दूसरी ओर ईरान इसका जवाब देने की बात करता है।

तनाव के स्वरूप का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि ईरान ने पैंतालीस दिन के युद्धविराम के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और कहा कि वह युद्ध की स्थायी और पूर्ण समाप्ति तथा फिर से ईरान पर आक्रमण नहीं किए जाने की गारंटी चाहता है। एक तरह से ईरान की इस मांग को समझा जा सकता है कि कूटनीतिक प्रयासों की सार्थकता तभी है, जब किसी भी वार्ता के माध्यम से स्थायी समाधान तक पहुंचा जा सके। अगर हल निकालने के लिए चल रही बातचीत में कोई तात्कालिक आश्वासन दिया जाता है और उसमें विश्वसनीयता की कमी होगी, तो ऐसे प्रयास युद्ध के मूल कारणों को दूर करने में नाकाम रहेंगे। बल्कि इसके विपरीत नतीजे भी निकल सकते हैं। जाहिर है, कुछ समय के युद्धविराम की गुंजाइश निकालने के बजाय संघर्ष को पूरी तरह खत्म करने के उपायों पर पहुंचने के उद्देश्य से बिना देर किए शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। मगर अभी युद्ध को लेकर जिस तरह की जिद देखी जा रही है, उससे किस तरह का समाधान निकाला जा सकता है। व्यापक पैमाने पर विनाश के बाद जब युद्ध थमेगा, तब किसी भी तरह के समाधान की कीमत क्या होगी?

धमकियों का जाल

देश भर में शिक्षा संस्थानों, अस्पतालों, सरकारी भवनों और अन्य सार्वजनिक स्थलों को बम से निशाना बनाने की झूठी धमकियों का बढ़ता सिलसिला सुरक्षा की लिहाज से चुनौती बन गया है। ई-मेल या फिर सोशल मीडिया के जरिए इस तरह की धमकियां दी जाती हैं, जिससे न केवल लोगों में दहशत फैलती है, बल्कि सुरक्षा एजंसियों का कीमती समय और संसाधन भी बर्बाद होते हैं। बीते सोमवार को चंडीगढ़ के कई स्कूलों और सरकारी इमारतों को बम से उड़ाने की धमकियां ई-मेल पर दी गईं, हालांकि जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। संभवतः धमकी देने वालों का मकसद महज दहशत फैलाना ही रहा होगा। मगर सवाल है कि आखिर इस तरह की घटनाओं पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है? क्या सुरक्षा एजंसियां धमकी देने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने में तकनीकी रूप से सक्षम नहीं है? ये प्रश्न इसलिए महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह के ज्यादातर मामलों में पुलिस या अन्य जांच एजंसियां अपराधियों तक पहुंच ही नहीं पाती हैं।

गौरतलब है कि हाल के वर्षों में बम की झूठी धमकियां देने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। मई, 2024 में दिल्ली-एनसीआर में एक ही दिन में करीब ढाई सौ स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी से पुलिस के हाथ-पांव फूल गए थे। हालांकि, इस तरह की तमाम धमकियां झूठी साबित हुईं हैं, लेकिन इससे जहां दहशत का माहौल पैदा हो जाता है, वहीं जांच एजंसियों के सामने कई चुनौतियां पैदा हो जाती हैं। ऐसे मामलों में अब तक की जांच में सामने आया है कि धमकी भरे ज्यादातर ई-मेल वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जरिए विदेशी आइपी पते से भेजे जाते हैं। मगर आज डिजिटल तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है कि इसके जरिए दुनिया के किसी भी कोने में छिपे अपराधी को खोजा या पकड़ा जा सकता है। मगर पुलिस और अन्य जांच एजंसियों में अलग से बनाई गई साइबर शाखाओं के विशेषज्ञ क्या डिजिटल तकनीक में इतने पारंगत नहीं हैं कि वे ऐसे अपराधियों का पता लगा सकें? सरकार और प्रशासन को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा, क्योंकि यह केवल दहशत फैलाने का मामला नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा और तकनीकी क्षमता का भी सवाल है।

जलवायु संकट से जटिल होती चुनौतियां

जलवायु संकट केवल पर्यावरणीय आपदा नहीं, बल्कि बहुआयामी चुनौती है। यह आर्थिक असमानता को गहरा रही है और सामाजिक स्थिरता को मुश्किल में डाल रही है। यह समस्या केवल मौसमी अनियमितताओं तक सीमित नहीं है। यह प्रणालीगत विफलता का भी द्योतक है।

अजय प्रताप तिवारी

वैश्विक प्रगति की दौड़ में, जहां मानव सभ्यता सतत विकास को आत्मसात करने का प्रयास कर रही है, वहीं जलवायु परिवर्तन एक अदृश्य, लेकिन दुर्जेय अवरोध के रूप में उभरा है। आज के विश्व में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में निहित आर्थिक समृद्धि, सामाजिक समानता और पर्यावरणीय संतुलन के त्रिविमीय उद्देश्य बाढ़, सूखा और प्राकृतिक आपदाओं की भंवर में उलझ जाते हैं। जलवायु संकट केवल पर्यावरणीय आपदा नहीं, बल्कि बहुआयामी चुनौती है। यह आर्थिक असमानता को गहरा रही है और सामाजिक स्थिरता को संकट में डाल रही है। यह संकट केवल मौसमी अनियमितताओं तक सीमित नहीं है। यह प्रणालीगत विफलता का भी द्योतक है।

हिमालयी क्षेत्रों में हिमनदों के तेजी से पिघलने से जल संसाधनों का संकट बढ़ रहा है। यह स्थिति भारत की कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगी, जहां साठ फीसद से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रपट चेतावनी देती है कि यदि वैश्विक तापमान वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर जाती है, तो सतत विकास लक्ष्य जैसे- सबको भोजन, स्वच्छ जल, आर्थिक समानता, जलवायु कार्रवाई जैसे लक्ष्य असाध्य हो जाएंगे। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की अवधि वर्ष 2030 निर्धारित है। वैश्विक लक्ष्यों में गरीबी खत्म करना, पर्यावरण की रक्षा, नवाचार, टिकाऊ उपभोग, आर्थिक असमानता को कम करना और सभी के लिए शांति और न्याय सुनिश्चित करना शामिल है। जबकि ऊर्जा संसाधनों पर एकाधिकार के लिए हो रहे युद्ध इस बात का संकेत है कि सतत विकास और समावेशी समाज के निर्माण का संयुक्त राष्ट्र का स्वप्न कभी पूरा नहीं होगा। पश्चिम एशिया में जारी अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष न केवल रणनीतिक नुकसान है, बल्कि यह एक बड़ा पर्यावरणीय संकट है। इसके प्रतिकूल परिणाम दीर्घकालिक होंगे।

ब्रिटेन स्थित पर्यावरणीय शोध संस्था 'कन्फ्लिक्ट एंड एन्वायरनमेंट आब्जर्वेटरी' ने युद्ध के दौरान तीन सौ से अधिक जगहों को चिह्नित किया है, जहां पर्यावरण को गंभीर नुकसान हुआ है। ईरान की तेल रिफाइनरियों पर हुए हमलों से हजारों टन तेल समुद्र में पहुंच रहा है, जो समुद्री जीवों के पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर रहा है। विस्फोट से विषैला धुआं श्वास रोग को बढ़ावा दे रहा है। इतना ही नहीं ऊर्जा, खाद्य संकट, गरीबी और महंगाई विकासशील राष्ट्रों के लिए विशेष रूप से जटिल समस्या है। जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक स्तर पर खाद्य संकट की समस्या पहले से बढ़ रही है। खाद्य संकट पर एक वैश्विक रपट के अनुसार 53 देशों में 29 करोड़ पचास लाख से अधिक लोग गंभीर भुखमरी से प्रभावित हैं। भारत सहित विकासशील देशों में कृषि पर वर्षा और मौसम का गहरा असर देखने को मिलता है। यहां के किसानों के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। यह समस्या करीबन हर साल सामने आती है।

दूसरी ओर कहा जा रहा है कि गेहूं और धान जैसी प्रमुख फसलों की कुल उपज में छह से 25 फीसद और धान में तीन से 15 फीसद तक कमी आ सकती है। अनियमित मानसून, सूखा और बाढ़ कृषि उत्पादन को

अस्थिर कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण जल संकट भी बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रपट से पता चला है कि वर्तमान समय में हर दूसरा व्यक्ति जल संकट की समस्या से जूझ रहा है। विश्व बैंक ने अपने एक अध्ययन में अनुमान लगाया है कि स्वच्छ जल की कमी से प्रत्येक वर्ष 260

> **जलवायु परिवर्तन, गरीबी, असमानता, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दे किसी एक देश तक सीमित नहीं हैं, लेकिन अब यह स्पष्ट है कि कुछ देशों के बीच युद्ध के कारण पूरी दुनिया में मानवता खतरे में है। इसी के साथ पशु-पक्षियों का जीवन भी संकट में है। पर्यावरण हितैषी जीवों की चिंता इस समय किसी को नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध और मानवता के लिए बनाए गए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय नियम सिर्फ कमजोर देशों के लिए बने हैं। जिनेवा सम्मेलन ने पर्यावरणीय नुकसान को युद्ध अपराध की श्रेणी में रखा है। यह अचरज की बात है कि संयुक्त राष्ट्र और रेडक्रास जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं महाशक्तियों के आगे मौन हैं।**

अरब डालर का नुकसान होता है। स्थिति गंभीर है क्योंकि अब दुनिया को आगाह किया जा रहा है कि जल संकट से जूझ रहे देशों को वर्ष 2050 तक आर्थिक विकास में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जलवायु परिवर्तन से उपजा आर्थिक संकट बड़ी चुनौती है। एक शोध में कहा गया है की 2060 तक वैश्विक स्तर पर 3.75 ट्रिलियन डालर का नुकसान हो सकता है। दुनिया भर के देशों में जलवायु परिवर्तन और युद्ध के कारण सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट दर्ज किया गया है। भारत भी जलवायु परिवर्तन का खमियाजा भुगत रहा है।

वर्ष 2022 में जलवायु परिवर्तन के कारण भारत के सकल घरेलू उत्पाद में आठ फीसद का नुकसान हुआ। मानव जनित जलवायु परिवर्तन के कारण पिछले वर्ष वैश्विक आर्थिक उत्पादन में लगभग 6.3 फीसद की कमी दर्ज की गई है। एशिया-प्रशांत के देशों में 2050 तक कुल सकल घरेलू उत्पाद का 2.6 फीसद नुकसान होने की संभावनाएं जताई गई हैं। दक्षिण-पूर्व एशिया और दक्षिण अफ्रीका के देशों में क्रमशः 14.1 और 11.2 फीसद कुल सकल घरेलू उत्पाद का नुकसान हो सकता है। युद्ध और जलवायु परिवर्तन मानव जीवन के लिए घातक है। एक तथ्य यह भी है कि वैश्विक स्तर पर हर दो सेकंड में एक नवजात का जन्म समय से पहले हो रहा है, वहीं हर 40 सेकंड में इनमें से एक शिशु की मौत हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान मुताबिक वर्ष 2030-2050 के बीच जलवायु परिवर्तन से हर साल 2.5 लाख मौतें होंगी। वायु प्रदूषण से पूरी दुनिया में स्वास्थ्य संकट गहरा रहा है। युद्ध और जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया में गरीबी, आय की असमानता और खाद्यान्न संकट के साथ भुखमरी जैसी समस्याएं बढ़ेंगी। आय में लगातार बढ़ती असमानता और खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि की वजह से दुनिया में करीब तीन अरब आबादी पोषक आहार से दूर हो जाएंगी, जिससे कई देशों में कुपोषण जैसी समस्याएं बढ़ेंगी। इससे पूरी दुनिया के सामने एक गंभीर चुनौती पैदा होगी, जिससे निपटना ज्यादातर देशों के लिए आसान नहीं होगा।

जलवायु परिवर्तन, गरीबी, असमानता, स्वच्छ ऊर्जा, और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दे किसी एक देश तक सीमित नहीं हैं, लेकिन अब यह स्पष्ट है कि कुछ देशों के बीच युद्ध के कारण पूरी दुनिया में मानवता खतरे में है। इसी के साथ पशु-पक्षियों का जीवन भी संकट में है। पर्यावरण हितैषी मूक जीवों की चिंता इस समय किसी को नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध और मानवता के लिए बनाए गए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय नियम सिर्फ कमजोर देशों के लिए बने हैं। जिनेवा सम्मेलन ने पर्यावरणीय नुकसान को युद्ध अपराध की श्रेणी में रखा है। यह अचरज की बात है संयुक्त राष्ट्र और रेडक्रास जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं महाशक्तियों के आगे मौन हैं। युद्ध जैसी घातक विपदा खत्म होने के बाद भी पर्यावरणीय घाव लंबे समय तक बने रहते है। वैसे तो सतत विकास के लक्ष्य वैश्विक हैं, इसलिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग के बिना इन लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव नहीं है।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विकासशील देशों को वित्तीय सहायता, तकनीकी ज्ञान और नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करना जरूरी है। मगर विकसित देश इसमें रुचि नहीं लेते। युद्ध और जलवायु परिवर्तन की बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए मानव सभ्यता के अस्तित्व के लिए सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी देशों को एक मंच पर आना होगा। यह केवल पर्यावरणीय चिंता का विषय नहीं है, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के लिए भी इससे खतरा है। इस संकट से निपटने के लिए हर स्तर पर समन्वित प्रयास आवश्यक है।

भरोसे की शक्ति

अनंतपद्मनाभन

मानव मन एक अद्भुत पहेली है, जो एक क्षण में ब्रह्मांड की सीमाओं को लांघ सकता है और दूसरे ही पल एक छोटी-सी आशंका के पिंजरे में कैद हो सकता है। हम कल्पना करें कि हमने अभी-अभी कोई महत्त्वपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया है। चारों ओर प्रशंसा के शब्द गूंज रहे हैं और हमें सम्मान मिल रहा है। सफलता के उस शिखर पर मन में केवल संतोष होना चाहिए, लेकिन जैसे ही शोर थमता है और हम खुद के साथ होते हैं, तो हमारा मन शांत होने के बजाय एक अजीब-सी उथल-पुथल में घिर जाता है। हमारा मस्तिष्क अचानक एक जासूस की भूमिका निभाते हुए पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करने लगता है। वह बार-बार उसी एक पल पर अटक जाता है, जहां कुछ 'अधूरा' रह गया था- 'मैं उस समय क्यों हिचकिचाया? क्या मैं और बेहतर बोल सकता था?' भले ही हमारी सफलता सौ फीसद रही हो, लेकिन दिमाग न जाने क्यों उस एक फीसद की 'खामी' को ढूंढ़ निकालता है। यह स्थिति एक ऐसे मानसिक भ्रम की रचना करती है, जो हमारी पूरी सफलता की चमक को सोखने लगती है। दरअसल, बरसों से हमारे दिमाग को गलतियां ढूंढ़ने और जोखिमों की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है।

जब हम दिन भर समस्याओं को सुलझाने और खुद को त्रुटिहीन बनाने की दौड़ में लगे रहते हैं, तो वही तेज दिमाग घर आने के बाद भी अपनी गति को नियंत्रित करना भूल जाता है। यह नकारात्मक चिंतन का एक चक्र है, जो हमारे निजी रिश्तों और खुशियों में दखल देने लगता है। हमें लगता है कि हम 'सुधार' के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह मन को थकाने वाला एक व्यर्थ चक्र है। इतिहास गवाह है कि बड़े-बड़े विद्वानों का मन भी कभी-कभी उनका साथ छोड़ देता था। आधुनिक विज्ञान के आधार स्तंभ सर आइजैक न्यूटन अक्सर छोटी-छोटी आलोचनाओं पर हफ्तों तनाव में रहते थे। न्यूटन का मस्तिष्क ब्रह्मांड के रहस्यों को तो सुलझा लेता था, लेकिन स्वयं की शांति बनाए रखना उनके लिए चुनौती थी। वे अपनी खोजों को दुनिया के सामने रखने से इसलिए डरते थे कि कहीं कोई उनमें कोई कमी न निकाल दे। इस तरह के उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि बुद्धि एक तेज औजार की तरह है। अगर इसे सही नियंत्रण के साथ नहीं संभाला गया, तो यह स्वयं को ही चोट पहुंचा सकती है। इसी तरह, महान सिविल इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया की नजर इतनी पैनी थी कि वे चलती रेलगाड़ी में केवल कंपन महसूस करके पटरी की दरार भांप लेते थे। कार्य के प्रति यह सजगता अद्भुत थी, पर इसका अर्थ यह भी था कि उनका मन हमेशा एक 'सतर्क भाव' में रहता था।

आज सब एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हैं। हम अक्सर अपनी छोटी-छोटी खुशियों की अनदेखी कर देते हैं। पहले हमारी तुलना केवल करीबियों से होती थी, लेकिन आज हम अपनी तुलना पूरी दुनिया से कर रहे हैं। हम अपनी सफलताओं का जश्न मनाने के बजाय अपनी कमियों का शोक मनाने में अधिक समय बिताते हैं। आत्म-आलोचना तभी तक उपयोगी है, जब तक वह हमें आगे बढ़ने में मदद करे। जब यह आलोचना हमें मानसिक रूप से कमजोर बनाने लगे, तो इसे तुरंत रोकने का समय आ जाता है।

सच्ची आजादी इसी में है कि हम अपने मन को 'आलोचक' के बजाय एक 'दोस्त' की तरह इस्तेमाल करना सीखें। हमें अपनी समझ को रोकने की जरूरत नहीं है, बस इसे सही समय पर सही दिशा देना सीखना होगा। अगर हम किसी एक ही बात को बिना नतीजे के बार-बार सोच रहे हैं, तो यह विचार नहीं, बल्कि मन का भटकाव है। नकारात्मक विचारों को एक तटस्थ दर्शक की तरह देखना और खुद से पूछना चाहिए कि क्या उन आशंकाओं का वास्तव में कोई आधार है। जब मन जासूस बनने लगे, तो उसे याद दिलाने की जरूरत है कि हमें मिली सफलता में हमारी मेहनत का हाथ है।

यह समझना भी जरूरी है कि हमारी मानसिक ऊर्जा सीमित है। अगर हम इसे पुरानी बातों को कुरेदने में खर्च कर देंगे, तो भविष्य की नई संभावनाओं के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। हर नया दिन एक नया अवसर होता है, और उसे कल की गलतियों की छाया में व्यर्थ करना बुद्धिमानी नहीं है। अपनी क्षमताओं को स्वीकार करना और अपनी सीमाओं के साथ शांति बनाना ही व्यक्तित्व विकास का असली आधार है। अक्सर हम दूसरों की नजरों में खुद को साबित करने की कोशिश में अपनी असली पहचान खो देते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि दुनिया हमें वैसे ही देखेगी जैसे हम खुद को देखते हैं।

जीवन के इस सफर में स्वयं को माफ करना और अपनी उपलब्धियों का सम्मान करना सीखना चाहिए। प्रत्येक बाधा केवल एक नया सबक है, न कि हमारी योग्यता पर कोई स्थायी प्रश्नचिह्न। काम के बाद प्रकृति के करीब समय बिताना या शांत बैठना दिमाग को संदेश देता है कि अब विश्राम का समय है। खुद के प्रति उदार होना ही वह चाबी है जो हमें इस वैचारिक जेल से बाहर निकाल सकती है। हमने अपने जीवन में जो मुकाम हासिल किया है, उसे बनाने में सालों की मेहनत लगी है। उस मेहनत का मूल्य समझना चाहिए और अपनी उपलब्धियों को केवल धन-दौलत के तराजू में नहीं तौलना चाहिए।

हमारी बुद्धि एक वरदान है। इसे खुद को नुकसान पहुंचाने का हथियार नहीं बनने देना चाहिए। कमियां ढूंढ़ने वाले मन को यह सिखाना हमारी जिम्मेदारी है कि उसे कब शांत होना है। हमारी भावनाएं कोई 'गलतियां' नहीं हैं, वे हमारे जीवित होने का प्रमाण हैं। दुनिया की तमाम सफलता एक तरफ है, लेकिन हमारा आंतरिक सुकून ही हमारी सबसे असली पूंजी है। हमें व्यर्थ की चिंताओं को त्यागना चाहिए और अपनी मेहनत काबिलियत पर अडिग विश्वास बनाए रखना चाहिए।

दुनिया मेरे आगे

> **जब हम दिन भर समस्याओं को सुलझाने और खुद को त्रुटिहीन बनाने की दौड़ में लगे रहते हैं, तो वही तेज दिमाग घर आने के बाद भी अपनी गति को नियंत्रित करना भूल जाता है। यह नकारात्मक चिंतन का एक चक्र है, जो हमारे निजी रिश्तों और खुशियों में दखल देने लगता है।**

व्यवस्था पर सवाल

हाल ही में पश्चिम बंगाल के मालदा में सात न्यायिक अधिकारियों को उग्र भीड़ द्वारा कई घंटे तक बंधक बना कर रखा जाना कानून-व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाता है। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन नागरिकों का अधिकार है, लेकिन जब यह विरोध हिंसक रूप ले ले, तब यह केवल राजनीतिक असहमति का मामला नहीं रह जाता, बल्कि प्रशासनिक विफलता का संकेत बन जाता है। चुनावी दौर में राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज होना सामान्य है, पर कानून-व्यवस्था बनाए रखना किसी भी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। यह अपेक्षा की जाती है कि प्रशासन निष्पक्ष और प्रभावी तरीके से कार्य करे, ताकि आम नागरिकों का भरोसा कायम रहे। यदि प्रशासनिक निर्णय राजनीतिक समीकरणों से प्रभावित होते प्रतीत हों, तो यह लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को कमजोर कर सकता है। बंगाल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध राज्य रहा है। ऐसे राज्य में कानून-व्यवस्था तथा सामाजिक सौहार्द बनाए रखना और भी अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

– अरविंद रावल, झाबुआ

संवाद का रास्ता

'समाधान की राह' (संपादकीय, 4 अप्रैल) पढ़ा। यह वर्तमान वैश्विक स्थिति को सरल और यथार्थ रूप में प्रस्तुत करता है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, विशेषकर ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच टकराव, अब वैश्विक चिंता का विषय बन चुका है। इसका असर उन देशों पर भी पड़ रहा है, जो सीधे इस संघर्ष में शामिल नहीं हैं। होर्मुज जलमार्ग के बाधित होने से तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे भारत सहित कई देशों में महंगाई और ऊर्जा संकट बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। ऐसे समय में यह जरूरी है कि सभी पक्ष संवाद का रास्ता अपनाएं। भारत द्वारा शांति, संयम और कूटनीति पर जोर देना उसके संतुलित और जिम्मेदार दृष्टिकोण को दर्शाता है। युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। यदि विश्व समुदाय मिल कर संवाद और सहयोग को प्राथमिकता दे, तो स्थिरता और शांति सुनिश्चित की जा सकती है।

– आशुतोष पांडेय, जम्मू

महंगी होती शिक्षा

पिछले कुछ वर्षों में स्कूली किताबों की कीमतों में लगातार वृद्धि ने अभिभावकों की आर्थिक स्थिति पर दबाव डाला है। सरकारी संस्थानों की अपेक्षाकृत सस्ती पुस्तकों के मुकाबले निजी प्रकाशकों की किताबें कई गुना महंगी हैं, जिससे शिक्षा में समान अवसर के बजाय असमानता की स्थिति पैदा हो रही है। यदि पूरे देश में समान पाठ्यक्रम और मानकीकृत पुस्तक व्यवस्था लागू हो, तो न केवल किताबों की कीमतों पर नियंत्रण संभव होगा, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच भी समान हो सकेगी। वर्तमान में अलग-अलग बोर्ड, निजी स्कूलों की मनमानी और प्रकाशकों की प्रतिस्पर्धा ने शिक्षा को बाजार का रूप दे दिया है। जरूरत है कि सरकार इस दिशा में ठोस नीति बना कर सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करे, ताकि हर वर्ग का बच्चा बिना आर्थिक बोझ के समान अवसर प्राप्त कर सके। शिक्षा के अधिकार का लक्ष्य पूरा करने में यह बड़ा कदम होगा।

– तेज बहादुर मौर्य, गाजीपुर, उप्र

दंभ का दायरा

'संवाद के बजाय' (संपादकीय, 3 अप्रैल) पढ़ा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ऐसे आक्रामक और दंभ भरे बयान देते रहते हैं, जिनसे स्थिति और जटिल हो रही है। उनके बयानों की वजह से ईरान की प्रतिक्रिया और अधिक आक्रामक रूप से सामने आती है। वह अमेरिकी और इजराइल के ठिकानों पर लगातार मिसाइल हमले कर रहा है। लगता है कि ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। प्रतिष्ठा की इस लड़ाई में दुनिया भर के देश इस संघर्ष की चपेट में आ रहे हैं और जिस प्रकार से ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है, उससे उद्योग धंधों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है। पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। ऐसे में वैश्विक संस्थाओं का मूक बने रहना ठीक नहीं। यह निश्चित है कि संघर्ष का अंत बातचीत से ही निकलेगा। मगर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, यह भविष्य बताएगा।

– वेद प्रकाश, गुरुग्राम

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सिर्फ नौकरी छोड़ने की क्रिया नहीं, बल्कि विशिष्ट अधिकार : न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नौकरी छोड़ने या काम बंद करने की क्रिया नहीं है, बल्कि यह कर्मचारी का विशिष्ट अधिकार है जो निर्धारित वर्षों की सेवा पूरी होने के बाद प्राप्त होता है। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 2019 के दो अलग-अलग आदेशों को चुनौती देने वाली अपीलों पर अपना फैसला सुनाया। एक बैंक ने यह अपील दायर की थीं। उच्च न्यायालय ने एक बैंक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने का निर्देश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस में निर्दिष्ट तीन महीने की नोटिस अवधि पूरी होने के बाद या काम पर आना बंद करने की तारीख से, उसे स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त माना जाए। उच्चतम न्यायालय ने गौर किया कि कर्मचारी की नियुक्ति सितंबर 1983 में हुई थी और अप्रैल 2007 में उसे प्रबंधक के पद पर पदोन्नत किया गया।

लोकसभा की संचार और प्रौद्योगिकी समिति ने की सिफारिश

कृत्रिम मेधा का दुरूपयोग रोकने के लिए कानून लाए सरकार

पंकज रोहिला

कृत्रिम मेधा (एआइ) के गलत प्रयोग से नागरिकों को बचाने के लिए एक नए कानून की आवश्यकता है। इन कानून (विधेयक) की मदद से नागरिकों को वित्तीय धोखाधड़ी, डराने धमकाने अथवा डीपफेक आडियो वीडियो से बचाया जा सकेगा। इस कानून का विशेष लाभ इस जाल में फंस जाने वाले महिलाओं व बच्चों को हो सकेगा। केंद्र सरकार को इस विधेयक पर तत्काल काम करने की आवश्यकता है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थाई समिति ने सरकार से इस विधेयक को तैयार करने की सिफारिश की है।

संसदीय समिति का मानना है कि एआइ का प्रयोग नैतिक व जिम्मेदाराना तरीके से होना चाहिए। विश्व के अनेक देश इस दिशा में कई पहल कर चुके है और कानून तैयार कर चुके हैं। ये कानून बाध्यकारी है। इसी तर्ज पर भारत में भी ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने इस रपट को संसद में पेश किया है। समिति ने कहा कि इस विधेयक में ऐसा भी प्रावधान किया जाए, जिसमें कुछ सोशल प्लेटफार्म पर आने के लिए आयु सीमा को भी तय किया जाए ताकि नागरिकों को एआइ के प्रयोग से रोका जा सके।

एआइ दुपयोग रोकने के लिए मानव संधान की विशाल मानव संसाधन की क्षमता को विकसित करने की सिफारिश संसदीय समिति की ओर से की गई है। इसमें विशेषतौर पर कालेज में एआइ को लोकप्रिय बनाने और सभी विश्वविद्यालयों में फैलोशिप, अकादमी अनुसंधान (पीएचडी), डेटा केंद्र, एआइ लैब और शिक्षण प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति योजना की भी सिफारिश सरकार को की गई है। इन योजनाओं मदद से भविष्य में एआइ को अधिक प्रभावी तौर पर लागू करने में भी मदद मिलेगी। मंत्रालय के मुताबिक संबंधित धोखेबाज विभिन्न तरीकों से मौजूदा बुनियादी ढ़ांचे का फायदा उठाते हैं, जिसमें बैंकिंग (म्यूल अकाउंट, वर्चुअल अकाउंट, पेमेंट एग्रीग्रेटर, पेमेंट गेटवे, सीबीडीसी का दुपयोग, क्रिप्टो करंसी आदि), टेलीकाम (म्यूल सिम, सिमबाक्स, एसएमएस हैंडल, काल) आदि का प्रयोग धोखेबाजी के लिए किया जाता है।

अवैध प्रवेश और डिजिटल सुरक्षा के लिए प्रयोग करें एआइ : एक अप्रैल 2026 से शुरू हुई मिशन मोड परियोजना के तहत आप्रवासन, वीजा विदेशियों का पंजीकरण और ट्रैकिंग के लिए एआइ आधारित मशीनों का प्रयोग करने की योजना है। इस आंकड़े का प्रयोग कर भविष्य में प्रामणिकता और सुरक्षा बढ़ाने पर काम होगा। समिति के सामने यह भी आया है कि अभी तक दुनिया के किसी भी देश के साथ आंकड़े साझा करने पर कोई सहयोग नहीं मिला है। इसलिए समिति ने इस कानून को और सख्त और मजबूत बनाने पर जोर दिया है।

इन कानून (विधेयक) की मदद से नागरिकों को वित्तीय धोखाधड़ी, डराने धमकाने अथवा डीपफेक आडियो वीडियो से बचाया जा सकेगा। इस कानून का विशेष लाभ इस जाल में फंस जाने वाले महिलाओं व बच्चों को हो सकेगा।

मांग

गृह मंत्रालय जल्द लाएगा, एआइ आधारित शिकायत प्रणाली

रपट में गृह मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी है कि वह आइ4सी 1930 साइबर अपराध सहायता के लिए एआइ सहायता प्राप्त शिकायत पंजीकरण प्रणाली लागू की योजना पर काम कर रहा है। दावा किया है कि इस पहल से शिकायत दर्ज करने में लगने वाले समय को कम किया जा सकेगा और उपयोगकर्ताओं के अनुभव के आधार पर इसमें सुधार किया जा सकेगा। हालांकि मंत्रालय ने बताया कि वह साइबरदोस्त के नाम से एक सोशल मीडिया हैंडल भी चला रहा है, जो मामले दर्ज करने की प्रक्रिया को आसान बना रहा है। इसके अतिरिक्त एक 'एप्लीकेशन' भी भविष्य के लिए मंत्रालय की ओर से विकसित की जा रही है।

पश्चिम एशिया संकट

गिरने लगा स्वदेशी चिकित्सा उपकरण का उत्पादन

जनसत्ता ब्यूरो

पश्चिम एशिया संकट के चलते देश में स्वदेशी चिकित्सा उपकरण का उत्पादन गिरने लगा है। कई छोटी इकाइयां बंद होने के कगार पर पहुंच गई है, जबकि काफी जगहों पर कच्चे माल की आपूर्ति प्रभावित होने से उत्पादन सुस्त होता जा रहा है। देश में हर दिन लाखों मरीजों के इलाज के लिए एक बार इस्तेमाल होने वाले चिकित्सा दस्ताने, 'सिरिंज' और 'आइवी सेट', 'कैथटर' सहित अन्य की जरूरत होती है। इस जरूरत का करीब 80 फीसद आपूर्ति भारत में निर्मित चिकित्सा उपकरण से ही होता है।

मौजूदा समय में देश की छोटी व मध्यम स्तर की कंपनियां इनकी आपूर्ति कर रही हैं, लेकिन युद्ध के कारण मार्च में इन कंपनियों का लाभ 15-25 फीसद तक कम हो गया। बावजूद इसके शुरुआत में अधिकांश कंपनियां लागत वहन करती रही, लेकिन अब कई निर्माताओं ने दीर्घकालिक अनुबंधों पर पुनर्विचार कर पिछले एक सप्ताह में गैर-अनुबंधित व्यवसाय के लिए कीमतों में 15-20 फीसद तक की वृद्धि कर दी है। इसका असर आने वाले दिनों में मरीजों के इलाज पर दिखेगा। चिकित्सा उपकरण के उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में हर साल पांच से सात अरब 'सिरिंज' और सुइयां बनती है। भारत अभी भी 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की 'सिरिंज' और सुइयां आयात करता है, जबकि 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की 'सिरिंज' निर्यात भी करता है। भारत की जरूरत को पूरा करने के लिए स्थानीय स्तर पर हो रहे उत्पादन से 70-80 फीसद मांग पूरी होती है। वहीं आयात प्रीमियम ब्रांड या ज्यादा व्यापार लाभ वाले कार्पोरेट अस्पतालों की जरूरतों को पूरा करते हैं। इसमें 30 फीसद 'कैथेटर' और 90 फीसद 'सिरिंज/ आइवी सेट' घरेलू होते हैं।

देशभर के सरकारी सहित छोटे शहरों के निजी अस्पतालों में इन सामान को सस्ते दर पर उपलब्ध करवाने की मांग आती है। लेकिन मौजूदा समय में पालिमर की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी (60-70 फीद), भू-राजनीतिक उथल-पुथल के कारण ऊर्जा की लागत में बढ़ोतरी (औद्योगिक इस्तेमाल वाले डीजल की कीमत 20 फीसद और पीएनजी की कीमत 60 फीसद से ज्यादा बढ़ी), जीएसटी दरों में विसंगति (इनपुट पर 18 फीसद बनाम आउटपुट पर 5 फीसद), और माल ढुलाई की लागत में बढ़ोतरी ने सस्ते दर पर उपलब्ध होने वाली सुविधा को प्रभावित कर दिया है। इसके अलावा आपूर्ति को कच्चे माल की कीमतों में अचानक उछाल और अगली कीमत बढ़ोतरी की घोषणा से पहले खरीदारों द्वारा माल जमा करने की होड़ भी दिख रही है। साथ ही कुछ निर्माता नुकसान कम करने के लिए उत्पादन सीमित कर रहे हैं या युद्ध जल्द खत्म होने की उम्मीद में अनुबंध के तहत आपूर्ति में देरी कर रहे हैं।

सरकार से की है मदद की मांग : भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग संघ के संयोजक राजीव नाथ का कहना है कि इन चिकित्सा उपकरण के उत्पादन पर कुल खर्च कर 60 फीसद हिस्सा कच्चा माल और पैकेजिंग का होता है। ऊर्जा संकट के कारण पिछले पांच सप्ताह में पालिमर की कीमतों में अचानक तेजी आई है। इन समस्याओं से हो रही परेशानी के बारे में सरकार को बता दिया गया है। यदि सरकार आयात शुल्क माफ करने के साथ दूसरी मदद करती है तो बड़ी राहत मिलेगी।

दाम बढ़ने के बाद भी बंद होने के कगार पर पहुंच रही छोटी इकाइयां, उपलब्ध नहीं हो पा रहा कच्चा माल, हर दिन लाखों मरीजों को होती हैं इनकी जरूरत।

80 फीसद आपूर्ति स्वदेशी उत्पादन से, निर्यात का सामान होता है बड़े निजी अस्पतालों में इस्तेमाल।

बूचड़खाने को निगम क्षेत्र से बाहर करने पर हंगामा

सुनील दत्त पांडेय

तीर्थ नगरी हरिद्वार के नगर निगम क्षेत्र में अब कोई बूचड़खाना नहीं रहेगा। अब यह सब दुकानें नगर निगम क्षेत्र से बाहर सराय गांव में स्थानांतरित की जाएगी। हरिद्वार के नगर निगम की एक बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। तीर्थ नगरी हरिद्वार के उपनगर ज्वालापुर क्षेत्र में 1970 के लगभग से बूचड़खाने की दुकानें चल रही हैं। सोमवार को ऋषिकुल आडिटोरियम में हुई नगर निगम बोर्ड महत्वपूर्ण बैठक में महापौर किरण जैसल की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित किया गया कि तीर्थ नगरी हरिद्वार के नगर निगम क्षेत्र में बूचड़खाना नहीं रहेगा और बूचड़खाने की सभी दुकानें नगर निगम क्षेत्र से बाहर सराय गांव में स्थानांतरित की जाएगी।

जब नगर निगम की महत्त्वपूर्ण बैठक में यह प्रस्ताव के पेश किया गया तो एक समुदाय विशेष के कुछ पार्षदों ने इसका विरोध किया और बोर्ड की बैठक में बवाल काटा। इस प्रस्ताव का कांग्रेस के कुछ पार्षदों ने विरोध किया। परंतु नगर निगम में भाजपा पार्षदों के बहुमत के कारण यह प्रस्ताव पारित हो गया। हरिद्वार नगर निगम की महापौर किरण जैसल ने कहा कि ज्वालापुर उपनगर क्षेत्र की जनता की लगातार मांग आ रही थी कि इस उप नगरी से बूचड़खानों की दुकानों को तुरंत हटाया जाए, जिससे एक वर्ग विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है और बूचड़खाने से महामारी फैलने का भी लगातार खतरा बना रहता है।

हरिद्वार हर की पैड़ी की प्रबंधकारिणी संस्था श्री गंगा सभा के अध्यक्ष पंडित नितिन गौतम ने नगर निगम क्षेत्र से बूचड़खाने की दुकानों को हटाने के नगर निगम बोर्ड के फैसले का जोरदार स्वागत किया है उन्होंने कहा कि ज्वालापुर उपनगर में तीर्थ पुरोहितों के आवास बड़ी तादाद में हैं, जो सदियों से यहां पर रहते आ रहे हैं और इससे तीर्थ नगरी हरिद्वार की मर्यादा का मान बढ़ेगा और पुरोहितों और सनातनियों की भावनाओं को सम्मान मिलेगा। ज्वालापुर में पुरोहितों और सनातनियों के अलावा मुसलिम वर्ग भी काफी संख्या में रहते हैं। संभावित महामारी फैलने को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार नगर निगम की महापौर किरण जैसल ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जैसल ने बताया कि काफी लंबे समय से ज्वालापुर के तीर्थ पुरोहितों और सनातनियों की ओर से लगातार यह मांग उठाई जा रही थी कि ज्वालापुर उपनगरी से बूचड़खाने की सभी दुकानों को नगर निगम क्षेत्र से बाहर किया जाए। यह फैसला जनहित में लिया गया है।

हरिद्वार नगर निगम के नगर आयुक्त नंदन कुमार का कहना है कि ज्वालापुर क्षेत्र में कच्चे मीट यानी बूचड़खाने की दुकानों को बंद करके नगर निगम क्षेत्र से बाहर सराय गांव में स्थानांतरित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सराय में 56 दुकानों का निर्माण किया गया है, जहां पर बूचड़खानों की दुकानें स्थानांतरित की जानी है और जल्दी ही इसे अमल में लाया जाएगा। रेस्तरां और ढाबों में पका हुआ मास परोसने वालों पर भी आने वाले समय में विचार होगा। जीत पुरोहित संगठन के अध्यक्ष उज्ज्वल पंडित ने कहा कि ज्वालापुर से बूचड़खाने की दुकानों को सराय में स्थानांतरित करने का फैसला स्वागत योग्य है। अखिल भारतीय परशुराम अखाड़े की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि नगर निगम का ज्वालापुर में स्थित बूचड़खाने को सराय क्षेत्र में स्थानांतरित करना सनातनियों का सम्मान है। दूसरी ओर, ज्वालापुर में बूचड़खाने की दुकानों का संचालन करने वालों ने नगर निगम हरिद्वार के इस फैसले का जबरदस्त विरोध किया है। बूचड़खाने की दुकानदारों के संगठन के प्रमुख मोहम्मद मौमिन ने कहा कि शहर से 8-10 किलोमीटर की दूरी पर सराय गांव में बूचड़खाने की दुकानों को स्थानांतरित करने से उनका रोजगार छिन जाएगा।

उत्तराखंड

हरिद्वार के उपनगर ज्वालापुर क्षेत्र में 1970 के लगभग से बूचड़खाने की दुकानें चल रही हैं, लेकिन अब बूचड़खाने की सभी दुकानें नगर निगम क्षेत्र से बाहर सराय गांव में स्थानांतरित की जाएगी। कुछ पार्षदों ने बोर्ड की बैठक में किया विरोध, फिर भी पारित हुआ प्रस्ताव।

सीप्लेन

ऋषिकेश के पशुलोक बैराज पर गंगा नदी के ऊपर एक डी हैविलैंड कनाडा डीएचसी-6 ट्विन ओटर सीप्लेन का परीक्षण किया गया।

विशेष बच्चों को करिअर चुनना होगा आसान

जनसत्ता ब्यूरो

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अब करिअर चुनना पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान और व्यवस्थित होने जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने 'करिअर कार्ड' जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य ऐसे विद्यार्थियों को उनकी रुचि, क्षमता और संभावनाओं के अनुसार सही मार्गदर्शन देना है। ये करिअर कार्ड राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने यूनिसेफ के सहयोग से तैयार किए हैं और अब इन्हें विशेष बच्चों तक भी पहुंचाया गया है, जो समावेशी शिक्षा की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

इन करिअर कार्ड के माध्यम से विद्यार्थियों को करीब 500 अलग-अलग करिअर विकल्पों की विस्तृत जानकारी दी गई है, जिनमें कृषि, कला, मीडिया, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशिक्षण जैसे विविध क्षेत्र शामिल हैं। हर करिअर कार्ड में किसी एक पेशे से जुड़ी पूरी जानकारी सरल भाषा में दी गई है, जिसमें उस क्षेत्र के लिए जरूरी कौशल, पढ़ाई और कोर्स, प्रवेश प्रक्रिया, संभावित छात्रवृत्ति, शिक्षा ऋण, नौकरी के अवसर और शुरुआती वेतन से लेकर भविष्य में वृद्धि की संभावनाओं तक का विवरण शामिल है। इतना ही नहीं, प्रत्येक कार्ड में विशेषज्ञों की राय भी जोड़ी गई है, ताकि विद्यार्थी उस करिअर की वास्तविकता और संभावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकें। यह पहल केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे व्यावहारिक रूप से उपयोगी बनाने के लिए स्कूलों में करिअर मेले, चर्चाएं और काउंसलिंग सत्र आयोजित करने की भी योजना है।

संभावना

शिक्षक और परामर्शदाता विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी रुचियों और क्षमताओं को समझेंगे और उसी आधार पर उन्हें उपयुक्त करिअर विकल्प चुनने में मदद करेंगे। विद्यार्थियों को भी प्रोत्साहित किया गया है कि वे इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लें, अपनी पसंद और नापसंद खुलकर साझा करें और किसी भी प्रकार की उलझन होने पर शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करें।

बायो गैस व सीबीजी का हो सकता है वाहन व रसोई ईंधन में इस्तेमाल

सर्वेश कुमार

पश्चिम एशिया संकट के दौरान ऊर्जा स्रोतों को लेकर दूसरे देशों पर निर्भरता की वजह से पैदा हो रही स्थिति से निपटने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत कृषि अवशेष खासकर पराली और रसोई से निलकने वाले अवशेषों से तैयार, बायोगैस, संपीडित बायो गैस (सीबीजी) और प्रोड्यूशर गैस के तौर पर ऊर्जा स्रोतों के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इनका इस्तेमाल वाहनों और रसोई गैस के तौर पर किया जा सकता है। जानकारों का कहना है कि इसके लिए संसाधन मौजूद हैं, लेकिन नीतिगत बदलाव करने की जरूरत है। इससे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को अपनाने में सहूलियत बढ़ेंगी और पेट्रोलियम के आयात पर निर्भरता भी धीरे धीरे कम होगी।

फसलों के अवशेष यानी पराली से बायोगैस बनाए जा रहे हैं। इसे संपीडित करने के बाद सीबीजी तैयार किया जाता है, जिसे वाहनों वाहनों में सीएनजी या घरेलू पीएनजी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यूरोप के कुछ देशों में इसे अपनाया भी जा रहा है जिसकी भूमिका प्रदूषण नियंत्रण के साथ साथ हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिहाज से अहम हो सकती है।

ऊर्जा विशेषज्ञ प्रो देबोजित पालित के मुताबिक, गैस के साथ डीएमई सम्मिश्रण से पेट्रोलियम पर निर्भरता को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारी रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि देश में बायोगैस और कोयले से गैस के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। इसमें हाइड्रोजन होता है, जिसे अलग कर डाइ मिथाइल ईथर (डीएमई) तैयार कर, एलपीजी के विकल्प के तौर इस्तेमाल कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि जिस तरह पेट्रोल में इथेनाल सम्मिश्रण को सफलता मिली है, ठीक उसी तर्ज पर गैसों के लिए डीएमई सम्मिश्रण को और बढ़ावा देना चाहिए। इसकी मदद से 'प्रोडयूसर' गैस तैयार कर, रसोई के लिए ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है जिसकी क्षमता कमोबेश एलपीजी की तरह ही है।

इससे जहां ऊर्जा संकट से निटपने में सहूलियत होगी तो दूसरी तरफ किसानों के लिए कृषि अवशेषों, खासकर पराली के जलाने से प्रदूषण की समस्या पर भी काफी हद तक नियंत्रण में मदद मिल सकती है। लेकिन, इसके लिए आपूर्ति शृंखला को और बेहतर करना होगा ताकि मांग के मुताबिक आपूर्ति भी की जा सके। इससे ऊर्जा स्रोतों के विकल्प बढ़ने के साथ दूसरे देशों पर निर्भरता भी कम होगी और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा मिलने से भारत ऊर्जा विकल्पों के मामले में भी आत्मनिर्भर हो सकेगा।

कचरे से रसोई गैस बनाने के लिए आइआइटी ने तकनीक विकसित की : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बाम्बे ने कचरे से रसोई गैस बनाने के लिए एक तकनीक विकिसत की है। इसके जरिए सूखे पत्तों और कचरे से रसोई ईंधन बनाया जा सकता है। इस तकनीक के इस्तेमाल से एलपीजी की कम खपत के साथ साथ पर्यावरण को भी फायदा मिल रहा है। आइआइटी ने बायोमास गैसीफायर मशीन तैयार किया है, जिसमें सूखे पत्तों और जैविक कचरे से रसोई गैस बनाया जा सकता है। संस्थान के इसके लिए पेटेंट तकनीक विकसित की है।

देश

कृषि अवशेष पराली और रसोई से निलकने वाले अवशेषों से तैयार, बायोगैस, संपीडित बायो गैस (सीबीजी) और 'प्रोड्यूशर' गैस के तौर पर ऊर्जा स्रोतों के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इनका इस्तेमाल ईंधन के रूप में वाहनों और रसोई गैस के तौर पर किया जा सकता है।

जिस तरह पेट्रोल में इथेनाल सम्मिश्रण को सफलता मिली है, ठीक उसी तर्ज पर गैसों के लिए डीएमई सम्मिश्रण को और बढ़ावा देना चाहिए।

चिंतन

मणिपुर हिंसा के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई जरूरी

पूर्वोत्तर का संवेदनशील राज्य मणिपुर लगभग तीन वर्षों से जिस हिंसा की आग में सुलग रहा है, वह अब केवल कानून-व्यवस्था का मसला नहीं रह गया, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक ताने-बाने के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है। कुकी समुदाय और मैतेई समुदाय के बीच अविश्वास और वैमनस्य इस हद तक बढ़ चुका है कि सामान्य नागरिक, विशेषकर महिलाएं और बच्चे, हिंसा का सबसे आसान निशाना बनते जा रहे हैं। इन हालातों ने राज्य को अस्थिरता के भंवर में धकेल दिया है। विभिन्न जातियों के संगठन अपने हितों के लिए हिंसा को समर्थन दे रहे हैं। इसके कारण राज्य के सभी विकास कार्य ठप होकर रह गए हैं। हिंसा के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। चूंकि हाल ही में एक अमेरिकी और 6 यूक्रेनी नागरिकों का पकड़ा जाना इस बात का प्रमाण है कि ऐसी ताकतें भी राज्य में अस्थिरता फैला रही हैं। इसके साथ ही मादक पदार्थों का अवैध व्यापार भी हिंसा की आग में घी का काम करता है। मादक पदार्थों से मिलने वाली आय से ऐसी घटनाओं को बल मिलता है। मंगलवार को दो मासूम बच्चों को निशाना बनाकर हत्या करना दर्शाता है कि हिंसा फैलाने वाले नहीं चाहते कि राज्य में अमन-चैन रहे। बिष्णुपुर जिले के मोइरांग इलाके में घर के भीतर सो रहे मासूम बच्चों पर बम फेंककर उनकी हत्या कर देना किसी भी सभ्य समाज के लिए कलंक है। पांच साल के एक बच्चे और छह महीने की नवजात की मौत केवल एक घटना नहीं, बल्कि यह इस बात का भयावह संकेत है कि हिंसा अब अपनी सारी सीमाएं लांघ चुकी है। बच्चों पर हमला उस स्थान पर किया गया है, जहां 2023 में जातीय हिंसा भड़की थी। यह साफ है कि यह हिंसा साजिशन है, क्योंकि ये बच्चे किसी भी हिंसा में शामिल नहीं थे और न ही इनका किसी से कुछ लेना-देना था। घटना के बाद जिस प्रकार विरोध प्रदर्शन हिंसक हो उठे, वाहनों को जलाना, पुलिस चौकियों पर हमला करना और यहां तक कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कैंप पर हमला करना वह स्थिति की गंभीरता को और बढ़ाता है। जवाबी फायरिंग में जान गंवाने वाले लोग इस बात के गवाह हैं कि हिंसा की आग अब नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस निरंतर हिंसा ने राज्य के विकास को पूरी तरह ठप कर दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। हजारों लोग विस्थापित होकर राहत शिविरों में जीवन बिताने को मजबूर हैं। बच्चों की पढ़ाई छूट रही है और एक पूरी पीढ़ी असुरक्षा और भय के साये में पल रही है। यह स्थिति किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अस्वीकार्य है। सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं, बल्कि ठोस और निर्णायक रणनीति अपनाए। जिस तरह देश ने नक्सलवाद पर सख्ती और समन्वित प्रयासों के जरिए काफी हद तक नियंत्रण पाया, उसी तरह मणिपुर में भी व्यापक और बहुस्तरीय कार्रवाई की जरूरत है। हिंसा में शामिल लोगों की पहचान कर उन्हें कठोरतम सजा दी जानी चाहिए, चाहे वे किसी भी समुदाय या संगठन से जुड़े हों। साथ ही, केवल सैन्य या पुलिस कार्रवाई से समाधान संभव नहीं है। दोनों समुदायों के बीच संवाद बहाल करना, विश्वास निर्माण के उपाय करना और सामाजिक सौहार्द को पुनर्स्थापित करना उतना ही जरूरी है। स्थानीय नेतृत्व, नागरिक संगठनों और केंद्र सरकार को मिलकर एक साझा मंच तैयार करना होगा, जहां समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान खोजा जा सके।

प्रतिनिधित्व

ममता कुशवाहा

लोकतंत्र में आधी आबादी की हिस्सेदारी

> भारत, जिसे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, ने स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक भागीदारी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। जब बात संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी की आती है, तो यह प्रगति असमान और कई बार निराशाजनक रूप से धीमी दिखाई देती है। जबकि महिलाएं देश की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, फिर भी उनकी उपस्थिति राजनीतिक संस्थाओं में अत्यंत कम है। ऐसे में महिलाओं के लिए आरक्षण की लंबे समय से चली आ रही मांग केवल एक राजनीतिक सुधार नहीं, बल्कि एक नैतिक आवश्यकता बन जाती है। साल 2023 में महिला आरक्षण अधिनियम का पारित होना भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

किसी भी जीवंत लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व केवल संख्या का खेल नहीं होता, बल्कि यह न्याय, समानता और समाज की सामूहिक आवाज़ का प्रतिबिंब होता है। भारत, जिसे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, ने स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक भागीदारी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। जब बात संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी की आती है, तो यह प्रगति असमान और कई बार निराशाजनक रूप से धीमी दिखाई देती है। जबकि महिलाएं देश की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, फिर भी उनकी उपस्थिति राजनीतिक संस्थाओं में अत्यंत कम है। ऐसे में महिलाओं के लिए आरक्षण की लंबे समय से चली आ रही मांग केवल एक राजनीतिक सुधार नहीं, बल्कि एक नैतिक आवश्यकता बन जाती है।

साल 2023 में महिला आरक्षण अधिनियम का पारित होना भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस कानून के माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। यह कदम दशकों से चली आ रही उस संरचनात्मक असमानता को स्वीकार करता है, जिसने महिलाओं को राजनीति में उचित स्थान नहीं मिलने दिया। हालांकि, असली चुनौती इस कानून को पारित करने में नहीं, बल्कि इसे समय पर और प्रभावी ढंग से लागू करने में है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, इस आरक्षण को अगली जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन से जोड़ा गया है, जो 2026 के बाद ही संभव है। इस शर्त के कारण यह आशंका पैदा होती है कि इस कानून का लाभ कई वर्षों तक टल सकता है। यहीं पर सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व के लिए और कितने समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिए? भारत ने अपनी लोकतांत्रिक यात्रा की शुरुआत में ही दूरदर्शिता दिखाते हुए महिलाओं को पुरुषों के समान मतदान का अधिकार दिया था। यह विश्व के सामने एक आदर्श उदाहरण था। लेकिन लोकतंत्र केवल मतदान तक सीमित नहीं है; इसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है। शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान और उद्यमिता जैसे अनेक क्षेत्रों में महिलाओं ने अपनी क्षमता का लोहा मनवाया है, लेकिन राजनीति में उनकी कम भागीदारी यह दर्शाती है कि सामाजिक और संरचनात्मक बाधाएं अब भी मौजूद हैं। आंकड़े इस असमानता को और स्पष्ट करते हैं। वर्तमान में लोकसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 14 प्रतिशत के आसपास है, जबकि कई राज्य विधानसभाओं में यह प्रतिशत इससे भी कम है। यह कमी महिलाओं की योग्यता या इच्छा की कमी के कारण नहीं, बल्कि पितृसत्तात्मक सोच, संसाधनों की सीमित उपलब्धता और पुरुष-प्रधान राजनीतिक ढांचे के कारण है। ऐसे में आरक्षण एक आवश्यक सुधार के रूप में सामने आता है, जो इस असंतुलन को दूर करने का प्रयास करता है। हालांकि, इस आरक्षण को लागू करने की प्रक्रिया कई तकनीकी और संवैधानिक जटिलताओं में उलझी हुई है, जिनमें सबसे प्रमुख है परिसीमन का मुद्दा। परिसीमन का अर्थ है जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण, ताकि प्रतिनिधित्व संतुलित

रहे। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन इसे महिला आरक्षण से जोड़ना एक अनावश्यक बाधा बन गया है। चूंकि परिसीमन एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, जिसमें समय और राजनीतिक सहमति दोनों की आवश्यकता होती है, इसलिए इसके पूरा होने तक इंतजार करना महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण को टालने जैसा है। इस स्थिति से निकलने के लिए हमें प्रतिनिधित्व की अवधारणा को नए सिरे से समझने की आवश्यकता है। यदि आरक्षण को केवल भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्रों तक सीमित न रखा जाए, तो एक मिश्रित प्रणाली अपनाई जा सकती है, जिसमें प्रत्यक्ष चुनाव और अनुपातिक प्रतिनिधित्व दोनों का समावेश हो। इस व्यवस्था में अतिरिक्त सीटें बनाई जा सकती हैं और उन्हें राजनीतिक दलों को उनके वोट प्रतिशत के आधार पर आवंटित किया जा सकता है, इस शर्त के साथ कि इन सीटों पर महिलाएं ही उम्मीदवार हों।

यह तरीका न केवल परिसीमन की आवश्यकता को टाल सकता है, बल्कि अधिक न्यायसंगत प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित कर सकता है। महिलाओं के लिए अतिरिक्त सीटों का निर्माण एक व्यावहारिक और नवोन्मेषी विचार है। इससे संसद की कुल सीटों की संख्या बढ़ाकर महिलाओं को स्थान दिया जा सकता है, बिना वर्तमान सांसदों को हटाए।

इससे राजनीतिक विरोध की संभावना भी कम हो जाती है, क्योंकि मौजूदा सीटों पर कोई खतरा नहीं रहता। साथ ही, बढ़ती जनसंख्या और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार संसद के विस्तार की आवश्यकता भी पूरी होती है। नया संसद भवन, जिसे अधिक सदस्यों को समायोजित करने के लिए बनाया गया है, इस दिशा में एक उपयुक्त अवसर प्रदान करता है। इस व्यवस्था का एक और महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह जनता के जनादेश का सम्मान करता है। जब सीटों का आवंटन वोट प्रतिशत के आधार पर होगा, तो यह सुनिश्चित होगा कि प्रतिनिधित्व वास्तव में जनता की इच्छा को दर्शाता है। इससे राजनीतिक दलों को महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा मिलेगी और धीरे-धीरे राजनीतिक संस्कृति में समावेशिता बढ़ेगी। भारत जैसे विविध और विशाल देश में, जहां चुनौतियां भी जटिल हैं, वहां ऐसे नवाचारी उपाय आवश्यक हो जाते हैं। तकनीकी पहलुओं से आगे बढ़कर, हमें महिला आरक्षण के व्यापक प्रभाव को भी समझना चाहिए। जब अधिक महिलाएं संसद और विधानसभाओं में होंगी, तो नीति निर्माण में भी बदलाव आएगा। महिला आरक्षण को लागू करने में देरी अब किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराई जा सकती। प्रक्रिया संबंधी कारणों का हवाला देकर इसे टालना इस सुधार की भावना के साथ अन्याय होगा।

यह भी समझना जरूरी है कि आरक्षण अपने आप में अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि समानता की ओर बढ़ने का एक साधन है। जैसे-जैसे समाज में बदलाव आएगा और महिलाओं के सामने खड़ी बाधाएं कम होंगी, वैसे-वैसे इस तरह के उपायों की आवश्यकता भी कम हो सकती है। लेकिन वर्तमान समय में, जब असमानता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, तब आरक्षण एक अनिवार्य उपाय बन जाता है। संसद में महिलाओं के आरक्षण की यात्रा भारत के लोकतंत्र की परिपक्वता की परीक्षा भी है और उसके भविष्य को दिशा देने का अवसर भी। इसे तेजी से लागू करने के लिए केवल प्रशासनिक दक्षता ही नहीं, बल्कि दूरदर्शी सोच और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। यदि भारत इस दिशा में साहसिक कदम उठाता है, तो वह एक बार फिर विश्व के सामने एक आदर्श प्रस्तुत कर सकता है। अब सवाल यह नहीं है कि क्या हम यह कर सकते हैं, बल्कि यह है कि क्या हम इसे बिना और देर किए करने का साहस दिखाएंगे।

(लेखिका शिक्षिका हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

मंथन

विवेक शुक्ला

सेहत और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे स्ट्रा

हम सब अपने पसंदीदा पेय ठंडी कॉफी, ताज़ा नींबू पानी या कोक को पीने के लिए स्ट्रॉ का इस्तेमाल बिना एक पल सोचे कर लेते हैं। ये हमें सुविधाजनक, साफ़-सुथरा और सुरक्षित लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह छोटा-सा प्लास्टिक या पेपर स्ट्रॉ हमारी सेहत और पर्यावरण दोनों को चुपचाप नुकसान पहुंचा रहा है? इन छोटे से स्ट्रॉ का केवल कुछ मिनटों के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए इनसे होने वाले नुकसान की कोई चर्चा ही नहीं हो पाती है। दुनिया भर में हर दिन इस्तेमाल किए जाने वाले स्ट्रा समुद्र तट और महासागर की सफाई के दौरान सबसे आम कचरे में से एक होते हैं। अपने छोटे और हल्के आकार के कारण स्ट्रॉ की शायद ही कभी रीसाइक्लिंग होती हो। ये नदियों, समुद्रों और कचरा स्थलों (लैंडफिल) में पहुंच जाते हैं, जहां ये सैकड़ों साल तक बने रह सकते हैं। राजधानी के पर्यावरणविद और उद्यमी गुरसेव चावला कहते हैं, "भारत में हमारी बड़ी आबादी और बढ़ती कैफ़े कल्चर के कारण स्ट्रॉ का उपयोग तेज़ी से बढ़ रहा है, जिससे समस्या और गंभीर हो रही है।" कुछ साल पहले, दुनिया के कई हिस्सों में प्लास्टिक स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगना शुरू हुआ, जिसका लोगों ने स्वागत किया। इसके बाद पेपर और मकई से बने प्लास्टिक के स्ट्रॉ बाज़ार में आए और उन्हें "पर्यावरण के अनुकूल" विकल्प के रूप में देखा गया, लेकिन लोगों की धारणा और वास्तविकता के बीच अंतर है। प्रख्यात चिकित्सक और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉ. विनय अग्रवाल कहते हैं, "कई पेपर स्ट्रॉ में रसायन होते हैं, जिन्हें 'फॉरएवर केमिकल्स' भी कहा जाता है। ये आसानी से नष्ट नहीं होते और लंबे समय तक पर्यावरण और हमारे शरीर में बने रह सकते हैं। इन्हें नष्ट करने के लिए विशेष औद्योगिक परिस्थितियों की जरूरत होती है, जो भारत के अधिकांश शहरों में उपलब्ध नहीं हैं।" प्लास्टिक स्ट्रॉ सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली एकल-उपयोग (सिंगल-यूज़) वस्तुओं में से एक हैं। जब ये गर्मी, धूप या नींबू पानी जैसे अम्लीय पेय के संपर्क में आते हैं, तो ये माइक्रोप्लास्टिक नामक छोटे कण छोड़ जाते हैं। माइक्रोप्लास्टिक बहुत छोटे प्लास्टिक कण होते हैं, जो हमारे भोजन और पेय के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। प्लास्टिक में ऐसे रसायन भी होते हैं जो हमारे हार्मोन को प्रभावित कर सकते हैं और समय के साथ हमारी सेहत को तबाह करने लगते हैं। एक स्ट्रॉ भले ही नुकसानदेह न लगे, लेकिन इसके नियमित इस्तेमाल से इसका प्रभाव बढ़ता जाता है और यह एक गंभीर चिंता का कारण बन सकता है। यह दिखाता है कि केवल प्लास्टिक को किसी अन्य सामग्री से बदलना पर्याप्त नहीं है-विकल्प वास्तव में सुरक्षित और टिकाऊ होना चाहिए। यहीं पर गन्ने के बगैस से बने स्ट्रॉ एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आते हैं। बगैस का हिंदी अर्थ खोई है, जो गन्ना या ज्वार का रस निकालने के बाद बचा हुआ सूखा, रेशेदार अवशेष होता है। यह मुख्य रूप से चीनी मिलों में ईंधन, बिजली उत्पादन, कागज़, लुगदी और पर्यावरण-अनुकूल पैकेजिंग सामग्री (डिस्पोजेबल प्लेट, कप) बनाने के लिए एक नवीकरणीय स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत में आसानी से उपलब्ध है। आप इसे देश के बड़े चीनी उद्योग का उप-उत्पाद कह सकते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि बगास से बने स्ट्रॉ के कई फायदे हैं। जैसा कि ये पूरी तरह प्लास्टिक-मुक्त और गैर-विषैले होते हैं, इनमें हानिकारक रसायन नहीं होते और ये प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाते हैं और घर पर भी गल सकते हैं। ये कृषि अपशिष्ट से बनाए जाते हैं, जिससे बेकार चीज़ उपयोगी बन जाती है। ये रोज़मर्रा के उपयोग के लिए पर्याप्त मज़बूत होते हैं और पेय में कोई हानिकारक पदार्थ नहीं छोड़ते। सबसे अच्छी बात ये यह है कि बगास आधारित उत्पादों का उत्पादन पहले से ही बढ़ रहा है। पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों की बढ़ती मांग और सिंगल-यूज़ प्लास्टिक पर सख्त नियमों के कारण कई व्यवसाय अब ऐसे विकल्प अपनाने लगे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के उपभोक्ता अधिक जागरूक हो रहे हैं। वे उन ब्रांड्स को पसंद करते हैं जो वास्तव में पर्यावरण की परवाह करते हैं। व्यवसायों के लिए सुरक्षित विकल्प अपनाने से विश्वास और ब्रांड छवि दोनों में सुधार हो सकता है। सरकारी नीतियां भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। केवल प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना पर्याप्त नहीं है। यह स्पष्ट होना चाहिए कि "सुरक्षित" और "कम्पोस्टेबल" किसे कहा जाए। भ्रामक दावों पर नियंत्रण होना चाहिए और कृषि अपशिष्ट का उपयोग करने वाले उद्योगों को समर्थन मिलना चाहिए। अब समय है कि हम सुविधा से आगे बढ़कर जागरूक विकल्प चुनें-एक-एक घूंट के साथ।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

हम अपने भीतर अच्छा स्वास्थ्य कैसे लाएं?

संकलित

दर्शन

क्या आप सचमुच स्वस्थ हैं? स्वास्थ्य का अर्थ है, रोग-मुक्त शरीर, कंपन-मुक्त श्वास, तनाव-मुक्त मन, संकोच-मुक्त बुद्धि, आसक्ति-मुक्त स्मृति, समावेशी अहंकार और दुःख से मुक्त आत्मा। समग्र स्वास्थ्य के लिए व्यायाम, श्वास और ध्यान का अभ्यास आवश्यक है। श्वास ही जीवन है। हमारा जीवन हमारी श्वास में है। यदि कोई श्वास नहीं ले रहा, तो इसका अर्थ है- वहां जीवन नहीं है। ध्यान, प्राणायाम और योगिक अभ्यासों का मुख्य उद्देश्य प्राण या जीवन ऊर्जा को बढ़ाना है। दरअसल प्राण भावनाओं से भी अधिक सूक्ष्म होता है। जब हम सूक्ष्म स्तर पर ध्यान देते हैं, तो स्थूल स्वतः ठीक हो जाता है। जब आप श्वास को संभालते हैं, तो शरीर स्वस्थ हो जाता है। यदि आपकी श्वास गरम, हिलती-डुलती, असमान या असहज है, तो यह रोग का संकेत है। श्वास का पैटर्न शरीर में उपस्थित विषाक्त तत्त्वों और संभावित रोगों की सूचना देता है। हमारी श्वास में अनेक रहस्य छिपे हैं। क्योंकि मन की हर भावना के साथ श्वास की एक विशेष लय जुड़ी होती है। हर लय शरीर के किसी विशेष भाग को प्रभावित करती है। जरा ध्यान से देखें। जब हम प्रसन्न होते हैं तो विस्तार का अनुभव होता है और जब दुखी होते हैं तो संकुचन का। हम इन अनुभूतियों को तो महसूस करते हैं, पर उनके बीच संबंध को नहीं पहचानते। इसलिए जब आप सीधे मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हों, तो श्वास के माध्यम से मन को नियंत्रित किया जा सकता है।

जब मन हो अशांत, इष्टदेव का ध्यान करें

संकलित

प्रेरणा

शुकदेव राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, उस समय राजा ने पूछा कि आजकल लोग इतने बेचैन क्यों हैं? लोगों का मन अशांत क्यों है? शुकदेव ने राजा को एक कथा सुनाई कि एक दिन पृथ्वी ने भी भगवान से यही बात पूछी थी। पृथ्वी ने भगवान से कहा था कि ये लोग जो खुद मौत के खिलौने हैं। ये सभी मुझे यानी धरती, राज्य जीतना चाहते हैं। अभी तक मुझे यानी धरती को कोई भी मृत्यु के बाद अपने साथ ऊपर नहीं ले जा सका है। लोग ये बात क्यों नहीं समझते हैं? शुकदेव ने राजा से कहा कि पृथ्वी ने ये सभी बातें भगवान से इसलिए कहीं थीं, कि धरती पर जो धन-संपत्ति है, वही सारे झगड़ों की जड़ है। सभी चाहते हैं कि मेरे पास दूसरों से ज्यादा वैभव हो, सभी इसी में लगे हुए हैं। जिस दिन इस दुनिया से जाएंगे, सब कुछ यहीं रह जाएगा। परीक्षित ने शुकदेव की बातें ध्यान से सुनीं और कहा कि आजकल इतनी अशांति है तो शांति पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शुकदेव ने कहा कि जब भी हमारा मन अशांत हो, हमें भगवान के नामों का जप करना चाहिए, ध्यान, पूजा-पाठ करना चाहिए। अपने इष्टदेव के नामों का जप करने से नकारात्मकता दूर होती है, मन शांत होता है। मंत्र जप से शरीर में जो परिवर्तन होते हैं, उनसे मन शांत होता है।

अंतर्मन

आज की पाती

शादियों का स्वरूप बहुत बदल गया

भारत में शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं बल्कि एक बड़ा सामाजिक आयोजन भी माना जाता है। यहां शादी में परिवार, रिश्तेदार, दोस्त और पूरा समाज शामिल होता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में शादियों का स्वरूप बहुत बदल गया है। आजकल कई शादियां इतनी भव्य और महंगी हो गई हैं कि उनमें करोड़ों रुपए तक खर्च किए जाते हैं। बड़े-बड़े होटल, महंगे कपड़े, विदेशी सजावट, मशहूर कलाकारों के कार्यक्रम और कई दिनों तक चलने वाले समारोह अब आम बात हो गए हैं। ऐसी शादियों का सबसे बड़ा प्रभाव गरीब वर्ग पर पड़ता है। जब समाज में अमीर लोग बहुत महंगी शादियां करते हैं तो बाकी लोगों पर भी वैसी ही शादी करने का दबाव बनने लगता है। आर्थिक क्षमता से अधिक खर्च बोझ बन जाता है।

- सुरेश यादव, बिलासपुर

ट्रेंड

पाक के टुकड़े होंगे

पाकिस्तान एक बार खामियाजा भुगत चुका है। आज से 55 वर्ष पहले पाकिस्तान दो टुकड़ों में खण्ड-खण्ड हो गया था। अगर उन्होंने हमारे बंगाल की तरफ नजर उठाकर देखने की कोशिश की तो कितने टुकड़े होंगे, यह ऊपर वाला ही जानता है।

- राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री

तकनीकी उत्कृष्टता

भारत परमाणु शक्ति के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। कलपक्कम में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हमारी तकनीकी उत्कृष्टता और राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। अपने विशाल थोरियम भंडार का उपयोग करके, भारत ऊर्जा क्षेत्र में वर्चस्व और दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक निर्णायक कदम उठा रहा है।

-योगी आदित्यनाथ, सीएम, यूपी

स्वास्थ्य सेवा प्रणाली

नर्सें हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की आधारशिला हैं। उनका समर्पण, निस्वार्थ भाव और सहानुभूति ही परिवारों को अपने प्रियजनों को उनकी देखभाल में सौंपने का सुरक्षित एहसास दिलाती है।

- राहुल गांधी, सांसद, सपा

शिक्षामित्रों का हक

भाजपा सरकार ने 9 साल शिक्षामित्रों का हक मारा और अब बढ़ाया भी तो भी सपा सरकार से 22 हजार कम है। अब जब भाजपा सरकार का परमानेन्ट रिटायरमेंट होने वाला है तब ये शिक्षामित्रों के प्रति सहानुभूति दिखा रहे है।

- अखिलेश यादव, सांसद, सपा

करंट अफेयर

यूक्रेन ने युद्ध के बीच बचाए गए चमगादड़ों को छोड़ा

कड़ाके की ठंड के बाद यूक्रेन के लोग युद्ध प्रभावित इलाकों से बचाए गए चमगादड़ों को अब छोड़ रहे हैं। राजधानी कीव के बाहरी इलाके में स्थित एक नेचर पार्क में रात ढलते ही बच्चे स्वयंसेवकों के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं, जो कपड़े के थैलों को सावधानीपूर्वक खोलकर चमगादड़ों को अंधेरे आसमान में उड़ने के लिए छोड़ते हैं। प्रत्येक चमगादड़ के हवा में उड़ान भरने पर वहां मौजूद 1,000 से अधिक लोग तालियां बजाकर उसका स्वागत करते हैं। देश के पूर्वी हिस्सों के युद्धग्रस्त क्षेत्रों से बचाए गए सैकड़ों चमगादड़ों को शनिवार देर रात यूक्रेन के विभिन्न हिस्सों में आयोजित कार्यक्रमों के तहत छोड़ा गया, जो वसंत ऋतु के आगमन के साथ आयोजित किए गए थे।

'यूक्रेनियन बैट रिहैबिलिटेशन सेंटर' की स्वयंसेवक अनास्तासिया वोल्क ने कहा कि यह कार्यक्रम संगठन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जीव संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में शामिल हैं और उनका संरक्षण बेहद जरूरी है। यूक्रेन में चमगादड़ों की सभी 28 प्रजातियों को इनकी घटती संख्या के कारण संरक्षित जीवों की सूची में रखा गया है। कई लोगों के लिए यह कार्यक्रम कड़ी सर्दियों के बाद राहत का अवसर था। सर्दियों में शून्य से नीचे तापमान, रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले तथा बिजली कटौती जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा था।

ऑफ बीट

हमारी दृष्टि एक-आंख वाले पूर्वज कीड़े से हुई विकसित

काफी समय से माना जाता रहा है कि इंसानों और अन्य कशेरुकी जीवों की आंखें, अकशेरुकी जीवों की आंखों से बुनियादी रूप से अलग होती हैं, क्योंकि

उनकी कोशिकाओं की संरचना और जन्म से पहले उनके विकसित होने का तरीका अलग होता है। हमारे अध्ययन से संकेत मिलता है कि हमारी आंखों की जड़ें एक ऐसे कीड़े जैसे पूर्वज से जुड़ी हैं, जो करीब 60 करोड़ साल पहले समुद्रों में विचरण करता था। हमने पाया कि ज्यादातर जीवों में आंखें और रोशनी महसूस करने वाली कोशिकाएं दो जगहों पर होती हैं- एक चेहरे के दोनों तरफ (जोड़ी में) और दूसरी सिर के बीच में, मस्तिष्क के ऊपर। हमने जिन जीवों का अध्ययन किया, उनमें चेहरे के दोनों तरफ मौजूद ये कोशिकाएं शरीर की गतिविधियों को दिशा देने में मदद करती हैं, जबकि बीच में मौजूद कोशिकाएं दिन और रात के फर्क के साथ-साथ ऊपर-नीचे की पहचान करने में सहायक होती हैं। हमारे निष्कर्ष के मुताबिक, सभी कशेरुकी जीवों के कीड़े जैसे पूर्वज ने करीब 60 करोड़ साल पहले जब समुद्र की तलहटी में बिल बनाकर स्थिर जीवन जीना शुरू किया, तो उसने दिशा नियंत्रित करने वाली अपनी जोड़ी आंखें खो दीं। दरअसल, जब यह जीव एक जगह रहकर पानी से बीन-बीनकर भोजन हासिल करने लगा, तो उसे चलने-फिरने की जरूरत नहीं रही।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का चुनावी बिगुल, 'राहत, सुधार और भविष्य' पर जोर

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए अपना विस्तृत घोषणापत्र जारी किया है। पार्टी ने दावा किया है कि उसका घोषणापत्र राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने, रोजगार बढ़ाने और आम लोगों को सीधी राहत देने पर केंद्रित है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस 'राहत, सुधार और भविष्य' के एजेंडे के साथ चुनाव मैदान में उतरी है। उन्होंने कहा कि पार्टी का उद्देश्य पश्चिम बंगाल की जनता को एक मजबूत और भरोसेमंद विकल्प देना है। घोषणापत्र में महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता, किसानों को 15,000 रुपए वार्षिक मदद और प्रत्येक नागरिक को 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देने का वादा किया गया है। इसके अलावा, सभी सरकारी रिक्त पदों को जल्द भरने, हर जिले में एआई सेंटर स्थापित करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात कही गई है।

महिला सशक्तिकरण के तहत पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा, फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना और आर्थिक भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। वहीं किसानों के लिए मुफ्त बिजली और बेहतर खरीद प्रणाली सुनिश्चित करने का वादा किया गया है।कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को लेकर भी कई घोषणाएं की हैं। पार्टी का कहना है कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, पुलिस को स्वतंत्र बनाया जाएगा और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किए जाएंगे। इस दौरान कांग्रेस ने राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि 15 वर्षों के शासन के बावजूद राज्य में अपेक्षित विकास नहीं हो सका और भ्रष्टाचार बढ़ा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया गया कि उसके पास रोजगार और औद्योगिक विकास को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं है और वह केवल ध्रुवीकरण की राजनीति करती है।

पार्टी ने कहा कि एक समय कोलकाता औद्योगिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था, लेकिन वर्तमान में युवाओं को रोजगार के लिए अन्य राज्यों का रुख करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने औद्योगिक कॉरिडोर विकसित करने और राज्य में निवेश बढ़ाने का वादा किया है। कांग्रेस ने जनता के सामने तीन विकल्प रखते हुए कहा कि एक ओर वर्तमान शासन है, दूसरी ओर ध्रुवीकरण की राजनीति, जबकि तीसरा विकल्प कांग्रेस का 'वेलफेयर, जॉब्स और सिस्टम रिफॉर्म' मॉडल है। पार्टी ने दावा किया कि कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में दी गई गारंटियों को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। कांग्रेस का कहना है कि उसका घोषणापत्र पश्चिम बंगाल की मौजूदा चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करता है और अब अंतिम निर्णय राज्य की जनता को लेना है। लंबे समय के बाद पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी अकेले अपने दम पर तब चुनावी मैदान में है जब संगठन के तौर पर कांग्रेस जमीन से लगभग गायब है। यही वजह है कि राजनीतिक प्रेक्षक कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति को एक सियासी रस्म अदायगी से ज्यादा मानने को तैयार नहीं।

घोषणापत्र 10 साल का एलडीएफ शासन 'विफल अवसरों की कहानी': प्रियंका

केरलम विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि केरलम में पिछले दस वर्षों का एलडीएफ शासन 'विफल अवसरों की कहानी' रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य पर भारी कर्ज, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है, जबकि वायनाड की समस्याओं के समाधान में केंद्र और राज्य सरकार, दोनों का सहयोग नहीं मिल रहा है। कलपेट्टा में आयोजित एक जनसभा में वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि जनप्रतिनिधि के तौर पर वह जनता की समस्याओं को हल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी निराशा यह है कि जनहित के कार्यों में न तो राज्य की एलडीएफ सरकार सहयोग कर रही है और न ही केंद्र की मोदी सरकार। इसके कारण जनता की समस्याओं का समाधान करना अत्यंत कठिन हो गया है।

भाजपा-एलडीएफ के बीच अंदरूनी समझौते का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि जब विपक्षी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो उन पर केस दर्ज किए जाते हैं और छापेमारी होती है। लेकिन इतने भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद केरलम के मुख्यमंत्री के खिलाफ केंद्र सरकार की किसी भी एजेंसी ने कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने कहा कि सीपीएम के नेतृत्व वाली एलडीएफ सरकार जनता के बजाय कॉरपोरेट हितों के लिए काम कर रही है। कांग्रेस महासचिव ने स्थानीय समस्याओं को उठाते हुए राज्य सरकार की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए। जानवरों के बढ़ते हमलों पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और फसल बर्बाद होने के कारण किसान तबाह हो रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मानव-पशु संघर्ष को सुलझाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने

समस्या को सुलझाने के लिए यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के समाधानों को सामने रखा। उन्होंने बताया कि यूडीएफ चाहती है कि मुआवजे में 50 प्रतिशत की वृद्धि हो और फसल बीमा मिले। यूडीएफ की प्राथमिकताओं में दीर्घकालिक समाधान के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन करना भी है। जल्द चेतावनी देने वाली तकनीक के उपयोग के साथ सीएसआर फंडिंग बढ़ाने की कोशिश की भी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार होने पर यह कार्य तेजी से करने में मदद मिलेगी।

प्रियंका ने चूरलमाला-मुंडक्कई भूस्खलन त्रासदी का उल्लेख करते हुए आगे कहा कि प्रभावितों के पुनर्वास के लिए जमीन हासिल करने और कागजी कार्रवाई के दौरान उन्हें हर कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि अंततः जब सरकार टाउनशिप का उद्घाटन करने के लिए तैयार हुई, तो उन्हें अनुमति मिली और फिर कांग्रेस उद्घाटन कर पाई। स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली पर चिंता व्यक्त करते हुए कांग्रेस महासचिव कहा कि मेडिकल कॉलेज की कमी के कारण हाल ही में बाघ और हाथी के हमलों में घायल लोगों की रास्ते में ही मौत हो गई।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने केंद्र सरकार को कई बार पत्र लिखा है और जल्द ही एक क्रिटिकल केयर सेंटर शुरू करने का आश्वासन मिला है। सड़क और बुनियादी ढांचे को लेकर कांग्रेस महासचिव ने कहा कि उन्होंने पूझीथोड-पडिंजाराथारा सड़क का दौरा किया और स्थिति देखने के बाद राज्य सरकार को पत्र लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसी के साथ उन्होंने बताया कि हाल ही में चुराम बाईपास परियोजना को लेकर उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर काम में तेजी लाने की मांग की। भाषण के अंत में उन्होंने जनता से यूडीएफ उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताने का आह्वान किया और कई चुनावी वादे भी गिनाए। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस वायनाड में एक वर्ल्ड क्लास ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोलना चाहती है।

खरगे ने असम सीएम को बताया सबसे भ्रष्ट

असम चुनाव में 72-73 सीटें जीतने का दावा

खरगे ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा को भारत का सबसे भ्रष्ट नेता बताया। उन्होंने हिमंता पर लगे आरोपों पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से जवाब मांगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने हिमंता बिस्वा सरमा पर निशाना साधा और कहा कि भारत में कोई भी मुख्यमंत्री उनके जैसा अहंकारी नहीं है। सरमा केवल अपने परिवार के विकास के लिए काम कर रहे हैं। वे चाय, स्कूल, कोयला, अंडा, भूमि सुपारी, हर चीज में सिंडिकेट चला रहे हैं। 73 सीटें जीतने का दावा किया।

सीएम ममता का सवाल

पाकिस्तान की धमकी पर केंद्र सरकार चुप क्यों?

कोलकाता। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी ने पाकिस्तान की धमकी पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाया है। नदिया में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि पाक के रक्षा मंत्री के कोलकाता पर विवादित बयान के बाद प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? शांतिपुर में ममता ने जांच कराने की मांग की कि क्या इस घटना के पीछे कोई गहरी साजिश है। ममता ने केंद्र पर राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति पर अभूतपूर्व हमला बोला है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने विस्फोटक दावा किया था।

राहुल ने केरल की नर्सों से की बातचीत

स्वास्थ्यकर्मियों को आने वाली चुनौतियों पर की चर्चा

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को केरल की नर्सों के साथ बातचीत की। इस दौरान राहुल ने उन्हें स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का नींव बताया। उन्होंने कहा कि उनका समर्पण, निस्वार्थ भाव और सहानुभूति ही वह चीज है, जिसके कारण परिवार अपने प्रियजनों को उनकी देखभाल में छोड़कर सुरक्षित महसूस करते हैं। एक्स पर राहुल ने कहा कि नर्सें हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की नींव हैं।

एक्स पर जंग, विजयन पर बरसे रेड्डी

केरल सीएम के विकास पर उठाए सवाल

तिरुवनंतपुरम। केरल में विधानसभा चुनावों से पहले राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के बीच शुरू हुआ विकास का विवाद अब व्यक्तिगत हमलों तक पहुंच गया है। दोनों के बीच एक्स पर बहस चल रही है।

खबर संक्षेप

चाचा ने भतीजे-भावज की ली जान, 6अरेस्ट

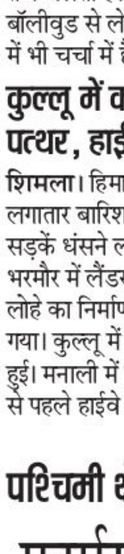

पटना। नगर के साहबेगपुर मोहल्ले में जमीन विवाद ने मंगलवार को भयावह रूप ले लिया। दो सगे भाइयों के परिवारों के बीच चल रहा विवाद अचानक हिंसक झड़प में बदल गया, जिसमें 2लोगों की जान चली गई और 2अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।छत से ईंट-पत्थर बरसाए गए और कुदाल से बेरहमी से वार किए गए। 6 को गिरफ्तार किया गया है।

महाठग सुकेश को कोर्ट से मिली जमानत

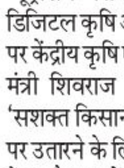

नई दिल्ली। महाठग सुकेश चंद्रशेखर को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है। सुकेश पर आरोप हैं कि उसने तमाम लोगों को करोड़ों का चूना लगाया है और ठगी के मामलों में उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। उसका नाम बॉलीवुड से लेकर सोशल सर्किल में भी चर्चा में है।

कुल्लू में कार पर गिरे पत्थर, हाईवे धंसा

शिमला। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से लैंडस्लाइड और सड़कें धंसने लगी है। चंबा के भरमौर में लैंडस्लाइड के चलते लोहे का निर्माणाधीन सिंयुर पुल टूट गया। कुल्लू में कार पर लैंडस्लाइड हुई। मनाली में लेफ्ट बैंक में अलेऊ से पहले हाईवे धंस गया।

होर्मुज संकट पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा

देश में पेट्रोल और एलपीजी की कोई कमी नहीं गैस कंपनियां कर रहीं सामान्य रूप से वितरण

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

मध्य पूर्व एशिया में जारी युद्ध की वजह से एलपीजी सप्लाई के मोर्चे पर बढ़ती चुनौती को देखते हुए देश में ईंधन और रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अहम और राहत भरा अपडेट जारी किया है। वर्तमान में आपूर्ति श्रृंखला को लेकर किसी भी प्रकार की अटकलों पर विराम लगाते हुए सरकार ने साफ किया है कि बाजार में एलपीजी और पेट्रोल की आपूर्ति पूरी तरह से सुचारू रूप से चल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव (मार्केटिंग और ऑयल रिफाइनरी) सुजाता शर्मा ने ईंधन वितरण की वर्तमान स्थिति के बारे में बताते हुए कहा कि एलपीजी वितरक कंपनियों में कहीं किसी 'ड्राईआउट' (यानी ईंधन पूरी तरह खत्म होने की) की कोई भी सूचना नहीं है। सरकार ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के लिए केवल डिजिटल माध्यमों का उपयोग करें और बिना जरूरत वितरकों (डिस्ट्रीब्यूटर्स) के पास न जाएं। सरकार ने यह भी कहा कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें।

गैस की कालाबाजारी, जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई तेज

देश में ईंधन और रसोई गैस की उपलब्धता सामान्य

कहीं से भी ईंधन खत्म होने की कोई सूचना नहीं

1 लाख से अधिक छापों में 52,000 से अधिक सिलेंडर जब्त

पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा

सरकारी तेल कंपनियों ने देश में एलपीजी की कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। मंत्रालय के अनुसार इस विशेष अभियान के तहत एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए देशभर में प्रवर्तन कार्रवाई के तहत 1 लाख से अधिक छापे मारे गए हैं और 52,000 से अधिक सिलेंडर जब्त किए गए हैं। 850 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं और 220 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सरकारी तेल कम्पनियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने औचक निरीक्षण के बाद 1,500 से अधिक कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। 118 एलपीजी वितरकों पर जुर्माना लगाया है और 41 वितरकों को निलंबित कर दिया है।

डिजिटल बुकिंग पर दिया जोर

सरकार ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के लिए केवल डिजिटल माध्यमों का उपयोग करें और बिना जरूरत वितरकों (डिस्ट्रीब्यूटर्स) के पास न जाएं।

आपूर्ति बंद होने की कोई घटना सामने नहीं आई

शर्मा के अनुसार मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति के कारण एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। एलपीजी वितरकों में आपूर्ति बंद होने की कोई घटना सामने नहीं आई है। उद्योग जगत में ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग में लगभग 97 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। माल की हेराफेरी को रोकने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) आधारित डिलीवरी में लगभग 90 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है।

प्रवासी मजदूरों के लिए 'वरदान' बना 5 किलोग्राम का सिलेंडर

पिछले 13 दिन के भीतर 5 किलोग्राम वाले एफटीएल सिलेंडर की बिक्री में अभूतपूर्व तेजी देखी गई है। इस छोटी अवधि में कुल 6.6 लाख से अधिक सिलेंडर बेचे जा चुके हैं। अकेले शनिवार ही 90,000 से अधिक सिलेंडरों की बिक्री हुई। कोई भी प्रवासी मजदूर या नागरिक बिना किसी पते के प्रमाण के, केवल एक वैध पहचान पत्र दिखाकर नजदीकी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर से यह सिलेंडर प्राप्त कर सकता है।

छापेमारी जारी रखी जाए

सरकार ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश छापेमारी जारी रखें ताकि कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों को गिरफ्तार किया जा सके। राज्यों को सलाह दी गई कि वे जमाखोरी, डायवर्जन और भ्रामक जानकारी के प्रसार पर कड़ी निगरानी रखें, ताकि अनावश्यक घबराहट की स्थिति उत्पन्न न हो। राज्यों से निगरानी और प्रवर्तन को और सुदृढ़ करने तथा दोषियों के विरुद्ध अनुकरणीय कार्रवाई करने का आग्रह किया गया। दरअसल, मध्यपूर्व एशिया में युद्ध की वजह से देश में एलपीजी के आयात पर असर पड़ रहा है। भारत जरूरत का 60फीसदी एलपीडी दुनियाभर के बाजारों से आयात करता है, जिसका 90फीसदी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरता है जो पिछले 39 दिनों से युद्ध क्षेत्र का हिस्सा बना हुआ है। युद्ध की वजह से भारतीय-ध्वज वाले 16 कार्गो जहाज होर्मुज के पश्चिम में फंसे हुए हैं, जिसमें एक बड़ा एलपीजी स्टॉक से लोड किया हुआ कार्गो जहाज शामिल है। कच्चे तेल से भरे 5 ऑयल टैंकर, एक एलपीजी टैंकर और 3 कंटेनर भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पश्चिम में फंसे हुए हैं।

चुनाव आयोग ने बंगाल का पहला डेटा दिया

45 फीसदी अवैध नाम हटाए गए, नादिया से सबसे ज्यादा

एजेंसी ⏭ कोलकाता

पश्चिम बंगाल में एक महीने पहले शुरू एसआईआर प्रक्रिया के बाद सोमवार को चुनाव आयोग ने अपनी अंतिम ड्राफ्ट लिस्ट जारी की। आयोग दके आंकड़ों के अनुसार बंगाल में मतदाता सूची से बाहर किए जाने के बाद विचाराधीन 60,06,675 नामों में से 27,16,393 यानी लगभग 45.22फीसदी नाम हटा दिए गए हैं।इसका मतलब यह है कि बंगाल में मतदाताओं की संख्या विशेष गहन पुनरीक्षण की शुरुआत में 7.66 करोड़ से घटकर 6.77 करोड़ हो गई है। सबसे अधिक पेंडिंग मामले अल्पसंख्यक बहुल मुर्शिदाबाद जिले (11 लाख) में थे, उसके बाद मालदा (8.28 लाख), दक्षिण 24 परगना (5.22 लाख) और उत्तर 24 परगना (5 लाख) का स्थान था। झाड़ग्राम (6682) और कलिम्पोंग (6790) में सबसे कम पेंडिंग केस थे।

सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में की गई समीक्षा समीक्षा

एसआईआर की शुरुआत 27 अक्टूबर 2025 को हुई थी और 28 फरवरी 2026 को अंतिम सूची प्रकाशित होने के बाद मतदाताओं की कुल संख्या घटकर 7.04 करोड़ रह गई थी। इसमें 60.06 लाख वो मतदाता शामिल थे जिनके नामों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारियों द्वारा समीक्षा के लिए चिह्नित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में 705 न्यायिक अधिकारियों द्वारा समीक्षा के बाद फैसला किया गया। सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों को फ्रीज करने से पहले समय बढ़ाने की याचिका स्वीकार नहीं की। ईसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी नेबताया कि फैसले के बाद जिन लोगों के नाम हटा दिए गए हैं वे न्यायाधिकरणों के समक्ष इसे चुनौती दे सकते हैं।

सबसे ज़्यादा मतदाता इन जिलों से हटे

आयोग के आंकड़ों के अनुसार प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा मतदाता मतुआ बहुल नादिया (77.86%) में हटाए गए हैं। दूसरा जिला हुगली (70.33%) है जहां मुसलमानों की संख्या अधिक है। इसके बाद पूर्वी बर्धमान (57.4%), उत्तर 24 परगना (55.08%) और पश्चिम बर्धमान (53.72%) से नाम हटाए गए हैं। अल्पसंख्यक बहुल मालदा (28.91%), मुर्शिदाबाद (41.33%), उत्तर दिनाजपुर (36.84%) और दक्षिण 24 परगना (42.70%) में दर्ज किए गए मामलों की संख्या सबसे अधिक थी, वहां प्रतिशत के हिसाब से कम मामले हटाए गए हैं। हालांकि संख्या के हिसाब से उनका हिस्सा अधिक है।

पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन में किसानों की आय बढ़ाने, फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रीशन पर 3 बड़े लक्ष्य

फार्मर आईडी से बदलेगा खाद, लोन और मदद का सिस्टमः शिवराज

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

जयपुर में मंगलवार को पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन से कृषि सुधारों के नए युग की शुरुआत हुई, जहां केंद्र–राज्य साझेदारी, किसानों की आय वृद्धि, फूड व न्यूट्रीशन सिक्योरिटी, फार्मर आईडी आधारित डिजिटल कृषि और लचीली योजनाओं के क्रियान्वयन पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ रोडमैप रखा। 'सशक्त किसान, समृद्ध भारत' के विजन को धरातल पर उतारने के लिए क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस की यह नई श्रंखला केंद्र और राज्यों के लिए साझा 'एक्शन-प्लेटफ़ॉर्म' के रूप में सामने आई हैं। जयपुर के होटल मैरियट में आयोजित पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक दिन की औपचारिक रबी–खरीफ मीटिंग की जगह अब अलग-अलग एग्रो-क्लाइमेटिक ज़ोन के लिए गंभीर, विषय-आधारित क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस

आयोजित की जा रही हैं। सम्मेलन की इस नई श्रृंखला की शुरुआत राजस्थान की धरती से होना उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण बताया, जहाँ राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गोवा के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक और प्रगतिशील किसान एक मंच पर जुटे, वहीं उद्घाटन सत्र में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। चौहान ने स्पष्ट किया कि यह केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि पूरे पश्चिमी क्षेत्र की कृषि पर संपूर्णता से मंथन का प्रयास है, जिसमें पूरे दिन प्रजेंटेशन, वीडियो और विषयवार चर्चा के बाद ठोस निष्कर्ष और 'टू-डू लिस्ट' के साथ राज्यों को आगे बढ़ने का रोडमैप तय किया जाएगा। उन्होंने भारतीय कृषि के लिए तीन मुख्य लक्ष्य रेखांकित किए- देश की खाद्य सुरक्षा, किसानों की आय वृद्धि और पोषण सुरक्षा। उन्होंने कहा कि गेहूं और चावल में भारत के भंडार इतने हैं कि रखने की जगह तक की चुनौती है, लेकिन दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता अभी हासिल करनी है ताकि खाद्य सुरक्षा पूरी तरह देश की अपनी उत्पादन क्षमता पर आधारित हो सके और आयात पर निर्भरता खत्म हो। केंद्रीय मंत्री चौहान ने सभी राज्यों से कहा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान अब एक साथ पूरे देश में न करके राज्यों की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार किया जाएगा और जो भी राज्य समय-सारिणी और कार्यक्रम भेजेंगे, वहां भारत सरकार वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों, अधिकारियों और प्रगतिशील किसानों की टीम भेजकर अभियान को गति देगी। राजस्थान के संदर्भ में उन्होंने आईसीएआर के वैज्ञानिकों की विशेष टीम भेजने की घोषणा की, जो राज्य के तय कार्यक्रम में खेत स्तर पर वैज्ञानिक सलाह और नवाचारों का विस्तार करेगी।

सबरीमाला पर सरकार की सुप्रीम कोर्ट में दलील

जज बोलीं-महिलाएं अछूत नहीं हो सकतीं...

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री मामले पर सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने माहवारी को लेकर अहम टिप्पणी की है। पितृसत्तामक व्यवस्था का सवाल उठा तो केंद्र ने इसकी परभाषा पर ही सवाल उठा दिया। केंद्र ने कहा कि भारत में महिलाओं को बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है और पितृसत्ता की जो बात कही जाती है वह गलत है। 9 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सबरीमाला मंदिर में हर उम्र की महिला के प्रवेश की वकालत करने वाले लोग पितृसत्ता का तर्क क्यों देते हैं?

लोग पितृसत्ता का तर्क क्यों देते हैं? एसजी मेहता

ऐसा नहीं होना चाहिए

उन्होंने कहा कि भारत पितृसत्तातमक या लिंग के आधार पर भेदभाव वाला समाज नहीं है, जैसा कि पश्चिमी देश समझते हैं। छूआछूत वाली टिप्पणी पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा, एक महिला के तौर पर मैं यह कह सकती हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर महीने के तीन दिन महिला को छूआछूत माना जाए और चौथे दिन जब माहवारी खत्म हो जाए तो वह छूआछूत नहीं है। ये कड़वी सच्चाई है।

ऐसी अवधाणाएं पेश करने के काबिल नहीं: एसी मेहता

मेहता ने कहा कि भारत में महिलाओं को न सिर्फ बराबरी का अधिकार दिया जाता है, बल्कि उन्हें ऊंचा दर्जा भी मिला है। कई फैसलों में पितृसत्तातमक समाज की अवधारणा की बात कही गई है। एक तरह का जेंडर स्टीरियोटाइप उनमें दिखता है, लेकिन भारत का मामला अलग है। हमें ऐसी अवधारणाओं को पेश नहीं करना चाहिए।

दैनिक जागरण

हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं

हठ छोड़ें अमेरिका-ईरान

ईरान पर होर्मुज समुद्री मार्ग खोलने के लिए दबाव बढ़ाने के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उसे दी गई अपनी नई धमकी में जिस तरह यह कहा कि रात भर में पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, जिसे फिर कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा, वह आज के युग की भाषा नहीं है। यह बर्बर कबीलाई युग की भाषा है, जब युद्ध के कोई नियम नहीं होते थे और हमलावर बर्बरता की पराकाष्ठा दिखाने में संकोच नहीं करते थे। 21वीं सदी में आदिम युग वाली भाषा सभ्य समाज के लिए चिंता का विषय है। क्या यह विचित्र नहीं कि ट्रंप एक ओर यह कह रहे हैं कि अमेरिका के हमलों में ईरान रात भर में मटियामेट हो सकता है और दूसरी ओर वे यह भी चाह रहे हैं कि ईरान के महान लोगों पर ईश्वर की कृपा हो? समझना कठिन है कि उनका इरादा क्या है? यदि वे समझौते की राह खोज रहे हैं तो उन्हें उसी हिसाब से सलीके से अपनी बात रखनी चाहिए। बीते कुछ दिनों से वे जैसी भाषा बोल रहे हैं, उससे तो बात बनने के बजाय बिगड़ती ही दिख रही है। इसमें संदेह नहीं कि अमेरिका ने इजरायल के साथ ईरान पर हमला बोलकर पश्चिम एशिया में एक गंभीर संकट खड़ा कर दिया, लेकिन इस संकट ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है तो ईरान के कारण भी।

ईरान ने समुद्री मार्ग होर्मुज को बाधित कर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। वह इस समुद्री मार्ग को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। यह वह जल मार्ग है, जिससे ऊर्जा के पांचवें हिस्से का नौवहन होता है। इस मार्ग के बाधित होने से पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट लगातार गहरा रहा है और इसके चलते तमाम देशों की सरकारों के साथ-साथ आम लोगों के समक्ष परेशानी खड़ी हो गई है। कहीं-कहीं तो उद्योग-धंधे बंद होने की नौबत आ गई है। गहराते ऊर्जा संकट के चलते महंगाई भी बढ़ रही है। एक तरह से ईरान ने होर्मुज पर कब्जा कर दुनिया को बंधक बनाने का काम किया है। उसकी लड़ाई तो अमेरिका और इजरायल से है। आखिर वह बाकी दुनिया को क्यों तंग कर रहा है? स्पष्ट है कि जहां अमेरिका को अपना रवैया बदलने की जरूरत है, वहीं ईरान को भी। ईरान का यह रवैया ठीक नहीं कि उसे अपनी बर्बादी की कोई परवाह नहीं। यदि वह युद्ध थामने के लिए लचीलेपन का परिचय देने के स्थान पर हठ दिखाता रहेगा तो फिर अपनी तबाही को ही निमंत्रण देगा। उसके जो समर्थक उसे अपने रवैये पर अड़े रहने के लिए उकसा रहे हैं, वे केवल अमेरिका और इजरायल को ही पस्त-परेशान होते हुए नहीं देखना चाहते। वे ईरान के भी शुभचिंतक नहीं कहे जा सकते, क्योंकि यह युद्ध जितना लंबा खिंचेगा, उसकी बदहाली उतनी ही बढ़ेगी। अच्छा होगा कि मानवता के लिए संकट बनते जा रहे इस युद्ध में बीच-बचाव करने के लिए भारत अपनी सक्रियता बढ़ाए।

कृषि ऊर्जा

हरियाणा में 'एग्री डिस्काम' के गठन का निर्णय कृषि क्षेत्र को अलग और केंद्रित ऊर्जा व्यवस्था देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। मिश्रित ढांचे में संचालित बिजली आपूर्ति को अलग करते हुए किसानों के लिए विशेष तंत्र तैयार करना केवल सुविधा नहीं, बल्कि संरचनात्मक सुधार का संकेत है। कृषि उपभोक्ताओं को सस्ती और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के साथ सब्सिडी के बढ़ते बोझ को संतुलित करना इस व्यवस्था का उद्देश्य है। वर्तमान में न्यूनतम दर पर दी जा रही बिजली और उस पर हजारों करोड़ की सब्सिडी ऐसी स्थिति की ओर इशारा करते हैं जहां दक्षता और पारदर्शिता की जरूरत स्वाभाविक हो जाती है। नई कंपनी के माध्यम से कृषि फीडरों, कनेक्शनों और आपूर्ति प्रणाली को एक ही ढांचे में लाना संचालन को सरल बना सकता है। इससे ट्यूबवेल कनेक्शन, ट्रांसफार्मर परिवर्तन और शिकायत निवारण जैसे कार्यों में तेजी आने की संभावना है। साथ ही, सौर ऊर्जा और अन्य वैकल्पिक स्रोतों को इस ढांचे से जोड़ने की योजना कृषि क्षेत्र को अधिक टिकाऊ ऊर्जा माडल की ओर ले जाने का प्रयास है। यह न केवल लागत संतुलन में मदद करेगा, बल्कि दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकता है। आज कृषि में लागत को कम करना बड़ी चुनौती है। लागत अधिक होने से किसानों को फसल पर अधिक लाभ नहीं मिलता। अगर हरियाणा सरकार के इस फैसले से इसमें कुछ कमी आती है तो यह कृषि हित में होगा और दूसरे राज्यों के लिए भी उदाहरण पेश करेगा।

नई कंपनी के माध्यम से कृषि फीडरों, कनेक्शनों और आपूर्ति प्रणाली को एक ढांचे में लाना संचालन को सरल बना सकता है

सत्ता की हैटट्रिक या विपक्ष की वापसी

राज कुमार सिंह

असम और केरलम में हार-जीत सिर्फ भावी सत्ता का ही फैसला नहीं, बल्कि दलों की दशा-दिशा को भी प्रभावित करेगी

अवधेश राजपूत

इस समय तमाम निगाहें पश्चिम बंगाल चुनाव पर टिकी हैं, जहां 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा, लेकिन उससे पहले नौ अप्रैल को होने वाले असम और केरलम के चुनाव में भी राजनीतिक दलों का बहुत कुछ दांव पर है। इन राज्यों में हार-जीत सिर्फ भावी सत्ता का ही फैसला नहीं करेगी, राजनीतिक दलों की दशा-दिशा को भी प्रभावित करेगी। दशकों तक कांग्रेस के दबदबे वाले असम के रास्ते ही भाजपा पूर्वोत्तर राज्यों की सत्ता पर काबिज हो पाई। जनसांख्यिकीय परिवर्तन से मूल पहचान के संकट को लेकर अर्से तक छात्र आंदोलन और हिंसा का शिकार रहे असम में 2016 में सरकार बनना भाजपा के लिए सुखद आश्चर्य ही था। वह आरएसएस और भाजपा की दशकों की मेहनत का भी प्रतिफल था, लेकिन कुछ श्रेय कांग्रेस की आत्मघाती राजनीति को भी दिया जाना चाहिए।

असम के बड़े कांग्रेस नेता रहे हिमंत बिस्वा सरमा के 2015 में भाजपा में शामिल होने के बाद ही पूर्वोत्तर राज्यों में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदले। बेशक असम का मुख्यमंत्री बनने के लिए हिमंत को पूर्वोत्तर में भाजपा के विस्तार की कठिन कसौटियों पर खरा उतरते हुए पांच साल इंतजार करना पड़ा, लेकिन आज वह उस क्षेत्र में पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। वे जिस तरह हिंदुत्व की आक्रामक राजनीति करते हैं, वह भाजपा को रास आ रही है। कांग्रेस में उनकी सेंधमारी जारी है और लगभग दो दर्जन पूर्व कांग्रेसियों को इस विधानसभा चुनाव में भाजपा से टिकट दिलवाने में भी वे सफल रहे हैं। हिमंत शैली की राजनीति असम समेत पूरे पूर्वोत्तर में ही भाजपा के लिए अभी तक फायदेमंद रही है। 126 सदस्यीय असम विधानसभा के चुनाव में हिंदू मतों का ध्रुवीकरण भाजपा की जीत का आजमाया हुआ नुस्खा है, जबकि कांग्रेस की आस अल्पसंख्यक मतों की गोलबंदी पर टिकी है, लेकिन वहां मूल और बाहरी का जटिल समीकरण भी है।

2016 के चुनाव में 64 प्रतिशत असमी हिंदुओं ने जहां राजग के पक्ष में मतदान किया, वहीं 24 प्रतिशत ने कांग्रेसनीत महाजोत को चुना। बंगाली हिंदुओं में 63 प्रतिशत ने राजग और 31 प्रतिशत ने महाजोत को वोट दिया। असमी मुसलमानों में 78 प्रतिशत ने महाजोत के पक्ष में मतदान किया, जबकि राजग को उनके सात प्रतिशत वोट ही मिले। बंगाली मुस्लिमों में से 76 प्रतिशत ने महाजोत को वोट दिया, जबकि राजग को मात्र छह प्रतिशत ने। 2021 के विधानसभा चुनाव में मतदान का रुझान बदला। राजग 67 प्रतिशत असमी हिंदुओं की पसंद बना, जबकि महाजोत को उनके 17 प्रतिशत वोट ही मिले। बंगाली हिंदुओं में भी राजग का मत प्रतिशत बढ़ कर 74 हो गया, जबकि महाजोत 23 प्रतिशत पर अटक गया, पर इसके बावजूद राजग 11 सीटें कम जीत पाया। महाजोत को 10 सीटों का फायदा हुआ। असम का सत्ता संग्राम इस बार भी इन दोनों गठबंधनों के बीच माना जा रहा है, लेकिन इस बार मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआइयूडीएफ महाजोत का हिस्सा नहीं है। पिछली बार महाजोत में 20 सीटों पर लड़कर 16 सीटें जीतने वाली एआइयूडीएफ इस बार अकेले लड़ रही है और उसे असदुद्दीन ओवैसी की एआइएमआइएम का समर्थन हासिल है। अजमल और ओवैसी की जुगलबंदी कांग्रेस के अल्पसंख्यक जनाधार में सेंध लगा सकती है। सीट बंटवारे पर कांग्रेस से तकरार के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा भी असम में पहली बार 16 सीटों पर किस्मत आजमा रहा है। उसकी उम्मीदें ऊपरी असम में केंद्रित चाय बागान कर्मियों के समुदाय पर टिकी हैं, जिन्हें आदिवासी माना जाता है। अन्य राज्यों से आकर बसे इन आदिवासियों की जनसंख्या, 2011 की जनगणना के मुताबिक 17 प्रतिशत के आसपास है। कई सीटों पर असर डाल सकने वाले ये आदिवासी मूलतः कांग्रेस समर्थक रहे हैं, लेकिन भाजपा भी इनमें सेंध लगाती रही है। एआइयूडीएफ और झामुमो की चुनाव मैदान में मौजूदगी कांग्रेस गठबंधन की मुश्किलें बढ़ाएगी, लेकिन विपक्षी मतों में इस बिखराव के बावजूद असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट सरीखे सहयोगियों के साथ मिल कर चुनाव जिताऊ बिसात बिछाने से भाजपा चूक गई तो पंथनिरपेक्षता के नाम पर वे अंततः कांग्रेस से ही हाथ मिलाएंगे।

केरलम की राजनीति वाम मोर्चा एलडीएफ और कांग्रेसनीत यूडीएफ के बीच बंटी रही है। केरलम ने हर चुनाव में सरकार बदल देने की अपनी परंपरा पिछली बार तोड़ दी। बंगाल और त्रिपुरा की सत्ता से बेदखल हो चुके वाम दलों के लिए 2021 का केरलम चुनाव परिणाम किसी संजीवनी से कम नहीं था। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में पासा पलट गया। 20 लोकसभा सीटों में से 18 यूडीएफ जीत गया। एलडीएफ के हिस्से एक ही सीट आई। भाजपा भी एक सीट जीतने में सफल रही। भाजपा तिरुअनंतपुरम में अपना मेयर बनाने में भी सफल रही, जहां से शशि थरूर सांसद हैं।

केरलम में राजग सत्ता का दावेदार भले ही न हो, पर अब वह राज्य की चुनावी राजनीति का तीसरा खिलाड़ी बन चुका है। उत्तरी केरलम क्षेत्र में यूडीएफ की बढ़त रहती है, पर सत्ता का फैसला आम तौर पर मध्य और दक्षिण क्षेत्र करते हैं। 26 प्रतिशत मुस्लिम और 18 प्रतिशत ईसाई मतदाताओं के मुकाबले केरलम में हिंदू वोटरों का प्रतिशत 56 है, पर भाजपा यहां उनकी पहली पसंद अभी तक नहीं बन पाई है। राजग को मिलने वाला मत प्रतिशत एलडीएफ और यूडीएफ के बीच सत्ता की जंग में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। एलडीएफ जीते या यूडीएफ, राष्ट्रीय राजनीति के नजरिये से सत्ता विपक्षी गठबंधन के ही पास रहेगी, लेकिन दलगत राजनीति की दृष्टि से यह चुनाव वामपंथ और कांग्रेस, दोनों के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। विजयन जनादेश पाने में सफल रहे तो एलडीएफ की सत्ता में हैटट्रिक होगी, वरना सत्ता राजनीति के मानचित्र से वामपंथ गायब हो जाएगा। अंतर्कलह से ग्रस्त कांग्रेस भी लगातार तीसरी चुनावी हार के बाद केरलम में भाजपा के विस्तार को शायद ही रोक पाए।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)
response@jagran.com

पश्चिम एशिया संकट : फंस गए रे ट्रंप

राजीव सचान

पश्चिम एशिया संकट का समाधान चाहे जब और जैसे हो, फिलहाल ट्रंप निरुपाय और कुंठित दिख रहे हैं

व्हाइट हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन में ट्रंप। प्रेट्र

वर्ष 2010 की चर्चित फिल्म 'फंस गए रे ओबामा' एक कामेडी फिल्म थी। यह एक त्रासदी से उपजी थी। इसकी कहानी राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में अमेरिका में उभरे आर्थिक संकट से ग्रस्त भारत आए एक एनआरआइ से संबंधित थी। जैसे अमेरिका में आई मंदी ने उस वक्त सारे विश्व को परेशान किया, वैसे ही अमेरिका की ओर से इजरायल के साथ मिलकर ईरान पर किए गए हमले से आज सारा विश्व त्रस्त है। इस युद्ध को जारी हुए एक महीने से अधिक का समय बीत गया है और कहना कठिन है कि यह कब समाप्त होगा? यदि अमेरिका इजरायल का साथ नहीं देता तो इस युद्ध की नौबत ही नहीं आती, लेकिन ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने अहंकार के चलते ईरान को वेनेजुएला समझ लिया और बिना यह विचारे उस पर चढ़ाई कर दी कि उसने कितनी एवं कैसी सैन्य क्षमता हासिल कर ली है? वे इसे भी भांप नहीं सके कि ईरान पड़ोसी देशों में हमले करके और होर्मुज समुद्री मार्ग अवरुद्ध कर उनके पसीने छुड़ा देगा। वह फिलहाल सचमुच ऐसा करने में समर्थ है और ट्रंप को सूझ नहीं रहा है कि वे इस युद्ध से कैसे निकलें? एक ओर वे सबसे शक्तिशाली शासक और विश्व के नीति-नियंता होने के गुमान में हैं और दूसरी ओर ईरान को होर्मुज खोलने के लिए मोहलत पर मोहलत देकर अपनी कमजोरी भी जाहिर कर चुके। यदि उनकी सेना इतनी ही शक्तिशाली है तो ईरान की मारक क्षमता कम होने का नाम क्यों नहीं ले रही है? वह ऐसी-ऐसी मिसाइलें दागने में लगा हुआ है, जिससे अमेरिका भी दंग है और इजरायल भी। ट्रंप कभी ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने की धमकी देते हैं और कभी उससे शांति वार्ता की पहल करते हैं।

ट्रंप ने ईरान के समक्ष शांति वार्ता का जो प्रस्ताव रखा, उसने उसे खारिज ही नहीं किया, बल्कि उनका उपहास भी उड़ाया। वह उन्हें जवाबी धमकी भी दे रहा है। ट्रंप ने ईरान पर हमला करते समय कहा था कि वे वहां सत्ता परिवर्तन के साथ परमाणु हथियारों के निर्माण की उसकी क्षमता खत्म करना चाहते हैं। ईरान में सत्ता परिवर्तन के कोई आसार नहीं, जबकि उसके सुप्रीम नेता खामेनेई समेत कई बड़े सैन्य अफसर मारे जा चुके हैं। यह कहना भी कठिन है कि अमेरिका और इजरायल के हमलों में उसके परमाणु संयंत्र इतने बुरी तरह तबाह हो गए हैं कि वह फिर कभी परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल नहीं कर सकेगा।

अपनी टैरिफ नीति की लाठी से दुनिया को हांकने वाले ट्रंप न तो खाड़ी देशों को ईरान के हमलों से बचा पा रहे हैं और न ही अपने मित्र देशों और यहां तक कि नाटो देशों को इस युद्ध में सहयोग देने के लिए राजी कर पा रहे हैं। उनके मित्र देश उनका सहयोग करने के लिए इसलिए भी आगे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बहुत समय नहीं हुआ, जब उन्होंने ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी देकर उन्हें तंग किया था। ईरान ने इस माहौल की हवा निकाल दी है कि दुनिया में वही होगा, जैसा ट्रंप चाहेंगे और उनकी जिद के सामने अन्य देशों को झुकना ही होगा। ट्रंप यह कहते रहे हैं कि वे शांति के राष्ट्रपति हैं और सात-आठ युद्ध रोके हैं, लेकिन उनके पास इसका कोई जवाब नहीं कि वे रूस-यूक्रेन युद्ध क्यों नहीं रोक सके, जिस पर उन्होंने सबसे ज्यादा रियाज किया। शांति का स्वयंभू मसीहा होने के नाते वे खुद को नोबेल पुरस्कार का अधिकारी बताते रहे हैं और उसके न मिलने पर विलाप भी करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुल मिलाकर दुनिया को अस्थिर और अशांत ही किया है। वे अपने विरोधी देशों के साथ मित्र देशों से भी बुरा बर्ताव करने के आदी हैं। ट्रंप यह चाहते हैं कि सारी दुनिया उन्हें सलाम करे, लेकिन वे इसके लिए धौंस-धमकी का सहारा लेते हैं। इसी कारण वे आदर और सम्मान के पात्र नहीं और न हो सकते हैं। ट्रंप एक अविश्वसनीय और अराजक शासक हैं, क्योंकि वे अपने कहे से मुकरने, मनमानी करने और झूठ बोलने में माहिर हैं। वे ऐसा दिखाते हैं कि उनके पास दुनिया की हर समस्या का समाधान है, पर पश्चिम एशिया संकट उनके गले की हड्डी बन गया है। इससे वे कितने कुंठित हैं, इसका पता गत दिनों की उनकी गाली-गलौज वाली पोस्ट से मिला। उनकी भाषा का स्तर कुछ-कुछ हिंदी फिल्मों के इस डायलाग जैसा था-कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगा।

पश्चिम एशिया संकट में बुरी तरह फंस गए ट्रंप सहानुभूति के पात्र नहीं, क्योंकि उन्होंने मनमानी ही की। चूंकि ईरान अमेरिका और इजरायली हमलों से जूझ रहा है, इसलिए वह दुनिया के एक बड़े हिस्से में हमदर्दी हासिल कर रहा है, लेकिन यदि अमेरिका और इजरायल ने मनमानी की तो ईरान भी दूध का धुला नहीं। वहां की सत्ता एक निरंकुश और अपने ही लोगों के प्रति निर्मम बर्ताव करने वाली सत्ता है। उसने अपने ही हजारों लोगों को मारा है। वह इजरायल को दुनिया के नक्शे से मिटाने की सनक से बुरी तरह ग्रस्त है। यदि ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो इजरायल के अस्तित्व के लिए तो गंभीर खतरा बनेगा ही, पश्चिम एशिया में दादागीरी कर सबको तंग करेगा और हमास, हिजबुल्ला जैसे आतंकी संगठनों की और खुलकर मदद करेगा। पश्चिम एशिया संकट का समाधान चाहे जब और जैसे हो, फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति वहां बुरी तरह घिर गए हैं और उन पर 'फंस गए रे ट्रंप' जैसी फिल्म बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे खुद चलती-फिरती कामेडी बन गए हैं।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

गलती और सुधार

मनुष्य का जीवन पूर्णता की यात्रा नहीं, बल्कि निरंतर सीखने की अनवरत प्रक्रिया है। इस यात्रा में गलतियां हमारे पथ के पत्थर नहीं, बल्कि मार्गदर्शक रूपी दीपक हैं। गलती वह आईना है, जिसमें हम अपनी अपूर्णता, अपनी सीमाओं और अपने अहंकार को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी भूलों को स्वीकार कर, उनसे सीखकर सुधार का साहस करता है, वही आत्मविकास की दिशा में अग्रसर होता है। हम अनजाने में अनेक त्रुटियां करते हैं। कभी शब्दों में कठोरता आ जाती है, कभी निर्णयों में शीघ्रता, तो कभी संबंधों में उपेक्षा। यदि हम इन भूलों को अनदेखा कर आगे बढ़ जाते हैं, तो यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपने घर का दरवाजा खुला छोड़कर निश्चिंत होकर सो जाए। तब बाहरी खतरे धीरे-धीरे भीतर प्रवेश कर जाते हैं और हमें आभास भी नहीं होता कि हमारी सुरक्षा कितनी कमजोर हो चुकी है। इस क्रम में गलतियां हमारे व्यक्तित्व में धीरे-धीरे स्थायी दोष बन जाती हैं।

गलती को अपना गुरु बनाना केवल उसे स्वीकार करना नहीं, बल्कि उसके कारणों की तह तक जाना है। यह आत्ममंथन की वह प्रक्रिया है, जिसमें हम अपने भीतर झांकते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि हमसे कहां भूल हुई। यह प्रक्रिया कभी-कभी कष्टदायक होती है, क्योंकि यह हमारे अहंकार को चुनौती देती है। हालांकि यही पीड़ा हमारे विकास का आधार भी बनती है। जैसे कच्चा सोना अग्नि में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही मनुष्य अपनी भूलों की तपिश में निखरता है। यदि हम अपने व्यवहार की गलतियों को पहचान कर सुधार लें तो रिश्तों में आई दरारें भी भरी जा सकती हैं। जीवन हमें बार-बार यह सिखाता है कि पूर्णता कोई स्थायी अवस्था नहीं, बल्कि निरंतर सुधार की प्रक्रिया है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से डरता नहीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन का शिक्षक बना लेता है, वही सच्चे अर्थों में प्रगति करता है।

ममता कुशवाहा

'नो न्यू कोल गोल' की राह पर इंडोनेशिया

सुधीर कुमार

कोयले का दहन वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैस बढ़ाता है, जो पर्यावरण सहित स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक होता है

इंडोनेशिया ने 'नो न्यू कोल गोल' के तहत 2040 तक कोयला आधारित पुरानी बिजली संयंत्रों को बंद करने और इस तरह के नए संयंत्रों की स्थापना को मंजूरी न देने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को समाप्त करना, 2050 तक 'नेट जीरो' का लक्ष्य हासिल करना तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास पर ध्यान देकर सतत विकास को बढ़ावा देना है।

इंडोनेशिया का आगामी डेढ़ दशक में सभी कोयला-आधारित बिजली संयंत्रों को बंद करने का संकल्प न केवल वैश्विक जलवायु लक्ष्यों की दिशा में एक अहम कदम है, बल्कि यह दक्षिण-पूर्व एशिया में ऊर्जा संक्रमण का मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है। हालांकि इस लक्ष्य को हासिल कर पाना इंडोनेशिया के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि उसकी मौजूदा ऊर्जा संरचना में कोयले की हिस्सेदारी बहुत अधिक है। दरअसल इंडोनेशिया दक्षिण-पूर्व एशिया का सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश है, जहां कुल बिजली आपूर्ति का लगभग 85 प्रतिशत हिस्सा कोयले पर आधारित है। जीवाश्म ईंधन पर अत्यधिक निर्भरता के कारण वहां अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उल्लेखनीय विकास नहीं हो पाया है। वर्तमान में अक्षय ऊर्जा आपूर्ति में भूतापीय और जल विद्युत की हिस्सेदारी क्रमशः आठ और जल विद्युत की पांच प्रतिशत है, जबकि पवन और सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी नगण्य है। जाहिर है, कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को चरणबद्ध रूप से बंद करने से पहले देश को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने और उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता कहीं अधिक है। वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक 'एंबर' के अनुसार, इंडोनेशिया को इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिवर्ष औसतन तीन गीगावाट कोयला आधारित ऊर्जा क्षमता को चरणबद्ध रूप से हटाने के साथ-साथ आठ गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता भी जोड़नी होगी। ठोस वित्तीय एवं तकनीकी ढांचे के बगैर ऐसा कर पाना मुमकिन भी नहीं होगा। कोयला आधारित ऊर्जा उत्पादन आज वैश्विक तापवृद्धि के सबसे बड़े कारक बनकर उभरे हैं। दुनियाभर में कुल बिजली उत्पादन का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा कोयले से उत्पादित होता है। भारत में बिजली संयंत्र अपनी वार्षिक बिजली उत्पादन का तकरीबन 75 प्रतिशत हिस्सा कोयले से प्राप्त करता है। कोयला एक समाप्य-अनवीकरणीय संसाधन है। इसका बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग न करने से आने वाली पीढ़ियों को ऊर्जा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

बहरहाल कोयले का दहन वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों की मोटी परत जमा करता है, जो स्थानीय पर्यावरण के साथ-साथ मानव स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक होता है। अतः इस पर निर्भरता घटाकर अक्षय ऊर्जा स्रोतों का दामन थामना ही श्रेयस्कर है।

(लेखक बीएचयू में शोधार्थी हैं)

मेलबाक्स

अराजकता से त्रस्त बंगाल

'बेतुकी बयानबाजी' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में बंगाल की मुख्यमंत्री एवं टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की पहलगाम आतंकी हमले को लेकर की गई बेतुकी टिप्पणी पर जो तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है, वह उपयुक्त ही है। पाकिस्तान के रक्षामंत्री की अनर्गल बयानबाजी को आधार बनाते हुए पहलगाम हमले के लिए भाजपा पर तोहमत मढ़ना, दुश्मन देश की झूठी बात को शह देने जैसा है। बंगाल में प्रमुख विपक्षी दल भाजपा और सत्ता संभाल रही टीएमसी के बीच प्रायः तीखी बयानबाजी होती रहती है, लेकिन इसकी भी एक सीमा-रेखा होनी चाहिए। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर बंगाल की सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाए रखने वाली टीएमसी किसी भी हद तक जाने को तैयार बैठी है। विधानसभा चुनावों को निष्पक्ष रूप से करवाने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग को इस राज्य में सबसे अधिक कवायद करनी पड़ रही है। इसका प्रमुख कारण राज्य की प्रशासनिक मशीनरी का राजनीतिकरण होना माना जा रहा है। मालदा की अराजक घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट को भी राज्य के प्रशासन पर भरोसा नहीं रहा। ऐसे में बौखलाईं टीएमसी प्रमुख एवं राज्य की मुख्यमंत्री अपने वोटबैंक को मजबूत करने के लिए हर हथकंडा अपना रही हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अनर्गल बयानबाजी से प्रोत्साहित होकर ही कुछ अराजक तत्व राज्य में एसआइआर ड्यूटी पर तैनात न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने का दुस्साहस कर बैठे। इस खौफनाक अराजक घटना का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल की ध्वस्त होती कानून-व्यवस्था पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी कि 'भरोसा गंवा चुके हैं बंगाल के अधिकारी' राज्य सरकार को शर्मसार करने के साथ टीएमसी प्रमुख एवं राज्य की मुख्यमंत्री के गैरजिम्मेदाराना रवैये को रेखांकित करने वाली ही है।

डा. वीपी पाण्डेय, अलीगढ़

जिलों को पीएनजी से जोड़ा जाए

भारत सरकार के सबसे बड़े उपक्रम, गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा एक अनुमान के तहत देश में 16,000 किलोमीटर से अधिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क का संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त गेल द्वारा 2,000 किलोमीटर से अधिक एलपीजी गैस पाइपलाइन का भी संचालन किया जाता है। गेल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से देश के 22 राज्यों के लगभग 90 से अधिक जिलों में गैस पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है, जिसके जरिये सीएनजी, एलपीजी तथा कुछ जिलों में पीएनजी गैस की आपूर्ति भी की जा रही है। यदि भारत सरकार अपने इस प्रमुख प्राकृतिक गैस उपक्रम के सहयोग से उन राज्यों के जिलों में, जहां से गैस पाइपलाइन गुजरती है, राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित कर जिला एवं तहसील मुख्यालयों को पाइपयुक्त प्राकृतिक गैस (पीएनजी) से जोड़ने की दिशा में ठोस पहल करे तो आमजन को गैस सिलिंडर के झंझट से काफी हद तक मुक्ति मिल सकती है। पीएनजी गैस एलपीजी की तुलना में अधिक सुरक्षित है और इससे प्रत्येक घर की रसोई में चौबीसों घंटे गैस की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकती है। साथ ही उपभोक्ताओं को उनकी वास्तविक खपत के अनुसार ही भुगतान करना होगा, जो इसे और अधिक सुविधाजनक बनाता है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में ऊर्जा संकट की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के चलते विश्व स्तर पर तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हो रही है, जिसका असर भारत सहित अन्य देशों पर भी स्पष्ट रूप से महसूस किया जा रहा है। ऐसे समय में भारत सरकार यदि उन राज्यों और जिलों में, जहां से गैस पाइपलाइन गुजरती है, पीएनजी कनेक्शन के विस्तार की योजना को प्राथमिकता देते हुए उसे क्रियान्वित करती है तो इससे देश पर गैस आपूर्ति का दबाव कुछ हद तक कम किया जा सकता है। राज्य सरकारों को भी चाहिए कि वे अपने-अपने राज्यों में गैस आपूर्ति को सुदृढ़ बनाने के लिए पीएनजी परियोजनाओं को प्राथमिकता दें और उन्हें शीघ्रता से लागू करें। यह न केवल नागरिकों के जीवन को सुगम बनाएगा, बल्कि ऊर्जा के सुरक्षित, सुलभ और सतत उपयोग को भी सुनिश्चित करेगा।

अरविंद रावल, झाबुआ (मप्र)

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

8 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है पिछले एक साल में भारतीय रुपये में डालर के मुकाबले। तमाम अन्य देशों की मुद्राएं भी इसी तरह की अस्थिरता से जूझ रही हैं।

आजकल

वैश्विक अनिश्चितता में फंसा रुपया

किसी मुद्रा का कमजोर होना केवल घरेलू समस्या नहीं होती, बल्कि यह व्यापक वैश्विक परिस्थितियों का प्रतिबिंब भी होता है। जब बड़ी अर्थव्यवस्थाएं संकट में होती हैं, तब निवेशक सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख करते हैं, विशेषकर अमेरिकी डालर की ओर, जिसे विश्व में सबसे सुरक्षित मौद्रिक विकल्प माना जाता है। इस कारण पूंजी का प्रवाह विकसित देशों की ओर बढ़ता है और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं पर दबाव बढ़ जाता है। इसका सीधा असर इन दिनों भारतीय रुपये पर भी दिख रहा है

नृपेंद्र अभिषेक नृप
आर्थिक मामलों के जानकार

रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिम एशिया में छिड़े संघर्ष ने भारतीय अर्थव्यवस्था की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। प्रतीकात्मक

आज का वैश्विक आर्थिक परिदृश्य अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। कभी भू-राजनीतिक तनाव तो कभी आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं, हर एक घटना का प्रभाव सीधे वित्तीय व्यवस्थाओं पर पड़ता है। मुद्रा बाजार अत्यंत संवेदनशील होता है, इसलिए वह इन वैश्विक हलचलों पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। किसी मुद्रा का कमजोर होना केवल घरेलू समस्या नहीं होती, बल्कि यह व्यापक वैश्विक परिस्थितियों का प्रतिबिंब भी होता है। जब बड़ी अर्थव्यवस्थाएं संकट में होती हैं, तब निवेशक सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख करते हैं, विशेषकर अमेरिकी डालर की ओर, जिसे वैश्विक आरक्षित मुद्रा माना जाता है। इस कारण पूंजी का प्रवाह विकसित देशों की ओर बढ़ता है और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं पर दबाव बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त वैश्विक स्तर पर बढ़ती महंगाई ने केंद्रीय बैंकों को सख्त मौद्रिक नीतियां अपनाने के लिए मजबूर किया है। विकसित देशों में ब्याज दरों में वृद्धि से निवेशकों को अधिक लाभ मिलता है, जिससे वे विकासशील देशों से पूंजी निकालने लगते हैं। इसका सीधा असर भारतीय रुपये जैसी मुद्राओं पर पड़ता है, जो धीरे-धीरे कमजोर होने लगती हैं। यह गिरावट अगर सीमित और अस्थायी हो तो सामान्य मानी जा सकती है, लेकिन जब यह लंबे समय तक बनी रहे या तीव्र हो जाए, तब यह अर्थव्यवस्था की अंदरूनी कमजोरियों की ओर संकेत करती है। ऐसे में त्वरित और दीर्घकालिक नीतिगत सुधारों की आवश्यकता होती है।

कमजोर होती रुपये की स्थिति : यह सच है कि वैश्विक संकट के समय उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राएं अक्सर दबाव में आती हैं, लेकिन रुपये की गिरावट की तीव्रता चिंता का विषय है। अन्य एशियाई देशों की तुलना में रुपये में अधिक गिरावट देखने को मिली है, जो बाहरी कारणों के साथ-साथ आंतरिक कमजोरियों को भी दर्शाती है। इस स्थिति का एक प्रमुख कारण भारत की आयात पर अत्यधिक निर्भरता है, विशेष रूप से कच्चे तेल के मामले में। जब वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तब डालर की मांग भी बढ़ जाती है, जिससे रुपये पर दबाव पड़ता है। जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक होता है तो चालू खाता घाटा बढ़ता है, जो मुद्रा को और कमजोर करता है। निवेशकों का विश्वास भी एक महत्वपूर्ण कारक है। जब वैश्विक निवेशकों को किसी देश की आर्थिक स्थिति या नीतियों पर संदेह होता है तो वे अपना निवेश वापस ले लेते हैं। इससे पूंजी का बहिर्गमन होता है और मुद्रा पर दबाव बढ़ जाता है। इस प्रकार रुपये की कमजोर स्थिति केवल वैश्विक संकट का परिणाम नहीं है, बल्कि यह भारत की आर्थिक संरचना से जुड़ी चुनौतियों को भी उजागर करती है।

तेल की कीमतों में वृद्धि : भारतीय रुपये की मजबूती या कमजोरी में तेल की कीमतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बड़े पैमाने पर कच्चे तेल का आयात करता है। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो भारत का आयात बिल तेजी से बढ़ जाता है। चूंकि इन आयातों का भुगतान डालर में किया जाता है, इसलिए डालर की मांग बढ़ती है और रुपये की कीमत गिरने लगती है। इसका प्रभाव केवल मुद्रा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे आर्थिक ढांचे पर पड़ता है। तेल की कीमतें बढ़ने से परिवहन और उत्पादन की लागत में वृद्धि होती है, जिससे महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ने पर आम जनता की क्रय शक्ति घटती है और आर्थिक संतुलन प्रभावित होता है। साथ ही महंगे आयात के कारण चालू खाता घाटा बढ़ता है, जो रुपये को और कमजोर करता है। जब-जब तेल की कीमतों में उछाल आता है, तब-तब रुपये में गिरावट दर्ज की जाती है। इसलिए ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश, ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण और रणनीतिक भंडार का निर्माण इस दिशा में सहायक हो सकते हैं। जब तक इस मूल समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक रुपया बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशील बना रहेगा।

किसी भी देश की मुद्रा को स्थिर रखने में विदेशी निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब विदेशी निवेशक किसी देश में निवेश करते हैं तो उस देश की मुद्रा की मांग बढ़ती है और उसकी कीमत मजबूत होती है। इसके विपरीत जब निवेशक अपना पैसा निकालते हैं तो मुद्रा पर दबाव बढ़ता है। हाल के वर्षों में भारत से पूंजी का बहिर्गमन देखने को मिला है, जिसने रुपये को कमजोर किया है। इसका एक प्रमुख कारण विकसित देशों में बढ़ती ब्याज दरें हैं। अमेरिका जैसे देशों में उच्च ब्याज दरें निवेशकों को अधिक लाभ देती हैं, जिससे वे अपने निवेश को वहां स्थानांतरित कर देते हैं। इससे भारत जैसे देशों में डालर की मांग बढ़ती है और रुपया कमजोर होता है। वैश्विक अनिश्चितता के समय निवेशक जोखिम से बचने की कोशिश करते हैं। उभरती अर्थव्यवस्थाएं अपेक्षाकृत अधिक जोखिम भरी मानी जाती हैं, इसलिए निवेशक वहां से पूंजी निकाल लेते हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए भारत को स्थिर आर्थिक नीतियां, पारदर्शिता और निवेशकों के अनुकूल वातावरण तैयार करना होगा। इससे न केवल निवेश बना रहेगा, नए निवेश भी आकर्षित होंगे।

केंद्रीय बैंक की नीतियां : मुद्रा की स्थिरता बनाए रखने में केंद्रीय बैंक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। भारत में यह जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक निभाता है। आरबीआइ समय-समय पर विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करता है, जहां वह डालर बेचकर रुपये को स्थिर रखने का प्रयास करता है। हालांकि इस प्रकार के हस्तक्षेप की सीमाएं होती हैं। विदेशी मुद्रा भंडार का अत्यधिक उपयोग लंबे समय तक संभव नहीं होता। इसलिए केंद्रीय बैंक को संतुलित नीति अपनानी होती है, जिसमें अल्पकालिक उपायों के साथ-साथ दीर्घकालिक रणनीतियां भी शामिल हों। ब्याज दरों में बदलाव, तरलता प्रबंधन और महंगाई नियंत्रण जैसे उपाय मुद्रा को प्रभावित करने में सहायक होते हैं। इसके अलावा पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखना भी आवश्यक है, क्योंकि यह बाहरी संकटों के समय सुरक्षा कवच का काम करता है। मजबूत भंडार निवेशकों में विश्वास बढ़ाता है और संकट के समय घबराहट को कम करता है, लेकिन केवल केंद्रीय बैंक की नीतियां ही पर्याप्त नहीं हैं, इसके लिए सरकार की वित्तीय नीतियों और संरचनात्मक सुधारों का भी सहयोग जरूरी होता है।

अतीत से सीख : भारतीय रुपये के इतिहास में कई ऐसे अवसर आए हैं, जब इसमें तीव्र गिरावट दर्ज की गई। वर्ष 2013 का टैपर टैंट्रम इसका प्रमुख उदाहरण है, जब अमेरिकी मौद्रिक नीति में बदलाव के संकेत मिलने पर वैश्विक निवेशकों ने उभरती अर्थव्यवस्थाओं से पूंजी निकाल ली थी। उस समय रुपये में भारी गिरावट आई थी, जिसने इसकी बाहरी कारकों पर निर्भरता को उजागर किया। उस अवधि में भारत उच्च महंगाई, बड़े चालू खाता घाटे और धीमी आर्थिक वृद्धि जैसी समस्याओं से जूझ रहा था। इन सभी कारकों ने मिलकर रुपये पर दबाव बढ़ाया। हालांकि सख्त मौद्रिक नीतियों, सोने के आयात पर नियंत्रण और वित्तीय अनुशासन जैसे कदमों से स्थिति को संभाला गया। आज के समय में भी ये सीख अत्यंत प्रासंगिक हैं। यदि संरचनात्मक कमजोरियों को दूर नहीं किया गया तो बाहरी झटकों का प्रभाव और अधिक गंभीर हो सकता है। इसलिए मजबूत आर्थिक आधार, संतुलित नीतियां और दीर्घकालिक दृष्टिकोण आवश्यक हैं।

चुनौतियों के बावजूद भारत के पास कई ऐसी ताकतें हैं, जो दीर्घकाल में रुपये को मजबूत बना सकती हैं। युवा आबादी, तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था और मजबूत स्टार्टअप संस्कृति भारत को एक आकर्षक निवेश गंतव्य बनाती हैं। ये सभी कारक आर्थिक विकास को गति देते हैं। इसके अलावा बुनियादी ढांचे का विकास, व्यापार करने में आसानी और सरकार की उत्पादन बढ़ाने वाली नीतियां भी अर्थव्यवस्था को मजबूत करती हैं। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रम आयात पर निर्भरता कम करने और निर्यात बढ़ाने में सहायक हैं। भारत का सेवा क्षेत्र, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी, विदेशी मुद्रा अर्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह आय रुपये पर पड़ने वाले दबाव को कुछ हद तक कम करती है। यदि इन सभी ताकतों का सही तरीके से उपयोग किया जाए तो वे रुपये को स्थिर और मजबूत बनाने में सहायक हो सकती हैं।

मुद्रा में गिरावट थामने के उपाय

मुद्रा की गिरावट को नियंत्रित करने के लिए संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है। अल्पकाल में विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप, ब्याज दरों में बदलाव और आयात नियंत्रण जैसे उपाय मददगार हो सकते हैं, लेकिन ये केवल अस्थायी समाधान हैं। दीर्घकाल में संरचनात्मक सुधार, आर्थिक विविधीकरण और घरेलू उद्योगों को मजबूत करना आवश्यक है। नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश, निर्यात को बढ़ावा और उत्पादकता में सुधार से बाहरी निर्भरता कम की जा सकती है। आयात पर निर्भरता को कम करना होगा, विशेष रूप से ऊर्जा और विनिर्माण क्षेत्रों में। घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर और निर्यात को प्रोत्साहित करके व्यापार संतुलन को सुधारा जा सकता है। इसके अलावा वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करना भी जरूरी है। बैंकिंग प्रणाली में सुधार, ऋण उपलब्धता और पारदर्शिता बढ़ाने से निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा। साथ ही वित्तीय अनुशासन बनाए रखना भी आवश्यक है, ताकि अत्यधिक कर्ज और महंगाई को नियंत्रित किया जा सके। श्रम कानून, भूमि अधिग्रहण और कर प्रणाली में सुधार से आर्थिक दक्षता बढ़ेगी। इन सभी उपायों से एक मजबूत आर्थिक ढांचा तैयार किया जा सकता है, जो रुपये को स्थिर बनाए रखने में मदद करेगा। रुपये की स्थिरता पूरी अर्थव्यवस्था की मजबूती पर निर्भर करती है। एक मजबूत मुद्रा केवल आर्थिक स्थिति का प्रतीक नहीं होती, बल्कि यह देश की स्थिरता और आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक होती है।

-नृपेंद्र अभिषेक नृप

खरी-खरी

सनक की ट्रंपकीयता

डा. प्रदीप मिश्र

जब शिष्य गुरु को पिता का दर्जा देने लगे तो समझिए वह पीएचडी वाला डाक्टर बनना चाहता है। मैंने पूछा, 'किस टापिक पर पीएचडी करना चाहते हो वत्स? कुछ सोचा है?' 'कुछ सोच सकता तो आपकी शरण में आता? टापिक आप ही बताएं गुरुदेव।' उसके अनुरोध पर मैं तत्काल टापिक-चिंतन की तंत्रा में उतराने लगा। काफी देर चिंतन-स्वांग करने के बाद मेरे मुख से टापिक निकला, 'ट्रंपकीय-सनक की विराटता के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक प्रभाव का वैचारिक अनुशीलन।'

शिष्य बोला, 'ट्रंपकीय-सनक का क्या अर्थ है गुरुदेव?' मैंने उसे बताया, 'जिस तरह रंग और स्वाद को शब्दों से परिभाषित नहीं किया जा सकता, उसी तरह ट्रंपकीय-सनक की सनकीयता को शब्दों की सीमाओं में बांध पाना संभव नहीं है। यह एक भाव है जिसमें ट्रंपकात्मकता महत्वपूर्ण होती है।' 'इसका कोई समानार्थी बतलाएं?' 'ट्रंपकात्मक सनक को कहीं हवाबाजी कहा जाता है तो कहीं लफ्फाजी। कहीं यही प्रक्रिया विष-वमन कहलाती है तो कहीं इसे खब्तीपना कहते हैं। कहीं इसे ढोंग-धतूरा भी कहने का चलन रहा है।' 'सनक के ट्रंपकीय प्रभाव पर कुछ ज्ञानवर्धन करें।' 'सनक की ट्रंपकीयता वैश्विक-स्तर पर लोगों को प्रभावित करती है। इस शब्द से संसार में अनिश्चितता की अखंड लहर उत्पन्न होती है। मिसाइल, बम, फाइटर प्लेन के साथ जुड़ने पर यह क्रूरता की खौफनाक अभिव्यक्ति होती है।' इसके अतिरिक्त ट्रंपात्मक टैरिफ ट्रंपशील-सनक का बेजोड़ नमूना है। इससे विश्व की अर्थगति दुर्गति को प्राप्त होती है।

'और उसके सामाजिक संदर्भ क्या हैं गुरुदेव?' 'सामाजिक संदर्भों में यह न्यूसेंस-वैल्यू का प्रतीक है। इससे धमक-चमक से नोबेल पुरस्कार अधिग्रहित किया जा सकता है।' 'ट्रंपकीय-सनक के राजनीतिक प्रभाव पर भी मेरे ज्ञान का परिमार्जन करें गुरुदेव।' शिष्य कुछ ज्यादा ही ज्ञानी होना चाहता था, जबकि पीएचडी में इतने ज्ञान की जरूरत होती नहीं है। मेरे क्रोध और हाथ में लहराते मिसाइलनुमा डंडे को देख शिष्य वहां से भाग खड़ा हुआ। उसे ट्रंपकीय-सनक का अर्थ समझ चुका था।

पोस्ट

डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह ईरान की पूरी सभ्यता को नष्ट करने की बात कर रहे हैं, उसमें आधुनिक इतिहास के सबसे जघन्य युद्ध अपराध की गूंज सुनाई पड़ती है।
मिन्हाज मर्चेंट@MinhazMerchant

कनाडा के अधिकांश लोग अब अमेरिका से ज्यादा चीन को अधिक भरोसेमंद मानने लगे हैं। इससे ज्यादा कहने को और क्या ही बचता है। शोन रेन@shaunrein

पाकिस्तान के एक सीनेटर संयुक्त अरब अमीरात को बेचारा, असहाय और जरूरतमंद बताकर उस पर कटाक्ष कर रहे हैं। इससे पाकिस्तान की वही कुख्यात छवि पुख्ता होती है कि वह ऐसा सांप है जो दूध पिलाने वालों को भी डसने से बाज नहीं आता।
जहक तनवीर@ZahackTanvir

जहां भारत भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को दुनिया भर में ले जा रहा है, पीएम बुद्ध का संदेश सब जगह ले जा रहे हैं और बुद्ध सर्किट बनाकर दुनिया के बौद्धों को आकर्षित कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान में मजहब में अंधे हो गए लोग आज भी बुद्ध की मूर्तियां तोड़ रहे हैं। जाहिल कहीं के।
दिलीप मंडल@Profdilipmandal

जागरण जनमत

कल का परिणाम

बांग्लादेश की नई सरकार भारत के साथ संबंध सुधारने के प्रति गंभीर दिख रही है?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या सबरीमाला मामले में केंद्र का यह कहना सही है कि यह मुद्दा न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर का है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

पवन 'ब' खेड़ा ने जड़ा ऐसा इक आरोप,
आया उस आरोप पर सरमा जी को कोप।
सरमा जी को कोप पुलिस ने मारा छापा,
अब पूरी कांग्रेस कर रही देखो स्यापा!
जहां नहीं आसान जीतकर खाना पेड़ा,
वहां बोल सच-झूठ करेंगे पवन बखेड़ा!!
- ओमप्रकाश तिवारी

पंजाब डायरी

फटकार के बाद आई पैनल भेजने की याद

इन्द्रप्रीत सिंह
ब्यूरो प्रमुख, पंजाब

सुप्रीम कोर्ट ने हाल में स्थायी पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति में देरी और नियमों के पालन में लापरवाही पर कई राज्यों को फटकार लगाई थी। इस फटकार के बाद पंजाब सरकार ने बीते दिनों संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को उन 14 अधिकारियों की सूची भेज दी है, जो स्थायी डीजीपी पद के लिए पात्र हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सख्त टिप्पणी में राज्यों को निर्देश दिया था कि वे तुरंत यूपीएससी को नामों की सूची भेजें, ताकि आयोग तीन अधिकारियों का पैनल तैयार कर राज्य सरकारों को भेज सके। अब लगभग पौने चार साल बाद पंजाब को स्थायी डीजीपी मिलने की उम्मीद है। हालांकि यह सवाल महत्वपूर्ण है कि प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार मामले में दिए गए स्पष्ट निर्देशों के बावजूद राज्य सरकारें स्थायी नियुक्ति में देरी क्यों करती रही हैं। निर्देशों के अनुसार, यूपीएससी तीन वरिष्ठ अधिकारियों का पैनल उनकी वरिष्ठता, सेवा रिकार्ड और योग्यता के आधार पर तैयार करता है। इसके बाद मुख्यमंत्री इन तीन अधिकारियों में से किसी एक को डीजीपी नियुक्त कर सकते हैं, जिन्हें कम से कम दो वर्षों का निश्चित कार्यकाल दिया जाना अनिवार्य है। इस अवधि के दौरान उन्हें मनमाने तरीके से हटाया नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इससे पुलिस की स्वतंत्रता और निष्पक्षता प्रभावित होती है।

दरअसल राज्य सरकारें पुलिस से अपने तरीके से काम करवाना चाहती हैं। संभवतः इसी कारण राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट के इन निर्देशों का पूर्ण पालन नहीं कर रही हैं। उनका तर्क है कि कानून-व्यवस्था राज्य का विषय है, इसलिए डीजीपी की नियुक्ति का अधिकार भी राज्य सरकार के पास होना चाहिए, न कि यूपीएससी के पास। पंजाब ने तो डीजीपी की स्थायी नियुक्ति अपने स्तर पर करने के उद्देश्य से पंजाब विधानसभा में पंजाब पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2023 भी पारित किया। इस विधेयक में यूपीएससी के माध्यम से चयन कराने के बजाय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का प्रविधान किया गया है। इस समिति में यूपीएससी, पंजाब लोक सेवा आयोग, गृह विभाग, गृह मंत्रालय सहित अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों को शामिल करने का प्रस्ताव है। हालांकि यह विधेयक तब से राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए लंबित है। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था, तब भी राज्य सरकार ने यही दलील दी कि विधेयक पारित हो चुका है और वह राष्ट्रपति की मंजूरी की प्रतीक्षा कर रही है। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की इस दलील को स्वीकार नहीं किया और स्पष्ट निर्देश दिया कि यूपीएससी को तत्काल नामों की सूची भेजी जाए, ताकि वह स्थायी डीजीपी के चयन के लिए तीन अधिकारियों का पैनल तैयार कर सके।

कार्यवाहक डीजीपी गौरव यादव के साथ मुख्यमंत्री भगवंत मान। फाइल

पंजाब में मार्च 2022 में जब आम आदमी पार्टी ने सत्ता संभाली, तब मौजूदा डीजीपी वीरेश कुमार भावरा को पद से हटाकर गौरव यादव को कार्यवाहक डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया। तब से अब तक पंजाब में कार्यवाहक डीजीपी के रूप में ही काम चल रहा है। गृह मंत्रालय ने तीन बार राज्य सरकार को डीजीपी की स्थायी नियुक्ति के लिए नामों की सूची भेजने को कहा, लेकिन राज्य सरकार हर बार टालमटोल का रवैया अपनाती रही। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह था कि यदि सूची भेजी जाती तो यूपीएससी संभवतः गौरव यादव का नाम तीन अधिकारियों के पैनल में शामिल न करता, क्योंकि कई अधिकारी उनसे वरिष्ठ थे। अब जब ये वरिष्ठ अधिकारी एक-एक कर सेवानिवृत्त हो चुके हैं और गौरव यादव का नाम पैनल में शामिल होना लगभग तय है, तब सरकार ने लगभग पौने चार वर्ष बाद स्थायी नियुक्ति के लिए सूची भेज दी है। इस 14 सदस्यीय पैनल में 1992 से 1995 बैच के वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी शामिल हैं, जो या तो डीजीपी रैंक में हैं या पदोन्नति के योग्य हैं। 1989 बैच के सबसे वरिष्ठ डीजीपी पराग जैन, जो वर्तमान में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रा) के प्रमुख हैं, का नाम इसमें शामिल नहीं किया गया है। जानकारी के अनुसार, उन्होंने स्वयं सरकार को लिखित रूप में सूचित किया था कि उन्हें इस पद में कोई रुचि नहीं है।

पंजाब सरकार द्वारा भेजी गई सूची में 1992 बैच के आइपीएस अधिकारियों में गौरव यादव, शरद सत्य चौहान, कुलदीप सिंह, हरप्रीत सिंह सिद्धू, गुरप्रीत कौर दियो, जितेंद्र कुमार जैन और शशि प्रभा द्विवेदी शामिल हैं। वहीं, 1995 बैच के अधिकारियों में सुधांशु शेखर श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार सिन्हा, एएस राय, वोरुवुरु नीरजा, अनीता पुंज, नरेश कुमार और राम सिंह के नाम शामिल हैं।

मंथन

ट्रंप से सवाल पूछते अमेरिकी

लोकतांत्रिक व्यवस्था के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति जब मनमौजी और तानाशाह की तरह व्यवहार करने लगता है तो फिर लोकतांत्रिक मूल्यों को गहरा आघात लगता है

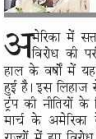

प्रेम प्रकाश
वरिष्ठ पत्रकार

अमेरिका में सत्ता के खिलाफ जन विरोध की परंपरा लंबी रही है। हाल के वर्षों में यह प्रवृत्ति और गहरी हुई है। इस लिहाज से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ विगत 28 मार्च के अमेरिका के तकरीबन सभी राज्यों में हुए विरोध प्रदर्शन इस प्रवृत्ति को कई अहम लोकतांत्रिक सवालों और सरोकारों के साथ आगे बढ़ाने वाले रहे। इस विरोध प्रदर्शन में जो नारा हर तरफ समान तौर पर गूंज रहा था, वह था- नो किंग्स। ट्रंप को कोई तंज में राजा नहीं कहा गया, बल्कि खुद के बारे में इस तरह की बात वे बोल और लिख चुके हैं। बीते वर्ष उन्होंने ट्रुथ सोशल पर न्यूयार्क की कंजेशन प्राइसिंग पालिसी को रोकने के फैसले के बाद लिखा था- 'कंजेशन प्राइसिंग खत्म, मैनहैट्टन और पूरा न्यूयार्क बच गया। राजा की जय हो!' इस पर न्यूयार्क की गवर्नर ने तब सधे अंदाज में कहा था कि अमेरिका में शासन कानून से चलता है, किसी राजा के हुक्म से नहीं।

दरअसल लोकतांत्रिक व्यवस्था के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति जब मनमौजी और तानाशाह की तरह व्यवहार करने लगता है तो फिर लोकतांत्रिक मूल्यों को गहरा आघात लगता है। लाखों की संख्या में ट्रंप के विरोध में सड़कों पर उतरे अमेरिकी नागरिकों की यही चिंता है। वे अपने राष्ट्रपति को एक निरंकुश राजा की तरह आचरण करते देख आहत हैं और इस वजह से वे विरोध की तख्तियां लेकर घरों से बाहर निकलने पर मजबूर हुए हैं। कई विश्लेषकों ने इसे हाल के वर्षों के सबसे बड़े एक-दिवसीय नागरिक प्रदर्शनों में से एक माना है। बड़ी बात यह कि यह प्रदर्शन किसी एक राजनीतिक दल द्वारा आयोजित नहीं था, बल्कि कई नागरिक संगठनों और सामाजिक समूहों के साझे नेटवर्क ने इसका समन्वय किया। लोगों को एकजुट करने के पीछे सबसे बड़ा तर्क यह था कि लोकतंत्र में सत्ता को सीमित और जवाबदेह रहना चाहिए। ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी जनता की गोलबंदी और उनका आक्रोश अभी थमा नहीं है। 28 मार्च के बाद भी खासतौर फिलाडेल्फिया और अन्य शहरों में अपने राष्ट्रपति की नीतियों के विरोध में उतरी जनता यह दिखा रही है कि अमेरिकी जनमानस में सत्ता की निरंकुशता के खिलाफ गहरा आक्रोश है।

जो अमेरिकी मीडिया पश्चिम एशिया के संकट को लेकर अपने राष्ट्रपति की नीतियों और युद्ध के दौरान होने वाली घटनाओं के बारे में एक तरह के राष्ट्रवादी आचरण को प्रश्रय दे रहा था, वह भी इन विरोध प्रदर्शनों को लेकर खासा मुखर दिखा। द न्यूयार्क टाइम्स और द वाशिंगटन पोस्ट सरीखे प्रमुख अखबारों ने इसे हाल के वर्षों में नागरिक असंतोष की बड़ी अभिव्यक्ति बताया।

अमेरिकी इतिहास में कई ऐसे दौर आए जब राष्ट्रपति की नीतियों ने व्यापक बहस और विरोध को जन्म दिया। हाल के वर्षों में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान उभरे जन असंतोष को इस आलोक में देखें-परखें तो लोकतांत्रिक मूल्यों की ताकत समझ में आती है। बीते कुछ दशकों में जिस राष्ट्रपति के दौर में सबसे व्यापक सामाजिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण देखने को मिला, वे निस्संदेह डोनाल्ड ट्रंप हैं। 2017 में ट्रंप के पहले कार्यकाल में शपथ ग्रहण के तुरंत बाद अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़े जन प्रदर्शनों में से एक आयोजित हुआ, जिसे 'वीमेंस मार्च' कहा गया। 2020 में नस्लीय न्याय का मुद्दा अमेरिकी राजनीति के केंद्र में तब आया जब जार्ज फ्लायड की पुलिस हिरासत में मौत हुई। इस घटना के विरोध में 'ब्लैक लाइव्स मैटर' के नारे और तख्तियों के साथ अमेरिका के तकरीबन हर बड़े शहर में रैलियां और प्रदर्शन हुए। इस दौरान अमेरिकी अखबारों ने अपने संपादकीय टिप्पणियों में नस्लीय न्याय और पुलिस सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। कई यूरोपीय विश्लेषकों ने इस खतरे की ओर संकेत किया कि ट्रंप की राजनीतिक शैली और तीखी बयानबाजी ने अमेरिकी राजनीति में ध्रुवीकरण को खासा गहरा कर दिया है। अलबत्ता ट्रंप समर्थक इन तमाम विरोध प्रदर्शनों को पहले दिन से एक उलट नजरिये से देखते रहे हैं। उन्हें लगता है कि ट्रंप पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती देने वाले नेता हैं और वे अमेरिकी राष्ट्रहित तथा आर्थिक प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

ट्रंप की नीतियों का अमेरिका में भी हो रहा विरोध। फाइल

बहरहाल एक ऐसे दौर में जब प्रखर नागरिक आंदोलनों के बावजूद कई देशों में लोकतांत्रिक सत्ता की स्थापना महज प्रहसन बनकर रह गई है, तब अमेरिकी समाज की चिंता और दिलेरी लोकतांत्रिक मूल्यों की हिफाजत के लिए एकजुट होकर खड़े होने की न सिर्फ नैतिक सीख देती है, बल्कि यह हमारे समय में नागरिक आचरणों को भी नए सिरे से व्याख्यायित करती है।

राष्ट्रीय संस्करण
बुधवार 8 अप्रैल, 2026
दैनिक जागरण
बिजनेस
www.jagran.com

बीते वर्ष टाटा स्टील का उत्पादन आठ प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली: टाटा स्टील ने कहा कि बीते वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसने भारत में 2.34 करोड़ टन कच्चे स्टील का उत्पादन किया है। यह किसी एक वर्ष में अब तक का सबसे अधिक उत्पादन है। इसमें इससे पिछले वित्त वर्ष की तुलना में आठ प्रतिशत की वृद्धि रही है। कंपनी ने बताया कि इस बढ़ोतरी का प्रमुख कारण कलिंगर संयंत्र से ज्यादा उत्पादन होना है। चौथी तिमाही के दौरान कंपनी का कच्चा स्टील उत्पादन बढ़कर 62.5 लाख टन रहा। (प्रेट्र)

ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमले से पश्चिम एशिया में भड़का संघर्ष उपनिवेशवाद की वापसी का संकेत है। भारत को मैन्यूफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर होना चाहिए।
- उदय कोटक, दिग्गज बैंकर

सेंसेक्स	74,616.58	▲ 509.73
निफ्टी	23,123.65	▲ 155.40
सोना प्रति दस ग्राम	₹1,53,200	▼ ₹600
चांदी प्रतिकिलोग्राम	₹2,40,000	▼ ₹2,000
डालर	₹93.06	▲ ₹0.16
क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$ 109	

एक नजर में

चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं

नई दिल्ली : खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने मंगलवार को कहा कि घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है और सरकार चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य को बढ़ाने की उद्योग की मांग पर विचार कर रही है। उद्योग संगठन इस्मा के एक कार्यक्रम से इतर खाद्य सचिव ने कहा कि चीनी की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं और पर्याप्त घरेलू आपूर्ति के कारण आगे भी कीमतों में उछाल आने की संभावना नहीं है। चोपड़ा ने कहा कि खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में कमी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। (प्रेट्र)

मंजूर आइपीओ को लाने की समयसीमा बढ़ाई

नई दिल्ली : कैपिटल मार्केट रेग्युलेटर सेबी ने मंगलवार को पहले से मंजूरी पा चुके आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) और राइट्स इश्यू को लांच करने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है। यानी अब कंपनी मंजूरी पा चुके आइपीओ और राइट्स इश्यू को 30 सितंबर तक ला सकती हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सेबी ने यह कदम उठाया है। मौजूदा नियमों के तहत सेबी से मंजूरी मिलने की तिथि से 12 या 18 महीने (जैसा भी लागू हो) में सार्वजनिक इश्यू लांच करना होता है। (प्रेट्र)

पीएफसी में 51% हिस्सेदारी बनाए रख सकती है सरकार

नई दिल्ली : केंद्र सरकार आरईसी के साथ विलय के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रही है। एक अधिकारी ने बताया कि इसमें प्रीफरेंस या नए इक्विटी शेयर जारी करना शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते बजट में पीएफसी और आरईसी के पुनर्गठन की घोषणा की थी, ताकि सार्वजनिक क्षेत्र की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम किया जा सके और कार्यक्षमता में सुधार लाया जा सके। (प्रेट्र)

युद्ध से प्रभावित एमएसएमई को मिलेगा गारंटी-मुक्त कर्ज

2.5 लाख करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी स्कीम लाने जा रही केंद्र सरकार

- एमएसएमई को दिए जाने वाले लोन की 85 प्रतिशत रकम की गारंटी सरकार लेगी
- कोरोना में भी लाई गई थी एमएसएमई के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: पश्चिम एशिया संकट से प्रभावित एमएसएमई के लिए वित्त मंत्रालय अब क्रेडिट गारंटी स्कीम लाने जा रहा है। इस स्कीम के तहत एमएसएमई को दिए जाने वाले लोन की 85 प्रतिशत रकम की गारंटी सरकार लेगी। मतलब अगर कोई उद्यमी एक करोड़ का लोन लेता है तो उसमें से 85 लाख के लोन की गारंटी सरकार लेगी और उद्यमी को बैंक के पास गारंटी के लिए कुछ भी गिरवी नहीं रखना होगा।

नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) के माध्यम से सरकार इस लोन की गारंटी लेती है। इस स्कीम के तहत प्रभावित सेक्टर को 2.5 लाख करोड़ रुपये के लोन दिए जा सकते हैं। 2.5 लाख करोड़ के लोन की गारंटी लेने के लिए सरकार को एनसीजीटीसी के पास 18,000 करोड़ जमा करना होगा। एक निश्चित समय तक ही इस स्कीम के तहत एमएसएमई लोन ले सकेंगे। वित्त मंत्रालय की तरफ से इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जा रहा है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद इसकी घोषणा हो सकती है।

कोरोना काल के दौरान भी एमएसएमई के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का एलान किया गया था। इसके तहत 3.5 लाख करोड़ से अधिक के लोन वितरित किए गए थे। लोन लेने के लिए कई शर्तें भी लगाई गई थीं। जिन लोगों ने पहले से लोन नहीं ले रखा था, उन्हें इस स्कीम का लाभ नहीं मिला था। वहीं बैंकों से डिफाल्टर घोषित हो चुके उद्यमी भी इस सुविधा से वंचित हो गए थे। सूत्रों का कहना है कि क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत लोन देने के लिए विभिन्न सेक्टर की पहचान की जाएगी और उन्हीं सेक्टर के लिए यह सुविधा होगी। अभी इन सभी चीजों पर काम किया जा रहा है।

निर्यातकों के लिए 500 करोड़ की स्कीम का हो चुका है एलान: कोरोना काल में भी एमएसएमई को इस प्रकार की छूट दी गई थी। इसका फायदा यह होता है कि तीन-चार महीने तक उद्यमी अपने किस्त नहीं भी देते हैं तो भी उनके लोन को गैर निष्पादित संपदा (एनपीए) की श्रेणी में नहीं रखा जाता है जिससे वे डिफाल्टर होने से बच जाते हैं। एक बार किसी उद्यमी का लोन एनपीए हो जाता है तो उसे दोबारा लोन लोन में दिक्कत होती है। पश्चिम एशिया संकट को देखते हुए सरकार निर्यातकों का बीमा खर्च घटाने के लिए 500 करोड़ की रिलीफ स्कीम का एलान कर चुकी है। 39 पेट्रोकेमिकल्स उत्पादों के आयात को शुल्क मुक्त कर दिया गया है।

जहाजों को बीमा देने वाली कंपनियों को सावरेन गारंटी दे सकता है भारत

1.5 अरब डालर का गारंटी फंड बनाने की योजना

नई दिल्ली, रायटर: केंद्र सरकार फारस की खाड़ी में यात्रा करने वाले जहाजों को बीमा कवर प्रदान करने वाली कंपनियों को सावरेन गारंटी (सरकारी गारंटी) देने की योजना बना रही है। सूत्रों के अनुसार, ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण जहाजों की आवाजाही से जुड़े जोखिम बढ़ गए हैं।

एक सूत्र के अनुसार, इस योजना में 1.5 अरब डालर का एक सावरेन गारंटी फंड शामिल है। इसका मकसद बीमा कंपनियों को पुनर्बीमा सहायता और लिक्विडिटी देना है, ताकि बीमा की लागत ज्यादा बनी रहती है तो उन्हें मदद मिल सके। इसके अलावा, घरेलू बीमा उद्योग के योगदान से एक अलग 30 करोड़ डालर का फंड भी बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य बीमा दावों में होने वाली किसी भी बड़ी बढ़ोतरी को निपटाने में मदद करना है। कुछ मामलों में समुद्री युद्ध जोखिम बीमा के प्रीमियम में एक हजार प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है। इसने इस रास्ते से माल भेजने वाले जहाज मालिकों, व्यापारियों और ऊर्जा कंपनियों के लिए लागत को काफी बढ़ा दिया है। उद्योग से जुड़े सूत्रों ने बताया कि बीमा नियामक ने हाल ही में कंपनियों से इस बारे में राय मांगी है कि उन्हें किस तरह के सहयोग की जरूरत है और फंडिंग को कैसे लागू किया जाए।

मार्गन स्टेनली ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का वृद्धि अनुमान घटाया

नई दिल्ली, आइएएनएस: वैश्विक वित्तीय सेवा फर्म मार्गन स्टेनली ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत का आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाकर 6.2 प्रतिशत कर दिया है। फर्म ने इससे पहले 6.5 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया था।

आर्थिक अनुमान में इस कटौती में कच्चे तेल की ऊंची कीमतों का असर दिखा है। पूरे वित्त वर्ष के दौरान कच्चे तेल की औसत कीमत लगभग 95 डालर प्रति बैरल रहने का अनुमान है। हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा है कि बढ़ती ऊर्जा लागत, आपूर्ति में रुकावटें और बाहरी दबाव नई चुनौतियां पेश कर रहे हैं, लेकिन भारत में आर्थिक वृद्धि की रफ्तार में बहुत फर्क नहीं आएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगे दामों पर क्रूड और गैस के आयात से व्यवसायों का उत्पादन खर्च बढ़ रहा है और यह महंगाई बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। साथ ही रुपये पर भी दबाव डाल रहे हैं।

एक वर्ष में 24.52 लाख ईवी की बिक्री

नई दिल्ली, प्रेट्र: बीते एक वर्ष यानी एक अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक देश में कुल 24.52 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की खुदरा बिक्री हुई है। फेडरेशन आफ आटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने मंगलवार को बताया कि इसमें एक वर्ष पहले की समान अवधि के मुकाबले 24.6 प्रतिशत की वृद्धि रही है।

फाडा ने बताया कि बीते वित्त वर्ष के दौरान इलेक्ट्रिक दोपहिया की खुदरा बिक्री वार्षिक आधार पर 21.81 प्रतिशत बढ़कर 14,01,818 इकाई रही है। इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों की बिक्री दो लाख से कुछ कम यानी 1,99,923 इकाई रही है। इसमें वार्षिक आधार पर 83.63 प्रतिशत की वृद्धि रही है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 1,08,873 इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों की बिक्री हुई थी। वर्ष के दौरान 78,811 इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों की बिक्री के साथ टाटा मोटर्स पहले और 53,089 वाहनों के साथ जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर्स दूसरे स्थान पर रही है।

मौजूदा माहौल में ब्याज घटने की उम्मीद कम

2026-27 की पहली एमपीसी बैठक के फैसलों की घोषणा आज, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से महंगाई बढ़ने का खतरा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच वैश्विक अनिश्चितता चरम पर है। कच्चे तेल की कीमतें 100 डालर प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई हैं, जिससे दुनियाभर के शेयर और वित्तीय बाजारों में भारी गिरावट की आशंका जताई जा रही है। ऐसे माहौल में आरबीआइ गवर्नर संजय मल्होत्रा बुधवार को वित्त वर्ष 2026-27 की पहली मौद्रिक नीति समीक्षा का एलान करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा भू-राजनीतिक तनाव और मुद्रास्फीति के बढ़ने के खतरे को देखते हुए मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) रेपो रेट में कोई कटौती नहीं करेगी। वर्तमान में रेपो रेट 5.25 प्रतिशत पर है और इसे यथावत बरकरार रखे जाने की संभावना है।

इस बात की उम्मीद है कि आरबीआइ गवर्नर पश्चिम एशिया के विवाद से भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले संभावित असर का आकलन पेश करेंगे। कमजोर होते रुपये को संभालने के लिए आरबीआइ के भावी कदमों पर भी बाजार की नजर रहेगी। अमेरिका-ईरान तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से आयातित मुद्रास्फीति बढ़ने का खतरा है, जो रुपये पर दबाव डाल रहा है।

रेटिंग एजेंसी इक्रा की रिपोर्ट बताती है कि कच्चे तेल की औसत कीमत 85 डालर प्रति बैरल मानते हुए वित्त वर्ष 2027 में थोक मूल्य सूचकांक 3.5 प्रतिशत और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 4.3 प्रतिशत रह सकता है। मोटे तौर पर कच्चे तेल की कीमतों में हर 10 प्रतिशत की वृद्धि से भारत में महंगाई दर में भी 40-60 आधार अंकों की बढ़ोतरी होती है।

आर्थिक विकास दर अनुमान में कमी संभव: आरबीआइ गवर्नर मल्होत्रा चालू वित्त वर्ष के लिए देश की आर्थिक विकास दर का क्या अनुमान लगाते हैं, इस पर भी बाजार व दूसरी एजेंसियों की नजर होगी। पश्चिम एशिया विवाद के शुरू होने के बाद कई देशी व विदेशी एजेंसियों ने भारत सहित पूरी दुनिया की विकास दर के अनुमान को घटाया है। इक्रा ने वित्त वर्ष 2027 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, जो वित्त वर्ष 2026 के 7.5 प्रतिशत से कम है। सभी आर्थिक एजेंसियां मान रही हैं कि अपनी ऊर्जा जरूरत का काफी ज्यादा हिस्सा बाहर से आयात करने की वजह से भारत पर पश्चिम एशिया विवाद का असर ज्यादा हो सकता है।

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

वोडाफोन के बकाया एजीआर पुनर्मूल्यांकन की समयसीमा बढ़ी

नई दिल्ली, प्रेट्र: दूरसंचार विभाग ने वोडाफोन आइडिया के लिए बकाया समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के पुनर्मूल्यांकन को पूरा करने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया है। सरकार ने हाल ही में वोडाफोन आइडिया को अपने बकाया और देनदारियों से राहत दी है। पहले पुनर्मूल्यांकन 31 मार्च तक पूरा होने का लक्ष्य था।

सूत्रों ने कहा कि स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क की समीक्षा चल रही है, जो संचार लेखा नियंत्रक द्वारा आंतरिक लाइसेंस शुल्क पुनर्मूल्यांकन के बाद की जा रही है। इसीलिए समयसीमा को जून तक बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर राहत दी है और इसके एजीआर बकाया को 87,695 करोड़ रुपये पर फ्रीज कर दिया है। यह एजीआर बताया वित्त वर्ष 2006-07 से 2018-19 तक की अवधि से जुड़ा है। इसी राशि का पुनर्मूल्यांकन हो रहा है।

बाजार में लगातार चौथे दिन तेजी, सेंसेक्स 510 अंक चढ़ा

- कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और वैश्विक बाजार में तेजी से बढ़त के साथ बंद हुए बाजार
- आइटी शेयरों में खरीदारी से शुरुआती नुकसान के बाद रिकवरी करने में मदद मिली

मुंबई, प्रेट्र: कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और वैश्विक बाजार में तेजी से मंगलवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 509.73 अंक या 0.69 प्रतिशत चढ़कर 74,616.58 पर बंद हुआ। दिन के दौरान, इसने 74,686.32 का उच्च स्तर और 73,282.41 का निचला स्तर छुआ, जिसमें 1,403.91 अंकों का उतार-चढ़ाव देखा गया। वहीं, 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 155.40 अंक, या 0.68 प्रतिशत चढ़कर 23,123.65 पर बंद हुआ। सूचना-प्रौद्योगिकी (आइटी) शेयरों में खरीदारी से शुरुआती नुकसान के बाद बाजारों को रिकवरी करने में मदद मिली।

सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचसीएल टेक्नोलाजीज, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, सन फार्मा और हिंदुस्तान यूनिलीवर सबसे ज्यादा फायदे में रहे। जबकि, इंटरग्लोब एविएशन, अदाणी पोर्ट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाइटन नुकसान में रहीं। ग्लोबल तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.71 प्रतिशत गिरकर 109 डालर प्रति बैरल पर आ गया। सोमवार को सेंसेक्स 787.30 अंक उछलकर 74,106.85 पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी 255.15 अंक चढ़कर 22,968.25 पर पहुंच गया था।

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि घरेलू बाजार में रिकवरी का सिलसिला जारी रहा। हालांकि, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और ईरान को लेकर ट्रंप की डेडलाइन से पहले बरती जा रही सावधानी के चलते बाजार की शुरुआत कमजोर रही।

अंतरराष्ट्रीय

वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुनाव में हो सकता हूं शामिल : डोनाल्ड ट्रंप

- अमेरिका के राष्ट्रपति ने मजाकिया लहजे में कही यह बात

डोनाल्ड ट्रंप। फाइल

कहा, वह वेनेजुएला के किसी भी नेता से ज्यादा लोकप्रिय हैं

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वह वेनेजुएला में काफी लोकप्रिय हैं और अमेरिका में कार्यकाल पूरा करने के बाद वह वहां के राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होने पर विचार कर सकते हैं। हालांकि ट्रंप ने यह बात मजाकिया लहजे में कही।

ट्रंप ने सोमवार को एक प्रेस कान्फ्रेंस में कहा, वह वेनेजुएला में अब तक के किसी भी नेता से ज्यादा पोल रेटिंग हासिल कर सकते हैं। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब गत तीन जनवरी को अमेरिका ने सैन्य अभियान में वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो व उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया था और वे ड्रग्स तस्करी के मामलों का सामना करने के लिए अमेरिका लाए गए थे। इसके बाद उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जिम्मेदारी संभाली। ट्रंप ने कहा, 'वेनेजुएला के लोग कहते हैं कि अगर मैं वहां राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ता हूं तो मुझे किसी भी व्यक्ति के मुकाबले ज्यादा वोट मिलेंगे। इसलिए मैं जब यहां अपना काम खत्म कर लूंगा तो वेनेजुएला जा सकता हूं।' कहा, 'मैं जल्द ही स्पेनिश सीख लूंगा। मैं वेनेजुएला जाऊंगा। मैं राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ूंगा, पर हम वहां के निर्वाचित राष्ट्रपति से बहुत खुश हैं।' ट्रंप ने बताया कि वेनेजुएला के साथ संघर्ष 45 मिनट में खत्म हो गया था।

फ्रांस के केंद्रीय बैंक ने न्यूयार्क में रखा अपना स्वर्ण भंडार को बेचा

- फ्रांसीसी बैंक ने 129 टन गैर-मानक सोने के बिस्कुट को बेचा
- फ्रांस का स्वर्ण भंडार लगभग 2,437 टन पेरिस में ही सुरक्षित

फ्रांस का केंद्रीय बैंक। फाइल

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

फ्रांस के केंद्रीय बैंक ने अपने स्वर्ण भंडार को देश में वापस लाने के लंबे समय से चल रहे प्रयास को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और इस प्रक्रिया को अहम वित्तीय उपलब्धि में बदल दिया है। बैंक ने पारंपरिक तरीके से सोना अमेरिका से लाने के बजाय एक रणनीतिक और आधुनिक दृष्टिकोण अपनाया, जिससे उसे समय, लागत और जोखिम तीनों में लाभ मिला है।

एक रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई 2025 से जनवरी 2026 के बीच बैंक डी फ्रांस ने न्यूयार्क में रखे 129 टन पुराने और गैर-मानक सोने के बिस्कुट बेच दिए। यह बिक्री ऐसे समय में की गई जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें रिकार्ड स्तर पर थीं। इस कदम से प्राप्त धनराशि का उपयोग बैंक ने यूरोपीय बाजार से अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सोना खरीदने में किया, जिसे पेरिस में रखा गया है। इस रणनीति ने बैंक को महाद्वीपों के बीच सोने के परिवहन व शोधन की जटिलताओं से बचाया। साथ ही, इससे यह सुनिश्चित हुआ कि फ्रांस का स्वर्ण भंडार आधुनिक वैश्विक मानकों के अनुरूप हो। यह पहल 2005 से चल रहे व्यापक आधुनिकीकरण कार्यक्रम का हिस्सा रही है। इन लेन-देन से बैंक को 12.8 बिलियन यूरो का राजस्व प्राप्त हुआ, जिससे उसकी वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ। वर्ष 2025 में बैंक ने 8.1 बिलियन यूरो का शुद्ध लाभ दर्ज किया। अब फ्रांस का स्वर्ण भंडार 2,437 टन हो गया है। इस कदम का प्रभाव अन्य देशों में भी देखने को मिल रहा है। जर्मनी में कुछ विशेषज्ञ अपने विदेशी भंडार को वापस लाने की मांग कर रहे हैं। भारत भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। रिजर्व बैंक ने मार्च 2023 से अब तक 274 टन से अधिक सोना देश में वापस लाया है। इसका उद्देश्य भू-राजनीतिक जोखिमों को कम करना और घरेलू स्तर पर भंडार की उपलब्धता बढ़ाना है।

बांग्लादेश की पहली महिला स्पीकर रहीं शिरीन चौधरी गिरफ्तार

- अप्रैल 2013 से लेकर सितंबर 2024 तक संसद की अध्यक्ष रहीं

शिरीन चौधरी। फाइल

ढाका, प्रेट्र : बांग्लादेश की पूर्व संसद अध्यक्ष (स्पीकर) शिरीन शरमीन चौधरी को मंगलवार को ढाका पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। उल्लेखनीय है कि शिरीन अप्रैल 2013 से सितंबर 2024 तक देश की पहली महिला स्पीकर रही थीं। उन पर छात्र आंदोलन और जन विद्रोह के दौरान हुई हिंसा एवं तोड़फोड़ से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। मुख्य मामला लालबाग थाने में दर्ज किया गया है, जबकि बनानी, उत्तरा और रंगपुर में भी केस लंबित हैं। अवामी लीग सरकार के पतन के बाद से ही शिरीन चौधरी छिपी हुई थीं। उन्हें धनमंडी स्थित एक रिश्तेदार के आवास से गिरफ्तार किया गया। वह रंगपुर-6 निर्वाचन क्षेत्र से सांसद थीं।

अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद राष्ट्रपति द्वारा संसद भंग किए जाने पर उन्होंने आधिकारिक उत्तराधिकारी के चयन से पहले ही पद से इस्तीफा दे दिया था। जुलाई 2024 में विद्रोह के बाद शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के अधिकांश शीर्ष नेता और पूर्व मंत्री या तो छिपे हुए हैं या फिर कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। वर्तमान में पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, जिसके बाद आगे की कानूनी कार्यवाही तय की जाएगी। बहुत से नेताओं का आरोप है कि प्रशासन उन्हें प्रताड़ित कर रहा है।

रूसी सेना ने यूक्रेन के दो शहरों को बनाया निशाना,आठ की मौत

- बसों पर किया गया हमला, कई लोग घायल, यूक्रेनी ड्रोन हमले में रूस में पांच मारे गए

रूसी हमले से मंगलवार को यूक्रेन के चेर्निहीव क्षेत्र के नोवहोरोड-सिवर्स्की में तबाह हुई एक इमारत में लगी आग को बुझाते बचावकर्मी। एपी

कीव, रायटर: रूस ने मंगलवार को दक्षिण-पूर्व यूक्रेन के दो शहरों को निशाना बनाकर हमला किया, जिसमें आठ लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। कीव ने मास्को पर आरोप लगाया कि वह ईस्टर युद्धविराम पर सहमत होने की जगह हमलों में तेजी ला रहा है। इधर, यूक्रेनी ड्रोन हमले में रूस में एक बच्चे और उसके माता-पिता समेत पांच लोग मारे गए।

यूक्रेन के ड्निप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र के गवर्नर ओलेक्स गांझा ने टेलीग्राम पर एक पोस्ट में बताया कि मास्को की सेना ने क्षेत्र के पूर्वी इलाके में दो बसों को निशाना बनाया। निकोपोल शहर के एक स्टाप की ओर पहुंच रही एक बस पर एफपीवी (फर्स्ट-पर्सन-व्यू) ड्रोन से हमला किया। कुछ देर बाद इलाके में एक अन्य बस पर हमला किया गया। अधिकारियों ने बताया कि निकोपोल में चार लोग मारे गए और 16 घायल हो गए। दूसरी बस पर हुए हमले में पांच लोग घायल हुए। जबकि खेरसन शहर पर लगातार आधे घंटे चले रूसी हमले में चार बुजुर्गों की जान चली गई और सात अन्य घायल हो गए।

इधर, रूस के व्लादिमीर क्षेत्र के गवर्नर अलेक्जेंडर अवदीव ने बताया कि क्षेत्र में रात के दौरान एक यूक्रेनी ड्रोन हमले में 12 वर्षीय बच्चे और उसके माता-पिता की उनके अपार्टमेंट में मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि रूसी बलों के नियंत्रण वाले दक्षिण-पूर्व यूक्रेन के जपोरीजिया क्षेत्र में एक स्कूल पर हमला किया गया। क्षेत्र के मास्को समर्थित गवर्नर ने बताया कि वेलिकाया ज्नामेंका का एक स्कूल यूक्रेनी ड्रोन हमले की चपेट में आया। इसमें पांच बच्चों समेत छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बच्चों को बचाने में एक स्थानीय अधिकारी की मौत हो गई। जबकि यूक्रेनी ड्रोन हमले में रूस के नियंत्रण वाले इलाके में एक महिला की भी जान चली गई।

श्रीलंका से लौटे 30 भारतीय मछुआरे

कोलंबो, प्रेट्र: श्रीलंका ने 30 भारतीय मछुआरों को रिहा कर भारत भेज दिया है। भारतीय उच्चायोग के मुताबिक, तमिलनाडु के ये मछुआरे अब सुरक्षित अपने घरों की ओर लौट चुके हैं। इन्हें फरवरी में मछली पकड़ने के दौरान अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा पार करने के आरोप में पकड़ा गया था।

श्रीलंकाई नौसेना ने इन्हें हिरासत में लेकर जाफना जेल में रखा था। अदालत की प्रक्रिया और दोनों देशों के कूटनीतिक प्रयासों के बाद 31 मार्च को रिहाई का रास्ता साफ हुआ। जरूरी औपचारिकताओं और स्वास्थ्य जांच के बाद सभी मछुआरे चेन्नई पहुंचे, जहां से उन्हें उनके गृह जिलों के लिए रवाना किया गया। श्रीलंकाई नौसेना के अनुसार, अप्रैल 2026 तक 15 ट्रालर और 102 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि दोनों देशों के बीच आए दिन मछुआरों द्वारा अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा का उल्लंघन किए जाने का आरोप लगता रहता है।

पाकिस्तान-अफगानिस्तान युद्ध खत्म करने के लिए मध्यस्थता कर रहा चीन

- पाक-अफगान के बीच फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद से दोनों देशों के बीच यह पहली बड़ी राजनयिक वार्ता है

चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का झंडा। फाइल

बीजिंग, प्रेट्र: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष समाप्त करने के लिए चीन की मध्यस्थता में चल रही वार्ता एक सप्ताह बाद भी जारी है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने मंगलवार को कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संवाद को सुगम बनाने के लिए चीन मध्यस्थता के प्रयास कर रहा है। इसमें लगातार प्रगति हो रही है।

पाकिस्तान- अफगानिस्तान के बीच फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद से दोनों पड़ोसी देशों के बीच यह पहली बड़ी राजनयिक बातचीत है। यह वार्ता चीन के शिनजियांग प्रांत की राजधानी उरुमकी में हो रही है। इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अधिकारी शामिल हैं।

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर आतंकियों को शरण देने का आरोप लगाया है, वहीं संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने कहा है कि इस्लामाबाद के पास अपने आरोपों के पक्ष में विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। अफगानिस्तान ने भी आरोपों से इन्कार किया है। संयुक्त मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर हमला संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत बल प्रयोग पर लगे प्रतिबंध का उल्लंघन है।

अदाणी ने की एसईसी का मुकदमा खारिज करने की मांग

न्यूयार्क, प्रेट्र : उद्योगपति गौतम अदाणी ने अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) द्वारा दायर प्रतिभूति धोखाधड़ी के मुकदमे को खारिज करने के लिए अमेरिकी अदालत में याचिका दायर की है। उन्होंने दलील दी कि यह मामला अमेरिकी कानून के अनुचित क्षेत्राधिकार के प्रयोग का है और इसमें व्यक्तिगत अधिकार क्षेत्र की कमी है। एसईसी ने नवंबर, 2024 में अदाणी समूह के संस्थापक और उनके भतीजे सागर पर मुकदमा दायर किया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने भारतीय अधिकारियों से जुड़ी कथित रिश्वत योजना को उजागर नहीं करके निवेशकों को गुमराह किया था। एसईसी ने यह मामला अमेरिकी प्रतिभूति कानूनों के तहत दायर किया था।